Tuesday, April 11, 1978
Chaitra 21, 1900 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Sixth Series)

Vol. XIII

[April 5 to 19, 1978/Chaitra 15 to 29, 1900 (Saka)]

Fourth Session, 1978/1899—1900 (Saka)

(Vol. XIII contains Nos. 31—40)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 35, *Tuesday, April* 11, 1978/*Chaitra* 21, 1900 (*Saka*)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions:	
*Starred Questions Nos. 678, 680 to 682, 685 to 687, 690, 692, 695 and 689	1—34
Written Answers to Questions:	
Starred Questions Nos. 677, 679, 683, 684, 688, 691, 693 and 694	34—43
Unstarred Questions Nos. 6371 to 6414, 6416 to 6500 and 6502 to 6530	44—227
Re. Reported burning of effigy of Shri Jagjivan Ram at Banaras .	227—31
Papers laid on the Table	231-32
Re. Notices under Rule 377	232—34
Calling Attention to matter of urgent public importance—	
Police firing at the Bailadila Iron a Ore Mines on 5-4-78 . .	234—63
Shri D. G. Gawai	234,240—42
Shri Biju Patnaik	234—40,242—44,262-63
Shri Vasant Sathe.	244—52
Shri Y. P. Shastri	253—58
Shri Daya Ram Shakya	260—62
Committee on Public Undertakings—	
Second Report	263-64
Matters under Rule 377—	
(i) Supply of Benzene by Hindustan Steel Plants to M/s Synthetics and Chemicals Ltd. Bareilly—	
Shri Surendra Bikram	264
(ii) Reported sacking of seven employees of Gandhi Darshan—	
Shri Vasant Sathe.	264-6

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

(iii) Reported police firing on agriculturists in Vedasandur village in Madurai District—

Shri R. V. Swaminathan 265-66

(iv) Service conditions of temporary officers in Indian Railway—

Dr. Vasant Kumar Pandit 266-67

Demands for Grants, 1978-79 :

Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture— 267—382

Shri Ram Naresh Kushwaha . . . . . . 267—78

Prof. Dilip Chakravarty . . . . 278—88

Shri Mukunda Mandal . . . . 281—92

Shri Vijay Kumar Malhotra . . . . . . 292—304

Shri R. Kolanthaivelu . . . . 304—308

Shri A.E.T. Barrow . . . . 308—16

Shri Bhanu Kumar Shastri . . . . 316—22

Shri Dhirendranath Basu . . . . 322—25

Chowdhry Balbir Singh . . . . 326—31

Shri Charan Narzary . . . . 331—36

Shri Vasant Sathe . . . . 336—40

Shri S. S. Das . . . . 340—45

Shri Om Prakash Tyagi . . . . 345—52

Shri A. Sunna Sahib . . . . 352—56

Shri Chandra Shekhar Singh . . . . 356—63

Shri Phirangi Prasad . . . . 364—68

Shri G. Narsimha Reddy . . . . 369—72

Shri Roop Nath Singh Yadava . . . . 372—79

Shrimati P. Chavan . . . . 379—82

LOK SABHA

Tuesday, April 11, 1978/Chaitra 21, 1900 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जिला गोरखपुर में एक उपरि-पुल का निर्माण

*678. श्री फिरंगी प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को प्रति वर्ष जनवरी में योगिराज श्री गोरखनाथ जी के मन्दिर में बहुत दिनों तक लगने वाले बड़े मेले मे जाने के लिए उत्तर प्रदेश में जिला गोरखपुर मे पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय की ओर से पश्चिम की ओर जाने के लिये लगभग ½ फर्लांग रेल लाइनों को पार करना पड़ता है और वहां पर कई दुर्घटनायें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थान पर उपरि-पुल का निर्माण करने के लिये हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है जिस से लोग रेल लाइन के दूसरी ओर आ जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री फिरंगी प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के (क) भाग में भी स्पष्ट है कि मेला लगता है कि नहीं ? दूसरी बात यह है कि रेल लाइन को क्रौस करके जाना पड़ता है कोई दुर्घटना होती है कि नहीं। यह तीनों बातें पहले ही प्रश्न मे है, और जैसा कि आप जानते हैं माननीय रेल राज्य मंत्री बस्ती के ही रहने वाले हैं, और यह बातें सही होने पर भी उत्तर में ना कर दिया गया है। इस पवित्र स्थान पर योगिराज गोरखनाथ का मन्दिर है और जितने भी राष्ट्रपति या राज्यपाल हुए हैं अधिकांश वहां गये हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया है, इसका मुझ दुःख है। तो क्या मंत्री जी अब भी इस उत्तर में संशोधन कर के यह बतायेंगे कि इतनी बातें होती हैं कि नहीं—मेला 14 जनवरी से शुरू हो जाता है। तो क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि अब भी यह बात सत्य है कि नहीं, तब मैं दूसरा प्रश्न आगे पूछूंगा।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष जी, मेला लगता है यह बात सही है हर जनवरी में और मेरे मित्र ने कहा कि वहां पांच साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वहां हमारा लेवल क्रासिंग है उस पर जाते हैं। डिमान्ड है ओवर ब्रिज की। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागत का अपना हिस्सा देने की स्वीकृति नहीं दी है। हम अपना शेयर देने को तैयार हैं। 50 परसेंट उत्तर प्रदेश सरकार का शेयर है और 50 परसेंट हमारा शेयर है। इस पुल को बनवा देंगे, लेकिन अगर वह अपना हिस्सा नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। इस के अलावा प्रदेश सरकार ने अभी तक इस काम को करने के लिये पहुंच मार्गों के नक्शे और एस्टीमेट नहीं दिये हैं। ओवर

ब्रिज बनाने के बाद समाचार बन्द करने की अभी तक उन्होंने अनुमति नहीं दी है और न हो पहुंच मार्गों के लिये भूमि अध्यापित की है।

श्री फिरंगी प्रसाद: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस क्रासिंग पर कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ? मेरी जानकारी यह है कि अभी 14 जनवरी, 1978 को ही वहां पर एक ट्रक और राज्य सड़क परिवहन की बस में भिड़न्त हो गई जिसमें 6 आदमी घायल हो गए, और एक आदमी मर गया। बाद में दो लड़कों के जीवन खतरे में होने की सूचना मिली है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर इतनी घटनाएं हो जाने के बाद क्या वह उत्तर प्रदेश की सरकार को इस के मानने या मनवाने के लिये पहल करेंगे ? क्या वह निश्चित रूप से बतायेंगे कि कितनी धनराशि लगेगी, क्योंकि 50 प्रतिशत से बात स्पष्ट नहीं होती ? कब तक इस पर पहल कर के निश्चित जानकारी करायेंगे ?

SHRI SHEO NARAIN: I require notice for the question. The information is not with me.

श्री हरिकेश बहादुर: माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिये उन को नोटिस चाहिये, यह ठीक बात है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर नार्थ ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर है और वहां 25 हजार रेलवे के कर्मचारी काम करते हैं। पूरे गोरखपुर में अगर किसी जगह पर फ्लाई ओवर बनाने की जरूरत है तो वह केवल गोरखनाथ क्रासिंग पर है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 50 फीसदी धनराशि देने के लिये वह तैयार हैं, अगर इतना ही पैसा राज्य सरकार दे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में लिखा है या यह काम वह हम लोगों पर छोड़ना चाहते हैं ? हम तो बराबर कहते रहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री शिव नारायण: स्टेट गवर्नमेंट हमारे मातहत नहीं है, हम उस को डायरेक्टिव नहीं दे सकते हैं, हम अपना शेयर दे सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल अपने रेल मंत्री जी से कह कर चीफ मिनिस्टर को इस बारे में चिट्ठी लिखा देंगे।

कीर्ति एक्सप्रेस, सोमनाथ मेल तथा सौराष्ट्र मेल में डीजल इंजन लगाने की व्यवस्था

*680. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीर्ति एक्सप्रेस (पोरबन्दर-मेहसाना) सोमनाथ मेल (वेरावल-अहमदाबाद) और सौराष्ट्र मेल (वेरावल-वीरमगांव) गाड़ियों में डीजल इंजन नहीं लगाये जाते हैं और यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ख) इन तीनों रेलगाड़ियों में कब तक डीजल इंजन लगाये जायेंगे और सौराष्ट्र के लोगों की मांग कब तक पूरी की जायगी; और

(ग) क्या उक्त तीनों गाड़ियों की गति बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस प्रकार का और गति कब और किस प्रकार बढ़ाई जायेगी तथा इन की वर्तमान गति क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) और (ख) जी हां, क्योंकि डीजल रेल इंजन सीमित संख्या में उपलब्ध हैं और साथ ही रेल पथ की हालत को ध्यान में रखते हुए रफ्तार पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इन प्रतिबन्धों के फलस्वरूप गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है।

(ग) रेलपथ और कर्षण की वर्तमान हालातों को देखते हुए गाड़ियों के चालान-

समय को कम करने के लिये सभी व्यावहारिक प्रयास किये जाते हैं । तथापि, वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर खण्ड को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। और इस आमान परिवर्तन के पश्चात इन खण्डों पर गाड़ियों की रफ्तार में सुधार हो जायेगा ।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : कीर्ति एक्सप्रेस, सोमनाथ मेल और सौराष्ट्र मेल वगैरह गाड़ियों के लिये डीजल रेल इंजन कब तक उपलब्ध किये जायेंगे, और इन गाड़ियों के रेल-पथ की हालत कब तक सुधारी जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते : रेल गाड़ियों की रफ्तार के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब तक नैरोगेज और मीटरगेज की गाड़ी चलती हैं उस में अगर हम डीजल इंजन लगा देते हैं तो गाड़ियों की रफ्तार कम करनी पड़ती है । अगर 65.75 की रफ्तार है तो उसे करीब करीब 50 तक करना होगा । मैं नहीं चाहता कि डीजल इंजन से रफ्तार कम हो क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आगे चल कर जब कन्वर्शन करेंगे तो यह हो सकता है ।

वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर खंड की लाइन पर हमारा काम चालू है, उस की पूरी कास्ट 60 करोड़ रुपये है, आज तक 20.3 करोड़ रुपया खर्च किया है और आने वाले साल के लिये 7.93 करोड़ की सेंक्शन हुई है । हमारी आशा है कि 1981 तक यह कनवर्शन का काम पूरा हो जायेगा । उसके बाद डीजल इंजन लगायेंगे; तो रफ्तार जरूर बढ़ सकती है ।

श्री धर्म सिंह भाई पटेल : मंत्री महोदय ने बताया है कि इन गाड़ियों के चालन समय को कम करने के लिए सभी व्यावहारिक प्रयास किए जाते हैं । पोरबंदर-मेहसाना कीर्ति एक्सप्रेस गाड़ी नम्बर 35 पोरबंदर से जैतलसर जंक्शन पर 6-15 बजे सायं पहुंचती है और 6-45 बजे सायं पर छूटती है और इस प्रकार जैतलसर पर उस का हाल्ट 30 मिनट का होता है । फिर वह राजकोट पर रात के 9-05 बजे पहुंचती है और वहां से रात के 9-45 बजे छूटती है; राजकोट में उस का हाल्ट 40 मिनट का होता है । फिर वह वीकानेर पर रात के 10-45 बजे पहुंचती है और वहां से रात के 11.20 बजे छूटती है । वीकानेर में उस का हाल्ट 35 मिनट का होता है । इसी तरह सुरेन्द्रनगर में उस का हाल्ट 20 मिनट और वीरमगाम में 20 मिनट का है । कुल मिला कर उस का हाल्ट 135 मिनट का होता है, जो कि बहुत ज्यादा है । इसी तरह सोमनाथ मेल और सौराष्ट्र मेल वगैरह गाड़ियां भी बहुत हाल्ट करती हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सभी गाड़ियों के हाल्ट को कम करने के लिए क्या मंत्री महोदय कोई कदम उठायेंगे, यदि हां, तो क्या और कब तक ।

प्रो० मधु दंडवते : कई माननीय सदस्यों का कहना है कि अगर हम हाल्ट का समय कम कर दें, तो गाड़ी का समय कम हो सकता है । लेकिन दिक्कत यह है कि हर लाइन की एक निश्चित लाइन कैपेसिटी होती है, और यह क्षमता अपर्याप्त होने की वजह से कई बार हम को गाड़ी तेज चलाने से मना किया जाता है, उस पर पाबन्दी लगाई जाती है; स्टेशन पर गाड़ी को ज्यादा देर तक ठहरना पड़ता है क्योंकि आगे चल कर लाइन क्लीयर नहीं मिलता है । सैचुएशन कैपेसिटी, अपर्याप्त कैपेसिटी होने की वजह से हम इस में तब्दीली नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा विचार चल रहा है कि कैपेसिटी को एडजस्ट कर के और लाइन कैपेसिटी को बढ़ा कर हर स्टेशन पर गाड़ी के ठहरने के समय को कम करने का इन्तजाम किया जाये ।

PROF. P. G. MAVALANKAR: While I am glad that the Minister replied to the original question in Hindi, that Hindi was slightly different from the Hindi he used in his answers to supplementary questions. So, I could not follow the original question fully.

Anyway, since I had raised this question myself, as you will recall, I would like to ask him specifically two things. In view of the fact that conversion from metergauge to broadgauge from Okha to Porbandar line, as he has mentioned, will take many more years, in the meantime, how does he go about speeding up the trains in Saurashtra region, where railway travel is notoriously very long; it consumes many many hours. He has answered that it is only after conversion that things will be all right.

MR. SPEAKER: These are particular questions relating to particular regions.

PROF. P. G. MAVALANKAR: All these trains are only in Saurashtra region. I have travelled by these three trains. I have also raised questions of these three trains more than once in the past one year. People like us who have no official cars have to travel by these trains. These trains take a lot of time. The hon. Minister is so dynamic; he spoke well yesterday in Hindi and the Prime Minister gave his compliments to him for his dynamism and I share the giving of that compliment. Will he not do something in this regard in Saurashtra region where for decades trains are so delayed and time consumed is too long? I would request him to come himself one day and look up this for himself. Please do not ask us to wait till the conversion is over by the end of this century.

PROF. MADHU DANDAVATE: In the first place, he has referred to the Hindi spoken by me. As the hon. Member knows, the style of written Hindi spoken and spoken Hindi will be always different. In my supplementaries, I might have used the simpler words than those which have been used in the written answer. For instance, for traction, the word used in the written answer is karshan. He would not have followed, and, therefore, I used the word traction in answer to supplementary questions. There is, therefore, no difference.

As regards particular region of Saurashtra, I wish to inform the hon. Member that there are certain short-range schemes and certain long-term projects. As far as conversion scheme is concerned, we have set the target date as 1981 and by that it will be positively completed, even before that. I might also remind the hon. Member that a similar question was put by him some time back and when I gave the detailed answer, he said in this very House "I am completely satisfied with the answer and I do not want to ask any other question."

PROF. P. G. MAVALANKAR: I agree. Even today I am satisfied.

PROF. MADHU DANDAVATE: In spite of that satisfaction, if some residual dissatisfaction is there, I will try my best with my dynamism to remove that.

Expenditure in connection with Civil Suit against U.S. Drug Firms in U.S. Courts

*681. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to lay a statement showing:

(a) whether it is a fact that the Government have spent more than Rs. 11 crores so far in connection with a civil suit filed by it in U.S. Courts against 6 American drug manufacturing companies—PFIZER, CYANA-

MIDE, SQUIBB, BRISTOL and MYERS, UPJOHN AND OLIN under the U.S. anti-trust laws for allegedly having entered into a conspiracy for price fixation on broad spectrum anti-biotics and over charging on domestic as well as overseas purchases; and

(b) if so, important details of the cases instituted case-wise, the period for which the cases are pending, expenditure incurred on each of such cases so far and further action proposed, provision made/estimated expenditure incurred on this account for 1978-79 and damages recovered so far or likely to be recovered?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No, Sir.

As at the end of November, 77 the total expenditure incurred for the payment of legal fees and services rendered by our Legal Counsel was of the order of US $ 1,32,592.31 or approximately Rs. 12.05 lakhs.

(b) A concerted Civil suit was filed against all the six US Defendant Companies in the US Courts on 11th October 1974. During the year 1978-79 a budget provision of Rs. 3.5 lakhs has been made for this. No expenditure has, however, been incurred so far against this provision.

Following the judgement of the US Supreme Court in January, 1978 that a Foreign Nation is also a "Person" within the meaning of the Clayton Act and thus entitled to sue for damages under the US Anti-Trust Laws, the Government of India, in consultation with the Legal Counsel are taking necessary action to file a Damage Brief' in the US Courts.

SHRI VASANT SATHE: The first thing I would like to know from the hon. Minister is: what is the extent of damage involved? What is the total amount that you expect or that you have showed them by way of damages in these cases?

Secondly, could you kindly give us, as I have already asked in the question, some important details of the case? That means, what is the charge actually against these concerns for which for a breach of contract or whatever it be, you have filed a suit for damages?

SHRI H. N. BAHUGUNA: The damage brief is being quantified currently and it will take sometime for the government to come to a conclusion on the exact amount....

SHRI VASANT SATHE: Approximately. After all you have filed suits already in 1974. How could you have filed the suits without quantifying the damages?

SHRI H. N. BAHUGUNA: The question initially was whether we can file a suit and whether we were included in the term 'a person' within the meaning and ambit of the Anti-Trust Laws. That question was a legal and theoretical question which has been decided now by the US Supreme Court and we have now to file the damage brief before the appropriate court. We have got to find out from different sources as to what were the total imports of this broad spectrum of anti-biotics for which they were over-charged. The basic thing was that they were over-charged. They should not have been charged at the level at which they were charged. This relates to the period 1953-54 to 1963-64 and we have got to find out from different sources—military, railways, CPC or the STC and organizations like the Medical Health Organisation as to what were the total imports and whether they were canalised items or non-canalised items. We have to find out the total amount ....

SHRI VASANT SATHE: Some broad idea you must be having.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I am telling you—I cannot at present give even a broad idea because that may be used against us by the defendants. This particular discussion here may be used by them to say, 'Initially you said 'X' amount and now you are saying 'Y' amount.' Therefore, as a matter of abundant caution, I cannot be exact. It may be somewhere. I cannot really exactly put myself on the figure. If I say anything, that will not be again exact. But I want to be exact on the whole question. Therefore, I am sorry the legal advice is that we should for the present not give it. But I would like to assure the House that as soon as we file the case, I will let the House know that we have filed a suit for so much of damages.

SHRI VASANT SATHE: It is not yet clear. If the matter is as old as you say 1953—61....

SHRI H. N. BAHUGUNA: 1964.

SHRI VASANT SATHE: Yes, 1964. Then the first point is which is that law? As you told just now, is it the Clayton Act under which you have filed the suit? And was it in your case that the Supreme Court gave this decision that a country is a person' or was it in some other case? Because why do you have to wait if it is a decision given in your case? In that case you should have formulated already your case and prepared the brief on a cause of action. What is that brief on the cause of action? Why cannot that be mentioned?

SHRI H. N. BAHUGUNA: We joined the legal proceedings following two issues before the U.S. Appeal Court. We joined at that stage. We became a party to the dispute and the two points were—

(i) Whether a foreign nation is a person as defined in the U.S. Anti Trust Laws entitled to sue the Defendant in the U.S. Court?

(ii) whether a foreign nation can bring action in U.S. Court as official representatives of the claims of its citizens?

We became a party on the basis of these two issues. The Court of Appeal decided first issue saying 'yes, the foreign nations were also a person! On Issue No. 2, they decided against us. We could not or a group of people cannot in any concerted way file an appeal for damages. That means imports made by individuals during this period could not be a subject matter which we could take up for a suit of damages. That means individuals will have to file ndividual cases. But if the Government has imported something through 'X' agencies, we could do it. The question, therefore, was one of principle in which we became a party at the stage of U.S. Appeal Court.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: Will the Minister be pleased to state, in view of the fact that enormous amounts are being expended for litigation, and there is no permanent machinery in the U.S. for conducting litigation, and many cases are lost because the period of limitation is over and a large number of officers have to go from here and stay there for a number of months, does the Minister propose to have a permanent machinery for litigation either Washington based or New York based?

SHRI H. N. BAHUGUNA: So far as the general question is concerned, I do not think this arises out of this. In this particular case arrangements were made in 1974. Agreement has been entered with a Company of Solicitors—Lawyers in U.S.A. Payment has been made to them. One of the officers went there for ten days to brief them. They have come here and taken the brief. I do not think, for this particular case there is....

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: There is an officer who has been staying there for the last ten months.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I am willing to check the information. The information as available to me is 'ten days'.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: I can mention the name if you want.

SHRI H. N. BAHUGUNA: The hon. Member has been the Minister of Law. Perhaps, it was during his period that the officer remained for ten months He must be knowing better.

Extension of Qutab Express to New Delhi Station

*682. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether despite the insistent and long standing public demand for the extension of the Qutab Express to New Delhi, Government have not seen its way to meet it; and

(b) whether now its less than optimum utilisation on account of its termination at Hazarat Nizamuddin is being made a ground for the cancellation of this train?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Extension of Kutab Express to and from New Delhi is operationally not feasible due to lack of terminal facilities at New Delhi.

(b) No, Sir. There is no proposal to cancel this train. However, this train is being extended to and from Jabalpur from May, 1978.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: A very reasonable and long standing demand and very trifling demand too, for the extension of the Qutab Express from Hazarat Nizamuddin to New Delhi has been turned down on the ground of feasibility. I may point out that apart from the time, trouble and inconvenience caused in getting a conveyance, the expenses from Hazarat Nizamuddin to New Delhi by taxi or scooter come to as much as Second Class Railway fare from Agra to Hazarat Nizamuddin. If you have got luggage, there is no end to the trouble. Yesterday, it took us we were three Members of Parliament—45 minutes to get a conveyance.

The demand has been turned down. Why? On the ground of feasibility. So far as feasibility is concerned, I msut say....

MR. SPEAKER: Please remember that this is Question Hour.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: It has to be devised. It has to be contrived. Where there is a will there is a way. Now, Sir. I ask this. Has the Minister taken into consideration the suggestion which we made? We made a suggestion that the Sri Nagar Express can be extended from Hazarat Nizamuddin to New Delhi and the Qutab Express can be extended in the reverse direction. It will satisfy our demands. It will not be difficult in any way. Sir, the pattern of traffic on this Agra—Mathura—Delhi route is just like the traffic between Bombay and Poona.

MR. SPEAKER: You are making a speech.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: I am just giving the background.

MR. SPEAKER: You are giving out a suggestion. That is evident. That should be done otherwise, not in Question Hour.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: I am only telling him about the pattern of traffic. The character and the pattern of traffic is just like that between Bombay and Poona. The facilities that exist there may also be given to us. That is our demand and that is the suggestion that is given.

MR. SPEAKER: He has made a suggestion.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): I may inform the Hon. Member that with all our desire to take that train to New Delhi, there are certain physical difficulties as to why we cannot take it to New Delhi. For extending any train to a further stage we have to ensure that there is adequate terminal capacity and terminal capacity does not merely consist of increasing the number of platforms. In order that the train should be allowed to terminate at a given station, the terminal capacity should consist of more platforms, more watching lines, more stabling lines, more shunting facilities and loco sheds where the locomotives can be changed. And since today the terminal capacity at New Delhi is totally saturated, just now there is no room for any additional train being taken there. But we will take his alternate suggestion into account. He must really know the difficulty that I will not be able to satisfy him but I will be able to create dissatisfaction in the minds of those who are going to Srinagar and therefore we have equitably to distribute the dissatisfaction between him and people coming from Srinagar.

MR. SPEAKER: Second supplementary. Not second speech.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Yes, Second Supplementary. Sir, I have made a suggestion. It does not affect the passengers coming from Srinagar because they will come *via* New Delhi to Hazarat Nizamuddin. Qutab Express can be extended in the reverse direction. May I get an assurance from the Hon. Minister in this regard? Will the Minister also arrange for a connecting train from Hazarat Nizamuddin to New Delhi, so that the present difficulty could be obviated? Secondly, I want to know whether he will attach two second class bogies to this train between Agra and Hazarat Nizamuddin if this train is extended to Jabalpur. Agra has now become an intermediate station instead of being a terminal station. You can well imagine the difficulties which arise therefrom in regard to reservation and accommodation in general.

PROF. MADHU DANDAVATE: There are two answers. If we try to provide them a connecting train with some time-lag in between the two, probably before they get into the train to reach New Delhi, prior to that, they will be able to take a taxi and reach New Delhi. He will withdraw his suggestion after he gets the experience. So, that is impracticable. But I will give him a good information. Already we have a scheme of remodelling the entire New Delhi Station. It is already in progress. And soon, if we are able to remodel it with increased terminal capacity, all his difficulties will be removed, to that extent.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : माननीय मंत्री जी ने कुतुबएक्सप्रैस को जबलपुर तक बढ़ा दिया है—इस के लिये में उन्हें धन्यवाद देता हूं । में मंत्री महोदय से जानना चाहता चाहता हूं—कुतुब एक्सप्रैस जो अब जबलपुर तक चलेगी वह मानिकपुर और झांसी के बीच में केवल करबी, बांदा और हरपालपुर पर रुकेगी, जब कि बीच में कई बड़े-बड़े स्टेशन्ज जैसे उत्तरी महौबा, मऊरानीपुर, निवाड़ी, छूट जाते हैं । क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि वह ट्रेन इन स्टेशनों पर भी रुके ?

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्यों की तरफ से दो प्रकार की मांगे आती हैं । चन्द एम०पीज यह मांग करते हैं कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई जाये लेकिन चन्द एम०पीज यह कहते हैं कि हाल्स बढ़ाये जायें । विशेषकर जिन की कांस्टीचूयएन्सीज से वह ट्रेन गुजरती है, उन की मांग यह रहती है कि हाल्टस ज्यादा दिये जायें । हमने इस के बारे में कुछ कसोटियां नय की हैं, कुछ नाम्जे निश्चित हैं । जब भी

किसी तरफ से कोई सुझाव आता है, हम उस कसौटी के आधार पर जांच करेंगे और जांच करने के बाद यदि हाल्ट दे सकेंगे तो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे ।

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है । आप मेरी बात सुन लीजिए । यह ट्रेन रोकने का मसला कोई राष्ट्रीय सवाल नहीं है । आप को यह जानकारी होनी चाहिये कि यह श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी और मेरे संसदीय क्षेत्र का सवाल है । . . . (**व्यवधान**) . . . . जब हम सवाल पूछते हैं तो आप नैक्स्ट क्वेश्चन कह देते हैं । मेरा निवेदन यह है कि मेरा संसदीय क्षेत्र इस से प्रभावित होता है । इसलिए मुझे इस बारे में सवाल पूछ लेने दीजिए ।

MR. SPEAKER: You have put the question.

श्री रामजी लाल सुमन : हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए इस ट्रेन का विशेष महत्व है । इसलिए विनम्र निवेदन है कि मेहरबानी कर के मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए ।

MR. SPEAKER: There is no point of order.

श्री रामजी लाल सुमन : इस में कहां की तुक है । मैं नहीं बैठूंगा ।

वर्ष 1978–79 में चलायी जाने वाली जनता रेलगाड़ियां

***685. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978–79 में पूरे देश में कितनी जनता रेलगाड़ियां चलाई जायेगी;

(ख) क्या सरकार, का विचार अमृतसर-मुरादाबाद-हावड़ा लाइन/रूट पर इस की महत्ता को देखते हुए जनता रेल गाड़ियां चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) 1978–79 के दौरान अब तक 145–146 मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस 6-4-78 से चलायी गयी हैं, जो श्रेणी रहित गाड़ी हैं । अक्तूबर, 1978 में जब समय-सारणी में संशोधन किया जायेगा, तब और अधिक श्रेणी-रहित गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

(ख) और (ग). हावड़ा और अमृतसर के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एक अतिरिक्त गाड़ी हावड़ा और अमृतसर के बीच में चलाना व्यावहारिक नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद डिवीजन की अमृतसर और हावड़ा के बीच में पिछले 30 वर्षों से लगातार अवहेलना की गई है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह जो मांग की गई है यह मांग बिल्कुल न्यायोचित है । वहां पर ट्रफिक इतना अधिक बढ़ चुका है कि उस को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन, जिस को जनता ट्रेन के नाम से सम्बोधित किया गया है, चलाना बहुत जरूरी है और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ट्रैफिक को देखते हुए और ट्रफिक के आंकड़ों के आधार पर क्या वे वहां पर ट्रेन चलाने की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं, व सही हैं और वहां पर ट्रैफिक डेंसिटी काफ़ी ज्यादा है और यातायात भी ज्यादा है लेकिन हम लोगों को दिक्कत यह है कि जहां तक अमृतसर स्टेशन का सवाल है, वहां करीब 76 पेसेन्जर ट्रेन्स जाती हैं और ऐसा होने की वजह से काफ़ी दिक्कत है लेकिन प्रसन्नता की एक बात मैं उन को बताना चाहता हूं और वह यह है कि आने वाली समय सारिणी में हम जांच

कर रहे हैं कि कहां कहां हम नई जनता ट्रेनें 'गीतांजलि' जैसी ट्रेनें चला सकते हैं जिन में सुविधाएं तो प्रथम श्रेणी की होंगी लेकिन वे द्वितीय श्रेणी की ट्रेनें होंगी और उन का द्वितीय श्रेणी का किराया होगा। इस प्रकार की जो नई ट्रेनें हम चलाने का विचार कर रहे हैं, वे हावड़ा, पटना, वाराणसी, लखनऊ, लुधियाना और जम्मू तक जाया करेंगी और भुवनेश्वर से सिकन्दराबाद, सिकन्दराबाद से बम्बई, पोरबन्दर, भावनगर से अहमदाबाद, इस प्रकार की गाड़ियों के लिए हम विचार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर इन्तजाम ठीक हो जाएगा, तो ये सब गाड़ियां शुरू करने में हमें सुविधा रहेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस के लिए मैं उन को बधाई देता हूं। इस के साथ ही यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो यह कहा कि अमृतसर से बहुत सी ट्रेनें छूटती हैं, उन की जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अमृतसर से आने वाली ट्रेनें अधिकतर दिल्ली हो कर जाती हैं और मुरादाबाद डिवीजन और लखनऊ डिवीजन को लगातार, जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 30 वर्षों से इग्नोर किया गया है, एवायड किया गया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आने वाली योजना के अन्तर्गत इस को और ट्रेनों से जोड़ेंगे। इस के लिए मैं उन को बधाई देता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जांच करवाएंगे तो यह पाएंगे कि दिन के समय मुरादाबाद डिवीजन में कोई भी ट्रेन ऐसी उपलब्ध नहीं है जो लखनऊ साइड या हावड़ा साइड या अमृतसर साइड की तरफ जाने वाली हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर दिन के समय आम जनता को ट्रेनें उपलब्ध हो सकें क्या माननीय मंत्री जी जनता गाड़ियों के साथ अन्य गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था वहां के लिए करेंगे?

प्रो० मधु दंडवते : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है, इस पर विचार करेंगे।

श्री एम० क० मोवलकर : इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल रेलवे पर कोई 50 वर्षों से केवल दो लाइनें दिल्ली से बम्बई की तरफ़ जाती हैं और उस के बारे में विचार करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है क्योंकि बम्बई में केन्द्रीय टर्मिनल की कपेसिटी कम है, तो क्या एक्चुअली कंसिडर कर के वे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलाने के लिए शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेंगे?

प्रो० मधु दंडवते : जब श्री मोवलकर खड़े हुए थे, तो उसी वक्त मुझे पता था कि ये क्या सवाल पूछने वाले हैं, इसलिए मेरा जवाब भी तैयार है। मैंने उन के साथ बातचीत भी की थी कि बम्बई पर टर्मिनल की सेचूरेशन कैपसिटी होने की वजह से वहां से गाड़ी नहीं निकल सकती। दिल्ली जाने के लिए सेन्ट्रल रेलवे पर लेकिन साऊथ की तरफ जाने वाली गाड़ियां बम्बई वी० टी से जो चल रही थी वे दादर से भी चलने लगी हैं और दादर की कैपेसिटी भी कम्पलीटली सेचूरेशन प्वाइन्ट पर आ गई है। ऐसा मैंने उनको वायदा किया है कि कल्याण या नासिक से दिल्ली तक जाने वाली सेन्ट्रल रेलवे की कोई गाड़ी हो सकती है या नहीं, उस पर हम विचार कर रहे हैं।

Wagon Allotment to Salt Industry

*686. **SHRI ANANT DAVE:** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any Memorandum from the Gandhidham Chamber of Commerce regarding salt Wagons has been received;

(b) the details of figure given by the Chamber regarding wagons;

(c) the reasons for which the salt industry and Minerals industry are not getting wagons; and

(d) actions taken by the Government in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The Chamber have requested for a special daily quota of wagons for movement of non-programmed salt under priority class 'E' and suggested an allotment of 100 wagons per day, both on the broad gauge and metre gauge, for this purpose.

(c) and (d). After a careful examination, daily quotas of 20 wagons on the broad gauge and 25 wagons on the metre gauge have been allotted on the Western Railway for movement of non-programmed salt. These quotas are being adhered to.

Loading of minerals from Kutch area is current.

श्री अनन्त दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बहुत बड़ी बधाई दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंटरी सवाल पूछने वाली कोई बात नहीं छोड़ी है, जो भी हमारी डिमाण्ड्स थीं वे सब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या हमें आश्वासन दिया जाएगा कि मिनरल्स के लिए जो हमें वैगंस नहीं मिल रहे है, वे भी हमें दिये जायेंगे, जब कि उन्होंने साल्ट के लिये वैगंस देने की बात को माना है?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सवाल पूछने के लिए ही सवाल पूछा है, वैसे उनका समाधान तो हो गया है। वैगंस के बारे में मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से हमारा जो नया फार्मूला है कि दस एकड़ की सीलिंग तीन एकड़ पर लायें और तीन एकड़ के नीचे की जमीन को [illegible] में ले आयें तो उनको जोनल सिस्टम में लाया जाए। इस तरह लायसेंस देने के बारे में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह सब काम हम जरूर करेंगे। अभी हमने एडहाक वेगन देने के बारे में तय किया है। मिनरल्स का लोडिंग तो करन्ट है।

PROF. R. K. AMIN: May I know from the hon'ble Minister since more than 60 per cent of the salt is being manufactured in Gujarat and that too concentrated in the western side of the coastal area would he think of evolving one gauge system—either broad or metre—so that carrying of salt to other parts becomes easier? Would he conduct an enquiry?

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, it is true that Gujarat area is a salty area and all the facilities should be given to them. As far as change of gauge is concerned I want to assure the hon'ble Member that if he relies only on the conversion of the gauge then he will have to wait for a longer time. Rather chain relying on gauge conversion the formula for wagon allotment will be preferable and this formula, I think, will be effectively implemented.

Construction of Railway Line in Iraq

\+

*687. SHRI R. V. SWAMINATHAN:
SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Iraq has offered a rail contract for construction of Baghdad Hsilah Akashat railway line;

(b) if so, whether India has accepted its offer;

(c) what are the details of agreement reached;

(d) whether Indian Railways have any such contract with some other foreign country during 1978-79;

(e) if so, the details of the same; and

(f) if not, whether Government propose to make any efforts in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (f). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

In response to a global tender notice issued by the Government of Iraq, the Rail India Technical and Economic Services Ltd. (RITES) and Indian Railway Construction Company Ltd. (IRCON), the two public sector undertakings under the Ministry of Railways, had jointly submitted a bid for the construction of the BAGHDAD-HSAIBAH-AKASHAT Railway line. Offers to undertake the construction of railway projects planned by other developing countries will also be made as and when tenders are issued.

No contract for such railway projects abroad has, however, been signed, so far.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: May I know whether it is a fact that one Mr. Jassim, President of the State Railway Organisation of Iraq and also some members of the High-Powered Commission of Iraq met the hon'ble Minister and had discussions. If so, what was the outcome of those discussions?

PROF. MADHU DANDAVATE: The discussions were of an informal type and exploratory in nature. They have only indicated that they would like to invite our team for further discussions and according to the invitation given to us our team of experts on behalf of the Railway Administration will be visiting Baghadad on 19th and 20th April. We have already submitted a global tender. There are some other countries who have also submitted their tenders and it is only after considering the relative merit and demerits of these tenders....which have been submitted by different countries that the final decision will be taken by the Iraqi Government for the final allotment of work. Anyway our team is proceeding to Iraq on 19th and 20th April and we hope that we will succeed in our task.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Regarding the contract, may I know from the hon. Minister—If the contract materialises—whether the experts will also include skilled and unskilled workers and they will be sent to Iraq and also to those countries where the contract is being undertaken?

PROF. MADHU DANDAVATE: Even our contract has not been accepted and he wants me to tell him about....

SHRI R. V. SWAMINATHAN: If it materialises....

PROF. MADHU DANDAVATE: It is against the international convention to give the details on the assumption that the contract has already been accepted. When even the engagement has not taken place, you are asking about the future of the couple.

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि कोलैबोरेशन के क्षेत्र को विस्तृत करने की दृष्टि से बन्दार अभास–वफ़ा रेलवे लाइन जो 700 किलोमीटर की ईरान में निर्माण की योजना है क्या भारतीय रेल की इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के द्वारा यह ऑफ़र दिया गया है ?

प्रो० मधु दंडवते : यह सवाल ईराक के बारे में है और जवाब ईरान के बारे में बोल रहे हैं ।

MR. SPEAKER: In your statement you have mentioned about Iran.

प्रो० मधु दंडवते : जो सुझाव हमारे पास आया है उसके बारे में विचार हो रहा है, चर्चा भी चल रही है अनौपचारिक तरीके से। लेकिन आखिर में कांट्रैक्ट होने के बाद ही हम बता सकते हैं अभी तफ़सील से नहीं बता सकता।

Promotion of Clerks Grade II to Grade I

*690. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no uniform policy is being observed in the matter of promotion of Clerks Grade I from amongst the Clerks Grade II who have come to new Mughalsarai Division from other Divisions and preference is being given to the clerks of Danapur Division ignoring the seniority of the staff of other Divisions who have come on transfer in the administrative interest;

(b) if so, the policy of the Government in this regard and action taken to stop the discrimination; and

(c) the policy of the administration to provide Railway quarters to the staff who have come on transfer to Mughalsarai and the action taken to provide them the actual possession of the quarters unauthorisedly occupied?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

In forming Mughalsarai Division the clerical strength for the Divisional office was to be obtained by bifurcation of the existing clerical strength of Danapur and Dhanbad Divisions. Because of opposition from the clerical staff of Danapur Division to moving men along with the posts, this bifurcation has not yet been completed. Meanwhile, for urgent requirements of work, some volunteers from other units have been taken. Pending finalisation of the cadre strength of Mughalsarai Division, the clerks transferred from other Divisions are kept separate. Each Group is being considered for promotion only against posts of their parent units. Posts of clerks Grade I falling vacant in the original strength of Danapur Division are being filled from Danapur Division staff only. This does not adversely affect the volunteers as they hold their lien in their parent units where their promotional prospects are protected.

Staff transferred from other Divisions are provided quarters along with other staff on the basis of station seniority, namely the date of joining at Mughalsarai. Departmental action is being taken against the staff who are occupying quarters unauthorisedly.

SHRI A. K. ROY: Mr. Speaker, Sir, whenever there is some room for discomfiture, a statement is always laid on the Table of the House. There is nothing clear. I would like to know from the hon. Minister the number of clerks of different Divisions who were transfered to Mughalsarai Division and in how many cases the principle of combined seniority has been violated.

PROF. MADHU DANDAVATE: Against 565 posts for the Divisional Office to be transferred from Danapur to Mughalsarai, 400 staff will have to be transferred. When orders were issued the staff having refused to accept the transfer, only 40 or so have so far carried out the transfer. The difficulty is that there is a difference of approach between the staff employed at Danapur and the staff at Mughalsarai. It is a ticklish question. Members belonging to the same Unions, members belonging to the same political parties, and members belonging to

the same organisations have been divided on this issue on geographical lines and therefore we are trying to establish a rapport between them. In the meantime we have given the stay order so that no hardship or harassment should be caused to any staff member and we assure you that in collaboration and in consultation with the parties and organisations concerned, we will amicably settle the problem.

SHRI A. K. ROY: The staff who have been transferred to the new Divisions, have been facing great difficulties because the quarters meant for them in the D. S. Colony have been occupied by somebody else. I would like to know from the hon. Minister the actual percentage of quarters for the Divisional Office. I would also like to know whether the quarters are being occupied by unauthorised persons. What is the percentage of quarters for the various categories of staff in this new Division?

PROF. MADHU DANDAVATE: Because the entire problem has remained pending, there is a lot of difficulty about the housing accommodation. But we propose to construct 245 quarters so that the problem can be solved. Even then it would not be solved hundred per cent because the accommodation is not provided to hundred per cent staff. But in order to facilitate the solution of the problem, we are undertaking the construction of 245 quarters. In the meantime, we will sort out the problem of transfer suitably and only when it is properly sorted out, we will see to it that the accommodation problem is tackled. In the meantime we are not disturbing the present arrangement of accommodation so that no harassment should be caused to the workers.

SHRI A. K. ROY: I just want to get one clarification. What is the percentage satisfaction of the workmen employed for whom the quarters have been built and what is the percentage of unauthorised occupation of quarters? He has agreed that there is unauthorised occupation. I want to know the extent of the problem in the mind or in the record of the Minister.

PROF. MADHU DANDAVATE: By giving the figures about unauthorised occupation, I do not want to legalise the unauthorised occupation and therefore, let us not go into the details, let us sort out the problem.

Overseas Operation by ONGC

*692. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether O.N.G.C. secured contracts in foreign countries for overseas operation; and

(b) if so, the countries with which contracts were made?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Yes, Sir. The O.N.G.C. has secured contracts in Iran, Iraq and Tanzania.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Is there any possibility of getting new contracts?

SHRI H. N. BAHUGUNA: Yes, Sir. Sure enough. We are trying all over the world and we are bound to get some more. I do not know where.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: What are the amounts for which the contracts have been signed in this affair?

SHRI H. N. BAHUGUNA: There are different contracts. With Iran, we have entered into an agreement with effect from 17-1-1965. This is in collaboration with NIOC of Iran as one party, Phillips Petroleum Company of USA and AGIP of Italy and Hydro Carbons India Private Limited, that is our company. The agreement was

signed on 17-1-1965. This says that the cost of exploration and exploitation will be shared under this agreement on this basis—fifty per cent of the produced oil would go to the NIOC and the remaining fifty per cent would be shared equally by the rest of the partners. So far as the other contracts are concerned we are doing it. Iraq National Oil Company had given us exploration and exploitation for an area of 4,175 sq. miles and this was ratified on 20th November, 1973. They have also given us some seismic and drilling contracts. It is not for oil sharing, it is a sort of money to be paid according to different type of work to be done. Now that is not the total sum but different items having different accounts. Then the third one is Tanzania. It was in December 1975 that ONGC entered into an agreement and the contract is for drilling operations which started in June 1976 again to be paid for different type of work. That is not something on a wholesale basis that so much money and so much work.

DR SUBRAMANIAM SWAMY: I would like to know from the hon. Minister in view of the fact that ONGC is in some kind of cloud due to the activities of the previous Government, how do the terms and payments given by the foreign countries to us or the ONGC compare with what we give them for doing their operations within this country.

SHRI H. N. BAHUGUNA: These are contracts which are already signed and I have not applied my mind to the comparative figures or the competitive figures. But the hard point is that this has put us on the world map.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: I would like to know from the hon. Minister the number of Indian technonogists and other type of personnel working in these countries on behalf of ONGC in Class, I, II, III and IV. Is there any condition laid down in the contract with regard to employing Indian personnel?

SHRI H. N. BAHUGUNA: So far as Tanzania and Iraq are concerned, we have hundred per cent complement of our officers and technical personnel of all clases. There are no Tanzanian or Iraqi nationals employed so far as these contracts are concerned. Our boys have gone there along with our equipment. So far as Iran is concerned, since there are more than one partner, therefore, there are different people. But we are also there.

SHRI K. LAKKAPPA: After entering into these agreements, have you thought of asking those governments for a reduction of oil price under these agreements?

SHRI H. N. BAHUGUNA: It is not something which is done because of the contract entered into with them, because it is a question of the quantity of oil in Iran which we get and not the price which we get. That oil sells at the same price as the world price or we bring it for ourselves. So far as Iraq is concerned, it is not a question of bringing oil. We are merely there on a job. The same is the case with Tanzania.

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यमों के अध्यापक

*695. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी माध्यम के लिए चुने गये अध्यापकों तथा अंग्रेजी माध्यम के लिए चुने गये अध्यापकों के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रवरता सूचियां बनाई जाती है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं जबकि उनके चयन के लिए कसौटी अलग अलग है ; और

(ग) क्या दोनों वर्गों के अध्यापकों के चयन में एकरूपता लाई जायेगी?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री चतुर्भुज: इस समय हिन्दी और अंग्रेजी के अध्यापकों की अलग अलग वरीयता सूचियां हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन में एकरूपता लाने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है।

SHRI SHEO NARAIN: The medium of instruction varies from zone to zone. Besides English and Hindi, in certain zonal regions, the students are taught in regional languages such as Bengali, Marathi, Telugu, etc.

श्री चतुर्भुज: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि रेलवे विभाग में हिन्दी और अंग्रेजी के अध्यापकों में एकरूपता लाने के लिए चयन-कार्य में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सिर्फ हिन्दी ही नहीं, बल्कि सभी देशी भाषाओं के के लिए लिस्टें रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी अध्यापकों की लिस्ट रखी हुई है। ये अलग अलग लिस्ट्स इसलिए रखी हुई हैं कि अलग अलग जोन्स में मराठी, गुजराती, बंगाली और तमिल आदि भाषाओं में अध्यापन-कार्य किया जाता है। कई जगह अंग्रेजी में किया जाता है। हम लोगों की लगातार यह कोशिश रहती है कि अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हों या देशी भाषाओं के, सभी अध्यापकों के लिए काम करने का एक ही तरीका रहे। जो अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में हैं, और तमिल या मराठी या बंगाली में पढ़ाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उन की पदोन्नति हो और वे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में चले जायें। हम ने यह व्यवस्था की है कि अंग्रेजी और देशी भाषाओं के शिक्षकों में किसी प्रकार की असमानता न हो, और वह कभी भी नहीं होगी, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री चतुर्भुज: रेलवे बोर्ड के अंदर कोई एजूकेशन का डायरेक्टर नहीं है तो क्या रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के अंदर किसी शिक्षा के डायरेक्टर की नियुक्ति करने का आदेश देंगे?

प्रो० मधु दंडवते: उन का जो सुझाव है उस पर हम विचार करेंगे लेकिन इन सब सवालों के बारे में विचार कर के हम लोगों ने आखिरी फैसले किए हैं। आप चाहते हैं कि बोर्ड की संख्या बढ़ा दें या कम कर दें तो उस के बारे में एक फैसला होना चाहिए। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने बहुत सोच समझ कर हमारे सामने कुछ नक्शा रखा था। उस को हम अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको भी कुछ सुझाव होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे।

श्री राम विलास पासवान: क्या रेल मंत्री को यह मालूम है कि विगत सरकार ने जो लोग अयोग्य भी थे, जिन को हिन्दी की कोई जानकारी थी ही नहीं, अंडर ग्रेज्युएट ग्रेज्युएट और वह भी थर्ड डिवीजन थे उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया था हिन्दी विभाग में? क्या सरकार कोई काइ-टीरिया निर्धारित कर के जो पुराने लोग पक्षपात पूर्ण तरीके से पिछली सरकार के द्वारा रखे गये थे उन को हटाएगी और फिर नये लोगों को उन की योग्यता के आधार पर रखेगी?

MR. SPEAKER: Mr. Paswan, it does not arise out of the question at all.

Policy regarding laying of New Railway Lines

*689. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a change in the policy of laying new

railway lines in the areas which do not have rail connections is under the active consideration of the Government and the "economically viable" criterion is to be given up; and

(b) if so, when a decision is likely to be taken and the new criteria evolved?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). A new policy for construction of railway lines in backward areas of the country is under consideration of the Government. The policy will be announced in the Parliament as soon as it is finalised.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, as it is clear from the answer of the Minister—so far the policy is yet to be announced. But there are some sectors in which the people are facing lot of hardships due to unavailability of railway lines. It results in the wastage of money and man hours. Will the hon. Minister take care to give first priority to those areas where survey has already been conducted, such as Haryana-Chandigarh railway lines, which need to have your first priority?

PROF. MADHU DANDAVATE: There are too many areas that are demanding priority No. 1 and the difficulty is that priority No. 1 can be only one. Therefore, to go into the problem we have already set up a Committee of officials that will review the capital structure of the railways and on the basis of our study we will make certain suggestions to the Finance Ministry and the Planning Commission and only under the overall policy of the Planning Commission we will have to function as far as the construction of railway lines is concerned.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: I would like to know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that in certain areas since Independence not even a single line is laid. For example, the Telengana area in Andhra Pradesh. You know. Sir, he is very dynamic—not only dynamic, but he happens to be my good friend. He was sitting here for six years with me. He will also appreciate the fact. In this connection I would like to know whether he is going to lay new lines from Ramagundam to Nizamabad via Karimnagar. That demand is there since Independence and for six years I have been fighting for it and he also sympathises. But he does not do anything at all with regard to this.

PROF. MADHU DANDAVATE: Let me assure the hon. Member that I was his friend not only when I was sitting there, but even when I sit here I continue to be his friend. I am also the friend of the area from which he has come because that is one of the most backward areas that has created more problems and on various lines which were under consideration from the point of view of the development of backward area. The region to which he has referred to is definitely in our mind. The only question is getting of more allocations for the development of lines in the backward areas. For that concrete alternatives have been formulated and the moment they are cleared we will be able to go in for the line to which he has made a reference.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTONS

Over-Crowding in Pashchim Express

*677. SHRI SOMJIBHAI DAMOR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on Western Railway A/C Express (De. luxe), Pashchim Express are running over-crowded;

(b) if so, what steps have been taken to help the passengers; and

(c) is it possible to provide one more Second Class ordinary coach in this train; and if not, why?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) 25/26 Bombay Central New Delhi/ Amritsar A.C./Paschim Expresses are popular trains. There is some overcrowding in the unreserved portion of the train and passengers are on the waiting list for reserved accommodation.

(b) and (c). Augmentation of the loads by these trains is not feasible as these trains are already running with maximum loads. Other measures are, however, under consideration to meet the passenger demand on this route.

Gas based Fertilizer Plants

*679. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have approved the proposals to set up four gas-based fertilizer plants in the country at a cost of Rs. 800 crores; and

(b) if so, the details of such proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) and (b). Two large sized fertilizer plants based on gas from Bombay High and South Bassein are proposed to be taken up for implementation. The plants would each have a capacity for the manufacture of 1350 tonnes per day of ammonia and 1800 tonnes per day of urea and are together estimated to cost Rs. 491 crores with a foreign exchange component of about Rs. 280 crores. A Task Force has been constituted to consider the environmental impact of these projects on different possible locations. A final decision on the location will be taken after the receipt of the report of the Task Force and thereafter the projects will be processed for the necessary approvals. The projects will be implemented by the 'Rashtriya Chemicals and Fertilizers'.

Based on gas available from Bombay High and South Bassein, it is also proposed to set up two large sized projects in Gujarat. These two projects would be implemented by IFFCO and M/s. National Fertilizers Limited. The two companies have been asked to prepare a common feasibility report for the projects.

There is also a proposal to set up a fertilizer plant at Namrup with a capacity of 600 tonnes per day of ammonia and 1000 tonnes per day of urea based on gas from the oil-fields in Assam.

अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

*683. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे में कितने अधिकारियों के पदों का (चिकित्सा-सेवाओं को छोड़कर) दर्जा बढ़ाया गया और कब-कब दर्जा बढ़ाया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कितने पदों का (चिकित्सा सम्बन्धी पदों को छोड़कर) दर्जा बढ़ाया गया ;

(ग) क्या विभिन्न श्रेणियों के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने की प्रतिशतता में अन्तर है ;

(घ) यदि हां, तो उनमें एकरूपता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) इस बारे में कब तक एकरूपता लाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) 1-4-1975 से अब तक अधिकारियों के 23 पदों का ग्रेड बढ़ाया गया।

(ख) उन पदों की संख्या जिनके ग्रुप "सी" अर्थात् श्रेणी III से ग्रुप "बी" अर्थात् श्रेणी II में ग्रेड बढ़ाये गये	497
उन पदों की संख्या जिनके ग्रुप 'सी' अर्थात् श्रेणी III के अन्तर्गत ही ग्रेड बढ़ाये गये	19,700
उन पदों की संख्या जिनके ग्रुप 'डी' अर्थात् श्रेणी IV के अन्तर्गत ही ग्रेड बढ़ाये गये	9,200

(ग) से (ङ). कार्यभार के महत्व के आधार पर ग्रुप 'सी' (श्रेणी III) के पदों का ग्रेड ग्रुप 'बी' (श्रेणी II) में बढ़ाया गया था। कार्यभार के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के लिए सुलभ पदोन्नति की सारणियों में अन्तर्विभागीय असमानता कम करने और अनावश्यक फ्लैट पिरैमिडल संरचना के संवर्गों को कुछ राहत देने के लिए ग्रुप सी (श्रेणी III) और ग्रुप 'डी' (श्रेणी IV) के अन्तर्गत पड़ने वाले पदों का ग्रेड बढ़ाया गया था। चूंकि इन पदों का ग्रेड प्रतिशतता के आधार पर नहीं बढ़ाया गया था और विशिष्ट संख्या में मंजूरी दी गयी थी, अतः इसमें अन्तवर्गीय तुलना करना सम्भव नहीं है।

Category of Posts of S.C./S.T. in Ministry and its Undertakings

*664. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) total number of posts in the Ministry and its attached and subordinate offices and the public undertakings filled in each category of posts with specific shares of S.C. and S.T. in such employment and also the number of posts de-reserved in each category during the entire period of Janata regime and reasons thereof; and

(b) total number of departmental promotions/upgradation of posts in each category of posts and how many posts went to S.C. and S.T.?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). A statement giving information relating to Ministry is placed on the Table of the Sabha. Information relating to other organisations/undertakings is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Statement

Name of the organisation	Group	No. of posts filled after 24-3-77	No. out of column 3 belonging to SC	ST	No. of posts de-reserved after 24-3-77	No. of posts out of col. 3 filled by promotion/upgradation	No. belonging out of col. 7 to SC	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Department of Petroleum	A	7	..	..	..	3	..	—
	B	16	2	1	..	10	2	1
	C	14	2	1	3	6	1	..
	D	2	..	..	1	2	..	..
Department of Chemicals & Fertilizers	A	19	2	..	..	3	..	..
	B	29	2	..	..	21	2	..
	C	52	2	..	5	10	2	—
	D	6	2	..	..	4	1	..

Note : Group 'A' : Posts carrying a pay or scale of pay with the maximum of not less than Rs. 1,300/-.

Group 'B' : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 900/- but less than Rs. 1,300/-.

Group 'C' : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 290/- but less than Rs. 900/-

Group 'D' : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum pay of Rs. 290/- or less.

Setting up Chemical Complex in Madhya Pradesh

*668. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the State Government of Madhya Pradesh have approached the Central Government for setting up a chemical complex based on lime stone and coal in Madhya Pradesh; and

(b) if so, what are the details of the proposal and the action taken by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में ईंधन गैस के एजेंट

*691. श्री मदन तिवारी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में इंधेन गैस के कितने एजेंट हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कुछ अन्य एजेंसियां खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 44।

(ख) और (ग). दिल्ली में नई गैस एजेंसियां के प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार उपलब्ध होने पर तरल पैट्रोलियम गस की अतिरिक्त मात्रा के रखरखाव की आवश्यकता और तरल पैट्रोलियम गैस की वितरण एजेंसियों के पुनर्गठन यदि आवश्यक हो, को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

Complaints against Burmah Shell Dealer at Ballabgarh

*693. SHRI DHARMA VIR VASISHT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government received complaints against a Burmah-shell dealer at Ballabgarh (Haryana) regarding adulteration of petrol and diesel resulting in large scale impairment of tractor and car engines, if so, the action taken thereon; and

(b) whether it is a fact that the said dealer had been challaned for the same offence earlier, also if so, reasons for continuing his dealership?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Complaint against a petrol dealer of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) at Ballabgarh (Haryana) was received in this Ministry from certain residents of Ballabgarh through the Hon'ble Member. The complaint related to the alleged adulteration of High Speed Diesel and Petrol by the said dealer, resulting in impairment of tractor engines. Some of the tractor operators complained to the police who took samples from the retail outlet. The samples were sent to BPCL by Gurgaon Police and these were analysed by BPCL. As per BPCL's report, the analysis showed that while the High Speed Diesel samples were found to be on specifications, the petrol samples failed on two counts namely, octane number and final boiling point. The petrol appeared to be contaminated to the extent of approximately 10 per cent with products like kerosene and mineral turpentine oil. BPCL had conveyed the test reports to the police authorities and simultaneously wrote to the dealer asking for his explanation. The dealer had replied saying that no adulteration had taken place at his site. BPCL have been asked to examine the matter further.

(b) According to information received from BPCL, the dealer concerned has not been involved in any case of adulteration in the past.

Proposal for Professionally Qualified Members on Company Law Board

*694. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some members of Company Law Board are also holding high posts in the Department of Company Affairs;

(b) whether it is also a fact that the members of the Company Law Board do not have any independent and separate status but are an integral part of the Department of Company

Affairs and are subservient to and function under the direction and control of the Minister of Law, Justice and Company Affairs;

(c) whether Government feel that it would be useful to have professionally qualified persons like Chartered or Cost Accountants or Economists who are well versed in Company matters on the Company Law Board; and

(d) if so, the steps Government have taken or propose to take to have professionally qualified persons like Chartered/Cost Accountants on the Company Law Board?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The Chairman and three out of the remaining 6 Members of the Company Law Board are also holding the posts of Secretary and Joint Secretary/Public Trustee respectively in the Department of Company Affairs.

(b) The constitution and the status of the Company Law Board is governed by section 10 E of the Companies Act, 1956 sub-section (6) whereof provides that in the exercise of its powers and discharge of its functions the Company Law Board shall be subject to the control of the Central Government.

(c) and (d). Persons who are appointed as Members of the Company Law Board have adequate background and experience in related disciplines such as Accountancy, Law, Economics Commerce, Finance, Industry etc. to enable the Board to take an integrated view on the various cases which come up before it. The composition of the Company Law Board broadly conforms to these requirements and includes Members who possess qualifications of Chartered Accountancy and Cost and Works Accountancy.

इज्जत नगर डिवीजन में अधिकारी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारी

6371. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे में इज्जतनगर डिवीजन के वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारियों के बारे में 28 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1096 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इज्जतनगर डिवीज़न में कितने अधिकारियों और श्रेणी तीन के कर्मचारियों का तबादला शिक्षा सत्र के बीच में किया गया और जिनके बच्चे उनके काम के पुराने स्थान पर ही ठहरे हुए हैं; और

(ख) काम के नये स्थानों पर स्थानान्तरित कितने कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट कर दिये गये हैं और जिनके क्वार्टर उनके पहले वाले काम के स्थानों पर खाली करा लिए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क)

अधिकारी . .	5
तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	78

(ख) 5 अधिकारियों में से 3 को तैनाती स्थान पर बंगला आवंटित किया गया है जबकि 2 को पुराने स्थान पर उन्हीं बंगलों में रहने की अनुमति दी गयी है।

तृतीय श्रेणी के 78 कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया था जिनमें से केवल 41 कर्मचारियों के पास अपने पहले वाले स्टेशनों पर रेलवे के क्वार्टर थे और उनमें से 19 कर्मचारियों को अभी स्थानान्तरण पर जाना है। शेष कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:—

14 कर्मचारियों द्वारा उनके पहले वाले स्टेशनों पर क्वार्टर खाली कर दिये जाने

पर तैनाती के नये स्थानों पर उन्हें क्वार्टर दिये जा चुके हैं। 8 कर्मचारियों को उनके पुराने तैनाती स्थानों पर क्वार्टर रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।

Acquiring of Shares of Balmer-Lawrie Group of Companies

6372. DR. BIJOY MONDAL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state what was the economic justification of Indo-Burma Petroleum Company Limited acquiring Balmer-Lawrie group of companies majority shares at a higher rate than the prevalent market rates?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): Balmer Lawrie and Company was a foreign equity company till some years ago. Its interests were in the tea trade, manufacturing activities and miscellaneous activities, including shipping, travel agency and other agencies. There were originally six subsidiary companies of Balmer Lawrie, two for manufacture of steel barrels; one for electrical equipment, including switch-gears; one for structural fabrication; one flour mill and one for steel windows manufacture. Two of these subsidiaries were sold by Duncan Brothers one before IBP came into the public sector and the other thereafter.

The shareholdings in Balmer Lawrie were as follows:

Name of the party	Number of shares	Percentage
Indo-Bruma Petroleum Company	43,341	30·09
Alex Lawrie and Associates of UK	39,675	27·55
Duncan Brothers (Goenka Group)	32,540	22·59
953 Small shareholders	28,474	19·77
TOTAL	1,44,030	100·00

The shares of Duncan Brothers and Alex Lawrie had been purchased by IBP to hold 80.23 per cent of the shares. This deal was finally negotiated between 20th May and 1st June, 1972. The price paid was Rs. 95 per share to Duncan Brothers and Rs. 85 per share to Alex Lawrie, giving an average of Rs. 89.50 per share.

The reasons for IBP acquiring Balmer Lawrie & Company shares from Duncan Brothers and Alex Lawrie at Rs. 95 and Rs. 85 per share respectively, are briefly set out below:—

1. IBP was the single largest shareholder of Balmer Lawrie since 1955, holding 30.09 per cent shares, and it controlled the company jointly with Alex Lawrie & Company (the original parent company of Balmer Lawrie) holding 27.55 per cent of shares.

2. In 1968, Alex Lawrie was taken over in the UK by Walter Duncan Group, who are associated with Duncan Brothers in India. Duncan Brothers purchased 22.59 per cent of Balmer Lawrie shares in India from L.I.C. and in the open market, and arranged with Walter Duncans to purchase Alex Lawrie shareholdings, which would give them 50.14 per cent shares, and the majority control.

3. Duncan Brothers obtained Government of India permission in January, 1969 to purchase Alex Lawrie shareholding at Rs. 95 per share.

4. In January, 1970, IOC acquired majority shareholding from a British Company in IBP and IBP thus became a public sector company.

5. IBP representative on the Board of Balmer Lawrie observed that Duncan Brothers were managing the company to suit their own interests and not looking after shareholders' interests. Government of India also received complaints regarding this and Company Law Board carried out an investigation, which confirmed the above.

6. As a result, Government of India appointed two Government directors on Balmer Lawrie Board under Section 408 of the Companies Act.

7. Under legal advice on a prior pre-emptive right regarding Alex Lawrie shares, IBP filed a suit in the Calcutta High Court and obtained an injunction restraining Alex Lawrie from selling their shares to Duncan Brothers.

8. After the above steps by the Government of India were taken, Duncan Brothers realised that they could not manage Balmer Lawrie in their own way till IBP had a shareholding in it. Therefore, in an effort to compromise they made two alternative proposals to the Government which after negotiations became as follows:—

(a) Duncans to acquire IBP shareholdings at Rs. 160 per share or

(b) IBP to acquire Duncans shareholding at Rs. 95 per share and also simultaneously purchase Alex Lawrie shareholding.

Besides the above two alternatives, the third alternative available to IBP was to maintain *status quo*, pursue the legal proceedings, which with appeals etc. could take several years; in the meanwhile the financial position of Balmer Lawrie group would have eroded.

9. The socio-economic problems in West Bengal required early action so that Duncan Brothers could not manage Balmer Lawrie group in a manner leading to closure of activities and increase unemployment. This consideration along with the fact that selling IBP shareholding to Duncan would have helped to increase the activities of a Larger House-Goenkas-and would have meant waiving of rights of a public sector company in favour of private sector, led the Government to decide in favour of takeover of Balmer Lawrie by IBP.

10. Regarding the price paid, the standard criterion adopted by the Government in valuation of shares is an average of the following three values:—

(a) Asset value;

(b) Market value;

(c) Profit earning capacity value.

In spite of taking market value at Rs. 68 and the profit-earning value based on the worst period of Balmer Lawrie (January 1971—May 1972) instead of normal practice of taking past three years results (which would have resulted in a higher value), the Department of Economic Affairs calculated the fair price of the share as Rs. 95.60 taking the asset value at Rs. 174.50 per share. But if we take the value of Balmer Lawries' investments at market value, and the present realizable value of its fixed assets, the intrinsic worth of Balmer Lawrie Shares is over Rs. 300 per share. Average price of IBP purchase works out to Rs. 89.50 per share.

11. It is incorrect to say that Balmer Lawrie was a losing concern. It incurred a loss for the first time in 1971. This was due to a slackening of the tea warehousing business leading to eventual closure in January, 1972; if the loss on this

account is excluded, the profit in that year would have been Rs. 17 lakhs. If Government had only looked at this single years' loss and decided to part with their shares, this would have only helped Duncans who were all the time keen and anxious to control Balmer Lawrie. The Business of Balmer Lawrie and its subsidiaries continues to remain sound and there are good prospects of expansion and improved performance.

12. Having decided to obtain control over Balmer Lawrie, the only course open to IBP was to purchase the shares at a negotiated price from Duncan Bros. and Alex Lawrie who together held 50.14 per cent of the shares. Even if market purchases were resorted to, only 4-5 per cent of the shares would have been available for purchase; the market price would have shot up and IBP would not have succeeded in securing controlling interest which was the objective. M/s. Alex Lawrie and Duncans had agreed between themselves to sell together. The price paid was reasonable and by this purchase, the Duncan Bros' designs to control an important group of industrial units had been effectively and finally averted.

Malpractices by Large Industrial Houses and Foreign Companies

6373. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some cases have been brought to the notice of Government recently regarding the large industrial houses and foreign companies for their indulging in trade malpractices prohibited under the Restrictive Trade Practice Act; and

(b) if so, the types of restrictive trade practices being indulged in by such companies and the number of such cases registered and the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the enquiries instituted by the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission against Indian Companies belonging to large industrial houses and foreign companies under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 between 1-1-1977 and 31-3-1978 is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2082/78].

गंगापुर में रेलवे वर्कशाप

6374. श्री मीठा लाल पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैगनों की पूरी मरम्मत करने के लिये गंगापुर शहर (पश्चिम रेलवे) रेलवे वर्कशाप में शीघ्र विशेष प्रबन्ध किये जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इससे वर्कशाप का विस्तार करना आवश्यक हो जायेगा और यदि हां, तो कितना विस्तार किये जाने की संभावना है और वहां पर कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी नहीं। गंगापुर सिटी में कोई कारखाना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Amount allocated to Bihar from the Railway Safety Fund

6375. SHRI SURENDRA JHA SUMAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the amount allocated to Bihar from the Railway Safety Fund since 1976; and

(b) what are the Safety works taken up in that State out of allocation from the fund and the progress of those works so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The amount allocable to the Bihar State out of Railway Safety Works Fund during the years 1975-76 to 1978-79 is as under:—

(Figures in thousands of Rs.)

1975-76	1851
1976-77	2116
1977-78 (Revised Estimates)	2127
1978-79 (Budget Estimates)	2127

(b) The following schemes for road over-bridges in replacement of level crossings in the State have presently been approved and included in the Railways Works Programme.

Sl. No.	Name of scheme	State Govt's share of cost reimburseable from R.S.W.F.	Remarks
1	Construction of a road over-bridge in replacement of level crossings Nos. 47 and 48 between Begusarai and Tilrath on North Eastern Railway	Rs. 7·36 lakhs	Work is in progress
2	Construction of a road over-bridge in replacement of level crossing No. 52 at Samastipur	Rs. 34·85 lakhs	Railway's portion of work i.e. the bridge across the tracks, has been completed. Work on the approaches is in progress by the State Government and is expected to be completed shortly.

The State Government's share of cost of above works, which comes to about Rs. 42.21 lakhs, is reimburseable to them from the Railway Safety Works Fund.

In addition to the above, 11 schemes of manning/upgradation of level crossings in the State of Bihar were approved during 1975-76 to 1977-78 for being financed out of 10 per cent of the Fund which is held in reserve only for such works. Works on these is in various stages of progress.

Accommodation in Trains

6376. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total number of sitting and sleeping accommodation available in all Indian trains in second class and first class and also in air conditioned class separately; and

(b) the daily average number of passengers travelling in the trains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Details of sitting and sleeping accommodation available on Indian Government Railways as on 31st March, 1977 were as under:—

Class	Number of Seats	Number of Berths
Air Conditioned .	3,309	3,309*
A.C. Chair-Car .	3,531	..
First . . .	160,965	60,422*
Second . . .	1,906,301	149,279*

*Included in seats also.

(b) The daily average number of Passengers carried on Indian Government Railways during 1976-77 was 9.04 millions.

Timings of Train No. 2ABQ

6377. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a representation has been given to the General Manager, Northern Railways and Divisional Superintendent Ferozpur about change in the timings of Train No. 2ABQ as to start from Qadian at 7.40 hours and to reach Amritsar at 9.30 hours by arranging cross with 3ABP at Verka; and

(b) if so what action has been or proposed to be taken by the Government in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) With effect from 1-4-78, 2ABQ has been scheduled to leave Qadian at 7.20 hours and arrive Amritsar at 9.25 hours after crossing 3ABP at Verka instead of Kathunangal.

Rules regulating Service conditions of R.D.S.O. Employees

6378. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what are those rules which regulate the Service Conditions of the all workmen, employed in the R.D.S.O. and where are those contained?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): The employees of the Research Dessigns and Standards Organisation are governed by the relevant provisions contained in the Indian Railway Establishment Code Volumes I & II and other rules and orders issued by the Ministry of Railways from time to time.

Minority Representative Associations Recognised

6379. SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what are these rules under which the Minority Representative Association had been recognised and the law under which these rules were framed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No Association representative of minorities i.e., formed on the basis of any caste, tribe or religious denominations or of any group or section of such caste. tribe or religious denomination has been recognised.

Alleged Discrimination against Casual Workmen

6380. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what are the discrimination being exercised with the casual workmen from those on the regular temporary establishment under Chapter XXIII of the Railway Manual?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Casual labourers are engaged for works of intermittent, sporadic and urgent

nature such as flood damages etc. They are generally on daily rates of pay. However, the following concessions are given to them if they are contained for long periods:

(a) Those casual labourers who are employed in the open line establishments of the Indian Railways continuously for four months' in the same type of work are granted temporary status and are eligible for almost all the rights and privileges applicable to temporary railway employees such as leave, passes, P.T.Os etc. They are, however, not entitled to retirement benefits, advance etc.

(b) Casual labourers on projects are granted scale rate of pay on completion of 6 months' continuous service, but not temporary status, and are not entitled to the benefits mentioned in (a) above.

(c) Casual labourers are screened and absorbed against regular vacancies and thereafter they become regular Railway employees.

Temporary Casual Labours

6381. SHRI SHYAMA PRASANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the reasons for which all the temporary casual labours already attained the status of Temporary Railway servant are not regularised as temporary regular railway servants strictly according to their seniority according to their length of service without any selection, based on their long experience of their working service on the same posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Casual labourers are engaged locally by Inspectors who are in charge of works without any selection. The normal rule is that there should be a selection before anyone enters regular Class IV service. In view of the service put in by casual labourers, a special relaxation has been made in their favour that they need not be subjected to selection but need only be screened by a Screening Committee and absorbed in the order of thier seniority as casual labour.

Treatment of Casual Labours as Temporary

6382. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state how many of the Casual labours have been treated as temporary railway servant in terms of Rule 2501 of the Indian Railway Establishment Manual?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Employees with 15—20 Years' Service not Confirmed

6383. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the persons employed in the Indian Railways rendering more than 15—20 years of service are still not confirmed in their respective post and on the other hand persons employed much later have been confirmed;

(b) if so, whether as a result of this practice interest of some officers have been affected adversely;

(c) if so, the categories in which such discrepancies have been pointed out; and

(d) steps proposed to protect the interest of such employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a)

Staff are confirmed against permanent post in their turn depending upon the availability of permanent posts.

(b) and (c). No discrepancies have come to the notice of the Government. There is no adverse effect because of non-confirmation as seniority for the purpose of promotion is based on the length of service irrespective of whether any employee is confirmed or not. Further after three years service, almost all the benefits of permanent service are available to temporary Railway Servants.

(d) Does not arise.

Off-Shore Exploration in Ratnagiri

6384. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 296 on 15th November, 1977 regarding off-shore oil exploration in Ratnagiri and state:

(a) what are the results of drilling of the well in the area about 55 Kms. from Ratnagiri coast;

(b) whether any geophysical survey in the area South of the well about 55 Kms from Ratnagiri coast has been made; and

(c) if so, what is the result?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No oil or gas shows were found in the well drilled in the area about 55 kms from Ratnagiri Coast.

(b) and (c). Geophysical survey carried out along Regional North South Line extending from Ratnagiri to Mangalore in the off-shore shows thinning of the sedimentary section South of Ratnagiri towards Goa.

Law on Dowry

6385. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government feel that the existing provisions of the Law are ineffective to check the evil of dowry;

(b) if so, whether Government propose to make giving and taking of dowry a cognizable offence; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH YADAV): (a) Government feel that the existing provisions of the law are not quite effective in checking the evil of dowry.

(b) and (c). Proposals to amend the Dowry Prohibition Act, 1961, including the question of making the offence thereunder cognizable, are under the active consideration of Government.

मेहसाना–तारंगा लाइन का विस्तार

6386. श्री मोतीभाई आर० चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में मेहसाना–तारंगा लाइन को पारखी से प्रमसाजी तक बढ़ाने की मांग की गई है ;

(ख) क्या थोड़ी दूर तक मार्ग पहले से ही उपलब्ध है और आगे यह बन के पार तक चला जाता है और भूमि के बेसर होने का प्रश्न ही नहीं है ;

(ग) क्या यह लाइन उस भाग में बिछाई जायेगी जो वन तथा खनिज सम्पदा में सम्पन्न है ; और

(घ) क्या भ्रमसाजी, जो एक प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र है, और इस कारण यात्रियों की भीड़ भी रहती है, लाखों लोग यात्रा करते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लाइन को बिछाने के लिए शीघ्र निर्णय करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (घ). इस लाइन के प्रस्तावित विस्तार के लिए अभी हाल में मार्च, 1978 के पहले सप्ताह में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। रेल प्रशासन को इस मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। रेलवे की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जायेगी।

Installed Caapcity of Fertilizer Plants

6387. SHRI RAJKESHAR SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number and names of fertilizer plants, State-wise together with their installed capacity and actual production during 1977;

(b) names of the States having no fertilizer plants; and

(c) programme, if any, for establishing these plants in such States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c). A statement giving the required information is attached.

Statement

Installed copacity of fertilizer plants

(a) The required information is given below:

(In 000 tonnes)

State/Units	Installed capacity in terms of		Actual production 1976-77		Actual production 1977-78 (upto 78)	
	Nitrogen	Phosphate	Nitrogen	Phosphate	Nitrogen	Phosphate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh						
1. Andhra Fertilizers (Tadepalle)	..	6·4	..	4·6	..	5·3
2. Andhra Sugars Ltd (Tanuku)	..	5·4	..	1·9	..	2·4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 Hyderabad Chemicals & Fertilizers (Hyderabad).	..	6·7	..	1·4	..	2·0
4 Krishna Industrial Corporation (Nidadavolu)	..	8·1	..	1·3	..	2·5
5 Coromandal Fertilizers Ltd (Vizag)	83	..	64·1	..	53·6	..
Assam:						
1 Namrup & Namrup Expansion (FCI)	197	..	..	..	92·8	..
2 Associated Industries (Chandrapur)	..	5·4	..	2·2	..	2·4
Bihar:						
1 Barauni (FCI)	152	..	24·8	..	38·1	..
2 Sindri (FCI)	90	..	25·0	..	9·4	..
3 Bihar Superphosphate Factory, Sindri	..	3·8	..	0·3	..	1·8
4 Tata Iron & Steel, Jamshedpur (By product)	4	..	3·3	..	2·7	..
Gujarat:						
1 Paushak (Baroda)	..	5·4	..	2·2	..	3·67
2 Adarsh Chemicals & Fertilizers (Udhana)	..	5·4	..	6·9	..	8·6
3 Anil Starch (Bhavnagar)	..	5·4	..	2·6	..	1·3
4 Gujarat State Fertilizers Company (Baroda)	216	..	173·5	..	156·0	..
5 IFFCO (Kandlo & Kalol)	215	..	158·0	..	195·3	..
6 Anish Chemicals (Ahmedabad)	..	1·0	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Kerala:						
1 Udyogmandal-FACT	82	7·2	43·1	3·7	46·9	4·5
2 Cochin I & II	192	..	80·5*	..	80·1	..
Karnatka:						
1 Chamundi Chemicals & Fertilizers, Raichur	..	6·5	..	..	..	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 Gammon Chemicals & Fertilizers, Mysore	..	5·2	Nil	..	..	5·02
3 Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd .	160	..	50·6	..	60·9	—
Madhya Pradesh:						
1 Hindustan Steel Ltd. Bhilai (By product) .	7	..	7·6	..	7·3	..
2 Dharmsi Morarji Chemicals Co Ltd, Cumhari . . .	—	12·0	—	12·3	..	13·2
Maharashtra:						
1 Trombay (FCI) .	81	..	94·6	..	78·6	..
2 Bharat Fertilizers Industries (Bombay) .	..	3·6	..	0·3	..	0·9
3 DMCC (Ambernath)	..	11·7	..	21·6	..	19·9
4 Western Chemicals Industries (Bombay)	..	0·5	..	0·3	..	0·16
5 West India Chemicals (Loni Kalbhore) .	..	5·3	..	5·8	..	5·4
6 Maharashtra Agro-Industries (Bombay) .	..	8·0	..	1·8	..	2·5
Orissa:						
1 Hindustan Steel Ltd. (Rourkela) . .	120	..	80·0	..	66·3	..
2 Hindustan Steel Ltd Rourkela, (By product) . . .	5	..	8·3	..	2·9	..
3 Orissa Chemicals & Fertilizers (Rourkela)	..	3·0	..	0·3	..	Nil
Punjab :						
1 Nangal (FCI) . .	80	..	80·0	..	49·8	..
Rajasthan :						
1 Hindustan Zinc (Udaipur)	..	12·2	..	5·1	..	5·6
2 Shri Ram Chemicals (Kota)	132	..	120·0	..	108·7	..
Tamil Nadu :						
1 Neyveli Lignite Corporation (Neyveli) .	70	..	43·0	..	36·3	..

(1)	(2)*	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 Madras Fertilizers Ltd. (Madras) . .	176	..	129·6	..	120·4	..
3 EID Parry (Ennore) .	16	..	8·4	..	7·8	..
4 SPIC (Tuticorin) . .	258	..	149·0	..	162·3	..
5 Kothari Ltd. (Madras)	..	7·2	..	1.6	..	4·6
6 Premier Fertilizer (Madras) . . .	..	6·5	..	..	..	..
7 Shaw Wallace (Madras) . . .	..	15·2	..	9·4	..	9·01
8 Coimbatore Pioneer Industries (Coimbatore) . . .	..	6·5	..	1·3	..	2·2
9 EID Parry (Ranipet) .	..	6·4	..	5·6	..	6·5
Uttar Pradesh:						
1 New Central Jute Mills (Varanasi) . .	10	..	5·1	..	4·2	..
2 Indian Explosives Ltd (Kanpur) . .	200	..	188·0	..	181·0	..
3 Gorakhpur (FCI) .	131	..	95·2	..	77·8	..
4 Rallis Chemicals (Kanpur) . . .	..	9·8	..	6·2	..	7·74
West Bengal:						
1 Jayshree Chemicals (Calcutta) . .	..	9·2	..	5·1	..	3·1
2 Phosphate Co. (alcutta) . . .	..	9·8	..	4·5	..	7·74
3 Durgapur (FCI) .	152	..	46·0	..	50·9	..
4 IISCO, Burnpur (By product) . .	4	..	1·5	..	1.5	..
5 Hindustan Steel Ltd., Durgapur (By product) . . .	4	..	3·1	..	2·7	..
Delhi:						
D.C.M. Chemical Works (New Delhi) .	..	33·0	..	19·0	..	13·4
Goa:						
Zuari Agro-Chemicals (Zuarinagar) . .	171	..	123·00	..	132·9	..

*Includes 3000 tonnes of Nitrogen produced by Phase II under trial run.

In addition to the fertilizer plants which are already in production, details of which have been given above, the following fertilizer plants are under construction in the States indicated below:

Name of the plant	State
I. *Public Sector*	
1. Nangal Expansion .	Punjab
2. Sindri Rationalisation .	Bihar
3. Trombay IV . .	Maharashtra
4. Ramagundam . .	Andhra Pradesh
5. Talcher . . .	Orissa
6. Sindri Modernisation .	Bihar
7. Bhatinda . . .	Punjab
8. Panipat . . .	Haryana
9. Haldia . . .	West Bengal
10. Trombay V . .	Maharashtra
II. *Private Sector*	
11. Broach	Gujarat
III. *Co-operative Sector*	
12. Phulphur	Uttar Pradesh

(b) There is at present no proposal to set up any fertilizer plant in the following States/Union Territories:

States

1 Himachal Pradesh

2 Jammu and Kashmir

3 Manipur

4 Meghalaya

5 Nagaland

6 Tripura

7 Sikkim

Union Territories

1 Andaman and Nicobar Islands

2 Arunachal Pradesh

3 Chandigarh

4 Dadra & Nagar Haveli

5 Lakshadweep

6 Mizoram

7 Pondicherry

(c) The location of a fertilizer project is based on techno-economic considerations which, *inter alia*, include factors such as availability of feedstock, infrastructure facilities, proximity to the market and demand of fertilizer in the economic marketing zone of the project. If the States, which do not have a fertilizer factory, are found to satisfy the above conditions, Government will no doubt consider establishing fertilizer factories in such States while planning for additional capacity.

Railway-Freight-Structure Enquiry Committee

6388. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway-Freight-Structure Enquiry Committee under the Chairmanship of Dr. H. K. Paranjape has started functioning as announced by the Railway Minister at his Bhubaneshwar Press Conference on 10th September, 1977; and

(b) if so, what has been its progress of work so far in respect of fare and freight revision?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes. The Rail Tariff Enquiry Committee which was set up under the Chairmanship of Dr. H. K. Paranjape *vide* Government of India Resolution dated 19-9-1977 has started functioning.

(b) Besides issue of a Notification in all the leading newspapers inviting suggestions from rail-users and public on the terms of reference of

the Committee, various Chambers of Commerce, Trade and Passenger Associations, Public and Private Sector Undertakings, Central Ministries, State Governments and the Universities have also been addressed inviting their suggestions. The memoranda/replies received are being studied by the Committee.

In addition to examining various reports and literature on the subject, relevant data is being collected by the Committee.

Freight Concession for Export Cargo

6389. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal under consideration for allowing freight concession for movement of export cargo; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) Does not arise.

Complaints and suggestions from Passengers of Bombay Local Trains

6390. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received a number of representations during the period of January and February, 1978 from the Federation of Bombay Suburban Passengers' Associations, Dombiwali, Distt., Thana (Maharashtra) regarding the complaints and suggestions of passengers on local trains;

(b) if so, the number of such representation;

(c) what action have Government taken in regard to the same; and

(d) if no action taken so far, the reasons thereof and when it will be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) Seventeen.

(c) and (d). Necessary corrective action has already been taken in case of thirteen representations, replies explaining the position sent in case of two representations and suggestions contained in other two representations are under examination.

हिन्दी सलाहकार समिति

6391. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से राजभाषा विभाग की सिफारिशों पर नामांकित सदस्यों की संख्या और नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख). सरकार द्वारा हाल ही में जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार एक नई हिन्दी सलाहकार समिति शीघ्र ही गठित की जाएगी।

Demand for Molasses Tanks

6392. SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the demand for molasses tanks in Delhi Division during last three months;

(b) the number of tanks supplied for molasses during the last three months to Delhi Division; and

(c) whether Government propose to meet the demand in view of short supply of molasses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). As on 1-1-1978, demands for 12 molasses tanks were pending. During the period 1-1-78 to 31-3-78 fresh demands for 135 tanks were received against which 117 tanks were supplied and loaded.

(c) As on 5-4-78 the outstanding demands were only for 18 tank wagons with the oldest date of registration being 23-3-78. These are also being met.

Selection of A.S.Ms. in Delhi Division

6393. SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some juniormost Assistant Station Masters were given outstanding report in the oral selection of Grade 455—700 in Delhi Division Northern Railway in year 1977;

(b) whether such selection held by *viva voce* are legal and had been held in other Railways/Divisions;

(c) whether the Railway Administration is justifying this selection held in emergency period; and

(d) whether the panel was formed to fill the vacancies and if not the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Four Assistant Station Masters of Delhi Division were classified as 'outstanding' in the selections for ASMs grade Rs. 455-700 (RS) held in 1977.

The selections were made on the basis of *viva voce* on all the Divisions in order to expedite implementation of the upgradation orders.

(c) The selections were held correctly and in accordance with rules and orders.

(d) Yes.

Reservation of Posts for SC/ST

6394. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether in view of his speech while inaugurating backward classes convention in Lucknow he has ensured that the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his Ministry and Public undertakings will be filled from the persons of these communities and that 50 per cent of the posts will be filled from persons of these communities till the posts against reserved quota for them is not filled;

(b) whether a separate roster in regard to reservation in promotion to the employees of the SC & ST Communities is being maintained in the Marketing Division, Refinery and Pipe line Division and the Chairman's Office of the Indian Oil Corporation; if not, why; and

(c) how the provisions of reservation in promotion contained in office memorandum No. 27/2/71/Est. (SCT) dated 27th November, 1972 issued by Cabinet Sectt.; are being implemented

in all the Divisions/Deptt. of Indian Oil Corporation in particular and other undertakings under his Ministry in General?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Necessary instructions have been issued to all undertakings of this Ministry.

(b) Separate rosters as provided under the Presidential Directives are being maintained by all Divisions of the Indian Oil Corporation.

(c) Promotions in the Indian Oil Corporations are normally made on the basis of merti-*cum*-seniority (promotion by Selection). and the Presidential Directive in this regard was made applicable w.e.f. 27-1-1978. Wherever promotions are made on the basis of seniority subject to fitness. the provisions of the Presidential Directives of 1971 and 1975 in this regard are followed by Indian Oil Corporation. The information in respect of other undertakings is being collected and will be laid on Table of the Sabha.

Reasons for Closure of Bengal Immunity Co. Ltd.

6395. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Government are aware of the closure of Bengal Immunity Co. Ltd. and all its units and sales offices by the management;

(b) what are the reasons for the closure and what steps have been taken by the Government to save the interests of the thousands of workers employed by the firm;

(c) is it also a fact that the Bengal Immunity Co. Ltd., is enjoying monopoly for the manufacture of certain life saving drugs etc.; and

(d) if so what remedial measures have been taken by Government to ensure that public at large will not be affected of it?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Closure of M/s. Bengal Immunity Company Ltd., proposed by the management is reported to have been deferred till 29th April, 1978 at the request of Government of West Bengal.

(b) The closure was proposed by the management namely due to uneconomic working of the Company. Government have issued an Order dated the 2nd March, 1978 under Section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act 1951, constituting a Committee to make a full and complete investigation into the circumstances leading to the present state of affairs in the company.

(c) The Company is manufacturing various essential bulk drugs and formulations including sera and vaccines which are manufactured by other units also.

(d) Such action as may be considered necessary will be taken by Government on receipt of the report of the Investigating Committee.

कोडीन फास्फेट की कमी

6396. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडीन फास्फेट की अत्यधिक कमी से देश औषधि-उद्योग में संकट पैदा हो गया है ;

(ख) देश में ड्रग्स और औषधियों का वर्तमान उत्पादन तथा आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) अन्तर्राज्यीय बाजार में कोडीन का मूल्य स्तर क्या है तथा देश के औषधि निर्माताओं को किस मूल्य पर इसकी सप्लाई की जाती है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान कोडीन फास्फेट की उपलब्धता और खपत को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। इससे यह पता लगता है कि इस मद की मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है।

(ग) सरकार से 29 दिसम्बर, 1977 को कोडीन बी०पी०, कोडीन फास्फेट और कोडीन सल्फेट का मूल्य क्रमशः 4214.00 रुपये, 3371.00 रुपये और 3376.00 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। इन मूल्यों के साथ उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है। ये मूल्य देश में औषध निर्माताओं द्वारा देशीय उत्पादन को देश में ही बेचने के लिये लागू हैं।

विवरण

वर्ष	आदि शेष कि० ग्रा०	निर्मित मात्रा कि० ग्रा०	आयातित मात्रा कि० ग्रा०	कुल कि० ग्रा०	बिक्री की मात्रा कि० ग्रा०	अन्त शेष कि० ग्रा०
1	2	3	4	5	6	7
1974–75 . . .	0.316	2493.600	3449.887	5943.803	5243.766	700.037
1975–76 . . .	700.037	2220.550	5229.565	8150.152	6794.936	1355.216
1976–77 . . .	1355.216	2925.250	1380.450	5660.916	5415.972	244.944

लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण

.6397 डा० रामजी सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की जनसंख्या में 50 प्रतिशत महिलायें हैं, इस संदर्भ में लोक सभा, राज्य सभा और राज्यों के विधान मंडलों में पुरुष सदस्यों की तुलना में महिला सदस्यों ने कितने स्थान प्राप्त किए हैं ;

(ख) क्या महिलाओं को विशेष अवसर प्रदान करने के सिद्धान्त पर उनके लिये इनमें 30 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण करना सरकार उचित समझती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस आशय का संविधान में संशोधन किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं, जिनमें (i) संसद और राज्य विधान मंडलों में स्थानों की कुल संख्या और (ii) संसद् और राज्य विधान मंडलों में महिला सदस्यों की संख्या दर्शाई गई है। विवरण ii में दी गई जानकारी, केवल राज्य सभा के विषय में छोड़कर 31-3-78 तक की है। उस विवरण में राज्य सभा में महिला सदस्यों की दिखाई गई संख्या अद्यतन है क्योंकि इस संख्या में वे महिला सदस्य भी सम्मिलित हैं जो अभी हाल ही में हुए द्विवार्षिक निर्वाचनों और द्विवार्षिक निर्वाचनों के साथ हुए दो उप-निर्वाचनों में निर्वाचित हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का जो सुझाव दिया गया है वह प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है और संविधान के उद्देश्यों को देखते हुए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

विवरण-I

संसद और राज्य विधान मंडलों में आवंटित स्थानों की कुल संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का का नाम	निम्नलिखित में कुल स्थानों की संख्या			
		राज्य सभा	लोक सभा	विधान परिषद्	विधान सभा
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश . .	18	42	90	294
2	आसाम . .	7	14	..	126
3	बिहार . .	22	54	96	324

1	2	3	4	5	6
4	गुजरात . .	11	26	..	182
5	हरियाणा . .	5	10	..	90
6	हिमाचल प्रदेश . .	3	4	..	68
7	जम्मू-काश्मीर . .	4	6	36	76
8	कर्नाटक . .	12	28	63	224
9	केरल. . .	9	20	..	140
10	मध्य प्रदेश . .	16	40	..	320
11	महाराष्ट्र . .	19	48	78	288
12	मणिपुर . .	1	2	..	60
13	मेघालय . .	1	2	..	60
14	नागालैण्ड . .	1	1	..	60
15	उड़ीसा . .	10	21	..	147
16	पंजाब . .	7	13	..	117
17	राजस्थान . .	10	25	..	200
18	सिक्किम . .	1	1	..	32
19	तमिल नाडु . .	18	39	63	234
20	त्रिपुरा . .	1	2	..	60
21	उत्तर प्रदेश . .	34	85	108	425
22	पश्चिमी बंगाल . .	16	42	..	294
23	अन्दमान निकोबार द्वीप समूह	..	1	..	..
24	अरुणाचल प्रदेश .	1	2	..	30
25	चंडीगढ़ . .	..	1	..	..
26	दादरा और नागर हवेली	..	1	..	..
27	दिल्ली . .	3	7	..	..
28	गोवा, दमन और दीव .	..	2	..	30
29	लक्षद्वीप . .	..	1	..	..
30	मिजोरम . .	1	1	..	30
31	पांडिचेरी . .	1	1	..	30

विवरण–II

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित में महिला सदस्यों की संख्या				टिप्पणियां
		राज्य सभा	लोक सभा	विधान सभा	विधान परिषद्	
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1	आन्ध्र प्रदेश	..	1	10	6	
2	आसाम	..	2	1	..	
3	बिहार	2	..	13	9	
4	गुजरात	1	1	3	..	
5	हरियाणा	..	1	4	..	
6	हिमाचल प्रदेश	1	..	1	..	
7	जम्मू-कश्मीर	..	2	1	1	
8	कर्नाटक	1	1	7	6	
9	केरल	1	..	1	..	
10	मध्य प्रदेश	5	..	10	..	
11	महाराष्ट्र	2	3	8	4	
12	मणिपुर	..	..	..	..	
13	मेघालय	..	..	1	..	
14	नागालैण्ड	..	1	..	..	
15	उड़ीसा	..	..	7	..	
16	पंजाब	3	..	2	..	
17	राजस्थान	1	..	8	..	
18	सिक्किम	..	..	1	..	
19	तमिल नाडु	1	2	2	2	
20	त्रिपुरा	..	..	1	..	
21	उत्तर प्रदेश	1	3	10	7	
22.	पश्चिमी बंगाल	3	2	5	..	
	योग (राज्यों के लिए)	22	19	96	38	

1	2	3	4	5	6	7
	संघ राज्यक्षेत्र					
23	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह .	..	..	..	..	
24	अरुणाचल प्रदेश . . .	..	..	..	..	
25	चंडीगढ़ . . .	..	..	..	..	
26	दादरा और नागर हवेली .	..	..	..	..	
27	दिल्ली . . .	..	..	4	..	
28	गोवा, दमण और दीव . .	..	..	2	..	
29	लक्षद्वीप . . .	..	..	..	..	
30	मिजोरम . . .	..	..	..	..	
31	पांडिचेरी . . .	..	..	..	..	
	योग (संघ राज्यक्षेत्र के लिए) .	..	..	6	..	
	नामनिर्देशित . . .	1	..	..	..	
	कुल योग . . .	23	19	102	35	

उच्च न्यायालयों में रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार

6398. श्री रामधारी शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में रजिस्ट्रारों तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रारों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है ; और

(ख) देश में प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए रजिस्ट्रारों, अतिरिक्त रजिस्ट्रारों तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रारों के कितने पद मंजूर किए गए हैं और उनमें से कितने पद इस समय रिक्त हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख). उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 229 के उपबन्धों के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के अधिकारियों पर होने वाला व्यय संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है। भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए रजिस्ट्रारों, अपर रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों के पदों की स्वीकृत संख्या क्या है, और यह कि इस समय उनमें से कितने पद रिक्त हैं।

Allocation of Kerosene Oil Quota to States

6399. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to lay a statement showing:

(a) what are the details of the allocation of kerosene oil quota to each State made during the last one year;

(b) what is the actual quantity of kerosene supplied to the States particularly the State of Orissa during the same period; and

(c) whether Government have taken steps to ensure that the rural population particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes get their quota regularly?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). A Statement giving the details of the allocation of kerosene made to the different States (including Orissa) and Union Territories during the calendar year 1977 as also the actual sales of kerosene made therein during the same period is attached.

(c) The actual distribution of kerosene within the State is the responsibility of the State Government. Oil companies supply kerosene oil to their agents on the basis of district-wise quotas laid down by the State Governments. These agents supply the product to the wholesalers or retail dealers licensed by the State Governments for sale to the public. The oil companies, on their part, ensure timely release of adequate quantities of kerosene supplies in order to fully meet the demands of all sections of the population.

Statement

Details of the allocation of kerosene made to different States (including Orissa) and Union Territories during the calendar year 1977 as also the actual sales of kerosene made during that period.

States	Quantity of kerosene allocated (in Metric Tonnes)	Sale of kerosene (in Metric Tonnes)
Andhra Pradesh .	259125	254563
Assam . . .	196017	225217
Bihar . . .	202379	181883
Gujarat . . .	311377	308368
Harayna . . .	57308	58862
Himachal Pradesh .	11509	12134
Jammu & Kashmir .	22705	19743
Karnataka . .	182261	185174
Kerala . . .	115428	119551
Madhya Pradesh .	169810	172913
Maharashtra . .	693349	695502
Manipur . . .	7875	7882
Meghalaya . .	6922	6654
Nagaland . .	3778	3347
Orissa . . .	69629	68441
Punjab . . .	112900	115533
Rajasthan. . .	97759	104270
Sikkim . . .	3794	3002
Tamil Nadu . .	294097	287982
Tripura . . .	11198	10944
Uttar Pradesh . .	333593	344612
West Bengal . .	312013	311605

1	2	3
Union Territories		
Andaman & Nicobar	727	848
Arunachal Pradesh .	945	1041
Chandigarh . .	7880	7590
Dadra and Nagar Haveli . . .	600	N.A.
Goa, Daman & Diu .	11429	1058:
Delhi . . .	85779	85011
Mizoram: . .	3045	2423
Pondicherry . .	4971	6220
GRAND TOTAL (ALL INDIA) . . .	3522070	3511796

Annual Meeting of Railways between India and Pakistan

6400. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Indian Railway Delegation to Islamabad and the Annual Meeting of Railways between India and Pakistan had agreed to a new proposal to boost up exchange of goods and parcels between the two countries;

(b) if so, how many wagons would be exchanged daily and on what terms and conditions regarding its procedure;

(c) what decision was taken on the exchange of parcel service between the two countries; and

(d) the figures of goods and parcels so inter-transported uptodate and the expected estimate of such traffic during 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). In the Annual Co-ordination Meeting held between the Railway Delegations of India and Pakistan at Islamabad in December, 77 the following proposals were mutually agreed upon for boosting up the exchange of goods and parcels between the two countries:—

(i) Pakistan Railways agreed to accept upto 100 wagons daily from India, provided the traffic on private trade account to Lahore does not exceed 40 wagons per day.

(ii) having regard to the increasing volume of iron and steel traffic from India to Pakistan it was mutually agreed that Bogie Open Flats will be interchanged between the two countries;

(iii) Pakistan Railways agreed to diversify the terminals to enable movement of bulk traffic;

(iv) the procedure and rules governing specifications of wagons which are fit for interchange between the two countries were streamlined to enable more wagons to be interchanged;

(v) Keeping in view the increasing trend of parcel traffic both the sides agreed that a daily parcel service should be introduced between Amritsar and Lahore.

(vi) It was also agreed that the rules governing the despatch of documents for customs clearance at Lahore should be simplified.

(d) The figures of goods and parcel traffic transported between the two countries is given below:—

Goods Traffic (Wagons)		Parcel Traffic (No. of Packages)	
From India to Pakistan	From Pakistan to India	From India to Pakistan	From Pakistan to India
Sept. '76 to February '78	Sept. '76 to February '78	August '76 to Frbruary '78	August '76 to February '78
11305	23	435513	871

No information is available about the estimated increase in traffic during 1978-79.

Stopage of Nilgiri Express

6401. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Nilgiri Express alias Blue Mountain Express which was introduced 50 years ago stops at Sankari Drug from the beginning;

(b) if so, the reasons why the downward train (Madras-Coimbatore) steps at the lower level platform and not at the regular platform for some time;

(c) since when, stopping at lower level platform started;

(d) whether Government have received representations regarding the inconvenience caused particularly to older people by stopping the train at lower level platform; and

(e) the steps taken or proposed to be taken to remove such inconveniences?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Available records show that this train has been stoping at Sankaridrug since December, 1946.

(b) and (c). After doubling of Anangur -Sankaridrug- Mavelipalaiyam section from 14-6-1969. 5Dn Nilagiri Express is dealt with on the Down rail level platform and the Up trains on the Up high level platform.

(d) Yes.

(e) It is not operationally feasible or advisable from the point of view of safety, to receive the Down Express on the Up high level platform. Considering the quantum of passenger traffic dealt with at the station, there is no justification for converting the rail level Down platform to high level at present.

Porters at Scheduled Rates

6402. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

SHRI ISHWAR CHAUDHRY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints that at big railway junctions porters refuse to carry luggage at the scheduled rates and demand high rates;

(b) whether it is also a fact that once a luggage is touched by a particular porter no other member of the fraternity will handle it and passen-

gers, particularly women are left with no other alternative but to agree to that high rates; and

(c) if so, the steps Government have taken for better passenger-porter relationship?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). A few complaints have been received by the Railway Administrations about over-charging the passengers by licensed porters at railway stations. Suitable action is taken against such licensed porters when complaints are received.

(c) Instructions already exist that the porterage rates approved by the Railway Administration should be displayed on a Notice Board conspicuously at each station for the information of the travelling public. In addition. rates are required to be inscribed prominently on the uniform of each porter and announcements made on Public Address System wherever provided, to educate the passengers about the approved rates of porterage at the individual station. Raliways have been asked to ensure that these instructions are compiled with scrupulously and complaints received from passengers on this score dealt with promptly in order to eliminate the causes of such complaints.

Reservations at Railway Booking Offices

6403. SHRI RAM KANWAR BERWA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether such complaints have been received by the Railway Department that the reservations made in railway booking offices in Delhi|New Delhi/Parliament House are allotted to other passengers by the conductors by striking off the names of actual passengers whereas the actual passengers travel by the same train and their names appear in the Chart also;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government against such corrupt employees; and

(c) if not, Government's reaction thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Two such complaints were received during the period 1-1-77 to 31-3-78.

(b) and (c). In one of the two cases, the Conductor could not spot the name of party in the chart quickly and he allotted other available accommodation in the train to avoid delay and inconvenience to the party. The concerned staff has been taken up for his carelessness and failure to act quickly.

In the other case, the irregularity complained of has not been fully established. The matter is, however. under further investigation and suitable preventive action will be taken in the event of any irregularity coming to notice.

Constant watch is maintained on the reservation and booking offices at important stations and on important trains by Officers, Anti-fraud squads and Vigilance organisations, to deter the corrupt practices and unsocial activities and the irregularities noticed are suitably taken up.

Setting up of Joint Sector Drug Formulation-Cum-Phyto Chemical Unit in Orissa by IDPL

6404. SHRI BAIRAGI JENA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal of IDPL for setting up a joint sector

drug formulation-*cum*-Phyto Chemical unit in Orissa in joint participation with the IPICOL;

(b) if so, has IDPL prepared feasibility report or not;

(c) if yes, what steps have been taken in this regard; and

(d) if not, the time it will take to prepare a feasibility report?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). The Feasibility Report has not been prepared as the product-mix is yet to be decided, keeping in view the range and availability of medicinal plants, quantity of active principles in them, cost of extraction and demand for the active principles, as well as the demand for drug formulations in Orissa. Extraction of active principles is the basic element of the technology, which is not available with IDPL as it is a new field of activity for them. The preparation of the feasibility report could be taken up only after all the above parametres are resolved.

Persons died in Railway Accidents

6405. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the toal number of passengers died and injured due to Railway accidents since March, 1977;

(b) total number of claims received and paid in both categories; and

(c) the number of claims pending and the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) During the period 1-3-77 to 31-3-78, 185 passengers were killed and 490 injured in train accidents.

(b) Out of total number of 387 claims, 175 for killed and 212 for injured received from the victims and their dependents involved in train accidents under the Indian Railways Act, 1890 during the period from March, 1977 to March, 1978, 82 claims 76 for killed and 6 for injured have been settled and compensation amounting to approximately Rs. 15.99 lakhs paid to the claimants.

(c) The balance 305 claims are pending settlement in the courts of Ad-hoc Claims Commissioners$Ex-officio Claims Commissioners and the papments will be arranged by the Railway Administrations on the basis of the verdict of the Court without any delay on their part.

कम्पनियों में वेतन और भत्तों का तुलनात्मक अध्ययन

6406. श्री ईश्वर चौधरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और देश में चल रही विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा अन्य परिलब्धियों की कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख). इस विभाग ने सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन ढांचे का कोई

औपचारिक अध्ययन नहीं किया है। तथापि सरकारी और निजी क्षेत्रों में अत्याधिक पारिश्रमिक के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रकट होता है कि निजी क्षेत्र के उच्च कार्यकारियों को देय पारिश्रमिक उन सरकारी क्षत्र से वास्तविक रूप से अधिक है। सरकारी क्षेत्र में उच्च कार्यकारियों का पारिश्रमिक सरकारी उद्यमों के ब्यूरो या संबंधित सरकारों द्वारा जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा शासित किया जाता है। सरकार उद्यमों के ब्यूरो के अनुदेशों के अनुसार, उच्च कार्यकारियों को देय वेतन अधिकतम 4,000 रु० प्रति मास इसके अतिरिक्त भविष्य निधि उपदान आदि के सामान्य लाभ तक प्रतिबंधित है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां और प्राइवेट लिमिटड कम्पनियां जो सार्वजनिक कम्पनियों की सहायक है, के संबंध में विद्यमान मार्ग संदर्शिका के अन्तर्गत प्रबन्ध पूर्णकालिक निदेशकों को 7,500 रु. प्रति मास वेतन के साथ में अधिकतम 45,000 रु० प्रतिवर्ष कुल लाभ पर कमीशन इसके अतिरिक्त उन सरकारी क्षेत्र के कार्यकारियों को देय की अपेक्षा वास्तविक रूप से ऊंचे दर पर परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

Strike due to Inter-Union Rivalry

6407. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have seen the press report in the *Indian Express* dated the 15th March, 1978 wherein it has been stated that Inter-Union rivalry could lead to another major railway strike b ythe middle of 1978; and

(b) if so, what steps Government propose to take to avoid this railway strike?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) The Working Committee of one Federation to which one group of recognised unions of railway employees is affiliated, has called upon its affiliated unions to hold meetings of appropriate bodies in accordance with their respective constitutions for ratifying strike ballot decision and complete this work by the end of April. 1978.

The General Council of another Federation to which another group of recognised unions is affiliated has called upon its affiliated unions to convene meetings by the end of March 78 to discuss issues in connection with a general strike and make specific recommendations on the nature of struggle to be undertaken for the consideration of the Federation's General Council/Working Committee so that a date for the strike ballot could be fixed.

In addition, it has been noticed that other unions have also been passing resolutions for direct action, etc. There have been discussions with both the recognised Federations and the Government's stand on various issues raised has been explained in great detail. Decisions on a number of issues have already been taken and announced.

Discussions have also been held by the Minister for Railways with some M.Ps and certain other representaives of staff.

Government is keeping a watch and wish to assure that the door for discussions and negotiations is always open. Government do not wish to pre-judge the issue now itself on the assumption that a strike will materialise.

N. G. Lines in Gujarat

6406. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the broad details of all the narrow gauge lines in the entire State of Gujarat;

(b) whether Government propose to convert the said narrow gauge lines into MG (Meter Gauge) or BG (Broad Gauge) lines progressively;

(c) if so, the full facts regarding such conversions now in progress; and

(d) if not, why not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). The list of narrow gauge lines in Gujarat is attached. The gauge conversion project is taken up when a section becomes saturated and is incapable of handling the additional traffic or when the magnitude of the transhipment involved is such that it is uneconomical or is not feasible at all or when it is needed for providing speedy and uninterrupted means of communication to areas which have potential for growth. In Gujarat, conversion of 44.64 Kms. long narrow gauge line from Wadia to Kapadvanj at an estimated cost of Rs. 4.05 crores has been included in the budget for 1978-79 and this forms part of the construction of new broad gauge line from Nadiad to Madasa (105.14 Kms.) estimated to cost Rs. 9.43 crores. An outlay of Rs. 10 lakhs for gauge conversion between Nadiad and Kapadvanj has been proposed during 1978-79.

Consequent on the recommendation of the Uneconomic Branch Line Committtee for conversion of Chhota Udepur-Pratapnagar and Chhuchhapura and Tankhala narrow gauge sections into broad gauge in order to improve the financial viability, a traffic survey was carried out in November 1970. According to the survey report, the existing narrow gauge lines will be sufficient to meet the requirements of passenger as well as goods traffic on the section in the near future. Taking into account the traffic density of the section and the costs of haulage, conversion of these narrow gauge lines is not justified.

Gauge conversion of Ankleshwar-Rajpipla narrow gauge line has been examined recently taking into account the traffic for the proposed river valley projects in the area at the time of construction as well as the traffic expected to be offered after the completion of these projects. It was found that the project would cost about Rs. 10 crores and would not be viable. The existing narrow gauge line is capable of carrying the traffic for these projects. This line is, therefore, not being considered for conversion at present.

The gauge conversion of the remaining line also cannot be considered at present on account of shortage of resources and limited prospects of traffic.

Statement

List of narrow gauge unremunerative lines on Western Railway in Gujarat State

Sl. No.	Name of Section	Length in Kms.	Year of opening
1.	Chhuchhapur-Tankhala	38	1925
2.	Kosamba-Umarpada .	62	1912/1929
3.	Jhagadia-Wetrang .	31	1920

S.No.	Name of Section	Length in Km*.	Year of openidg
4.	Ghoranda-Motikoral	19	1921
5.	Samni-Dahej	39	1930
6.	Godhra-Lunavada	41	1913
7.	Piplod-Devgadhbaria	16	1929
8.	Joravarnagar-Sayla	27	1948
9.	Champaner-Shivrajpur	49	1911
10.	Dabhoi-Timba Road	100	1913—1919
11.	Broach-Jambusar-Kavi	76	1914/1929
12.	Ankleshwar-Rajpipla	63	1897—1917
13.	Chhota-Udepur-Jambusar	150	1880/1917
14.	Chandod-Malsar	87	1879/1921
15.	Nadiad-Kapadvanj	45	1913
16.	Billimora-Waghai	63	1914/1929
17.	Nadiad-Phij-Bhadran	58	1914/1953
18.	Morvi-Ghantila	45	1904/1934
19.	Bhavnagar-Talala-Mahuva	209	1926/1938

Salary and perquisites of top Management Cadres of Certain Companies

6409. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) ceiling of salary, emoluments, perquisites of the top management cadres are entitled to as per provision of the Companies Act;

(b) whether the particular provision of the Companies Act is being adhered to;

(c) whether it has been alleged that salaries emoluments and perquisites of the top management cadres of the following companies have been substantially enhanced during 1975, 1976 and 1977 namely; (i) Bharat Commerce and Industries Ltd., (ii) Swadeshi Polytex Ltd., (iii) Southern Petrochemical Corporation Ltd., (iv) Hoechst Dyes and Chemical in contravention of the provision of the Companies Act; and

(d) if so, what are the facts thereof and action taken thereto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Sections 198, 309 and 387 of the Companies Act, 1956 contain the relevant provisions relating to ceiling on managerial remuneration. As per the said provisions of the Act, the remuneration payable to the Managing/wholetime directors/managers by way of salary, commission and perquisites put together but excluding sitting fee is subject to a ceiling of 5 per cent of the net profits of the company. The remuneration (excluding sitting fee) payable to all the directors of the company is subject to a further ceiling of 11 per cent of the net profits of the company.

The ceiling referred to above can be exceeded only with the approval of Central Government.

Under section 314(IB) of the Act approval of Central Government will be required for payment of remuneration in excess of Rs. 3,000 per mensem to certain executive of the company, who are related or otherwise connected with any director or manager of the company.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). Yes, Sir. This Department received an allegation relating to substantial increase in salaries of the managerial personnel of four companies referred to above. On an examination, it was found that they

mostly relate to increase in emoluments of employees of the companies which do not require the approval of the Department of Company Affairs. However, a list of cases where approvals have been accorded under the provisions of the Companies Act for increase in managerial remuneration in respect of the four companies. given in the statement, is enclosed.

These increases have been allowed in accordance with the guidelines followed by this Department at the relevant time.

Statement

(1) Bharat Commerce and Industries Limited:

The Directors of the company were together sanctioned 1 per cent of the net profits of the company subject to a maximum of Rs. 1.20 lakhs per annum for the period 29-5-1972 to 31.12. 1975. On a representation made by the company, the ceiling was increased vide this Department's letter dated 12th December, 1975 to Rs. 1.50 lakhs taking into account the increased profits of the company. This commission is divisible among the directors of the company who were 8 in number at the time of application.

(2) Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd.

The salary of Shri R. Narasimhan, Whole-time director of M/s. Southern Petrochemicals Corporation Limited was increased from Rs. 4000/-per month in the scale of Rs. 3500—250—5000 to Rs. 4500/- per month in the scale of Rs. 4500—500—6500 with effect from the 15th July. 1974, keeping in view his seniority in the company vide this department letter dated 24th March, 1975.

(3) Hoechst Dyes and Chemicals Ltd.

The remuneration of Mr. F. S. Reporter Managing Director of the company was increased by allowing commission at the rate of 1 per cent of the net profits of the company, subject to a maximum of 25 per cent of the salary, when he was reappointed with effect from 1st May, 1976, vide this Department letter dated the 12th October, 1977.

टिस्को को चूना-पत्थर भेजने वाली फर्में

6410 श्री शरद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिस्को (टाटानगर) में मैहर काहनगांव और निवार (मध्य रेलवे) में गत सात वर्षों में किन किन फर्मों से चूना-पत्थर के कितने रेक प्राप्त किए ;

(ख) प्रत्येक रेक में कितने वजन के आधार पर भुगतान किया गया ; और

(ग) प्रत्येक रेक में कितने वजन के लिए रेल भाड़ा अदा किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में रोजगार

6411. श्री रामजी लाल सुमन : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा उसमें और कितने श्रमिकों को रोजगार दिया जायेगा ;

(ख) उन श्रमिकों में स्थानीय व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है तथा भविष्य में कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा ; और

(ग) क्या इस तेल शोधक कारखाने का उद्देश्य स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). मथुरा तेल शोधक कारखाने का क्योंकि अभी निर्माण किया जा रहा है। अत: इस परियोजना में अधिकांश ठेकेदारों द्वारा ही अधिकांश रोजगार प्रदान किया जाता है। ठेके की शर्तों के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को आसपास के गांवों से उपलब्ध कुशल कारीगरों तथा श्रमिक वर्ग के कामगरों को लेना पड़ता है। इस मामले में, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें तथा उनके आश्रितों को तरजीह दी जाती है। फरवरी, 1978 के अन्त की यथा स्थिति के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कामगरों की संख्या 3929 थी, जिसमें से 2094 स्थानीय श्रमिक थे और 65 ऐसे कामगर थे जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी। यह संख्या कुल लगाये गये श्रमिक बल का 54% है। इसके अतिरिक्त फरवरी, 1978 के अन्त की यथा स्थिति के अनुसार परियोजना प्राधिकारी अर्थात् आई ओ सी ने 123 कार्मिक नियुक्त किये थे, जिसमें 47 अधिकारी और 76 कारीगर थे। 76 कारीगरों में से 22 कारीगरों को निगम की अन्य इकाइयों से स्थानान्तरित किया गया है। भर्ती किये गये 54 कारीगरों में से 51 कारीगर अर्थात् 94% ऐसे हैं जो स्थानीय व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वर्तमान लक्षणों के अनुसार, मथुरा तेल शोधक कारखाने के काम आरम्भ करने पर इस शोधनशाला के लिए कुल 1200 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आई ओ सी द्वारा विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं कि निर्माण और कार्य संचालन से संबंधित दोनों स्तरों पर रोजगार प्रदान करने के मामले स्थानीय व्यक्तियों को तरजीह दी जाये।

गैंगमैनों के लिए काम के घण्टे

6412. श्री युवराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैंगमैनों को प्रतिदिन 16 घंटे तक काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर दो-तीन गुनी कर दी गई है, परन्तु कर्मचारियों की संख्या अभी भी उतनी ही है; और

(ग) यदि हां, तो गैंगमैनों के काम के घंटे कब नियत किये जायेंगे और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कब की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) रेलों पर इंजीनियरी विभाग के गैंगमैनों के काम के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे निश्चित किये गये हैं और इसके अलावा जहां कहीं आरंभिक और पूरक काम प्रतिदिन 15 मिनट या 45 मिनट से कम अवधि के लिए करना अपेक्षित हो, वहां उन्हें प्रतिदिन आधा घंटा ऐसा काम इसके अलावा करना होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में किसी दिन उन्हें इस सीमा से अधिक काम करना अपेक्षित होगा तो वर्तमान नियमों के अन्तर्गत देय समयोपरि भत्ता देकर उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ख) अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या का निश्चय साधारणतया काम की मात्रा के सन्दर्भ में किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Auction of Articles Found at Lost Property Offices

6413. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made of the amount realised through public auctions of the articles and property which find their way to lost Property Offices of the railways;

(b) if so, the amount realised during the last one year; and

(c) what is the mode of advertising before auctions and the ways in which the real owner is searched for and the time after which auctions are declared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Yes. During the year 1976-77 a sum of Rs. 151.44 lakhs was realised from auction of unclaimed and unconnected goods etc.

(c) Before holding auctions notices for auction sale are published in local newspapers where available, at least 15 days before the intended auction sale. Where there are no local newspapers, notices are displayed on the notice board of stations, goods sheds, station platforms, second class waiting halls etc. Packages/consignments received at Lost Property Offices are opened and the owners thereof contacted on the basis of addresses, marks, if any, found on the articles. When it is not possible to establish the ownership of the consignments, these are sold by public auction after a period of three months.

Gold, Silver, etc. lying at Lost Property Offices

6414. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the amount of gold, silver and other properties lying in the custody of the Lost Property Office of the Railways;

(b) what steps are proposed to dispose of the property;

(c) the rules regarding the recovery of lost property is so troublesome that people who lose property are unable to get their property back in view of the rules; and

(d) if so, the brief outline thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Platen Machine

6416. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1806 on 29th November, 1977 regarding Platen Machine in Kurseong Railway Press and state:

(a) whether the Enquiry Report has been submitted; and

(b) if so, what is the report and what action has been taken against those responsible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The Enquiry Report has already been submitted by the Committee on 6-12-77.

(b) Findings of the Committee are that there was no human failure but there was sudden mechanical failure of Brake causing the accident. Findings have been accepted by N. F. Railway Administration and no body has been held responsible for the accident.

Manufacturers of Spurious Lubricants

6417. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the exiting laws are not sufficient to cope the unlicensed manufacturers of spurious lubricants; and

(b) if so, measures taken to contain these activities?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). The State Governments/ Union Territories have been advised to invoke the powers available with them under the Indian Penal Code and deal severely with adulterators of petroleum products.

2. Apart from initiating follow up action on the measures suggested by an expert panel set up by the Government to look into the problem of adulteration/mis-use of lubricants, Government have prescribed a scheme of discipline in regard to distribution of lubricants which is required to be implemented by all the major oil companies. Oil Companies have been conducting surprise checks on their retail outlets/agents with a view to ensure that there are no malpractices in distribution of lubricants through their outlets. The oil companies have also been asked to increasingly take up direct sales to all the major consumers. Some of the further steps being contemplated with the objective of minimising the circulation of spurious lubricants are set out below:—

(i) Government propose to make use of the ISI mark mandatory for all manufacturers of automotive oils, industrial oils and greases. The details in this regard are being worked out in consultation with the ISI and other concerned organisations.

(ii) Stricter control has been prescribed over allocation of feedstocks for the purpose of lube manufacture. The idea is to ensure proper accountal of feedstock releases as related to the output of the end-product.

(iii) The oil companies have been asked to eliminate inter-mediaries and prevent multiplication of agencies engaged in lube distribution. so as not to weaken effective control by the oil companies over their operations.

(iv) Oil companies have been asked to launch a major publicity drive to bring about greater consumer awareness and involvement.

(v) Specifically in regard to the activity of re-refining of used lubricants which is potentially a major source for adulteration of lubricants, decisions have recently been taken to introduce a scheme for voluntary registration of re-refiners who fulfil the basic quality criteria and possess the requisite facilities including inprocess quality controls.

3. An Industry Group is presently engaged in the task of evaluating in depth the problems in this field including the specific aspect of the adequacy of the existing laws for curbing the activities of manufacturers of spurious lubricants. They have been asked to come up to the Ministry with definite and concrete suggestions for implementation.

Sale and Collection of Tickets at Halt Stations

6418. SHRI D. N. TIWARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any commission is given to the contractors for selling and collecting Railway tickets at Halt Stations;

(b) whether any limit has been fixed for such work;

(c) if so, the limit;

(d) whether any incentive is given to those ticket contractors who by their integrity and efforts sell and collect larger number of tickets; and

(e) if so, the form of incentive?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) to (e). The contractors are paid commission as a percentage on the sale of tickets effected by them subject to a maximum limit of 15 per cent of the total sale proceeds. The commission paid can in no case be less than Rs. 75 per month and a commission of Rs. 300 per month is considered as a reasonable amount though this is not the maximum limit and a contractor can now earn more. This system of payment of commission on percentage basis itself is incentive oriented.

Claims against Railway Administration

6419. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that heavy claims were made against the Railway Administration during 1973—75 for loss of 126 Handloom bales, brass consignment and other miscellaneous items, correctly received at New Delhi Railway Station but were found missing after their book delivery;

(b) whether it is also a fact that the investigation of those losses were not entrusted to Delhi Railway Police/C.B.I./Vigilance Department of the Administration; and

(c) the total amount of claims preferred against the Administration during those years and reasons for not transferring the Chief Parcel Clerk who was previously suspended for the above loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) Investigation of these losses was done by the Railway Protection Force.

(c) The total amount of claims preferred against the Administration during those years was Rs. 6,10,029 for handloom cloth and Rs. 1,94,257 for brass.

An enquiry under the Discipline and Appeal Rules is under progress against the Chief Parcel Clerk, New Delhi. It was not considered necessary to transfer him particularly in view of the fact that individual responsibility for loss of some handloom bales was fixed on three other Parcel Clerks after a factual enquiry.

Memorandum from A. I. Station Masters' Association

6420. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a memorandum of demands was submitted to the Government by the All India Station Masters' Association Ferozepur Division during November, 1977;

(b) if so, the details of the demands; and

(c) whether Government have since considered those demands and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की संख्या

6421. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जोनवार रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की संख्या कितनी है तथा उनके मासिक लाइसेंस के शुल्क की राशि कितनी है तथा उन्हें रेलवे विभाग ने क्या सुविधाएं दी हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर काम कर रहे लाइसेंसधारी भारिकों की संख्या नीचे बतायी गयी है :—

रेलवे	काम कर रहे भारिकों की संख्या
मध्य रेलवे .	4064
पूर्व . .	7160
उत्तर . .	8745
पूर्वोत्तर . .	3425
पूर्वोत्तर सीमा .	1998
दक्षिण . .	2875
दक्षिण मध्य .	2697
दक्षिण पूर्व .	3632
पश्चिम रेलवे .	4115
जोड़ . .	38,710

भारिकों से ली जाने वाली लाइसेंस फीस 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक है जो प्रत्येक स्टेशन के महत्व और वहां होने वाले यातायात की मात्रा पर निर्भर करती है। आम तौर पर लाइसेंस धारी भारिकों को स्टेशनों पर प्राप्त सुविधायें निम्नलिखित हैं :—

(1) रेलवे अस्पताल/डिस्पेंसरी में केवल स्वयं के लिए बाह्य रोगी के रूप में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा यदि लाइसेंस धारी भारिक रेलवे परिसर में यात्रियों का सामान ले जाते समय घायल हो जाये तो उसकी रेलवे अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में चिकित्सा।

(2) एक कलेन्डर वर्ष में उतनी नैमित्तिक छुट्टियां जितनी की स्टेशन मास्टर/अधीक्षक दे सके।

(3) यात्रियों का सामान ले जाने के लिए रेलवे की हल्की ट्रालियों/हथठेलों का निःशुल्क उपयोग।

(4) दूसरे दर्जे के वास्तविक यात्रियों के उपयोग के लिए स्टेशनों पर उपलब्ध प्रतीक्षालयों, शौचालयों, कैन्टीनों आदि जैसी सुविधाएं।

(5) रेलवे के स्कूलों में उनके बच्चों की भर्ती बशर्ते कि स्थान उपलब्ध हों।

(6) बूढ़ा हो जाने पर अथवा शारीरिक दृष्टि से अक्षम हो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर उनके लाइसेंस बैज का उसके पुत्र अथवा निकट सम्बन्धी के नाम हस्तान्तरण।

(7) जहां कहीं उपलब्ध हो, वहां विश्राम आश्रयों का निःशुल्क उपयोग।

रेलवे पर दावे

6422. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977–78 में कितने मामलों में रेलवे पर दावे किये गये और उनकी कितनी राशि थी ;

(ख) उन में से कितने मामलों को वर्ष के अन्त तक निपटान कर दिया गया और वे कितनी राशि के थे ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों को निपटान करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अप्रैल, 1977 के प्रारम्भ से फरवरी, 1978 के अन्त तक की अवधि में रेलों के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये नये दावों की संख्या 366092 है। दावे प्रस्तुत करते समय पार्टियां, सभी हालतों में रकम निर्दिष्ट नहीं करती।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भुगतान के लिए निपटाये गये मामलों की संख्या 154250 है और क्षतिपूर्ति के रूप में किये गये भुगतान की कुल रकम 13.06 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किसी दावे के निपटारे पर लगने वाला औसत समय 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। इस लक्ष्य पर जमे रहने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

Advertisements given to Congress Souvenir in West Bengal

6423. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether during Emergency or a year prior to it West Bengal Congress arranged for publication of a Souvenir;

(b) whether letters were issued to various industrial and trade concerns for giving advertisement to such Souvenir amounting to about rupees Ten thousand;

(c) if so, the person in whose name letters were issued to various industrial and trade concerns;

(d) total amount collected for the Souvenir;

(e) facts about whether the collected fund have been properly accounted;

(f) whether CBI inquired into the matters; and

(g) if so, the findings of the CBI?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (g). No specific enquiry has been made regarding the publication of souvenirs by West Bengal Congress. But enquiries have been made from all public limited companies and private companies belonging to Large Industrial Houses regarding payments made by them for advertisement charges in souvenirs published by political parties during the period from 1-1-74 to 31-3-77. From information so far received it is seen that 1013 companies registered in various states of the country paid about Rs. 10 crores to the Congress party and its various organs for such advertisements. These figures, it may be added, include 188 companies registered with the Registrar of Companies, West Bengal, who in all paid about Rs. 88.53 lakhs for such advertisements and this includes some payments to the West Bengal Congress. The CBI is not making any separate enquiry in regard to the collection for the souvenirs by the West Bengal Pradesh Congress.

Diploma Courses for Company Secretaryship

6424. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) specific reasons for not treating two years Post-Diploma in Company

Secretaryship of Delhi Administration as prescribed qualifications for 'Company Secretary' as has been done in similar case of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi;

(b) why there is a discrimination for appointment of a Company Secretary in a company with a paid-up capital of Rs. 25 lakhs and above and less than this limit and what steps Government is taking to remove this discrimination especially when qualified Company Secretaries are still unemployed; and

(c) whether it is necessary to continue various similar courses of Company Secretaries, not fully recognised, run by Central Government/Delhi Administration/Autonomous bodies etc. in Delhi, particularly the course of two years Post-Diploma in Company Secretaryship of Delhi Administration, which are leading to spoil the career of ambitious students?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) (a) The Post Diploma in Company Secretaryship of Delhi Administration has not been recognised under rule 2(a) of the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975 on equal status with the membership of the Institute of the Company Secretaries of India, New Delhi because of the fact that the examination for Company Secretary was originally conducted by the Department of Company Affairs till 1968 when the said Institute was established by the Government. The syllabus for the examination and the practical training before awarding the membership of the said Institute prescribed under the Company Secretaries Regulations, 1971 are designed to impart a thorough knowledge and practical experience to its members to perform the duties of a top administrator in any industrial, trading and commercial organisation. The syllabus of the Institute includes all important subjects like Commercial Law, Accountancy, Economics, Company law, MRTP Law. Secretarial Practice, Business Administration and Management, Personnel Administration, Labour Laws and Relations etc. etc. as provided for in Chapter VI of the said Regulations. The Government considers that the knowledge and experience in all these subjects which is required by a general administrator of the company, are not being imparted by any Institution providing for the Diploma or Post Diploma Courses in Company Secretary ship including the Institute of Commercial Practice, Delhi. These are the specific reasons for Government's preference for recognising the membership of the Institute of Company Secretaries of India under Rule 2(a) of the said Rules for appointment its associate members as Secretaries in Companies with paid up capital of Rs. 25 lakhs and above.

(b) In view of the complexities of modern business, and the various laws which the management of a company are required to comply with, reliance upon qualified secretaries is now a common feature of medium-sized and big-sized companies. However, such a compulsory provision in the case of small-sized companies may involve a disproportionately heavy burden on them. Therefore, under section 383A of the Companies Act, 1956 compulsory appointment of whole-time company secretaries has been made only in the case of companies having paidup share capital of Rs. 25 lakhs or more.

(c) It is for the Delhi Administration/autonomous bodies which are training students for various courses of company secretariat examination to continue such courses or not. Since the number of companies registered in India are increasing year after year the career of students who pass such examinations are not adversely affected.

मनमाड मुदखेड़ लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6425. श्री केशव राव धोंडगे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मनमाड मुदखेड़ लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) यदि यह कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण मनमाड-परमनी-पुर्ली-बैजनाथ आमान परिवर्तन परियोजना पर काम शुरु करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब इस परियोजना के मनमाड-औरंगाबाद खंड के प्रथम चरण का काम 1978-79 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। परमनी-मुदखेड़ खंड के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण का काम महाराष्ट्र सरकार के खर्च पर किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

Railway Maintenance Workshops

6426. SHRI S. S. LAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a strange disease has developed among the technical workers in the railways maintenance workshops in the country;

(b) if so, whether the Government have set up a high powered experts' committee to go into the details and find out the causes of the same; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

सिंदरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण

6427. श्री रामसेवक हजारी : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उस पर कितनी लागत आयेगी और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) इस के परिणामस्वरूप उर्वरक के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है और इससे अन्य कम्पनियों को नई तकनीक और जानकारी प्राप्त करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जानेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी, हां। सिन्दरी में वर्तमान संयंत्र जो संभरण सामग्री के रूप में कोक और कोक ओवन गैस और प्रोद्योगिकी पर आधारित हैं की आर्थिक दृष्टि से उपयोगता समाप्त हो गई है। अमोनिया उपलब्धता में सुधार करने और वर्तमान संयंत्र में उत्पादन में प्रधान बाधाओं पर काबू पाने के लिए आधुनिकीकरण की एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना में ईंधन तेल के आंशिक आक्सीजेषन पर आधारित प्रतिदिन 900 मी०टन अमोनिया संयंत्र को स्थापित करना शामिल है। इस

संयंत्र से प्रतिदिन 600 मी०टन अमोनिया का नए संयंत्र में प्रतिदिन 1000 मी०टन यूरिया के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाएगा और शेष अमोनिया का अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिए वर्तमान सुविधाओं में प्रयोग किया जाएगा।

सिन्दरी आधुनिकी करण परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 152.04 करोड़ रुपये है। परियोजना जिसकी मूलता नवम्बर 1977 तक यान्त्रिक रूप में पूरा होने की संभावना थी अब उसकी 1978 तक पूरी होने की संभावना है। आधुनिकी करण योजना न केवल वर्तमान सुविधाओं में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिए अमोनिया की सप्लाई जारी रखेगी अपितु यूरिया के रूप में प्रतिवर्ष 129,000 मी०टन की अतिरिक्त उर्वरक क्षमता भी बढ़ाएगी।

Number of Railway Coolies

6428. SHRI B. C. KAMBLE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total number of railway coolies and the class IV Railway servants in Central, Western, Southern and Eastern Railways' who are temporary.

(b) the maximum period of service and minimum period of service these employees have put in together till today; and

(c) whether Government propose ot issue orders to make them permanent, if any one of them has put in all three years service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Maintenance of Tunnels between Gauhati and Silchar

6429. SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the condition of the existing (forty) Tunnels and Bridges between Gauhati and Silchar is deteriorating day by day and the Railways cannot assure safety (journey) on this line;

(b) what is the amount, if any, spent by the Railways on maintenance of these tunnels and bridges, year-wise, during the last 10 years and amount spent on Patrolling these tunnels, etc. during the last three years and action taken to avoid Bijni (Bongaigaon) type of accident on this Gauhati-Silchar route;

(c) what is the financial aspect involved in reconstructing the entire tunnels and bridges, in order to provide safer journey;

(d) whether it is also a fact that in view of the financial aspects, the Railway Board proposes to divert the existing line and if so, the details of such proposals; and

(e) what is the proposal of Government to modernise this Route during the next three years, as part of Government's policy to develop Backward and Rural areas in so far as this line is concerned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No. All the bridges and tunnels are regularly inspected every year at various levels and necessary repairs/ maintenance carried out regularly. Strengthening, rebuilding or regirdering of bridges is taken up on a programmed basis wherever considered necessary.

(b) (i) Expenditure incurred approximately on the maintenance of the tunnels and bridges is as under:

Year	Expenditure incurred
	Rs. in lakhs
1968-69	3·46
1969-70	3·36
1970-71	5·35
1971-72	1·66
1972-73	3·66
1973-74	5·43
1974-75	5·90
1975-76	7·55
1976-77	22·16
1977-78	40·74
	99·27

(ii) Expenditure incurred approximately on patrolling is as under:

Year	Expenditure incurred
	Rs. in lakhs
1975-76	4·83
1976-77	4·83
1977-78	4·83
	14·49

(iii) Following measures are being taken to avoid the type of accident that occurred at Bijni (Bongaigaon):

(1) Examination of rails by Rail Flaw Detector and replacement of rails found to have internal defects.

(2) Examination of rail ends at the time of lubrication of rail joints and replacement of rails found defective at the time of such examination.

(3) Conducting of gap survey at rail joints and adjusting gaps between rails where necessary.

(c) Question does not arise as the condition of the existing bridges and tunnels does not warrant their wholesale reconstruction.

(d) There is no such proposal.

(e) Diesel traction has already been introduced on most of the train services. Long welded rails are being laid down between Gauhati and Lumding and improved track maintenance techniques such as measured shovel packing are being introduced. Route relay interlocking work at Lumding and Badarpur Junction has been sanctioned and is in progress. Moreover, a number of works are in progress to minimise the incidence of hill slips and slides between Lumding and Badarpur.

Strike by Officers of Indian Oil

6430. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

SHRI LAXMINARAYAN NAYAK:

SHRI R. K. MHALGI:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 200 officers of Indian Oil are to go on a 24-hour token strike on the 22nd March, 1978 at the four refineries at Koyali, Gauhati, Barauni and Haldia and their units in metropolitan towns; and

(b) if so, reasons thereof and reaction of the Government of India in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). It is a fact that 2069 officers of the Indian Oil Corporation, including 1029 from the IOC refineries. were absent from duty on 23-3-1978 in support of certain demands like bonus, special oil allowance, conveyance allowance, house rent allowance etc. raised by the Officers Association of the Indian Oil Corporation. Government's reaction has already been indicated during the course of the discussions on the Demand for Grants for this Ministry in the Lok Sabha on 30.3.1978.

Price of Fertilizers

6431. SHRI B. P. MANDAL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) at what cost per ton fertilizers of different variety are sold in retail for use of agriculturists in the country;

(b) what is the cost per ton of the manufacture; and

(c) whether the cost is not uneconomical?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) and (c). The cost of production of fertilizers varies from plant to plant depending upon such factors as the capital cost, feedstock used, vintage, process adopted, location, cost of utilities, etc. The cost of production of fertilizers in India compares well with that elsewhere if a comparison is made on the basis of international cost of plant and equipment and inputs. In order to ensure the healthy growth and viability of the industry, Government have now introduced a system of individual retention prices in respect of the units producing nitrogenous fertilizers, which provides for a post-tax return of 12 per cent on the net worth, provided that the units operate at 80 per cent of capacity and satisfy the established consumption norms in regard to inputs, raw materials, utilities, etc.

Statement

A. *Prices of Statutorily controlled sraight nitrogenous fertilizers*

Name of Product	Maximum Retail Price (Rs. per M.T.)
Urea	1550
Ammonium Sulphate	935
Calcium Ammonium Nitrate	1015

B. *Prices of indigenous phosphatic fertilizers*

Name of Company	Product	Maximum Retail price (Rs. per M.T.)
E.I.D. Parry, Ennore	16:200	1700
	18:9:0	1320
Gujarat State Fertilizer Co., Baroda .	19·5:19·5:0	1820
	18:46;0	2120* *2210 outside Gujarat)
Coromandal Fertilizers Limited, Vizag	28:28:0	2340
	14:35:14	2230
Indian Farmers Fertilizer Co-operatives, Kandla	10:26:26	1890
	12:32:16	2000
	22:22:11	2100
	24:24:0	2080
Madras Fertilizer Ltd. . . .	17:17:17	1810
	24:24:0	1950
	14:28:14	2045
	18:46:0	2210

Name of Company	Production	Maximum Retail price (Rs. per M.T.)
Zuari Agro Chemicals, Goa	28:28:0	2340
	19:19:19	2020
	18:46:0	2210
Fertilizers and Chemicals Travancore Limited . .	16:20:0	1700
	20:20:0	1845
	28:28:0	2340
	17:17:17	1810
	18:46:0	2210
Rashtriya Chemicals and Fertilizers, Trombay . .	15:15:15	1520
	20:20:0	1760
Southern Petrochemicals Industries Corporation, Limited .	14-14:14	1620
	18:46:0	2210

C. *Prices of imported fertilizers supplied by Central Fertilizer pool*

Name of product	Price (Rs. per M.T.)
Ammonium Sulphate Nitrate .	1060
Ammonium Chloride 1 . . .	995
Muriate of Potash	
100 kg packing	795
50 kg packing	805
Sulphate of potash	1295
Ammonium Phosphate	
20:20:0	1590
19:20:0	2090
Diammonium Phosphate (18:46:0)	2210
Monoammonium phosphate .	2325
Ammonium Nitro Phosphate	
20:20:0	1590

Name of production	Price (Rs. per M.T) (Rs. per M.T.)
23:23:0	1760
26:14:0	1555
24:24:0	2045
N.P.Ks.	
15:15:15	1520
14:14:14	1450
14:28:14	1855
10:26:26	2200
12:32:16	2350
14:36:12	2535
13:13:13	1340
12:24:12	1570
11:11:11	1150
17:17:17	1810
17:8:9	1190
20:10:10	1770
13:13:20	1905
17:17:16	2090

Export of Goods by Trains

6432. SHRI MOHINDER SINGH SAYIANWALA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there are proposals under consideration of the Government to export goods to neighbouring countries by trains;

(b) whether he has been consulted in the matter; and

(c) if so, what are his reactions to the proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a)

to (c). India is already exporting goods by rail to its neighbouring countries i.e., Pakistan, Bangladesh and Nepal. Also as and when an agreement is signed with a neighbouring country for rail movement the Minister of Railways is always kept in the picture.

उज्जैन स्थित शराब बनाने के कारखाने में बनी शराब की किस्में

6433. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री उज्जैन में शराब बनाने के कारखाने द्वारा लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन स्थित शराब बनाने के कारखाने में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, किस-किस किस्म की कितनी-कितनी शराब बनाई गई ;

(ख) वहां बनी शराब के सरकार क्या भाव निश्चित किये तथा डिस्टिलरी (शराब-कारखानों) के मालिकों ने इसे किस भाव पर बेचा और उस की प्रतिवर्ष कितनी राशि की बिक्री हुई तथा बिक्री करने की प्रणाली क्या थी ; और

(ग) क्या उक्त शराब-कारखाने में बनी शराब उज्जैन जिले में तथा मध्य प्रदेश से बाहर बेची जाती है और शराब-कारखानों के मालिकों को किन शर्तों पर लाइसेंस दिये गये थे तथा वहां उपलब्ध प्रत्येक किस्म की शराब का वर्तमान स्टाक कितना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उज्जैन में शराब बनाने के कारखाने में केवल महुआ पर आधारित स्पिरिट का उत्पादन किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान शराब बनाने के कारखानों में महुआ स्पिरिट का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

1975-76	15,16,270	प्रूफ लीटर
1976-77	12,19,952	वही
1977-78	7,62,161	वही

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई शराब/स्पिरिट के निर्धारित मूल्य तथा मालिक द्वारा उस सरकार को बेचे गये इस मद के मूल्य एक जैसे होते हैं अर्थात् 1.70 रुपये प्रति प्रूफ लिटर क्योंकि स्पिरिट सरकार को परचून विक्रेताओं को सप्लाई करने के लिए बेची जाती है । 1977-78 वर्ष में उत्पादित स्पिरिट 7.62 लाख प्रूफ लिटर थी जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1.70 रुपये प्रति प्रूफ लिटर के हिसाब से लागत मूल्य अदा किये जाते हैं। शराब-निर्माता अपने व्यय से भिन्न-भिन्न सरकारी गोदामों में स्पिरिट भेजते हैं जहां पर निर्धारित संख्या से कम किये जाने के पश्चात् इसकी लाइसेंस प्राप्त परचून विक्रेताओं को सप्लाई की जाती है। शराब-कारखाने में तैयार की गई स्पिरिट केवल राज्य सरकार को बेची जाती है।

(ग) उज्जैन-शराब कारखाने में उत्पादित देसी स्पिरिट 1-4-78 से उज्जैन के जिले मंदसौर तथा रतलाम में बेची जाती है। देसी स्पिरिट मध्य प्रदेश से बाहर नहीं बेची जाती है 'डी—2 लाइसेंस' नामक लाइसेंस की शर्तें जैसा कि शराब-कारखाने तथा शराब गोदामों के नियमों में निर्धारित हैं मध्य प्रदेश उत्पादन अधिनियम 1915

(1915 का 11) के अन्तर्गत लागू की गई है। स्पिरिट का विद्यमान स्टाक 32,121 प्रूफ लिटर है।

खान पान ठेके

6434. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेल मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिये गये खान-पान ठेकों के बारे में 21 फरवरी 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में 7 बड़े तथा 176 छोटे खानपान ठेके कब दिये गये थे, उनका मूल्य कितना था और ये ठेके किन नामों पर दिये गये ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने ठेकों का नवीकरण किया गया, कितनी बार नवीकरण किया गया, कितने ठेकों में नाम बदल दिये गये और कितने ठेके रद्द कर दिये गये और कितने रद्द किये गये ठेके कब दिये गये तथा किन नामों पर दिये गये और क्रियान्वित नहीं हुए ठेकों की इस समय संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Wagon Requirement

6435. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it was estimated that the wagon requirement per year of the Railways during the Fifth Five Year Plan of the Railways will be 20,000;

(b) if so, what was the performance in this respect in 1976-77; and

(c) what are the prospects for next year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). As against the provision of 1 lakh wagons (in terms of 4-wheelers) envisaged in the Draft Fifth Plan, only 54,837 wagons (in terms of 4-wheelers) were provided in the final Fifth Plan of the Railways. During 1976-77, 11981 wagons (in terms of 4-wheelers) were procured. During 1977-78, upto February, 1978, 11039 wagons (in terms of 4-wheelers) have been procured. During 1978-79, 10,000 wagons are proposed to be procured.

मथुरा–गंगापुर सेक्शन का विद्युतीकरण

6436. श्री मीठा लाल पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम रेलवे के मथुरा–गंगापुर (सिटी) सेक्शन के विद्युतीकरण के लिए लागत और व्यवहार्यता सर्वेक्षण कर रही है और यदि हां, तो कब से तथा उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) सर्वेक्षण के पश्चात् कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या ऐसा सर्वेक्षण राजस्थान के किसी अन्य सेक्शन में भी किया जा रहा है और यदि हां, तो इस राज्य में उन सेक्शनों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, मथुरा–गंगापुर सिटी खण्ड के विद्युतीकरण के लिए लागत तथा व्यावहारिकता सर्वेक्षण का काम 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया

है। सर्वेक्षण काम का अनुमान विचाराधीन है। उसके बाद सर्वेक्षण के काम में लगभग 6 महीने लगेंगे।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि मथुरा-गंगापुर सिटी खण्ड की विद्युतीकरण का काम कब शुरू किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

Length of Platforms

6437. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many stations in the Gomoh—Barkakhana line in the Eastern Railway having platforms of length shorter than that of the trains they handle;

(b) whether it is a fact that in the night trains it creates grave danger of accidents because of the inadequacy of the platform and several public complaints have been made in this respect; and

(c) if so, the steps taken thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). There are 13 stations on the Gomoh—Barkakhana line on the Eastern Railway which have platforms shorter than what is required for stopping the longest train at the stations.

Longer trains are being introduced from time to time on various Zonal Railways to meet the growing demand from passengers. While every effort is made to increase the length of platforms simultaneously it has not always been possible to do so, in view of large magnitude of outlays required, limitation of resources and occasionally for technical reasons. Within the resources available, every effort is made to increase the length of platforms at these stations on a programmed basis.

Bagaha—Gorakhpur Railway line

6438. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is there any plan to link Bagaha (West Champaran, Bihar) with Gorakhpur (Uttar Pradesh) with a railway line crossing the river Gandak;

(b) if so, what step has been taken uptil now to fulfil this plan; and

(c) whether the Government contemplate this link as vital, if not, why not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) and (c). Restoration of the metre gauge link between Chhitauni and Bagaha has been approved. The section from Bagaha to Valmiki Nagar Road of this link has been opened for goods traffic from 28.12.76. It has not been possible to take up any further work on the project so far as no settlement has been reached with the Governments of Uttar Pradesh and Bihar regarding the sharing of the cost of the river training works of Gandak bridge which forms a part of the project. Further, Gandak river has shifted its course towards the East necessitating re-examination of the location of the bridge and the design of river training works and the same is being done by the Irrigation Research Institute, Roorkee at the instance of the Railway Administration. Further progress on this project can be made only after the above issues get finalised.

Work done by MRTP Commission

6439. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a Monopolies and Restrictive Trade Practice Commission is functioning; and

(b) if so, the work done by it during 1977-78?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) As required under Section 62 of The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, an Annual Report of Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission for the year 1977 will be laid before both Houses of Parliament which will contain the work done by the Commission during the Calendar year 1977.

Steps to decide within Two Years Cases in Courts

6440. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he had recently declared that steps would be taken that the cases would be decided within two years from the date of initiation in the lowest court to the highest court of India; and

(b) if so, whether any plan has been formulated in this respect, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). Government are desirous that steps be taken to ensure that over a period of time no case remains pending for more than twelve months from the time of its filing in the lower court to its final disposal by the highest court. It is, however, not practicable to ensure this immediately. Observations to this effect were made some time back. The following steps have been taken to speed up the disposal of cases:—

(i) The Judge strength of Supreme Court has been raised from 13 to 17 with effect from 31st December, 1977 by amending the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956. Vacancies existing in the Supreme Court before 31st December, 1977 were filled up and the strength of that court was full on 30th December, 1977. The vacancy occuring on 1st January, 1978 on the retirement of Justice Goswami has also been filled.

(ii) The Judge strengths have also been increased since 1st April, 1977 in the High Courts in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the dates the posts are filled up:

Madhya Pradesh.—6 extra posts of Additional Judges.

Allahabad.—6 extra posts of Additional Judges.

Patna.—3 extra posts of Additional Judges.

Himachal Pradesh.—1 extra pos of Additional Judge.

Karnataka.—1 extra post of permanent Judge and 1 extra post of Additional Judge.

(iii) A substantial number of vacancies in the High Courts have been filled up. Initiative has been taken by the Central Government to call for proposals from the State Authorities and wherever required reminders have been issued to the concerned State Authorities/Chief Justices.

(iv) The general question of reducing delays has been referred to the Chief Justice of India for working out certain measures/proposals.

(v) The Law Commission have also been requested to suggest suitable measures to tackle the general problem of arrears. They are seized of the matter.

(vi) Letters have been addressed to the Bar Councils and Bar Associations of various States requesting them for cooperation and also for suggestions for speedy disposal of cases.

(vii) Attention of the Chief Ministers has been invited to the pendency of Criminal cases in the Subordinate Courts and they have been requested to find ways and means for tackling this problem immediately.

(viii) The Supreme Court Rules have been amended recently to facilitate early disposal of cases in the Supreme Court.

Manufacture of DBCT/Nemagoon

6441. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether DBCT/Nemagoon is manufactured in India, if so, total production;

(b) whether the above item is imported, if so, how much; and

(c) who are the producers of the above item in India and whether DBCT/Nemagoon is being produced in Public Sector or Private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) DBCT|Nemagoon technical is not manufactured in the country.

(b) and (c). Negligible quantities of this pesticide were being imported. However, keeping in view the reported restrictions on its use in the U.S.A., the Central Insecticides Board set up under the Insecticides Act has suspended its use and import since November 1977 till detailed scientific investigations are carried out.

Changes under Companies Act, 1956

6442. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of cases involving changes in object clause or location of registered office under sections 17, 18 and 19 of the Companies Act, 1956 during each of the past three years;

(b) the total number of cases under Sections relating to issue of shares at discount during the above period.

(c) the total number of cases under section 141 relating to rectification of Register of Charges during the same period; and

(d) the total number of cases under Section 186 relating to convening of a general meeting during the past three years?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) 203 in the year 1975, 203 in the year 1976 and 239 in the year 1977;

(b) nil.

(c) 411 in the year 1975, 428 in the year 1976 and 444 in the year 1977; and

(d) 2 in the year 1975 and 3 in the year 1977.

Stoppage of IAPU Train at Kathunangal

6443. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that train IAPU does not stop at Kathunangal and Chira on Amritsar-Jammu Tawi Section thereby causing great hardships to the passengers particularly factory workers;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether a representation of this effect was given to the General Manager, Northern Railway and the Divisional Superintendant, Ferozepur;

(d) if so, what action Government have taken or propose to take thereon; and

(e) whether the Northern Railway have made any survey in the matter, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Presumably the reference is to IAPJ. IAPJ is not scheduled to stop at Kathunangal and Chhina stations.

(b) IAPJ train provides a fast passenger service between Amritsar and Jammu Tawi and as such is not scheduled to stop at unimportant stations. On the Amritsar-Pathankot section this train does not stop at 8 stations including Kathunangal and Chhina.

(c) Yes.

(d) and (e). Provision of stoppage of IAPJ at Kathunangal and Chhina has been examined but not found justified or operationally feasible.

कीर्ति एक्सप्रेस का कुछ स्टेशनों पर रुकना

6444. श्री धर्मसिंह भाई पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोरबन्दर—मेहसाना (कीर्ति एक्सप्रैस) रेलगाड़ी संख्या 35 और 36 पोरबन्दर जेतल्सर रेलगाड़ी संख्या 335 और 336 और पोरबन्दर-जेतल्सर रेलवे गाड़ी संख्या 337 और 338 में कौन-कौन सी रेलगाड़ियां गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जेतल्सर से पोरबन्दर आते समय फरेनी, दुधियानी, खाटवीजलिया, कोटेडा बवीशी, तरसाई, राणा-बोरडी, तपाड़ा आदि रेलवे स्टेशनों पर रुकती हैं;

(ख) क्या जनता की यह मांग है कि जेतल्सर से पोरबन्दर अथवा पोरबन्दर से राजकोट बरास्ता जेतल्सर के लिये एक नई रेलगाड़ी आरम्भ की जाये जिससे उन स्थानों पर तथा आसपास के ग्रामों में रहने वाले व्यक्तियों को सुविधा हो सके और यदि हां, तो यह गाड़ी कब तक चलाई जायेगी; और

(ग) रेलगाड़ी संख्या 335/336 को, जिसे 1973 अथवा 1974 के दौरान बन्द कर दिया गया था अथवा रद्द कर दिया गया था, पुनः चलाये जाने की जनता की पुरानी मांग को कब तक पूरा किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) भादितपाड़ा, राणावोर्दी, तारसई और खाखीजलिया स्टेशनों पर 337 अप/338 पोरबंदर—जेतल्सर फास्ट पैसेंजर गाड़ियां ठहरा करती हैं। 335/336 डाउन पोरबंदर—जेतल्सर फास्ट पसेंजर गाड़ियां कोटाडा बावीसी और खाखीजालियर स्टेशनों पर ठहरती हैं। 336 डाउन फरेनी और

झुन्भिसली स्टेशनों पर भी रुकती है। 35 अप/36 डाउन फिर्ती एक्सप्रेस इन स्टेशनों पर नहीं ठहरती है।

(ख) और (ग). जी हां। लेकिन, पोरबन्दर, जेतलसार/राजकोट खंड पर वर्तमान सेवाओं में स्थान उपयोग को देखते हुए रुकने वाली एक अतिरिक्त गाड़ी जिसमें पहले चलने वाली 335/336 सवारी गाड़ियों को पुनः चालू करना भी शामिल है, की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं समझा जाता।

वेरावल वीरमगांव तथा सोमनाथ मेल गाड़ियों का कुछ स्टेशनों पर रोका जाना

6445. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जेतासर से वीरावल वाले मार्ग पर वेरावल वीरमगांव तथा सोमनाथ मेल गाडियां चोरी-सोरठ, वैंधनाथ बाडोडर मैस्वन, भादुरी तथा आडरी-रोड़ स्टेशनों पर नहीं रुकती है;

(ख) यदि हां, तो 349 जूनागढ़-राजकोट, 350 राजकोट-जूनागढ़, 341 जूनागढ़-राजकोट तथा 342 राजकोट-जूनागढ़ पोस्ट रेलगाडियां जूनागढ़ से वेरावल तक इन छोटे स्टेशनों तथा निकटवर्ती गांवों की सुविधा के लिये क्यों नहीं बढ़ाई जाती हैं; और

(ग) ये दोनों रेलगाड़ियां इन स्टेशनों के तथा निकट के गांवों के यात्रियों की सुविधा के लिये जूनागढ़ से वेरावल तक कब तक बढ़ाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, सिवाय इसके कि 23/24 सोमनाथ मेल चोकी सोरथ पर रुकती है।

(ख) और (ग). रुकने वाली वर्तमान गाडियों में स्थान का उपयोग तथा इन स्टेशनों पर आने वाले यातायात के विश्लेषण से पता चलता है कि इन स्टेशनों के लिए अतिरिक्त सेवा की व्यवस्था करने के लिए यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है।

R.D.S.O. Part of Indian Railways

6446. SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is the RDSO a part of the Indian Railways;

(b) if not, reasons therefor;

(c) is the RDSO an Industrial Establishment within the meaning of the terms legislated by the Central Legislature; and

(d) what are the activities of the RDSO and in connection with or for the purpose of which Establishment Industry the RDSO works?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Research Designs and Standards Organisation is an attached office of the Ministry of Railways.

(b) Does not arise.

(c) Research Designs and Standards Organisation is not an "industrial establishment" for the purpose of the Industrial Disputes Act, 1947.

(d) Research Designs and Standards Organisation undertakes Research Designs and Standardisation work in respect of various items of railway equipment and materials and acts as technical adviser on various aspects of Railway Technology to the Ministry of Railways, the Zonal Railways and Production units under the Ministry of Railways.

Workmen's Compensation Act, 1923

6447. SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the reasons for not applying the Workmen's Compensation, Act, 1923 in the RDSO and the details of exemption granted by Parliament to RDSO?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Workmen's Compensation Act, 1923 is not applicable to the employees of the Research Designs and Standards Organisation because they are not "Workmen" within the meaning of Section 2(1) (n) of the Workmen's Compensation Act, 1923 read with Section 3(7) of the Indian Railway Act, 1890. No exemption has been given by Parliament in this regard.

Service Conditions of R.D.S.O.

6448. SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the rules, contained in the Indian Railways Establishment Codes/Manual, which do not apply on the workmen employed in the RDSO; and

(b) the reasons why these rules do not apply to regulate the service conditions of the RDSO Employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). The Research, Designs and Standards Organisation is an attached office of the Ministry of Railways. The employees of this Organisation are governed by the relevant provisions in the Indian Railway Establishment Codes Vol I and II and the Indian Railway Establishment Manual. Since Research, Designs and Standards Organisation is an attached office of the Ministry of Railways with its own separate cadres of staff, such of the rules as are specifically framed for governing the conditions of service of the employees of the Zonal Railways and the Production Units, are not applicable to the employees of this Organisation.

Railway Servants Medically Unfit

6449. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) have all the medically unfit railway servants (casual labours) of 1973-74 been considered equally for their re-medical examination, or any discrimination has been exercised; and

(b) if any particular groups have been considered for re-medical examination, who are they and why have others not been considered at par?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Railway Strike Victims

6450. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of victimised railwaymen of Railway strike and the number of victimised railwaymen of the emergency period who have already been taken on duties zone-wise and who else have yet been left out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Two statements regarding May '74 strike and the period of Emergency, giving the requisite information, are attached.

Statement I

1. Reinstatement of Employees who were dismissed, removed or had their services terminated

Out of a total of 16,898 employees who had been dismissed or removed from service or had their services terminated, all have been taken back to duty except 16, who could not be taken back for various reasons given below:

(i) Undergoing life imprisonment	3	(Central—1) (S.E.—2)
(ii) Under suspension for charge of murder (cases could be finalised only after the judgement is delivered)	4	(Central)
(iii) Dead	1	(N.F. Rly).
(iv) Where abouts not known	2	(Central—1) (S.C.—1)
(v) Not reported for duty	6	(Northern—1) (N.F.—5)

2. Taking back to Duty of those under Suspension.

Out of a total of 10,170 employees who had been suspended in the context of May '74 strike, all have been taken back except 13 employees of Central Railway who are undergoing trial on a charge of murder.

3. Taking back to Duty of Casual Labour/Substitutes

The services of a total of 24,570 casual labour/substitutes had been dispensed with initially. Out of them, all have been re-engaged except 472, break-up for which zone-wise is given below:—

(i) Whereabouts not known	110	(Eastern—79 Northern—9, Western—22)
(ii) Since expired	54	(Eastern—1,) (S.E.—53)
(iii) Not reported for duty though intimation was sent to them	304	(Eastern —7,) (N.E. —34, S.C. —203, S.E. —17, Western —43)
(iv) Not joined due to medical reasons	4	(South Eastern)

Statement II

Out of 6,020 who were dismissed/removed or who were prematurely retired during the Emergency period, 4,552 have been taken back. The zone-wise break-up of those not taken back is given below:—

Railway	Number not taken back after review	Number whose cases are under review
Central . . .	109	17
Eastern . . .	108	4
Northern . . .	125	..
North Eastern . .	368	..
N.F.	40	10
Southern . . .	64	33
South Central . .	152	62
South Eastern . .	171	131
Western . . .	47	27
TOTAL .	1184	284

Posts surrendered in R.D.S.O.

6451. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many of the lower posts have so far been surrendered in each category and how many higher posts have been created and in what categories in the whole RDSO;

(b) how and under what authorities the RDSO Management has surrendered lower posts and created higher posts;

(c) is this matching surrender for creation of gazetted posts and in the intermediate grade, according to whims of the Officers; and

(d) if so, how many posts have already been created in this process and in what categories and grades till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (d) A statement is attached.

(b) and (c). Higher grade posts in lieu of lower grade posts have been created on the basis of the actual workload and worth of charge after appropriate financial scrutiny, and under the sanction of competent authority in accordance with the extent orders of the Government.

Statement

Particulars of higher grade posts created

Name of the Section/Wing/Directorate	Particulars of higher grade posts created		Particulars of lower grade posts surrendered held in abeyance	
Electrical Design	Sr. Design Asstt. (Rs. 650-960)	4	Design Asstt. 'A' (Rs. 550-750)	5
Research Civ-II Engg. Wings of the Research Directorate	Chief Res. Asstt. (Rs. 650-960)	4	Jr. Res. Asstt. (Rs. 425-700)	14
	Sr. Res. Asstt. (Rs. 550-900)	10	Lab. Assistant (Rs. 260-430)	8
Research (B&F) Wing	Inspector of Works Grade I (Rs. 700-900)	2	Inspector of Works Grade II (Rs. 550-750)	3
Metallurgical & Chemical Directorate .	Chief Res. Asstt. (Rs. 650-960)	2	Sr. Res. Asstt. (Rs. 550-900)	2
			Jr. Res. Asstt. (Rs. 425-700)	1
Clerical (Ministerial)	Assistants (Rs. 425-800)	10	L.D.C. (Rs. 260-400)	19
Sig. & Telecom, Directorate	Section Officer, Class II (Rs. 650-1200)	1	Asstt.-in-charge (Rs. 425-800+Rs. 50/- spl. pay)	1
			L.D.C. (Rs. 260-400)	1

Employees of RDSO

6452. SHRI SHYAMA PRASANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the exhaustive list of the labour laws which regulates the service conditions of the employees employed in the RDSO; and

(b) what are the labour laws for which Parliament has granted exemption from its operation for regulating service conditions of the workmen employed in the RDSO?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) As RDSO is not an 'industrial establishment', the service conditions of the employees in RDSO are not governed by the various labour laws. The employees in the Research Designs and Standards Organisation are governed by the relevant provisions contained in the Indian Railway Establishment Codes/Manual, Recruitment Rules and other orders as are issued from time to time by the Ministry of Railways.

(b) Does not arise.

Payment of Wages Act, 1936

6453. SHRI SHYAMA PRASANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is the payment of Wages Act, 1956, applicable in the RDSO to regu-

late the payment of wages to the persons employed in the RDSO; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) The employees of RDSO are not governed by the Payment of Wages Act, 1936, in view of the provision made under Section 1(4 of that Act and as the RDSO is not a 'railway' within the meaning of this Section.

Casual Labourers declared Regular

6454. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state how many of the workmen have already been declared regular out of all the casual labours already attained the state of "TEMPORARY RAILWAY SERVANTS' and how many have yet to be declared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Since the earmarking of regular vacancies in Class IV for Casual labour in December 1969, 1.24 lakhs of Casual Labour have been appointed to regular posts.

Seniority for Promotion

6455. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that seniority for future promotions in the Indian Railways are reckoned from the date of confirmation in a particular post;

(b) if so, whether it is also a fact that in the absence of time bound programme for confirmation in the Railways the promotion chances of a number of officers have been affected and Junior officers (in the length of service) have been promoted; and

(c) if so, what steps Government propose to ractify this and fix a time bound programme for confirmation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The seniority of officers appointed to various Indian Railway Services (Class I) is determined on the basis of date for increment on time scale, which in the case of Direct Recruits is the date from which they commence earning increment in the regular scale while in the case of Class II officers and temprary officers who are permanently promoted to Class I, this date is determined by giving weightage upto a maximum of five years taking into account fifty per cent of the service rendered by them prior to absorption in Class I.

(b) and (c). It is presumed that the Hon. Member is referring to the confirmation of temporary Assistant Officers. In accordance with the terms and conditions of their appointment, these officers are permanently absorbed in Class I by a positive act of selection made through a Departmental Promotion Committee under the aegis of the U.P.S.C. The number to be so absorbed is as per an annual quota earmarked for the purpose. The Government has already increased the annual quota for confirmation of these officers recently in consultation with the U.P.S.C.

रेल इंजनों का निर्माण

6456. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 1965—66 से 1976—77 तक की अवधि में रेल इंजन कर्मशालाओं में कुल कितने रेल इंजनों का निर्माण हुआ ;

(ख) 1965-66 तक कुल कितने रेल इंजनों का निर्माण हुआ तथा इस समय कितने इंजनों का निर्माण किया जाता है;

(ग) क्या रेल विभाग इंजन निर्माण क्षमता को बढ़ाने में विफल रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(क) यदि नहीं, तो निर्माण क्षमता में अपेक्षित मात्रा में वृद्धि न होने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क) 1965–66 से 1976–77 की अवधि के बीच चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने, और डीजल रेल इंजन कारखाने में निर्मित रेल इंजनों की कुल संख्या—

I. चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन

भाप इंजन (बड़ी लाइन और मीटर लाइन) . .	507
बिजली रेल इंजन (बड़ी लाइन) . .	543
डीजल शंटर डब्ल्यू० डी० एस०–4 (बड़ी लाइन) .	279
डीजल रेल इंजन (छोटी लाइन) . .	30
जोड़	1359

II. डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी

डीजल-बिजली रेल इंजन (बड़ी लाइन) .	732
डीजल-बिजली रेल इंजन (मीटर लाइन) .	182
डीजल-बिजली शंटर डब्ल्यू० डी० एस० 5 (बड़ी लाइन)	21
डीजल-बिजली शंटर डब्ल्यू० डी० एस०-6 (बड़ी लाइन)	27
पावर पैक्स एण्ड जेनरेटिंग सेट्स . .	26
ओ० वी० ओ० शंटर	5
जोड़	993

(ख) वर्तमान उत्पादन (1977–78) की तुलना में 1965–66 तक रेल इंजनों का कुल उत्पादन—

1. चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन

	1965–66 तक उत्पादन	1977–78 के दौरान वर्तमान उत्पादन
भाप रेल इंजन (बड़ी लाइन और मीटर लाइन) .	1981	—
बिजली रेल इंजन (बड़ी लाइन) .	82	59
डीजल शंटर डब्ल्यू० डी० एस०–4 (बड़ी लाइन) .	—	31
डीजल रेल इंजन छोटी लाइन .	—	—
पावर पैक्स .	—	4
जोड़	2063	94

2. डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी

	1965–66 तक उत्पादन	1977–78 के दौरान वर्तमान उत्पादन
डीजल बिजली रेल इंजन बड़ी लाइन	61	91
डीजल बिजली रेल इंजन मीटर लाइन .	—	19
डीजल-बिजली शंटर डब्ल्यू डी एस–6 .	—	4
पावर पैक्स एण्ड जेनरेटिंग सेट्स .	—	26
जोड़	61	140

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) डीजल रेल इंजन कारखाना और चितरंजन रेल इंजन कारखाना में रेल इंजनों का उत्पादन, योजना आयोग से वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी की निर्माण क्षमता 150 रेल इंजन/पावर पैक्स प्रति वर्ष की जा रही है ।

रसायनों के ब्रांड नामों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

6457. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुभव करती है कि देश में बनने वाले रसायनों के ब्रांड नामों के कारण एक जैसे गुणों वाले परन्तु नये ब्रांड वाले रसायनों की बिक्री में बहुत कठिनाई हो रही है जो देश के कारखानों के लिए समस्या बन गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में उत्पादित वस्तुओं के ब्रांड नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार के पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है जिसमें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव किया गया हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ोदरा स्थित उद्योगों को गैस की सप्लाई

6458. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ोदरा स्थित कितने उद्योगों को प्राकृतिक तेल और गैस आयोग द्वारा गैस की सप्लाई की जा रही है तथा उन्हें यह गैस कब से सप्लाई की जा रही है ;

(ख) क्या प्राकृतिक तेल और गैस आयोग ने कहा है कि इन उद्योगों को गैस की सप्लाई केवल 31 मार्च, 1978 तक ही की जायेगी ; और

(ग) यदि इन उद्योगों के लिये भविष्य में गैस की सप्लाई रोक दी गई तो इनकी क्या स्थिति होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बड़ोदरा में 2 उद्योगों को 1966 की विभिन्न तारीखों से गैस की सप्लाई कर रहा है ।

(ख) और (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्थिति पर पुनर्विचार किया गया और इन उद्योगों को गैस की सप्लाई वर्तमान बात के आधार पर 1 अप्रैल, 1978 से एक वर्ष के लिए और जारी रखने का निर्णय लिया गया है ।

Coal Commercial Staff, Dhanbad

6459. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) Is it a fact that chart for Avenues of Promotion of the Coal Commercial Staff, Dhanbad is changed frequently;

(b) if so, why;

(c) whether by the frequent change any channel particularly the post of Weighman Inspector which was from these line staff has been barred for them;

(d) is it not a fact that this post is directly linked with the regular work of Commercial Staff;

(e) if so, while closing this channel for them it has been opened for others who are not connected with this nature of job; and

(f) is it proposed to rectify the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (f). The avenue chart was first revised in March 1965 and thereafter in August 1977 in consultation with organised labour. According to the avenue chart of 1965, Head Weigh clerks in grade Rs. 425—640 had avenue of promotion to posts of Weighment Inspector in the same grade along with Coal Tracers in grade Rs. 330--560. Subsequently three additional posts of Chief Weigh Clerk in grade Rs. 455—700 were made available in the cadre of Weigh Bridge Clerks. After the restructuring of the cadre while a number of posts of Weigh Bridge Clerks were available, no posts in higher grade were available for Coal Tracers. There were a number of representations for betterment of avenue of promotion of Coal Tracers. Besides, because Head Weigh Clerks are in a higher grade, they were in an advantageous position for being posted as Weighment Inspector. Considering all these aspects the avenue chart was revised to exclude Head Weigh Clerks Rs. 425—640 from the channel of promotion of Weighment Inspectors in the same grade. This decision has been taken in consultation with the recognised Unions.

Re-girdering work of Mahanadi Bridge at Cuttack

6460. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the date (roughly month and year) when the re-girdering-work in the Mahanadi Bridge at Cuttack (Orissa) began;

(b) the number of re-girdering done uptil now;

(c) the number of re-girdering yet to be done;

(d) the time (month and year) when re-girdering will be completed; and

(e) whether the re-girdering work is impeded because of the delay in supplying the accessories for the work, if so the name or names of the firms or companies who are the supply contractors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) In January, 1976.

(b) Out of a total of 64 spans, regirdering of 44 spans has been completed uptil now.

(c) Regirdering of 20 spans remains yet to be done.

(d) The regirdering work is expected to be completed by the end of December, 1980.

(e) There has been some impediment to the completion of the regirdering work due to delay in the supply of new girders by M/s. Braithwaite, Burn & Jessop Co., Calcutta.

Cancellation of Puri-Tirupati Express

6461. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether he is aware of the cancellation of the Puri-Tirupati Express service from November last without proper notification;

(b) if so, why has the train been cancelled; and

(c) what substitute the Railways have provided in its place?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). No. 79/80 Puri-Tirupati Express were cancelled from 21-11-1977 due to floods and cyclone in Andhra Pradesh.

(c) The train was restored between Kakinada and Vijayawada from 12-2-1978 and extended to Tirupati from 26-2-1978. It was restored between Puri and Tirupati from 1-4-1978.

Recognition of Games by Railway Sports Control Board

6462. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) which Indian and Foreign games have been recognised by Railway Sports Control Board and since when;

(b) whether it is a fact that Indian Game 'Khokho' has not been included in the recognised games-list even though it is a national game;

(c) whether it is also a fact that there is a consistent demand to include 'Khokho' in the said list;

(d) what are the difficulties in not including the said 'Khokho' Indian popular game in the list;

(e) what efforts are made so far to overcome the said difficulties; and

(f) If no efforts made so far, the reasons thereof and now what shall be done within next six months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) A statement in attached.

(b) Yes.

(c) to (f). Except for a representation from one particular railway employee there is no demand for recognition of the game of 'Kho Kho' by the Railway Sports Control Board. At present, the R.S.C.B. is not affiliated with the 'Kho Kho Federation of India' and the game of 'Kho Kho' is not played on Indian Railways as an Inter-Railway Tournament. The question of recognition would be considered as and when the game gains popularity and there is a general demand among Railwaymen.

Statement

S. No.	Game	Year in which recognised by Railway Sports Control Board
1.	Athletics	1928
2.	Bridge	1977
3.	Football	1928
4.	Hockey	1928
5.	Aquatics	1959
6.	Badminton	1953
7.	Ball Badminton	1961
8.	Basketball	1958
9.	Billiards	1961
10.	Boxing	1928
11.	Cross Country	1969
12.	Cricket	1953
13.	Cycling	1958
14.	Golf	1954
15.	Gymnastic	1971
16.	Kabaddi	1950

1	2	3
17. Rifle Shooting	. . .	1965
18. Table Tennis	. . .	1958
19. Tennis	. . . .	1952
20. Volleyball .	. . .	1953
21. Weightlifting]	. . .	1958
22. Wrestling .	. . .	1957

पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के विरुद्ध जांच

6463. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के बारे में 28 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1094 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस ठेके को देने के संबंध में रेलवे को कितनी हानि हुई जिसके बारे में 1962 में पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के विरुद्ध जांच की गयी थी ;

(ख) 1969 में नियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरूप कौन से तथ्य प्रकाश में आये ;

(ग) जनरल मैनेजर को अन्य रेलवे में स्थानान्तरित करने के संबंध में किन बातों पर विचार किया गया ;

(घ) रेलवे को हुई हानि को कैसे पूरा किया गया ;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर की पदोन्नति मंत्री मंडल की नियुक्ति समिति द्वारा व अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों का अतिलंघन करके की गयी थी और इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार उसे अन्य रेलवे में स्थानान्तरित करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नयी जांच करवाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (च). 1961 में, पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर में चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के लिए टाइप–I के 31 यूनिट, टाइप–II के 10 यूनिट, टाइप–III के 3 यूनिट और टाइप-IV के 3 यूनिट क्वार्टरों के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किये थे। जबकि प्राप्त टेंडरों की अभी छान-बीन ही हो रही थी, तभी टाइप–I के 31 यूनिट क्वार्टरों के संबंध में स्थान-परिवर्तन करने का विनिश्चय किया गया। स्थान–परिवर्तन के फलस्वरूप अतिरिक्त कुरसी की आवश्यकता पड़ी जिसमें मिट्टी और ईंटों का अतिरिक्त कार्य शामिल था। मूल रूप से प्रस्तावित स्थल पर किये जाने वाले काम की मात्रा के संबंध में जिस ठेकेदार का टेंडर सबसे कम था, उसे ठेका दे दिया गया। नये स्थल पर अतिरिक्त कार्य के लिए उसकी दरें अन्य ठेकेदारों द्वारा दी गयी दरों से अधिक थीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच से पता चला था कि नये स्थल पर काम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अगले उच्चतर टेंडर की तुलना में ठेके की राशि 32,500रु. बढ़ गयी। जांच संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया गया और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके यह विनिश्चय किया गया कि इस मामले में उचित सावधानी बरतने में असफल रहने के कारण संबंधित अधिकारी को चेतावनी दे दी जाये। संबंधित अधिकारी को जो उस समय उप मुख्य इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था, प्रशासनिक हित में तथा अधिकारी के अपने हित में पूर्वोत्तर रेलवे से स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ङ) पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक की नियुक्ति अवरण के क्षेत्र में अधिकारियों

के अपेक्षाकृत गुण–दोषों को ध्यान में रखकर तथा मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात की गयी थी।

(च) उपर्युक्त भाग (क) से (घ) तक के उत्तर को देखते हुए, इस मामले में और अधिक तहकीकात करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

Simulation Studies

6464. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) whether simulation studies are being done at present;

(b) if so, when; and

(c) the results?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes Sir.

(b) and (c). Reservoir simulation studies are being done by Oil India Limited and Oil and Natural Gas Commission for the past few years. The studies have helped to forecast the production rate of oil and gas and to plan for well spacing, optimum production rates, gas lift facilities, procurement of campressors, water treatment and disposal facilities, workovers and pressure maintenance/secondary recovery schemes.

35 अप कीर्ति एक्सप्रैस का साखपुर पर रुकना

6465. **श्री धर्म सिंहभाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 35 अप कीर्ति एक्सप्रैस गाड़ी गत लगभग 10 वर्षों से अप्रैल तथा सितम्बर के बीच गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पोरबन्दर के निकट साखपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 10 मिनट तक रुका करती थी परन्तु गत वर्ष उस "हाल्ट" को रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप हरी मिर्च तथा अन्य सब्जियों के 300 से 400 बोरों को, जिन्हें सूरत, अहमदाबाद, भावनगर, मेहसाना तथा आबू को यहां से प्रति दिन भेजा जाता था, भेजने में कठिनाइयां हो रहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अप्रैल से सितम्बर के बीच नई समय सारिणी के अधीन यहां पर इस गाड़ी का हाल्ट बनाकर साखपुर तथा अन्य गांवो के लोगों को उक्त सुविधा पुनः प्रदान करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं, 35 अप कीर्ति एक्सप्रैस अभी भी साखपुर पर 2 मिनट के लिए रुकती है।

(ख) और (ग). साखपुर पर हरी मिर्च और अन्य सब्जियों के आने वाले यातायात की निकासी 35 अप कीर्ति एक्सप्रैस के निर्धारित ठहराव के अन्तर्गत तथा 335 अप और 337 अप पोरबन्दर—जेतलसर तेज सवारी व संबंधित गाडियों द्वारा होती है।

Sleeping and Seating Quota for Keshod Station

6466. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the merchants Association, Keshod, district Junagadh, Gujarat has sent in a representation dated 7th December, 1977 to the Bombay and Bhavnagar railway authorities demanding increase in sleeping and seating quota from Keshod station;

(b) if so, the nature of demands made therein;

(c) the action taken or proposed to be taken in each demand; and

(d) the names of trains for which the above quota exists at present and how much?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) The following quotas were demanded for Keshod station:

(i) Eight second class sleeper berths by 6 Up Saurashtra Mail,

(ii) Four second class sleeper berths by 23 Up Somnath Mail in Veraval-Ahmedabad 2-tier sleeper coach.

(c) and (d). At present, the following quotas are allotted to Keshod station:

	First class	Second class	
		Berths	Seats
(*i*) 6 Up Saurashtra Mail	..	1 (in Viramgam-Bombay Central Coach).	..
(*ii*) 18/113/83 trains	..	2 (in Viramgam-Nagpur Partial sleeper coach).	2
(*iii*) 35/23/2 trains	..	.. (in Porbander-Delhi sleeper coach).	1
(*iv*) 23 Up Somnath Mail (For Ahmedabad)	1	4	2
[illegible]p/30 Dn	1	1 (in Veraval-Bhavnagar sleeper coach).	..

The quota for Keshod has been increased by 23 Up Somnath Mail, to 4 second class sleeper berths and 2 seats, with effect from 15-1-1978. The present quota of 1 second class berth by 6 Up Saurashtra Mail is not fully utilised. Hence increase in quota is not justified.

Loss in accident of Jayanti-Janata Express

6467. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state details of the compensation paid to the victims of accident of Jayanti-Janata Express near Nagpur on 16th March, 1978 and special steps taken/proposed to avoid accidents of fast and super fast trains on this route?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): In this accident, one Gangman was killed and two Gangmen were grievously injured. Payment of compensation due under the Workmen's Compensation Act in the case of the deceased employee is under process. The two grievously injured employees are receiving medical treatment. As soon

as they are discharged from the hospital, the extent of loss in their earning capacity due to permanent disablement, if any, would be assessed and necessary compensation, as may be due under the Workmen's Compensation Act, will be paid to them.

Measures to prevent accidents include warning the staff not to adopt short cut methods while attending to the failure of equipment to avoid detention to trains; strict adherence to rules during non-inter-locked working i.e. clamping of points and piloting of trains during repairs and maintenance work by signalling and telecommunication staff under disconnection memp; issue of special instructions in the form of 'do's and don'ts' regarding maintenance of curves and welded track; issue of manual of instructions on laying and maintenance of welded rails; pre-monsoon precautions on hill sections and posting of stationary watchmen at vulnerable locations during rains for taking preventive action in case of boulders falling down suddenly; monsoon patrolling of track; ultrasonic testing of rails in the track for internal defects intensifying inspections at various levels; careful examination of components of locomotives and coaches; sealing and locking of various sophisticated signalling and telecommunication equipment to prevent unauthorised interference etc.

Introduction of Double-Decker Trains on Poona-Bombay Line

6468. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Government have taken a decision to introduce double decker trains on Poona-Bombay line;

(b) if so, the important details of the proposals such as the name of the train, likely date of introduction, frequency and the estimated cost;

(c) whether double decker trains are also proposed to be introduced on other routes; and

(d) if so, the details of the proposals to be implemented during 1978-79 and subsequent years, if finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Double Decker coaches are being introduced in the second week of April' 78 on 309/10 Bombay-Pune Janata Express which runs daily. This train is being renamed as 309/310 Sinhagad Express. The estimated cost of manufacture of each double decker coach is approximately Rs. 8.5. lakhs.

(c) and (d). Double Decker coaches will be introduced on other suitable short distance routes. Provision for 24 double decker coaches has been made in 1978-79 Rolling Stock Programme.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए खान-पान प्रबन्ध संबंधी ठेके

6469. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या रेल मंत्री अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गये खान-पान ठेकों के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को क्रमश: 56 और 12 ठेके कब दिए गए थे और वे ठेके कहां-कहां तथा किस-किस प्रयोजन के लिए दिए गए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश ठेके अन्य लोगो द्वारा चलाये जा रहे हैं क्योंकि मूल ठेकेदारों के पास धन का अभाव है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और किन-किन स्थानों पर ये स्टाल चलाये जा रहे हैं ; और

(घ) सभी डिवीजनों में ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनके पास छोटे और बड़े एक से अधिक ऐसे ठेके हैं जो उनके परिवार के सदस्यों के नाम में हैं और ऐसे ठेके किस-किस स्थान पर हैं तथा इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खान-पान और अन्य स्टालों का आवंटन

6470. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेल मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिये गये खान पान के ठेकों के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खान पान और अन्य स्टालो के आवंटन के लिए पश्चिम रेलवे के सभी डिवीजनों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदन पत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के थे;

(ख) कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और कितने व्यक्तियों को ये स्टाल आवंटित किये गये हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. जो पहले से ही खान पान और अन्य स्टालों को चला रहे हैं और उन्होंने भिन्न भिन्न नामों से स्टालों के लिए आवेदन किया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्टाल चला रहे हैं

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

6471. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद और रामपुर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए कुल कितने क्वार्टर हैं :

(ख) क्या इस बारे में मांग को पूरा करने के लिए नये क्वार्टर बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्टेशन क्वार्टरों की संख्या

मुरादाबाद	1729
रामपुर	45

(ख) जी हां, मुरादाबाद स्टेशन पर।

(ग) मुरादाबाद स्टेशन पर 36 यूनिट क्वार्टरों के निर्माण की 1978-79 के रेल निर्माण कार्यक्रम में व्यवस्था की गयी है । इस वर्ष के दौरान रामपुर स्टेशन पर किसी क्वार्टर के निर्माण की योजना नहीं बनायी गयी है ।

पलवल-असौती स्टेशनों के बीच यात्रियों का लूटा जाना

6472. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ डाकुओं ने 16 मार्च, 1978 को दिल्ली—आगरा लाइन पर पलवल असौती स्टशनों के बीच एक यात्री रेलगाड़ी के यात्रियों को लूट लिया था, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण): (क) 15, 16–3–1978 की रात्रि को पलवल और असावती के बीच दो गाड़ियों के यात्रियों को लूटने की रिपोर्ट मिली है। 360 अप दिल्ली झांसी यात्री गाड़ी में यात्रा कर रहे 15 यात्रियों को जैसी कि रिपोर्ट है, 4 तोले सोने के गहनों, 5 कलाई की घड़ियों तथा 1385 रुपये से वंचित कर दिया गया था। लूटी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य 4785 रुपये था। एक दूसरी गाड़ी, 361 डाउन आगरा छावनी—नयी दिल्ली यात्री गाड़ी में 4 यात्रियों से 3 घड़ियां एक सोने की अंगूठी तथा 65 रुपये लूट लिए गए थे। लूटी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य 765 रुपये था।

(ख) 360 अप यात्री गाड़ी में अपराध के सम्बन्ध में सरकारी रेल पुलिस, हरियाणा ने एक मामला दर्ज किया था, तथा उसकी जांच पड़ताल हो रही है 361 डाउन में अपराध के सम्बन्ध में सरकारी रेल पुलिस, हरियाणा ने एक मामला दर्ज किया था तथा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 300 रुपये मूल्य की दो कलाई की घड़ियां बरामद की गई थीं। मामले की जांच पड़ताल चल रही है। हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में, दिल्ली मथुरा खंड पर सभी रात्रि गाड़ियों को राज्य की सशस्त्र पुलिस के नियमित अनुरक्षण में चलाया जा रहा है।

गाजियाबाद के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर बकाया राशियां

6473. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर रेल यार्ड एवं रेलवे साईडिंग के रखरखाव प्रभारों के रूप में 1 मार्च, 1978 को कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) रेलवे प्रशासन ने इस भारी बकाया राशि को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1–3–78 को गाजियाबाद में साईडिंग मालिकों के नाम मालभाड़ा और रखरखाव प्रभारों के कारण रेलवे को देय बकाये की कुल राशि नीचे दिखायी गयी है :—

माल भाड़ा प्रभार— कुछ नहीं
रखरखाव प्रभार— लगभग 1,841 95,00 रुपये।

(ख) रखरखाव प्रभारों के कारण बकाये का शीघ्र भुगतान करने के लिए जिन पार्टियों के विरुद्ध दावे प्रस्तुत किये गये हैं जिन्होंने बढ़ी हुई दरों पर आपत्ति की है। अब उनके द्वारा की गई आपत्तियों की जांच की जा रही है।

Railway Employees Demand of Bonus

6474. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether attention of the Government has been drawn to the press report in the *Hindustan Times* dated 15th March, 1978 under the heading "No Lethargy, Fernandes cautions railwaymen";

(b) if so, whether he has advised the railwaymen that change would have to be brought about;

(c) if so, whether he has also stated that system had to be changed as well as habits and attitudes;

(d) if so, whether this type of advice has encouraged the railway employees to go in for agitations in regard to their demand of bonus, created indiscipline in the railway employees and deterioration in the working of the employees; and

(e) if so, to what extent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). Yes, according to the Press report referred to.

(d) and (e). No.

Loss to Railways in recent Bihar Agitation

6475. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total loss Railways suffered due to the recent agitation in Bihar;

(b) if so, whether the Railways were the main target of attack of the agitators;

(c) whether the railway traffic remained suspended for many days; and

(d) if so, what steps were taken to repair the damage caused to the Railways?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

6476. श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है और उनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ख) कुल न्यायाधीशों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदाय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सब आरक्षित पद भर दिये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। 3 अप्रैल, 1978 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 316 स्थायी और अपर न्यायाधीश पदासीन थे।

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां संविधान के उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं और उनमें किसी आरक्षण का उपबन्ध नहीं है।

Indane Gas Agents in Rajnandgaon district, Madhya Pradesh

6477. SHRI MADAN TIWARY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of Indane gas agents in Rajnandgaon district in Madhya Pradesh at present and the total number of gas connections there at present; and

(b) the additional number of gas connections proposed to be provided by Government in this district during the current financial year with a view to meet the increasing demand of the people therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Due to its limited availability, Indane Gas is not being marketed in Rajnandgaon District, Madhya Pradesh, at present.

With the anticipated large-scale increase in the LPG availability in the country from 1980, it may be possible to extend its marketing in due course to new places based on the following:—

(i) Anticipated customer potential;

(ii) Nearness of market from the source of supply;

(iii) Availability of safe/convenient mode of transport;

(iv) Maximum utilisation of distribution equipment; and

(v) Viability in operations.

Switching over to use coal and gas in Fertilizer Factories

6478. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Fertilizer Corporation of India Ltd. is switching over to use coal and gas in the factories in which Naphtha was used initially; and

(b) if so, the factories in which such change was effected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) and (b). In the Trombay fertilizer factory, which is now with the Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd., naphtha is being replaced by gas as feedstock for the existing ammonia and methanol plants. Till such time as gas is available for such purpose, fuel oil will also be replaced by gas in the steam raising facilities at Trombay.

There is no proposal to substitute naphtha by coal in any of the existing fertilizer plants.

तीसरे वेतन आयोग की अध्यापकों के बारे में सिफारिशें

6479. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और क्या शिक्षा मंत्रालय के अध्यापकों को 1 जनवरी, 1973 से चयन ग्रेड दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन अध्यापकों को 1 अप्रैल, 1978 से चयन ग्रेड क्यों दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उनको बकाया की अदायगी कब की जायेगी और क्या इस बारे में कोई समयावधि निर्धारित की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : स्कूलों में अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों की जिन

कोटियों के लिए प्रवरण ग्रेड 1-1-73 को या उससे पूर्व किसी अन्य तारीख को लागू कर दिया गये थे। उनके सम्बन्ध में प्रवरण ग्रेडों के आबंटन के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें 1-1-73 से लागू की गयी थीं। इस प्रकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने के पूर्व अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में रेलों पर कोई योजना मौजूद नहीं थी, इसलिए 1-1-73 से उसे लागू करने का प्रश्न नहीं उठा तथापि रेलों पर यह योजना पहली बार 1-4-76 से कार्यान्वित की गयी।

(ग) बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

Non-utilisation of Rail Wagons

6480. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of rail wagons are not being utilised due to decline in goods traffic;

(b) whether the decline in goods traffic is due to losses and pilferages of goods from the wagons in transit;

(c) whether road transport of goods is cheaper and more secure and the railways are losing on this account also; and

(d) what steps are being taken to make goods traffic on rail wagons more cheap and secure in order to fetch more revenue by utilising the rail wagons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). No.

(c) Generally rail transport for goods is cheaper than road transport and railways are not losing on this account. However, road transport has certain inherent advantages like door-to-door transport of goods, lesser overall transit time and flexibility to choose the traffic etc.

(d) Studies are made to ascertain whether decline, if any, is due to higher freight rate classification for vulnerable commodities and classification is revised where found justified. Block rakes of certain important commidities are escorted. Customer oriented services like freight forwarder scheme and container services are being operated successfully.

Sub-standard of U.S.S.R. drill pipes

6481. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached with the U.S.S.R. in regard to Russian drill pipes which were found sub-standard;

(b) if so, when the matter was discussed with them last;

(c) what are the points of dispute now;

(d) by what time the matter will be settled;

(e) whether in view of the stiff attitude of the U.S.S.R. in this regard Government are considering to approach the U.S.A. and Canada for the same;

(f) if not, the main reasons for the same; and

(g) whether France has agreed to supply drilling pipes on reasonable rates?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (d). The matter is still under negotiation; it was last discussed with the Soviet side on March 17, 1978.

The points of dispute between the two sides relate to the interpretation of the USSR standards of inspection for the drill pipes with regard to wall thickness, cracks, overlaps and ovality. It is hoped to reach an agreement in the near future.

(e) to (g). At this stage it would not be correct to say that USSR has adopted a stiff attitude in the matter. It is ONGC's policy to make purchases by global tendering on competitive basis, suiting its requirement. During the past about 2 years' there has been no specific demand for drill pipes and the Commission has not floated any tender therefor. Against this backward, if any French party on its own has made any offer for drill pipes, ONGC had not taken any action thereon as in any other case.

Fees charged by Lawyers

6482. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering to ask the lawyers to lower fees charged by them;

(b) if so, whether in certain cases the fees charged by the lawyers is Rs. 1600 per day and in miscellaneous matters the charge is Rs. 800/-;

(c) if so, whether the Government are considering to reduce and fix some rate so that the legal service is available to the common people; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH YADAV): (a) No such proposal is under consideration of the Government at present.

(b) Yes, Sir.

(c) No such proposal is under the consideration of the Government at present.

(d) The fees payable by a client to his lawyer is settled by agreement between them, and the Government have no legal power so far, to get the lawers's fees reduced.

Ex-Cell-O Corporation

6483. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ex-Cell-O India's shares will soon be offered to the Indian public;

(b) if so, whether the Ex-Cell-O Corporation of U.S. which at present hold 75 per cent of the equity capital of the company has decided to invest its holdings in the Indian company;

(c) if so, whether the scheme has already been prepared;

(d) if so, whether the Indian company which was incorporated in 1958 had set up two plants one in Thana in Maharashtra and other in Nasik will increase its production capacity by the above decision; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUHAN): (a) to (c). As per the balance sheet of M/s. Ex-Cell-O India Limited for the period ended 30-11-1977, the total paid-up capital of the company was Rs. 53,40,000 divided into 53,400 equity shares of Rs. 100 each, out of which 40,000 shares

representing 75 per cent of the capital of the company were held by M/s. Ex-Cell-O Corporation of U.S.A. According to information furnished by the Ministry of Finance, that Ministry has received an application from Ex-Cell-O India Limited for permission to sell the entire shareholding of the U.S.A. company to Indian nationals, and the company's application is under consideration.

(d) and (e). Government have no information as to whether the Indian company has any proposal to increase its production capacity.

Procurement of wagons

6484. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during 1978-79 the Railway Board have plans to procure 8500 wagons only;

(b) if so, how far this is true;

(c) whether the hopes that the wagon industry pinned on earlier reports of a significant step up in the Railways Board's plans to procure wagons during 1978-79 have proved illusory;

(d) if so, whether the wagon industry feels that this decision of Railway Board of procuring only 8500 wagons will hit the industry hard; and

(e) if so, what steps are being taken to help the wagon industry which is already a victim of gross under-utilisation of capacity and will thus continue to face stagnation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). In line with the funds allotted by the Planning Commission, Ministry of Railways have planned to procure during 1978-79, 10,000 wagons in terms of four wheelers (8500 units from the Industry and 1500 units from the Railway Workshops).

(c) Ministry of Railways had not given any indication to the wagon industry that there will be a significant step up in their plan to procure wagons in 1978-79. It is well known to the industry that wagon production will be regulated by the Ministry of Railways within the funds allotted by the Planning Commission.

(d) and (e). Ministry of Industry have represented to Ministry of Railways that any cut back in production will adversely affect the industry. The Ministry of Industry have taken up the matter with the Planning Commission and Ministry of Finance for suitable additional allocation of funds to Ministry of Railways to enable higher level of wagon production during 1978-79. In case this does not materialise there is no alternative for the industry but to diversify their spare capacity or secure export orders.

Monopolistic positions of large houses

6485. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what steps Government have taken to ensure that the big undertakings belonging to large houses do not continue to occupy monopolistic positions in the industry to which they belong;

(b) whether Government have undertaken any study of the pricing policy, profitability, marketing policies or distribution system adopted by the monopoly undertakings; and

(c) if so, what are the results thereof and what steps Government have taken to check the harmful effects of the monopolistic practices?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The Government has been taking steps to ensure that the growth of all monopoly undertakings covered by the provisions of Part A of Chapter-III of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 is in accordance with the provisions of the said Act, keeping in view the two main objectives of preventing concentration of economic power to the common detriment and prohibiting monopolistic and restrictive trade practices within the guidelines provided in section 28 of the Act. Besides, the Industrial Licensing Policy as revised from February, 1973 also subjects M.R.T.P. undertakings to the restrictions envisaged in respect of large industrial houses for purposes of industrial licensing under the Industrial (Development & Regulations) Act, 1951. The statement on Industrial Policy, laid before Parliament on the 23rd December, 1977, also spells out the latest policy of the Government towards large industrial houses and the role of large-scale industries. It may also be stated that the present provisions of the M.R.T.P. Act are being reviewed currently by a High Powered Expert Committee with a view to making recommendations for improving the efficacy of the statute.

(b) and (c). A few studies have been made, as a result of which references in respect of three multinational companies were made under section 31(1) of the M.R.T.P. Act to the M.R.T.P. Commission for making an inquiry. The references have, however, been challenged through writ petitions filed in the Delhi High Court and the inquiry proceedings by the Commission have been stayed under orders of the Court. A reference made under section 27 of the M.R.T.P. Act in respect of an Indian company has also been stayed in a similar manner by an order of the Delhi High Court.

Wagon for loading forest produce

6486. DR. VASANT KUMAR PANDIT:

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is it a fact that the contractors are getting regular and adequate railway wagons to load their forest produce on South Eastern Railway in Madhya Pradesh;

(b) are the same facilities given to the Government of Madhya Pradesh to load their forest produce; and

(c) if not, reasons for this disparity between the Government of Madhya Pradesh and the private contractors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). Traffic in forest produce on State Government account enjoys priority class 'C' under the Schedule of Priorities and is, therefore, entitled to higher priority than the traffic on trade account, which moves under the lowest priority i.e. class 'E' of the Schedule. The demand of traffic on State Govt. account has been much less than that on trade account. Whereas demand for 147 wagons was only pending as on 31.3.78 on State Govt. account, demand for 9,377 wagons was pending on the same date on trade account.

Railway lines in M.P.

6487. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total railway route length per thousand sq. Kms. in M.P.;

(b) what is the total railway route length per thousands sq. Kms. for whole of India;

(c) whether it is not a fact that the States Reorganisation Commission had recommended laying of more railway lines in M.P.; and

(d) if so, whether the Government are taking any steps in view of the recommendations of States Reorganisation Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Route kilometres per 1000 square kilometres area in M.P. and whole of India are 12.95 and 18.94 respectively.

(c) Yes.

(d) A statement is attached.

(d) The States Re-organisation Commission, 1955 had recommended the construction of the following rail links:—

(1) Rail link from Jabalpur to Lalitpur or Jhansi.

(2) Rail link from Jabalpur to selected points in the South West and the South East on the Central and South Eastern Railway respectively.

(3) New railway line running East to West through Vindhya Pradesh.

Recommendations for construction of new railway lines/gauge conversions have been received from the State Government of Madhya Pradesh from time to time and the present position of the projects recommended by the State Government is given below:—

Sl No.	Name of the work	Present position
1	Construction of a new broad gauge line from Dhalli Rajahara to Jagdalpur.	Survey completed.
2	Construction of a new broad gauge line from Satna to Beohari via Rewa.	Survey carried out for the project revealed that the project will attract very little traffic. Reappraisal made recently for Satna-Rewa portion of the line also revealed that this section will attract very little traffic.
3	Construction of a new broad gauge line from Mahoba to Khajuraho.	The project has not been found to be viable as it will attract very little traffic.
4	Construction of a new broad gauge line from Ratlam to Banswara.	Survey have recently been completed.
5	Construction of a new broad gauge line from Ranchi to Korba.	Survey completed. The project will attract very little traffic.
6	Construction of a new broad gauge line from Indore to Mhow.	Surveys carried out for the project revealed that the project will attract very ittle traffic.
7	Construction of a new broad gauge line from Guna to Maksi.	The line has been completed and opened to traffic.
8.	Construction of a new broad gauge line from Jabalpur—Damoha—Tikamgorh—Lalitpur.	In view of the present difficult financial position of the Railways it may not be possible to take up the surveys for these rail links in the State of Madhya Pradesh at present.

Sl. No.	Name of the work	Present position
9	Construction of a new broad gauge line from Tikamgarh-Chhatarpur-Khajuraho-Panna-Satna.	In view of the present difficult financial position of the Railways it may not be possible to take up the surveys for these rail links in the State of Madhya Pradesh at present.
10	Construction of a new broad gauge line from Sagar-Kareli-Narsinghpur-Chhindwara.	
11	Construction of a new line from Maksi to Sivepuri.	
12	New Broad gauge line from Khandwa to Dohar via Bhikangaron, Khargaon, Barwan	
13	Coversion of Ujjain-Agar and its further extension upto Kota via Nalkheda, Sursar and Jhalwar.	Owing to the very limited availability of funds it will be difficult to consider this proposal at present.
14	Construction of a new broad gauge line from Indore to Dohad via Dhar and Jabhua.	Do.
15	Construction of a new broad gauge line from Chirimiri-Barwadih Baikhunthpur-Ambikapur.	A preliminary Engineering-*cum*-Traffic survey for a new BG line from Barwadih and Karonji has been included in the Budget for 1978-79.
15	Lalitpur to Singrauli via Khajuraho, Satna and Rewa in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.	A preliminary Engineering-*cum*-traffic survey has been included in the Budget for 1978-79.

The question of construction of the above mentioned new lines projects will depend upon the overall availability of resources for meeting similar demands from all parts of the country.

कर्मचारी कल्याण निधि

6488. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977–78 में कर्मचारी भविष्य निधि की पूरी राशि खर्च नहीं की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि उसमें बचत पूरी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था न करने अथवा इसके लिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्रावधान करने के कारण हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी अधिकाधिक चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों में कर्मचारी कल्याण निधियों की स्थापना हो चुकी है जिनके लिए प्रति अराजपत्रित रेल कर्मचारी (उन्हें छोड़कर जिन्हें पूंजी पर प्रभारित किया जाता है) के लिए 7 रुपये की दर से वार्षिक भुगतान रेलवे राजस्व से किया जाता है। कर्मचारी कल्याण निधि का संचालन एक समिति

करती है जिसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए रुपये खर्च करने का अधिकार होता है :—

1. कर्मचारियों और उनके बच्चों की शिक्षा, जब नियमों के अन्तर्गत शैक्षिक सहायता अन्यथा अनुमेय न हो।

2. कर्मचारियों और उनके बच्चों का मनोरंजन और मनोविनोद।

3. संकट में ग्रस्त कर्मचारियों या उनके परिवारों की सहायता करना जिसकी व्यवस्था वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत प्रदान नहीं की जाती है।

4. जो कर्मचारी डाक्टरी परिचर्या और उपचार नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं उन कर्मचारियों के परिवारों की बीमारी या प्रसूति में हितकारी योजनाएं। चूंकि निधि में से किया गया अंशदान अन्तिम अनुदान होता है और प्रबन्धक समिति द्वारा वर्ष विशेष के दौरान इसका पूरा उपयोग न किये जाने की स्थिति में इसके समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

1977—78 के दौरान, रेल कर्मचारियों के सभी वर्गों के सहयोग और समर्पण की भावना से किये गये काम से, सरकार ने कर्मचारी कल्याण और सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों को क्वाटरों और कालोनियों में सुधार, संशोधित शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुविधायें आदि के लिए 15 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान स्वीकार किया है। चूंकि यह योजना 1977—78 के उत्तरार्ध में स्वीकृत की गई थी, 1977—78 में उपयोग में न लायी गई शेष राशि की व्यवस्था 1978—79 के लिए की जा रही है और इस प्रकार 15 करोड़ का पूरा अनुदान उपयोग में लाया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेल कर्मचारियों के सुझाव प्राप्त हो रहीं हैं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सुविधाएं दी जा रही हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय जोनों में भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन

6489. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री 14 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रीय जोनों में भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रबन्ध पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रीय जोनों में कार्य के विभाजन के पश्चात् संबद्ध कारखानों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1-4-1978 से एफ. सी. आई. तथा एन. एफ. एल. का पांच कम्पनियों में पुनर्गठन किया गया है।

(ख) पुनर्गठन के फलस्वरूप नई तीन कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है जिस पर सरकार द्वारा लगभग 82 लाख रुपए पंजीकरण फीस के रूप में खर्च किया गया है। यह अनुमान है कि प्रशासनिक व्यय, पंजीकरण फीस को शामिल करके, एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होंगे।

(ग) संशोधित ढांचे का उत्पादन आदि पर प्रभाव का इतना शीघ्र मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

6490. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 घंटे की ड्यूटी लागू कर दिये जाने के बाद पश्चिम रेलवे में मऊ, रतलाम, उज्जैन और नीमच में लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है ;

(ख) उनके लिए इस समय क्या वैकल्पिक अथवा अस्थायी प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) रिहायशी आवास कब उपलब्ध किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग). लोको रनिंग कर्मचारी जो 10 घंटा नियम द्वारा शासित होते हैं उनकी कुल संख्या और इन स्टेशनों पर उनके लिए उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

स्टेशन		कर्मचारियों की संख्या	उपलब्ध रेलवे क्वार्टरों की संख्या
मऊ	.	311	115
रतलाम	.	480	200
उज्जैन	.	323	145
नीमच	.	256	106

जिन कर्मचारियों के पास रेलवे का आवास नहीं है वे अपना प्रबन्ध करते हैं । अधिक क्वार्टरों का निर्माण धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है । अतः यह कहना संभव नहीं है कि उपर्युक्त स्टेशनों पर सभी लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था कब की जायेगी ।

Appointment as dealers of Indian Oil Corporation from Ex-soldiers

6491. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) Number of Dealers of Indian Oil Corporation (B-Site Petrol Pumps) appointed so far and from how many of them security Deposit has been taken;

(b) is it a fact that no additional advantage is conferred on a small fraction of Indian Oil Corporation dealers including Ex-Soldiers from whom huge security deposit is taken whereas all those in large numbers from whom no security deposit is taken suffer from no disadvantage on that account; what does Government propose to do to rectify this discrimination and how soon;

(c) how many ex-soldiers have been appointed dealers Indian Oil Corporation and from how many of them security deposit has been taken; and

(d) whether Government proposed to help ex-soldiers in their resettlement by refunding their security deposit?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Out of a total of 448 'B' Site retail outlets commissioned by the Indian Oil Corporation under its 'Dealer Finance Scheme' introduced in January 1976, security (trade) deposit has been recovered from 417 dealers.

(b) No, Sir.

(c) 24 ex-servicemen have been appointed under IOC's 'Dealer Finance Scheme' and deposit has been collected from 10 such dealers.

(d) IOCs is considering refund of security deposit to ex-servicemen selected under 'Dealer Finance Scheme'.

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के मार्केटिंग डिवीजन में काम कर रहे लेखाकारों को पदोन्नति के लिए सामूहिक वरिष्ठता

6952. **श्री मही लाल :** क्या **पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के मुख्य कार्यालय, मार्केटिंग डिवीजन, रीजनल सेल आफिस तथा सेंट्रल आफिस में काम कर रहे लेखाकारों की पदोन्नति के मामले में सामूहिक वरिष्ठता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस श्रेणी के लिये इस विषय से संबंधित संशोधन किस तारीख को किये गये तथा इन संशोधनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त संशोधनों के बारे में सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया था ;

(घ) क्या प्रबन्धकों ने उक्त संशोधन अपने कुछ चहेते लेखाकारों की अवैध रूप से पदोन्नति करने के लिये किये थे, और यदि हां, तो कितने लेखाकार अपने कनिष्ठ साथियों से कनिष्ठ हो गये हैं ;

(ङ) क्या वरिष्ठता की सूची लेखाकारों को परिचालित की गई थी ; और

(च) क्या सरकार ने अनियमितता तथा भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मुख्यालय के नई दिल्ली स्थित विपणन प्रभाग में कार्यरत लेखापाल और केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत लेखापाल एक ही काडर में आते हैं और उनकी वरिष्ठता भी एक ही है। कम्पनी के विपणन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों/डिपों में नियुक्त लखापाल अलग काडर/वरिष्ठता में आते हैं।

(ख) लेखापालों की वरिष्ठता के बारे में निर्धारित नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता, आई०डी०पी०एल० ने रिपोर्ट भेजी है कि ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ङ) वरिष्ठता सूची उपलब्ध है लेकिन उसे परिचालित नहीं किया गया है क्योंकि उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था।

(च) लेखापालों की पदोन्नति के बारे में जब कोई अनियमितता अथवा पक्षपात का मामला सरकार के ध्यान में लाया जाये तो उसकी जांच की जायेगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० में वरिष्ठता संबंधी नीति

6493. **श्री मही लाल :** क्या **पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के कारखानों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से स्थानान्तरित लेखाकारों और अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उन्हें अपनी वरिष्ठता में परिवर्तन करने का विकल्प दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). लेखापाल जो या तो अपनी प्रार्थना पर या कम्पनी के हित में प्रबन्धकों द्वारा स्थानान्तरित किए गए थे वरिष्ठता के लिए अपने मूल काडर में तब तक रहेंगे जब तक कि उनके उच्चतर पद में पदोन्नति द्वारा अथवा अन्य प्रकार से उनके वर्तमान काडर से संबंध समाप्त नहीं किए जाते हैं । उनकी नीति के अनुसार वरिष्ठता में परिवर्तन चुनते की स्वीकृति नहीं दी जाती है । अधिकारियों के काडर के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों को नीति के अनुसार एक संयंत्र/कार्यालय स दूसरे संयंत्र/कार्यालय में सामान्यतः स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जाती हैं । तथापि यदि कर्मचारी की इच्छा पर उसका स्थानान्तरण किया जाता है तो वह नये स्थान की नियुक्ति के काडर में सब से जूनियर माना जायेगा ।

कासगंज तथा अछनेरा स्टेशनों पर जंजीर खींचने की घटनाएं

6494. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कासगंज तथा अछनेरा मीटर गेज लाइन के विभिन्न स्टेशनों पर वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान स्टेशनवार जंजीर खींचने की कितनी घटनायें हुई और इस कारण रेलवे को वर्षवार कितना कितना घाटा हुआ ; और

(ख) उक्त मामलों में सरकार ने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और सावधानी बरतने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के मीटर लाइन के कासगंज-अछनेरा खंड पर 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान खतरे की जंजीर खींचने और वैक्यम प्रणाली में गड़बड़ करने के कारण गाड़ियों को स्टेशनों पर अथवा स्टेशनों के बाहर रोकने की क्रमशः 485 और 428 घटनायें हुई। इस कारण गाड़ियों के चालन-समय में 1976–77 के दौरान 66 घंटे 22 मिनट और 1977–78 के दौरान 63 घंटे 6 मिनट की हानि हुई ।

(ख) प्रत्येक वर्ष में पांच-पांच व्यक्ति पकड़े गये और उन पर मुकदमा चलाया गया। चल टिकट परीक्षकों तथा विशेष जांच दलों द्वारा की जाने वाली सामान्य चैकिंग के अतिरिक्त सादी पोशाक में चल टिकट-परीक्षकों द्वारा घात लगाकर भी जांच की गई थी। रेल उपयोगकर्ताओ की सूचना के लिये शिक्षा-संबंधी पोस्टर्स और पर्चे लगाये गये थे। इस खंड में सिविल प्राधिकारियों के समन्वय से जांच कार्य में और तेजी लाई जा रही है ।

नैनी गेट पर शटल गाड़ी का रुकना

6495. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होने 30 दिसम्बर, 1977 को सी०ओ०डी० शटल गाड़ी को छिपकी (इलाहाबाद) प्लेटफार्म पर रुकने के स्थान पर नैनी गट पर रुकने का आदेश दिया था लेकिन उक्त आदेश का सम्बद्ध अधिकारियों ने पालन नहीं

किया है और दुर्घटनाओं के कारण 12 व्यक्ति पहले ही मारे जा चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश का उल्लंघन करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख). जी नहीं। किन्तु छिवकी यार्ड के आगे के दो समपार गेटों, अर्थात एक मुख्य लाइन पर और दूसरा माल लाइन पर, में से किसी पर भी गाड़ी का ठहराव संरक्षा की दृष्टि से वांछनीय नहीं है। आदेशों के पालन न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों द्वारा सुझाव

6496. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि भूतपूर्व रेल मंत्री श्री सी० एम० पुनाचा ने सब श्रेणियों के कर्मचारियों को दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुझाव देने को कहा था।

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार स्टेशन मास्टर, गार्ड, सी० एण्ड डब्लू स्टाफ ड्राइवर और सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों जैसे गाड़ी संचालन कर्मचारियों से दुर्घटनाएं रोकने के लिए मार्ग–उपाय आमन्त्रित करने का है।

(ग) क्या संचालन कर्मचारियों में अधिकारियों के रवैये के विरुद्ध भारी असंतोष व्याप्त है जो उन्हें परेशान किये रहते हैं और इसी कारण 24 अक्टूबर, 1977 के सुरक्षा पखवाड़े के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनके क्या विचार हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख). दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए न केवल रेल कर्मचारियों से बल्कि दूसरों से प्राप्त सुझावों का भी स्वागत किया जाता है। रेल दुर्घटना जांच समिति जो कि हाल ही में दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा गाड़ियों का सुरक्षित चालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान संगठन उपस्कर तथा पद्धतियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय सुझाने के लिए बनायी गयी है, निस्संदेह विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के विचारों को ध्यान में रखेगी।

(ग) जी नहीं, वास्तव में नवम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 तक के चार महीनों के दौरान पिछले चार महीनों अर्थात जुलाई, 1977 से अक्टूबर, 1977 के मुकाबले कम रेल घटनाएं हुई थीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली टिकटों की बिक्री

6497. **श्री राम कंवर बरवा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि नई दिल्ली स्टेशन पर जाली टिकटें बेचे जाती हैं जिससे यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थान के लिए दो तीन गुना अधिक किराया देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाई की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे विभाग को नयी दिल्ली स्टेशन पर जाली टिकटों की बिक्री के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन, एक सूचना के प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच पड़ताल करने से यह शंका पैदा हो गयी है कि नयी दिल्ली स्टेशन के एक या अधिक टिकट परीक्षकों के पास अतिरिक्त किराये की जाली टिकट पुस्तकें हैं।

(ख) और (ग) जांच पड़ताल संबन्धी प्रारंभिक रिपोर्ट को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास और आगे जांच पड़ताल और कारवाई के लिए अग्रेषित की गयी है। रेल मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामला दर्ज कर लिया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

Availability of crude to oil Refineries

6498. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Oil Refineries are not working in full capacity due to non-availability of crude;

(b) if so steps taken to improve the production; and

(c) the steps taken to use the Bombay High Crude in different Refineries?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No, Sir. As much crude as is necessary keeping in view the demand for petroleum products, is being made available to the refineries.

(b) Does not arise.

(c) Arrangements have already been made to process a total of 5.2 million tonnes per annum of Bombay High Crude in Bharat Refineries, Cochin Refineries and Caltex Oil Refineries (India) Ltd. However, during monsoon period crude oil cannot be despatched by tankers to Cochin Refineries and CORIL, Vizag. For this reason the capacity to refine Bombay High Crude is redirected to Bharat Petroleum Corporation Ltd., Bombay only at the rate of 4.0 MTPA during this period.

Facilities are being provided at the Koyali Refinery to process 2 MTPA of Bombay High Crude and to increase the capacity at BPCL/CORIL refineries to process Bombay High Crude by 1 MTPA. The Mathura refinery under construction will handle 3 MT of Bombay High Crude per annum when it is commissioned.

Representation regarding Trains between Calicut and Shornur

6499. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether he has received representation dated the 2nd November, 1977 from some citizens from Malabar area in Kerala regarding train facilities specially between Calicut and Shoranur;

(b) i so, what are the main points o the representation; and

(c) what is the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) The demands were for extension of 514 Cannanore-Calicut Passenger to Cochin/Shoranur, restoration of No. 65 Cochin-Cannanore Passenger and introduction of an additional Passenger train between Calicut and Shoranur.

(c) The run of 65 Cochin-Cannanore Passenger was curtailed on Shoranur-Cannanore section due to poor occupation. However, a compensatory service has been provided on this section by extending a passenger train on Olavakkot-Cannanore section (No. 511 Passenger). This provides a convenient connection at Shoranur for passengers coming from Cochin by No. 65 Cochin-Shoranur Passenger and wanting to travel to Cannanore. For Passengers from Cannanore towards Cochin No. 62 Cannanore-Comibatore Passenger, closely following 514 Cannanore-Calicut Passenger, provides a convenient connection with 66 Shoranur-Cochin Passenger at Shoranur. Therefore, it is not desirable to extend No. 514 Passenger to Cochin or No. 65 Passenger to Cannanore.

The traffic offering between Calicut and Shoranur is adequately served by 3 pairs of passenger services running on this section. There is no justification for introduction of an additional train.

Railwaymen of Jamalpur Workshop

6500. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) has the Railway Minister received an SOS from Railwaymen of Jamalpur Workshop, submitted by Eastern Railwaymen Union, Workshop Branch, Jamalpur;

(b) if so, what is the reaction of the Government thereto; and

(c) is it a fact that the Workshop and its Steel Foundry, Forge Shop and Rolling Mills are suffering for want of work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes, a representation was received last year.

(b) It has been decided to introduce additional lines of production to compensate for reduction in steam loco periodical overhaul workload. A scheme for setting up facilities in Jamalpur Workshop at a cost of Rs. 1.22 crores for POH of diesel Hydraulic locomotives has been included in the Budget for 1978-79.

(c) Adequate workload exists, at present, in Jamalpur Workshop and no subunit is suffering for want of load.

Less use of Loco Sheds

*6502. SHRI P. G. MAVAANKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the loco sheds in various parts of the country are gradually getting less used on account of electrification and/or other factors;

(b) if so, facts thereof;

(c) if not, whether the said loco sheds are being used to their optimum capacity and efficiency; and

(d) if so, how?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) In some of the sections electification has resulted in reduction of workload in steam loco sheds.

(b) to (d). In order to use the steam loco sheds to their optimum capacity and efficiency, consequent upon the fleet of steam locomotives having been reduced commensurate with the reduction in workload due to dieselisation/electrification, suitable readjustment of staff and assets has been carried out.

Areas affected by Pollution due to Drilling and Exploration

6503. PROF. G. MAVALANKAR: Will the Minister of PETROLEUM,

CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that extensive areas in Gujarat, Bombay, Assam, etc. where Oil and Natural Gas are found, drilled and further explored have been adversely affected by any kind of pollution;

(b) if so, broad details thereto; and

(c) steps being taken by the Government to remedy the situation?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Over Charging by U.S. Pharmaceutical Companies

6504. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply to Starred Question No. 9 dated the 21st February, 1978 regarding Anti-Trust Suits against U.S. Pharmaceutical Companies and state:

(a) estimated over-charging of the domestic as well as overseas purchases by each of the U.S. Pharmaceutical firms mentioned in the reply;

(b) *modus operandi* of over-charging by these firms;

(c) when exactly this illegal operation was detected;and

(d) what follow-up action, if any, is being taken in the light of the U.S. Supreme Court judgment?.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (d). Following the report of a Committee of the U.S. Senate it came to the notice of the Government of India in 1969 that six (6) U.S. Drug Companies, namely Pfizer, Cyanamid, Squibb Bristol Mayors, Upjohn and Olin had allegedly entered into a conspiracy in concerted price fixation of certain Broad Spectrum Antibiotics and thereby had over-charged the domestic as well as the overseas purchasers of the same during the period 1954—67, Government of India had filed a civil suit in U.S. Courts against all the six companies on 11th October, 1974.

The amount over-charged made by these companies in respect of purchases by India and the damages in relation thereto is being determined in consultation with the Government Attorneys.

Now that the U.S. Supreme Court has ruled that a Foreign Nation is also a "person" within the meaning of the Clayton Act, enabling the Nation to use a Damage Brief will have to be filed in the U.S. Courts by the Government of India. Action in this regard is being taken.

Union Carbide India Limited

6505. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the paid up capital and assets of Union Carbide India Ltd., a U.S. Multinational firm operating in India;

(b) composition of the Company's board of directors;

(c) whether the present Managing director of the company was, till recently, Managing Director of Backalyte Hylum which is a sister concern of Union Carbide India Ltd.;

(d) whether the Government has received an unsigned memorandum from some employees of the company containing serious allegations of irregular activities in contravention of the provisions of the Companies Act, against the present Managing Director

and other top management personnel of the company; and

(e) what action, if any, has been taken on the said allegations?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Union Carbide India Ltd., is a subsidiary of a multinational company, *viz.* Union Carbide Corporation of U.S.A. As per its latest Annual Report as at 25th December 1977 the company's paid-up capital amounted to Rs. 18.43 crores and the value of its assets to Rs. 68.19 crores.

(b) The composition of the company's Board of Directors as given in its Annual Report for the year ended 25th December, 1977 was as under:—

1. Keshub Mahindra—Chairman
2. B.V. Salenius—Vice-Chairman.
3. W. R. Gorrea—Managing Director.
4. P. C. Banerjea—Deputy Managing Director.
5. A.M.M. Arunachalam.
6. V. P. Arya.
7. J. B. Law.
8. A. W. Lutz.
9. Bhaskar Mitter.
10. N. J. Moden.
11. R. Natarajan.
12. James S. Raj.
13. J .M. Rehfield.

(c) Yes, Sir. Dr. W. R. Correa who was appointed as Managing Director of Union Carbide India Limited on 15th August, 1977 was Managing Director of Bakelite Hylam Ltd. a sister concern of the former till 15th August, 1977.

(d) No, Sir. No such unsigned memorandum has been received by the Department of Company Affairs.

(e) Does not arise.

Railway Link between Agartala and Assam

6506. SHRI JYOTIRMOY BOSU:

SHRI JANARDHANA POOJARY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 135 on the 21st February, 1978 regarding Railway link between Agartala and Assam and state:

(a) whether the present Chief Minister of Tripura, Nripen Chakravarty called on him on 12th January, 1978 to press for the immediate extension of the railway line from Dharamnagar to Kumarghat and thereafter to Sabroom *via* Agartala;

(b) whether the people of Tripura observed one day's peaceful bandh demanding extension of Railway facilities; and

(c) if so, what steps, if any, are being taken on the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Yes.

(c) Dharmnagar-Kumarghat line in Tripura is one of the six lines proposed by the North Eastern Council for construction in the North Eastern Region. The Planning Commission has appointed a Committee to examine these proposals in depth and a decision on the construction of the lines would depend upon the recommendations of the Committee, which has been allowed 8 months to finalise its report.

Railway Facilities in and around Haldia

6507. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether General Secretaries of Haldia Refinery Employees' Union and

Fertilizer Corporation of India Employees' Union, Haldia, submitted a memorandum to him on November, 14, 1977 urging upon the Government to extend railway facilities in and around Haldia;

(b) if so, the text of the said memorandum; and

(c) what action, if any, is being taken on the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). The memorandum of Haldia Refinery Employees' Union and F.C.I. Employees' Union has not been received. However, a copy of representation dated 1st February, 1978 from Shri Madan Mohan Bose, President, Haldia Refinery Employees' Union, has been received wherein provision of the following facilities have been suggested:

(i) Constuction of Sealdah-Namkhana rail link *via* Budge Budge, Raichak;

(ii) Direct link between Haldia and Calcutta through regular launch services on the Hoogly river between Kukrahati and Raichak which will provide shorter and economical route to Calcutta through Budge Budge-Namkhana rail link, as compared to the existing route via Panskura.

(c) A final location survey for the proposed Budge Budge-Namkhana rail has been included in the Budget for 1978-79. The suggestions will be kept in view at the time of carrying out the survey.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए चूना पत्थर की लदाई

6508. श्री शरद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सुन्दरसन्स, मैहर ने मैहर, मध्य रेलवे से दुर्गापुर (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड) के लिये माल डिब्बों में चूना पत्थर की लदाई की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से अनियमितताओं के बारे में जांच की गई थी और उसके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा मैसर्स एस० एन० सुन्दरसन्स का नाम काली सूची में रखा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के परिणामस्वरूप क्या ऐसे तथ्य पता लगे जिनके परिणाम स्वरूप फर्म को दोषी पाया गया और क्या इस फर्म का कोई निदेशक जैड० यू० आर० सी० सी० तथा डी० यू० आर० सी० सी० का सदस्य रहा है और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, मार्च 1975 तक।

(ख) और (ग) जी हां। मैसर्स सुन्दरसंस द्वारा की गयी तथाकथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रांची द्वारा जांच पड़ताल शुरू की गयी थी लेकिन हिन्दुस्तान स्टील लि०, दुर्गापुर द्वारा अभी तक मैसर्स सुन्दरसन्स का नाम काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है। इस जांच पड़ताल के परिणाम दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों इस्पात एवं खान मंत्रालय या रेल मंत्रालय को ज्ञात नहीं हुए है, मैसर्स सुन्दरसंस लि० को मध्य रेलवे का क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति मंडल रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श को समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, लेकिन श्री एस० एन० बेरी की जो इस समय फर्म के निदेशक है सचिव, सतना लाइम स्टोन कम्पनी सतना के रूप में "विशेष

हित" को ध्यान में रखते हुए मंडल रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति, जबलपुर में 1972 और 1973 तथा 1-9-75 से 31-12-1977 तक प्रतिनिधित्व दिया गया था।

महर से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को भेजे गये पत्थर चूने के रेक

6509. **श्री शरद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रलवे के मैहर, काहन गांव निवाड़ स्टेशनों से टाटा नगर (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) को गत सात वर्षों में चूने पत्थर के कितने रैक भेजे गये ;

(ख) प्रत्येक रैक में चूने पत्थर का वजन क्या था जिसके भाड़े का भुगतान किया गया और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने चूने पत्थर के कितने वजन के लिये भुगतान किया ;

(ग) कौन सी फर्म चूना पत्थर सप्लाई करती रही है और उसके भाड़े का भुगतान किसने किया है ; और

(घ) वर्ष 1970 से 1977 तक कितने रेकों का लदान किया गया और प्रत्येक रेल के वजन में कितना अन्तर था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

6510. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में कुल कितने अनुभाग है और उनमें ऐसे अनुभागों की संख्या क्या है जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं ;

(ख) ऐसे कितने अनुभाग है जहां टिप्पण-प्रारूपण हिन्दी में होते हैं, शेष में ऐसा न होने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या सभी अनुभागों को हिन्दी में टिप्पण और प्रारूपण तैयार करने के लिये स्पष्ट अनुदेश भेज दिये गए हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) इस मंत्रालय/विभाग में कुल 75 अनुभाग है। इनमें से 69 अनुभागों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं।

(ख) जिन अनुभागों में टिप्पण और प्रारूपण कार्य हिन्दी में किया जाता है, उनकी कुल संख्या 14 है। विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग और कम्पनी कार्य विभाग है। इन विभागों में जो कार्य किया जाता है वह विधिक प्रकृति का कार्य है ; अत: बाकी अनुभागों में टिप्पण और प्रारूपण में हिन्दी के प्रयोग के अवसर सीमित है। तथापि, जब कभी अपेक्षित होता है ये अनुभाग भी अपने टिप्पण और प्रारूपण कार्य में हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

(ग) जी हां।

Working Hours of Running Staff

6511. SHRI YASHWANT BAROLE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a decision on the question of working hours for the running staff is being actively considered by his Ministry;

(b) if so, whether any assessment has been made of the additional hands that would be required to fill up the gap; and

(c) when a decision will be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). A decision to reduce the working hours of running staff in principle from 12 to 10 hours has already been taken. 2700 additional posts were sanctioned by the Ministry of Railways between December 1977 and January, 1978 to enable the zonal Railways to implement this decision.

Crimes on Running Trains

6512. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of heinous crimes committed on running trains in 1976 and 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Representation by Indian Rope Manufacturers Associations

6513. SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Indian Rope Manufacturers Association has represented against the high price of jute batching oil; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) The representation that there has been an increase in price as a result of the Budget proposals for 1978-79 is under examination by the Government.

Prohibition of Coaching Clerks as Commercial Apprentice at New Delhi Railway Station

6514. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some relieving Coaching Clerks working at New Delhi Railway Station were promoted as Commercial Apprentice in 1975-76;

(b) if so, whether those employees were given one advance increment also, if so, number of such employees and action taken by Government for irregular benefit may please be quoted; and

(c) whether their parents were also given award/advance increment and other benefits, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Yes. In one case one of the Railway employees who was working as Parcel Clerk was, appointed as Commercial Apprentice in 1975-76. He had himself been given an advance increment as Parcel Clerk for his loyalty during Railway Strike in 1974. The question of the correctness

of the benefits given in this case is being reviewed by the Railway Ministry.

(c) The father of the employee had originally been given cash award which was later on converted into advance increment. Subsequently towards the end of 1975 benefit of advance increment was withdrawn consequent on his son's appointment as Commercial Apprentice.

Retrenchment of Casual labour

6515. DR. BIJOY KUMAR MONDAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is it a fact that there are proposals to retrench the Railway Casual labour in hundreds working under Deputy Chief Engineer (Const.) Waltair though they have put in 8 to 17 years of continuous service, against the basic policy of this Government;

(b) whether any steps are taken to save these labours from retrenchment and to accommodate them either in permanent vacancies or to absorb in alternative projects;

(c) in case of absorbing them in alternative projects any steps are taken to protect their rate of pay; and

(d) what are the reasons for keeping the panel pending even though these labour were screened on 6th October, 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Jammu-Udhampur Line

6516. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total expenditure incurred this year for the construction of railway line from Jammu to Udhampur;

(b) if no expenditure has been incurred the reason for the same, keeping in view the commitment made by the Minister on the floor of the House; and

(c) is it also under active consideration of his Ministry to make Jammu a railway junction by connecting Jammu with Punch via Akhnoor or round about?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Final Location (Engineering) Survey for Jammu—Udhampur B.G. rail link is in progress. The estimated cost of this survey is Rs. 11.69 lakhs. No decision has been taken for taking up the project and it would depend upon the availability of resources.

(c) There is no proposal at present under consideration for construction of a railway line from Jammu to Punch via Akhnoor.

Appointment of High Officers through, U.P.S.C.

6517. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a number of Junior Officers have submitted any representation during February, 1978 to the Government in regard to discrimination practice followed by the Railway Board in regard to the appointment of high officers by interview through UPSC;

(b) if so, contents of the representation made thereon;

(c) whether it is also a fact that such appointments of high officers were declared invalid by Allahabad High Court sometime back; and

(d) if so, Government's reaction thereto and what action has since been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). It is presumed that the Hon'ble Member is referring to the Temporary Assistant Officers who were recruited through the Union Public Service Commission. A representation has been received from these officers about their permanent absorption in Class I, seniority based on their total length of service and promotional prospects.

(c) No.

(d) Does not arise.

जोनवार विक्रेताओं (वेंडर) की संख्या

6518. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के विक्रय विभाग के विक्रेताओं को दिये जाने वाले कमीशन की दर क्या है तथा इन विक्रेताओं की जोनवार संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): कमीशन की दरें 2% से 25% तक भिन्न-भिन्न होती हैं। 30-6-77 को कमीशन वेंडरों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार थी :—

1. मध्य	537
2. पूर्व	938
3. उत्तर	853
4. पूर्वोत्तर	385
5. पूर्वोत्तर सीमा	44
6. दक्षिण	332
7. दक्षिण-मध्य	204
8. दक्षिण पूर्व	46
9 पश्चिम	176

Fresh Appointment in Railways

6519. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) fresh appointment given in the Railways to unemployed youngmen, including skilled and unskilled categories after the formation of Janata Government till 31st January, 1978;

(b) break-up of their figures (i) Railway-wise (ii) Headquarter-wise (iii) important junction station-wise (iv) temporary or casual (v) permanent, and (vi) various categories of appointments; and

(c) the estimated figures of various recruitments likely to be made by the Railways during 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Off-shore Drilling in Coastal Region in West Bengal

6520. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether off-shore drilling in the Coastal region of Bay of Bengal in West Bengal area has been abandoned;

(b) if so, (i) the company which undertook such drilling, (ii) the depth of drilling, (iii) cause for not under taking drilling at greater depth;

(c) whether drilling in other places in West Bengal Coastal region (off-shore) will be undertaken;

(d) if so, or if not, facts thereabout; and

(e) facts about the scientific data regarding prospects of finding off-shore oil in Bay of Bengal adjacent to West Bengal and Orissa Coast?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (e). The Carlsberg India Group drilled two wells on two separate structures in the offshore area off the coasts of West Bengal and a portion of Orissa to the total depth of 4069 metres and 4648 metres respectively. Not having discovered hydrocarbons these wells were abandoned and the Group exercised its option for the termination of the contract effective from 1-8-1977. The drilled depths were considered adequate for an evaluation of the potential hydrocarbon traps in the two structures.

As per the prognostic assessment of oil and gas prospects of the country made by a joint Indo-Soviet Team the prognostic reserves of oil and free gas for West Bengal basin come to about 450 million tonnes of oil and 2050 billion cubic metres of free gas. Out of these the prognostic assessment of recoverable reserves for oil comes to nearly 130 million tonnes comprising of 40 million tonnes from land and 90 million tonnes from offshore and for free gas the assessment comes to nearly 1650 billion cubic metres. As per the same study, the prognostic assessment of reserves for Mahanandi Basin comes to 5 million tonnes of oil and 45 billion cubic metres of free gas. Out of these the prognostic assesment of recoverable reserves is estimated at 1.5 million tonnes of oil and 35 billion cubic metres of free gas.

The offshore data obtained from the geophysical survey and exploratory drilling in the area alongwith similar data from onshore part are being analysed by the ONGC with the help of a team of Russian experts. Future programme for exploration in the area will dependent on the outcome of the analysis.

विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता

6521. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है और उनमें से कितने प्रतिशत उर्वरकों की आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जा रही है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनका उत्पादन किस सीमा तक बढ़ने की सम्भावना है; और

(ग) उर्वरकों के मामले में देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1977-78 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन और आवश्यकता निम्नप्रकार है :-

नाइट्रोजन के लिए मात्राएं लाख मी०टनों में

	आवश्यकता (अनुमानित)	उत्पादन	आवश्यकता की तुलना में उत्पादन की प्रतिशतता
1	2	3	4
नाइट्रोजन	28.88	20.13	69.7 प्रतिशत
फास्फेट	8.27	6.70	81 प्रतिशत
पोटाश	4.69	पोटाश (के2 ओ) का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता है ।	

(ख) और (ग) उर्वरक क्षमता के विस्तार के लिए बड़े पैमाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 बड़े आकार वाली उर्वरक परियोजनाएं अभी कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से 1982-83 तक अर्थात् छटी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 52.50 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 16 लाख मीटरी टन फास्फेट के अनुमानित मांग की तुलना में नाइट्रोजन का 41 लाख मीटरी टन तथा फास्फेट का 11.25 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है। अन्तर को कम करने तथा आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने के लिए बम्बई हाई/दक्षिण बेसीन स्ट्रक्चर से उपलब्ध गैस पर आधारित चार बड़े आकार वाले नाइट्रोजनयुक्त संयंत्र तथा असम में आयल इंडिया लि० और ओ० एन० जी० सी० के तेल क्षेत्रों से उपलब्ध गेस पर आधारित एक संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मैसर्स नागारजुना फर्टिलाइजर्स, आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा नामक स्थान पर एक उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहा है। मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लि० का अपने कानपुर स्थित विद्यमान उर्वरक संयंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव है।

इंडियन रेलवे कानफ्रेंस एसोसिएशन

6522. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन की स्थापना कब की गई थी और उसके उद्देश्य क्या-क्या हैं ;

(ख) इसका वर्तमान क्षेत्राधिकार तथा कार्य क्या है; और

(ग) क्या इसकी अनुपयोगिता को देखते हुए इसे समाप्त करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण : (क) वर्ष 1904-05 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके उद्देश्य इस प्रकार थे :—

(1) यानांतरण यातायात के प्रबन्ध के लिए नियम बनाना।

(2) माल-डिब्बा पूल का रखरखाव।

(3) कम्पनी रेलों के बीच यानांतरण स्थलों पर माल-डिब्बों का तटस्थ परीक्षण।

(ख) सभी सरकारी रेलें, लाइट रेलें, पोर्ट ट्रस्ट रेलें, पार्ट ट्रस्ट रेलें, आदि इस सम्मेलन की सदस्य हैं। भारतीय रेल सम्मेलन के वर्तमान कार्य इस प्रकार हैं:—

(1) तटस्थ नियंत्रण परीक्षण।

(2) माल डिब्बों का भाड़े पर लेने और हिसाब से सम्बन्धित काम जिसमें पाकिस्तान और बंगला देश की रेलों के साथ लेन-देन सम्बन्धी बिलों का आदान-प्रदान शामिल हैं।

(3) वाणिज्यिक समितियां।

(4) माल-डिब्बों के यानांतरण से सम्बन्धित सूचना का प्रकाशन, एकत्रीकरण और समालोचन तथा ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर इसे सौंपे जायें।

इसके अलावा भारतीय रेल सम्मेलन इस समय मीटर लाइन यानांतरण सम्बन्धी काम सम्हाल रही है जिसे यथा समय बोर्ड के संगणक केन्द्र द्वारा सम्हाला जाना निश्चित हुआ है जैसा कि बड़ी लाइन यानांतरण सम्बन्धी काम के बारे में हो चुका है।

(ग) भारतीय रेल सम्मेलन के जिम्मे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसलिए उसे समाप्त करने का विचार नहीं है।

राठवाड़ा डिवीजन में पुराने स्टेशन

6523. **श्री केशव राव धोंडगे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा डिवीजन के कितने पुराने स्टेशनों को प्राधुनिक बनाने तथा वहां सुविधाएं प्रदान करने का सरकार का क्या विचार है; और

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं; जिनको नया रूप दिया जायेगा तथा प्राधुनिक बनाया जायेगा ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : मराठवाड़ा क्षेत्र में एक स्टेशन अर्थात् औरंगाबाद के नवीकरण का प्रस्ताव है।

Amount of Deposits against Cooking gas Cylinders in Maharashtra

6524. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the total amount of deposits against the cooking Gas-Cylinder with the various Agents of Maharashtra as on 1st March, 1978;

(b) whether the customers are paid interest on the deposits so made and at what rate;

(c) whether the deposits amount is alone with the Agents or a part of it is deposited with the concerned company; and

(d) how the deposit amounts are utilized?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (d). In the case of Liquified Petroleum Gas (cooking gas) cylinders, the security deposit carrying no interest goes to the marketing company which owns the cylinders, as at any time, more than one cylinder is required per consumer to take care of maintenance, transit time, etc. This requires extra investment. On the other hand, no rent is charged on the cylinder from the consumer. The security deposit is refunded when the cylinder is surrendered. This is an industry practice. The Oil Prices Committee have taken this practice into consideration in fixing marketing margins.

In Maharashtra, marketing of LPG, is done by three Oil companies namely, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited and Caltex Oil Refining (India) Limited. Distribution of LPG is done directly by the Bharat Petroleum Corporation Limited, while the Hindustan Petroleum Corporation and Caltex Oil Refining (India) Limited are distributing LPG mainly through concessionaires.

The cylinder deposit amount is utilised for replenishment of cylinders and for operating and maintaining the LPG facilities at an efficient level.

In the case of Bharat Petroleum Corporation Limited, the cylinder deposits are kept with the Corporation itself. While the total amount of deposit collected all over India and kept with the BPCL is about Rs. 5.79 crores, as on 1-3-1978, separate figures of such deposits in respect of Maharashtra State are not available.

In the case of Hindustan Petroleum Corporation Limited, the cylinder deposit amount is retained by the concessionaires who own the cylinders except where the HPCL itself has invested in cylinders and regulators. The total amount of deposits from HP Gas consumers in Maharashtra as on

1.3.1978 is Rs. 326 lakhs out of which a sum of Rs. 274 lakhs is with the concessionaires and the balance of Rs. 54 lakhs is with HPCL.

In the case of Caltex Oil Refining (India) Limited, before its take-over by Government, the cylinders were procured by the concessionaires. An amount of about Rs. 51.36 lakhs is with the concessionaries against the cylinders procured by them. Towards the cylinders provided by CORIL, after Government take-over, an amount of about Rs. 14.98 lakhs is kept with the said Company.

Piling up of stones in Western Railway

6525. SHRI CHATURBHUJ: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to the shortage of wagons at Kota Modak, Bhawani Mandi, Ramganj Mandi and other stations in Western Railway huge quantity of stones have piled up in those places with the result that 15,000 labourers employed there are apprehending retrenchment; and

(b) if so, the action taken by Government to make available wagons at these stations soon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). Kota, Morak, Darah and Ramganj Mandi are the principal stone loading stations on Western Railway. No traffic in stone is offered at Bhawani Mandi. Consistent with the commitments of Railways to clear essential commodities on preferential basis, efforts are being made to clear the backlog in stone traffic as expeditiously as possible. As many as 13,910 wagons were loaded with stone on Western Railway during the year 1977-78. There has been some backlog in the clearance of this traffic, which was caused by a sharp increase in the lead of originating traffic on the Western Railway. This rose from 506 KMs per tonne of traffic carried in 1976-77 to 552 KMs in 1977-78 and has affected wagon availability.

Allotment of Wagons to Gujarat

6526. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the allotment wagons to the Gujarat state during the 1977-78 was much less than the previous years;

(b) if so, the main reasons for the same;

(c) whether from 1st March 1978 the railway wagons to the State were still much less and in certain cases the shortage of wagons have greatly affected the movement of crude from Kandla; and

(d) if so ,whether the Union Government have been urged to increase the allotment of wagons to the State of Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Allotment and loading of wagons at railway stations in Gujarat State during 1977-78 was about 9,000 wagons more on the broad gauge and 12,900 wagons more on the metre gauge than last year.

(b) Does not arise.

(c) Allotment and loading of wagons in March, 1978, also has been higher than last year. There is no programme of movement of crude oil from Kandla.

(d) Does not arise.

खण्डवा तथा दोहद के बीच लाइन

6527. श्री अक्षय सिंह ठाकुर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खण्डवा तथा दोहद के बीच बरास्ता भीकम गांव खारगांव और बादवानी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जानी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, पश्चिम निमार, घाट के आदिवासी जिलों के आर्थिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक विकास के लिए खण्डवा और दोहद के बीच एक रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) रतलाम के आमान परिवर्तन स्थल होकर खण्डवा पहले से ही दोहद से मिला हुआ है और यह दूरी 370 कि०मी० है। प्रस्तावित 290 कि०मी० लम्बी बड़े आमान की इस लाइन पर वर्तमान मूल्यों के अनुसार लगभग 54 करोड़ रुपए लागत आएगी। संसाधनों की कठिन स्थिति के कारण, इस समय इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

Contracts and Licences Granted to S.C./S.T.

6528. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state the total number of contracts/licences granted by his Ministry, its attached and subordinate offices including the public sector undertakings and the share there, if any, to S.C. and S.T. in each category of such contracts/licences during the entire period of Janata regime and if not, why?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): There is no reservation for SC/ST in the award of contracts. The statistics of the number of contracts or of the community of the person to whom any contract is awarded are not maintained.

No licences are issued by this Ministry or the undertakings.

Principles for Appointment of High Court Judges

6529. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the principles followed by Government for appointment of High Court Judges; and

(b) how many of the High Court Judges belong to the minority communities and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Appointments to the High Courts are made in accordance with the provisions of article 217 of the Constitution.

(b) The information is being collected from the various High Courts and will be laid on the Table of the House.

Transfer and Appointment of Judges

6530. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a controversy created over the transfer of certain Judges and Chief Justice; and

(b) if so, do the Government made any proposals to evolve new norms for transfer and appointment of Judges?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The transfers of Judges made during the emergency without their consent did raise a controversy.

(b) There is no proposal under the consideration of Government for adopting a policy of transferring Judges from one High Court to another, without their consent. There has been no occasion, therefore, of considering the adoption of any norms for transfers. In so far as the appointment of Judges is concerned, is it governed by Article 217 of the Constitution. The question whether any improvement can be brought about in the

procedure of appointment of Judges has been referred to the law Commission.

---

12. hrs.

MR. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

RE. REPORTED BURNING OF EFFIGY OF SHRI JAGJIVAN RAM AT BANARAS

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Sir, today in the papers a report has come about the effigy of Babu Jagjivan Ram having been burnt because he said in Banaras that a non-brahmin should become the Vice-Chancellor of the Sanskrit University. This is not the first time that Babu Jagjivan Ram, who is a leader of the Harijans and a national leader, has been insulated in the State of Uttar Pradesh. And formerly, our Members were exercised and were in great anger and anguish over these incidents, and it is unfortunate that only 3 days after we discussed the matter of atrocities on Harijans in this august Parliament, has this happened again. I would request you, since he is the Defence Minister of the country, to write to the Chief Minister of U.P. to see that such incidents do not recur, and that this insult to the Harijan community and to the down-trodden people in the country as a whole is not repeated. Parliament takes this in all seriousness. He is the Union Defence Minister; and time and again we are complaining that these things are recurring again and again. It is dangerous for the country that the atrocities are continuing, and the insults on the down-trodden people and atrocities on them are continuing. My friend has also given a motion.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I have given a Calling Attention motion.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, I would request you to admit it, because these atrocities are occurring off and on, in spite of the important discussions that we have here. (*Interruptions*).

SHRI VAYALAR RAVI: I have given a Calling Attention motion. Please accept it.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): What is happening in U.P. is a most surprising incident. It must be stopped, and it is the duty of the State Governments to see that such types of things do not take place. These types of incidents are agitating the minds of all the people in the country.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): This is how the Chief Minister of U.P. is running the Government. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Would it not be better if we go according to the rules? There are ways of opening these debates. This is not the way—barging in and making a statement.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: There is no such thing as Zero Hour now. It becomes a zero time, and zero work. Therefore, we have evolved so many things. There is 377.

SHRI K. GOPAL (Karur) (*rose*)

MR. SPEAKER: There is absolutely ....I have not found a single rule providing for a zero time or zero hour.

SHRI SAUGATA ROY: If you, in your wisdom, reject the motion, there is no way in which our feelings can be made known to this august House. (*Interruptions*) That is why we take this opportunity of zero hour. When the effigy of Shri Jagjivan Ram 's burnt in Banaras...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You have mentioned it.

SHRI K. GOPAL: There must be... (*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA: How long can we go on like this?

SHRI SAUGATA ROY: You don't like us to exercise our rights this way. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: But you have been doing it.

SHRI SAUGATA ROY: It is an important matter, Sir. (*Interruptions*) Will they write to the Chief Minister of U.P.? (*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA: The Prime Minister is sitting here. I would like to put a question to the hon. Prime Minister. Will he say something about this?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : (वाराणसी) बाबू जगजीवन राम जी का जो पुतला जलाया गया है, यह श्री कमलापति त्रिपाठी और श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से निरंतर बदनाम करने का प्रयत्न है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have already mentioned that.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Sir, with your permission, I will make only two submissions. Firstly, on the 7th evening, what the Prime Minister and the Leader of the House has stated has set the tone for our own attitude to such incidents. We should always be ashamed of any such incidents anywhere in the country. Secondly, my hon. friend, Shri Roy, has described Shri Jagjivan Ram as the leader of the Harijans. It is intentional. Please see the records... (*Interruptions*)

SHRI SAUGATA ROY: It is a wrong statement. I said: he is one of the national leaders to whom the Harijans look up to in this country. When there has been...... (*Interruptions*)

श्री राम अवधेश सिंह (बिक्रमगंज) पुलिस की मौजूदगी में रक्षा मंत्री का पुतला जलाया गया, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

SHRI K. LAKKAPPA: Is any Government running in U.P.?

MR. SPEAKER: Let the Parliament run first.

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): There was a Calling Attention given notice of yesterday on which you said that you will consider it on Wednesday. From the newspaper reports it is very clear that there has been a constitutional break-down and the army has been called.

MR. SPEAKER: Yesterday I have said that I would call a meeting of the leaders tomorrow. I have already mentioned that tomorrow we are meeting to discuss it.

SHRI VAYALAR RAVI: I have given notice of one Calling Attention and one notice under rule 377 regarding the incident of the burning of the effigy of Shri Jagjivan Ram, not because he is...

MR. SPEAKER: It has not come to my hand. When did you give notice?

SHRI K. GOPAL: Your office is not giving...

MR. SPEAKER: Mr. Gopal, Mr. Ravi is capable of looking after himself.

SHRI K. GOPAL: My submission is that your office does not even care to inform us whether it has been admitted or not.

MR. SPEAKER: Mr. Gopal, Mr. Ravi is making a representation and he can defend himself.

SHRI K. GOPAL: You say you have not received it. Last week we gave some notice and so far we have not been told as to what happened to that. We do not believe that, even if you receive it, any action will be taken.

SHRI VAYALAR RAVI: I am making my submission because of the seriousness of the matter. It is not a question about Shri Jagjivan Ram alone. Many other things are involved. Already several Calling Attention Notices have been given. I am not concerned about any firing in any State. There is large-scale firing in different States. About 10 to 12 people have died in Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and also in Andhra Pradesh. So, in different States ruled by different parties, police firing has taken place, resulting in the death of 10 or more people, why it is happening? What is the intention of the police? We will not be satisfied with a reply that it is a State subject. This is a matter in which the House itself should feel concerned, because people are being killed as if in a slaughter house. In Madhya Pradesh and in Tamil Nadu in the firing about 11 or 12 people died. It is a very serious matter. Apart from the party affiliations, we will have to go into the root of the matter. Let us have a discussion.

12.10 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT RE. SETTING UP OF ADVISORY COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): I beg to lay on the Table a statement (Hindi and English versions) regarding setting up of an Advisory Committee on Chemicals and Fertilizers together with a copy of Government Resolution No. L. 16013(4)/78-Ch. II/Desk dated the 20th April, 1978. [*Placed in Library. See* No. LT-2063/78].

ANNUAL REPORT OF DEVELOPMENT COUNCIL FOR ORGANIC CHEMICAL INDUSTRIES FOR 1976-77

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कार्बनिक रसायन उद्योग विकास परिषद् के वष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[*Placed in Library. See* No. LT-2064/78].

12.11 hrs.

RE. NOTICES UNDER RULE 377

SHRI R. V. SWAMINATHAN (Madurai): Sir, I have given notice under rule 377. I think it has been circulated. Of course, I do not want to raise it at this stage. There is a serious situation in Tamil Nadu. Firing has taken place in Madurai district day before yesterday and also yesterday.

MR. SPEAKER: You have given notice under rule 377. It is under my consideration.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I have been told that it has been admitted.

MR. SPEAKER: You will be called in due course.

SHRI KANWARLAL GUPTA (Delhi Sadar): With your kind permission, may I submit that I gave a notice to you under rule 377 regarding the withdrawal of consent by the Karnataka Government to C.B.I. to investigate criminal offences? This is a serious matter, and it affects Centre-State relations.

MR. SPEAKER: If you make a statement now, I need not allow it. I have not disallowed it. The matter is under consideration.

SHRI K. GOPAL (Karur): You were kind enough to say that you were considering my notice, but some procedure should be evolved. Notices are sent and whoever is allowed is informed, but in respect of notices which are not allowed, the office should have the courtesy at least to inform the Member that it has not been allowed.

MR. SPEAKER: You are misunderstanding the position. Notices which are not allowed today may be allowed tomorrow.

SHRI K. GOPAL: I have not heard about last week's notice till today.

MR. SPEAKER: Only if it is rejected you are informed, because we select five notices every day. What I consider to be more urgent I select earlier. That is all. That does not mean that your notice has been rejected.

श्री राम सेवक जी हजारी (रोसड़ा): मैंने 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया है कि मेरी कांस्टीटुयेन्सी में एक गांव में 400 घर जल गए हैं। उस गांव से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को प्रति वर्ष 13 लाख रुपया उत्पादन शुल्क मिलता है और वहां पर 400 घर जल गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से जो रिलीफ मिलता है, वह न के बराबर है।

MR. SPEAKER: If you make the statement now ,I will not allow it later. Your notice is under consideration.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Indian nationals have been drafted as mercenaries by the Lebanese. I have given notice. It is a very serious matter. Therefore, I draw your attention to it.

MR. SPEAKER: Yesterday, the Foreign Minister made a statement. You were not here.

SHRI K. LAKKAPPA: That is not correct.

12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED POLICE FIRING AT THE BAILADILA IRON ORE MINES ON 5 APRIL, 1978

श्री डी० जी० गवई (बुलढाना): मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर इस्पात और खान मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "5 अप्रैल, 1978 को बस्तर में बेलाडीला लौह अयस्क खान क्षेत्र में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने, जिससे कई श्रमिक मारे गए तथा अनेक घायल हुए का समाचार।"

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Sir, it is with a sense of deep grief and distress that I rise to inform the House of the unfortunate incidents which took place at the Bailadila Iron Ore Mines of the National Mineral Development Corporation, in Bastar District on the 5th April 1978, in which 9 persons, including a Police Head Constable, lost their lives and several others, including State Government Officers and men

[Shri Biju Patnaik]

and mining workers received serious injuries. Two more persons later succumbed to their injuries in hospital. The Minister for Tribal and Harijan of the Government of Madhya Pradesh, Shri Baliram Kashyap accompanied by the Inspector General of Police have visited the site of the incidents on the 6th April, 1978. The Chief Minister of Madhya Pradesh has also announced that a judicial enquiry headed by a High Court Judge would be held. He has also announced immediate ex-gratia payment of Rs. 5,000 each to the families of the deceased persons including the head constable, Rs. 1,000 to each person with bullet injuries and Rs. 250 to each of the persons otherwise injured and hospitalised.

N.M.D.C. has also announced immediate ex-gratia payment of Rs. 5,000 to the family of each of the deceased and Rs. 1,000 to all persons injured and hospitalised (60 persons). Additionally, an amount of Rs. 100 will be given by N.M.D.C. to all those whose huts have been destroyed in fire. The Contractor has also announced ex-gratia payment of Rs. 1,000 to the relatives of each of the deceased.

While we shall have to await the findings of the Judicial Enquiry, I am sure the Hon'ble Members will join me in conveying the sympathies of this House to the bereaved families.

As I had stated in the Rajya Sabha on the 3rd March 1978, manual mining of float ore, through a system of contracts, was resorted to in the Bailadila area as a temporary measure, till such time as the production from the mechanised mines came up, to meet the commitments under a long-term iron ore export contract entered into by the MMTC with the Japanese Steel Mills. In terms of this contract, an annual quantity of iron ore, increasing from 4.9 million tonnes in 1971-72 to 8 million tonnes in 1975-76 and each year thereafter upto 1981 was to be exported to Japan from Bailadila *via* Visakhapatnam.

Over the last 2 or 3 years, however, due to the acute recession in the steel industry all over the world, and more particularly in Japan, where this year the production has been cut back from a capacity of about 140 million tonnes to about 100 million tonnes, the Japanese steel industry have consented to take only 6 million tonnes of Bailadila ore during 1978-79 as against a quantity of over 8 million tonnes. Last year, in 1977-78 also, for the same reason, the Japanese Steel Mills lifted only 6 million tonnes against the provision of 8.16 million tonnes but manual mining was kept going under my orders by the N.M.D.C. at Bailadila in the hope of an improvement in the Japanese off-take in 1978-79. As a result, an all time high stock of 20 lakh tonnes of Bailadila ore has accummulated at the mines and at Visakhapatnam port as on the 1st of April, 1978 and further stock-piling has become a physical impossibility. In these circumstances, the phasing out of manual mining operations undertaken as a temporary measure had become inescapable. All our efforts to find other outlets for our iron ore have not met with any success in view of an unprecendented world-wide recession in the Steel industry.

Four Manual Mining contracts have been in operation in Bailadila for the last 2/3 years, employing about 7000 workers. These manual mining contracts were planned to be phased out progressively over a period of 12 months starting from 1st April, 1978 and keeping in view the build up of production from the new mine at Bailadila 5. One contract of M/S Ashok Mining Co., employing about 1,375 workers, came to a close on 31-3-1978. Two other contracts are coming to a close in August/September, 1978 and the remaining 4th contract extends only upto 31st March 1979, the quantity to be delivered during 1978-79 under these continuing contracts is as large as 15 lakh tonnes. As I have explained earlier NMDC already have a saturation stock of 20

[Shri Biju Patnaik]

lakh tonnes and can hardly accommodate a further intake of even 5 lakh tonnes. In these circumstances, there was obviously no possibility of extending the mining contract which was to close on the 31st March 1978.

With the imminent conclusion of their float ore mining contracts M/S Ashok Mining Company issued retrenchment notice to their workers in December, 1977. At this stage, one of the Unions, the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh Union, raised an industrial dispute for withdrawal of the retrenchment notice by the Contractor and on 10-2-1978, threatened to resort to direct action. Subsequently, the SKMS Union and the Metal & Mines Workers Union organised relay hunger strikes, processions and slogan shouting between 10th and 28th March, 1978 at Bailadila. Apart from NMDC's Union leaders and office bearers, some outside element also seem to have arrived in Bailadila towards the end of March, made provocative speeches and incited workers to resort to violence.

The Management of the N.M.D.C. held several meetings with the Union leaders and the Contractor and the whole position arising out of the recession in the Japanese Steel Industry was explained to them. The Contractor also offered to provide alternative temporary employment to about 800 workers in other places. The SKMS Union, however, called for a total strike from 30th March, 1978 and on the 30th they organised a procession and the workers were deliberately provoked to break the police cordon, gate crash into the administrative building premises and trespass into 'protected' areas. Willing workers engaged in loading of wagons were obstructed and intimidated on the night of 30th.

On the 31st March, a group of workers was instigated to enter the office of the General Manager and indulge in rowdyism and gherao. 31 arrests had to be made. On the 1st April again, there were instances of interference with the movement of iron ore trains and the movement of buses carrying workers to the mines. A violent mob tried to force entry into the NMDC Office and when prevented from doing so indulged in pelting of stones. Tear gas shells had to be exploded to control the violent mob.

In the meantime, following persuasion by the management and the Contractor, the workers who were actually affected by the retrenchment had agreed to accept retrenchment benefits. Between 1st and 3rd April, 1978, out of 1375 workers/employees of the Contractor eligible for payment of retrenchment benefits, 1327 had already collected their dues and most of them had left for their homes. However, some elements appear to have made a determined bid at this stage to exploit the situation and instigated other workers who had not been retrenched at all, to indulge in arson and violence as would be evident from the subsequent events.

From early morning of 5th April, 1978 some Union and outside leaders incited workers to resort to violence and to gherao the General Manager's residence. At about 7.30 A.M. when willing workers assembled to proceed to their work sites, other workers resorted to violence and stone throwing against them. At about 10.00 A.M. a police party led by the Sub-Divisional Magistrate, Dantewara, was attacked with lathis and lethal weapons. The SDM and 28 other police officers and men received severe injuries and one head-constable, Shri Kamal Singh, later succumbed to his injuries. Thereafter, an unruly mob of workers ran to the residence of the General Manager of the N.M.D.C. and assaulted the men on duty there. In defiance of the prohibitory orders under Section 144 Cr. P.C. which had been promulgated in the area, a mob collected and charged the police force and captured and severely manhandled some police personnel. The police burst 11 tear gas

[Shri Biju Patnaik]

shells to disperse the crowd but without success. Eventually. the police had to fire 21 rounds in self-defence under the orders of the Magistrate. From the information received it appears that, as a result of these incidents, apart from the 11 fatal cases, a total of 95 persons, including 29 police personnel, were injured. 60 persons were hospitalised; including one magistrate, 16 police personnel and 43 workers.

To bring the situation under control curfew was imposed from 3.00 P.M. on the 5th April, 1978 for 24 hours but again, at 8.30 P.M. in the night some unruly elements set fire to a number of hutments in two areas. A water supply pipeline which was meant for the workers was also damaged on the same day.

Curfew has been lifted from 7.00 A.M. on the 7th April, 1978. The State Government authorities are maintaining a close watch on the situation. Section 144 Cr. P.C. is still in force and no further incidents have been reported for the last 4 or 5 days.

While I have every sympathy with the workers who have had to move out from Bailadila due to the dwindling manual mining operations and look for employment in other places, the House will agree with me that such ups and downs in the world economy which have inevitable repercussions on us should not be allowed to be mischievously used for narrow purposes in callous disregard of the workers interest and lives as appears to have been done by some elements in Bailadila. If Mr. Stephen is a party to it, then I can only feel ashamed.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): You may feel ashamed; you must.

SHRI BIJU PATNAIK: The situation needs to be handled with care and consideration. I sincerely hope that the House would agree with me that violence would not solve the problem of unemployment in the iron ore industry thrust upon us by world conditions.

I would like to add that I have many more informations at my disposal—the manner or brutality how the police party was attacked, with their eyes gouged out, and so on. I do not wish to inform the House of the ghastly conditions because there is a High Court judge sitting as a Commission to inquire into it; I would not like to say anything which would prejudice the working of the Commission.

श्री डी० जी० गवई : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बेलाडीला के हत्याकांड और गोलीबारी के बारे में जो वक्तव्य दिया है, उससे ऐसा लगता है कि वह बहुत दिनों की पुरानी है, 5 अप्रैल को नहीं हुई। इस्पात, लोहा अयस्क खदान में काम करने वाली मजदूरों की आजीविका खान के काम पर निर्भर है। यह बहुत गरीब होते हैं और उनमें ज्यादातर आदिवासी, हरिजन और पिछड़े हुए समाज के लोग काम करते हैं। लोहा और पत्थर तोड़ने वाले लोग कौन होते हैं? वह अत्यन्त गरीब होते हैं जो रोज खून का पसीना कर के अपने खून की एक एक बूंद उस लोहे और पत्थर पर गिराते हैं। उनकी कुछ समस्या पैदा नहीं हुई, उन लोगों की छंटनी करना ठेकेदारों ने शुरू कर दिया। उनके बाल बच्चे भुखमरी का शिकार होने लगे। खदान में काम करने वाले को अगर निकाल दिया गया तो वह काम करने कहां जायगा, अपने बाल-बच्चों के मुंह में दाना डालने के लिये कहां से लायेगा? इसलिय वह अपने न्याय के अधिकार की मांग करता है कि हम इसी खदान में काम करते हैं, हमें जरूर ही काम मिलना चाहिये, हमारे बाल-बच्चों का गुजारा होना चाहिये और हमको रोज की रोटी नसीब होनी चाहिये। लेकिन उन गरीबों की आवाज किसी ने नहीं सुनी, न मंत्रालय ने सुनी और न ठेकेदारों ने सुनी। बस गरीब पर अन्याय करना चालू कर दिया। अब वह अपनी न्याय की मांग

को लेकर यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा खान मालिकों, ठेकेदारों या सरकार के पास जाता है तो उसको न्याय मिलना चाहिये। अगर मंत्री महोदय अप्रैल के पहले मार्च में बैलाडीला के उन मजदूरों, ठेकेदारों और कर्मचारियों की एक-आध बैठक बुलाकर उन लोगों को तसल्ली देते कि तुम सब को काम मिल जायेगा, तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बाल-बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तो जो घटना 5 अप्रैल को घटी है, वह टल सकती थी। 5 अप्रैल को सवेरे, सूर्य की पहली किरण से पहले, बेचारे मजदूर, जो भूखे पेट थे, अपने भूखे बाल-बच्चों को छोड़ कर न्याय मांगने के लिए गये कि हम को रोटी दो, काम दो, हमारा काम मत छीनो, हमारा हक मत छीनो, हमें भी जीने दो, हम ने भी जीना है, काम कर के जीना है, खून का पसीना कर के जीना है। लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। और उन की मांग सही थी। क्या ऐसे भूखे-प्यासे लोगों पर गोली चलाने या उन को पकड़ लेने से समस्या हल हो सकती है?

मैं यह नहीं कहता कि कामगरों में इतनी उत्तेजना पैदा हो जानी चाहिए कि वे आवेश में आ कर तोड़-फोड़ करने लग जायें। लेकिन हमारे देश की पुलिस इतनी निर्दय बन गई है कि जान लेना उन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है—एक क्या, हजारों जानें लेना उन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भूखे-प्यासे मजदूर जब 7½ बजे न्याय की मांग करने गये, तो उन की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वे पुलिस पर पथराव करें या पुलिस के साथ धींगा-मुश्ती करें या किसी का घर जलायें। गरीब आदमी गरीब का घर नहीं जला सकता है। झोंपड़ी में रहने वाला झोंपड़ी में रहने वाले के दुख को समझता है। वह जानता है कि झोंपड़ी में कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वह किसी की झोंपड़ी जलाने के लिये नहीं जायेगा।

लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि झोंपड़ियां मजदूरों के एक गुट ने जलाईं। मैं कहूंगा कि झोंपड़ियां जलाने वाले पुलिस और खान के ठेकेदार थे—उन्होंने झोंपड़ियां जलाईं और गरीबों को बेघर कर दिया, उन के रहने का ठिकाना छीन लिया, और फिर उन पर गोली बारी कर दी। उस में कितने ही लोग मर गये। मंत्री महोदय कहते हैं कि बहुत कम लोग गोलीबारी का शिकार हुए हैं, लेकिन दुनिया, अखबार वाले और इस देश की जनता कहती है कि उस खदान में कम से कम सौ व्यक्ति गोली का शिकार हुए हैं। उस में कुछ पुलिस वाले भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन में पुलिस वाले नहीं हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस घटना के घटने से पहले बैलाडिला क्षेत्र में जा कर क्या कदम उठाये और इन हत्याओं को रोकने के लिए क्या सुझाव दिये। अगर उन्होंने इस बारे में कोई कार्रवाई की होती, तो जरूर इस दुर्दैव को टाला जा सकता था, जिस पर हमें शर्म आती है, कि हमारे गरीब लोगों पर इस तरह से गोलीबारी की जाये। मेरी विनती है कि वह अब भी उन लोगों की जानें बचाने के लिए कुछ करें।

SHRI BIJU PATNAIK: Sir, Mr. Gawai knows very well that I have been to Bailadilla. Some time back I went there and discussed this matter with the authorities of the National Mineral Development Corporation, with the Union leaders and others. I had made statements from time to time that because of the world-wide recession the iron-ore industry going to be in great difficulties and I cautioned all these people—the contract workers and other workers—that there would be some need for retrenchment from time to time because we cannot escape the wrath of world recession either especially in the steel industry, as I have stated in my statement.

[Shri Biju Patnaik]

Mr. Gawai talked of poor Adivasis. Mr. Gawai should know that it is not poor Adivasis who are working there but poor Oriyas from my State who are working there, whom I had to retrench. They took their retrenchment benefits and left for home. It is not they who created the trouble, but the persons****.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, now that the judicial enquiry is going on...

SHRI BIJU PATNAIK: I agree with you, Sir, but these are the facts.... (*Interruptions*).

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): How can you make allegations, when it is under an enquiry? How can you do that?.

SHRI BIJU PATNAIK: One is still absconding. Such are the leaders. I would like this House to be convinced that such are the union leaders who hide themselves and send ordinary workers.... (*Interruptions*) I condemn such people.... (*Interruptions*).

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: On a point of order, Sir, he cannot make such allegations in the House.. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I am accepting your point of order, Madam. The Minister should not refer to any individuals at this stage, because the matter is under a judicial enquiry. Particularly, when you mention, Mr. Minister, it becomes very...... You can make a general statement, but do not name anybody.

I am removing from the record any reference to any individual having incited or taken part in the matter; that would not form part of the record. On the other side also, there should be no insinuation against anybody, because there is a judicial enquiry.

Mr. Minister, anything further?

SHRI BIJU PATNAIK: I have nothing else to say.

SHRI C. M. STEPHEN: Is that all over?

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): He has not replied fully.

SHRI CHITTA BOSU (Barasat): He has not replied.

SHRI BIJU PATNAIK: I have replied to all his points in my statement already. The Speaker has quite rightly prohibited me from dilating on this case as a judicial enquiry is going on. I have myself said that in the statement also. I do not propose to make any further statement.

MR. SPEAKER: Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE (Akola): There are two points.... (*Interruptions*).

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): What precisely was the Minister doing in that place? The House is interested to know that and before stating that, he got infuriated.... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Your name is not in the list of members in this Calling Attention. Now Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE: Two main questions arise in this Calling Attention. This whole problem was related to the question of employing about 7000 persons for manual work, when you had an idea and a long term contract with Japan, as you say in your statement, upto 1981. Annually, they were to take eight million tonens of iron ore. This was to increase from 4.9 million tonnes in 1971-72 to eight million tonnes in 1975-76 and upto 1981. If this was a long-term contract already, in terms of the contract, the Japanese Government or with whom you have the contract, were also bound. When you make a long-term arrangement, employ certain workers, is it not the moral responsibility of your Ministry to see that these persons are

****Expunged as ordered by the Chair.

provided for, because you cannot play with the employees. Today, you employ them, tomorrow because of a recession, because the Japanese party lift up only six million tonnes and do not lift up the remaining balance of two million tonnes, you throw out your employees. Next day, the party there will say: All right, we will lift eight million tonnes. In that case, you will call them back. This is playing with the lives of the people. The contractors also are bound to discharge certain responsibilities of finding alternate employment. After all, what were you paying them? You are paying them hardly Rs. 108 per month through the contractors for working 12 hours a day. ....

SHRI CHITTA BASU: With no other benefits.

SHRI VASANT SATHE: Yes, with no other benefits. This was the state of affairs. This is called sweated labour by any standards. ....

SHRI BIJU PATNAIK: Started in 1971. You overlook that.

SHRI VASANT SATHE: Yet, you do not consider. ...... (*Interruptions*). You must know that we can both do it. ....

SHRI BIJU PATNAIK: I do not know whether you can, but I can.

SHRI VASANT SATHE: I know what you have done. You are trigger-happy, you have used bullets. ....

AN HON. MEMBER: ..which you never used?

SHRI VASANT SATHE: This was brought to the notice of the hon. Minister as far back as December and the leaders from the Union came to meet him and they also called on the Prime Minister and brought to his notice that some arrangements must be made. When in 1978 the first contract was to be over, some arrangements, some alternate arrangements ought to have been made for these 1375 employees. Instead of doing that, what does the Minister tell them? He is alleged to have said—the response of the central leaders apart from not being helpful—this is what Mr. Patnaik is reported to have said, 'Do what you like. My problem is to retrench a lakh of people all over the country....

SHRI BIJU PATNAIK: Who said that?

SHRI VASANT SATHE: ....in the mining industry. This is what was reported. But what is the promise of this Janata Government? One million people will be found jobs every year. But, here, the poorest of the poor who are already employed in the mining industry are being thrown out of jobs and you cannot find even temporarily alternate jobs for them.

Then, what is the allegation? The most serious parts now are these. 1375, he says, was the number of employees and due to his persuasion—please see page 5, para 10—1327 already collected their dues and left for their homes. So, the balance is only 48. ....

SHRI BIJU PATNAIK: That is right.

SHRI VASANT SATHE: Now, are you trying to tell this House that 4 employees created such a chaos and situation that you had to open fire on them? Because, who were the persons concerned? The agitated persons—their number is only 48.

SHRI BIJU PATNAIK: They were not.

SHRI VASANT SATHE: He said 'No, others came and instigated.' After all whom could they instigate? Those who were concerned, those who were feeling the pinch, those who were starving and those who were thrown out. That, according to you, is only 48. And then the most blasphemous, if I may say so, and callous statement

[Shri Vasant Sathe]

by the hon. Minister is when he says in para 12:

> "To bring the situation under control, curfew was imposed from 3 p.m. on 5th April, 1978 for 24 hours, but, again at 8.30 p.m. in the night some unruly elements set fire to a number of hutments in two areas.".

It is suggested thereby that it was not the Police who were let loose on the poor workers because a Head Constable lost his life....

MR. SPEAKER: Now you are coming to that area.

SHRI VASANT SATHE: I am careful. I have not said a single name.

MR. SPEAKER: Even the Police—whether they have set fire or not.

SHRI VASANT SATHE: This is the allegation in the case.

MR. SPEAKER: The allegation is 'Some unruly elements....'

SHRI VASANT SATHE: That is their case. But the allegation of the employees which is being inquired into—they have also registered cases with the Police—is this, and I am making a statement which is already reported in the Press. I am not naming anybody. I am not naming Constable Mr. X or Constable Mr. Y or Constable Mr. Z. I am saying, how can you say as if some third parties burnt the hutments. Here an indirect suggestion is being given as if the other people themselves burnt the huts of the employees. I want to know what is the attitude of the Government? Rs. 5,000/- are now being paid to the family of those who lost their lives. You do not worry when they are alive to see that they are kept alive. You just throw a pittance at the family of the persons who are killed. Last year in this very area Rajarah Mines—workers were killed.

I am finding a tendency. I do not want to accuse the present Government, but I am finding a tendency growing of easily opening fire on the workers, on the poor people to suppress them when they are making their grievance for their legitimate demands—either wage rise or livelihood to protect their services. If this is the attitude to the working class that is going to be adopted, I know because instances speak for themselves, I would say that preventive action could have been taken. This dispute could have been resolved. Their emoluments, livelihood, service could have been protected. If really an alternate employment was found for them or they had willingly accepted that and if the workers themselves were satisfied, it is wrong to suggest that anybody could provoke the workers to class violence which will lead to such atrocities. I have received a telegram which says that wives of trade union leaders have been arrested and are being held as hostages and are being ill treated and harassed.

Will the hon. Minister, the Prime Minister is also here, look into this. if similar things are being done this is a matter to be seriously taken note of. This is again I would say of no use in the larger context to have a post martem. Every time this happens. Will some assurance be given by the hon. Minister to prevent all this and he should try to resolve it? There is no problem that cannot be solved if you have a proper approach and peole have been aproaching in December..

MR. SPEAKER: That must include.

SHRI VASANT SATHE: I am not excluding myself....

MR. SPEAKER: I am mentioning about the concluding of the debate here.

SHRI VAANT SATHE: I am submitting in all anxiety, will some measure be taken and mainly of a feeling of approach? Let there be a feeling in the people that if they are peaceful,

there will be no violence on the side of the Government, because the gun is with the government and not with the people. I want this assurance and what is going to be done....

SHRI BIJU PATNAIK: I am very sorry you have permitted him to say all these things....(*Interruptions*).

MR. SPEAKER: That is not a matter of enquiry.

SHRI BIJU PATNAIK: It is a matter of enquiry.

MR. SPEAKER: No, no. (*Interruptions*).

SHRI BIJU PATNAIK: You have been a Supreme Court Judge.

MR. SPEAKER: That is why I am saying.

SHR BIJU PATNAIK: He said: 'Police have been trigger happy....'

SHRI VASANT SATHE: No: I said: You are trigger happy.'

MR. SPEAKER: If he has said 'deliberately killed' I will remove it.

SHRI BIJU PATNAIK: I have read the statement. The police party were attacked and a constable was killed. To protect themselves under the orders of the Magistrate they had to open fire.

SHRI VASANT SATHE: You let loose the whole (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I will examine the records and if there is something I will remove that. (*Interruptions*)**

SHRI VASANT SATHE: Would you be happy with this?

SHRI BIJU PATNAIK: I am not happy with this.

SHRI VASANT SATHE: Why do you defend this? Don't defend it.

SHRI BIJU PATNAIK: I am not happy with your manner of presentation.

SHRI VASANT SATHE: My friend is defending this sort of arson, loot and murder by whoever they are. Therefore, my question is this. Will you take steps to see that hereafter at least in your Ministry, in the Mines, such instances will not take place? Will you see that employees are not thrown out of their jobs like this and such conditions will not arise? Will he assure us on this point?

SHRI BIJU PATNAIK: Mr. Sathe you have asked for it and now you must be at the receiving end. In 1971 —I have said this earlier—Mr. Sathe and his Government headed by Mrs. Indira Gandhi, were bent upon having mechanisation. They wanted machines instead of man-power. (*Interruptions*) Listen to it carefully, my friend This work could have been done by hand but they introduced machines. Hundred crores have been invested, of this nation's money, on machines. And machines are ready. They are working. In the meantime the world steel-industry came to a collapse. And in the last whole year, Mr. Sathe, not by your asking, not by any labour unions' asking, I had deliberately allowed these men to continue with the work so that today 2 million tonnes of iron ore is stocked at Bailadilla in the rail head, in the port and everywhere. The total stock today of iron ore in all the ports and at the rail heads held by the MMTC is more than 6 million tonnes. Please listen to fact Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE: You cannot use their ore inside.

SHRI BIJU PATNAIK: Naturally you cannot just burn them inside with the furnaces. You may be a magician Mr. Sathe! And he talks of us

****Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Biju Patnaik]

being trigger-happy. Well, Mr. Sathe must understand what I said. I made a polite statement. I said, the world steel industry has virtually collapsed. There is a 35 per cent reduction in Japan. There is a 25 per cent reduction in the Enropean countries. Please listen to that....

SHRI C. M. STEPHEN: What have you got to say in reply to his question?

SHRI BIJU PATNAIK: These insinuations by Mr. Sathe is something which I strongly repuidiate. Here is a case where I warned them, I told them, this is bound to come, you make arrangemenets, it is not possible for Government to provide you with jobs. Government cannot provide employment. With the world production having come down in the iron ore industry Government has to provide work to crores of people in the countryside. So, these people can break stones somewhere. They can do some other work somewhere. They are not even hand-operators, they are hand workers. So, it is not a question cf 7,000 workers being collected there and doing the work there. It is not possible. Some had gone from Ganjam district of Orissa, some 600 of them. There is not one adivasi among these. There is not one adivasi of that district and of that area, who are wounded, who are killed, or anything like that. This was not instigated by people who were retrenched. This was instigated by the union leaders who wanted to force the other people. I do not want to say more. That gentlemean is absconding till now; he is such a here after having seen that the people are killed! Sir, I do not wish to say anything more as you have directed and quite correctly. A High Court judge is going into it and I do not wish to add anything more. But the world condition is such everywhere, not only here. In Orissa, in Bihar and in Mysore (Karnataka) there is bound to be some retrenchment. (*Interruptions*). Listen to me. I am not yielding.

SHRI VASANT SATHE: Don't yield. I say that a six year old boy by name, Shri Maya Ram was shot dead on the spot. Was he trying to be violent? I would like to know that.

SHRI BIJU PATNAIK: I have no such information.

SHRI VASANT SATHE: I am giving you the information—the name.

SHRI BIJU PATNAIK: All this will have to be gone into by the Judge. So, I do not wish to say anything at this stage. (*Interruptions*) Your former Government used to shoot down many in Delhi. You did not bother about it. Let the High Court judge look into this. We do not break the laws, we do not denigrate the judiciary as Mr. Sathe and his Government had done We will not do so. (*Interruptions*) My lips are sealed. So also the Government's. The high court judge is sitting over it. I will not say any more on this. That is the end of it. (*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE: What is his reply, Sir?

MR. SPEAKER: He says he has no further reply to give as there is a judicial enquiry.

SHRI BIJU PATNAIK: I will not go into this as it is now within the jurisdiction of the High Court judge.

SHRI VASANT SATHE: I have asked him as to what measures he is going to take to ensure that in future such contingencies of retrenchment and hardships to employees will not arise. What are you going to do about it?

SHRI BIJU PATNAIK: Retrenchment in the iron ore industry is bound to take place and such men who are working as temporary labour will find work elsewhere.

MR. SPEAKER: Mr. Ram Kishan. He is not here. Shri Yamuna Prasad Shastri.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चूंकि यह मेरे घर, मध्यप्रदेश का मामला है, इसलिए मुझे थोड़ा अधिक समय दिया जाए। श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, मैं समझता हूं कि उस वक्तव्य से किसी को संतोष नहीं हो सकता है। श्रीमन् यह कहना गलत है कि वहां आदिवासियों की जानें नहीं गयीं। यह मामला तीन-चार महीनों से चल रहा था। उनको छटनी का नोटिस दिया गया था। यह कहा गया था कि काम कम है, जापान में इस्पात उद्योग में रिसेसन आ गया है, इसलिए छटनी करने का मामला उठा है। श्रीमन् बड़े आश्चर्य की बात है कि स्टील के मामले में हमारा देश इतना सम्पन्न नहीं हुआ है कि हम अपने आयरन ओर का पूरा उपयोग न कर सकें। हमारे यहां स्टील का उत्पादन दस मीलियन टन भी नहीं होता है जबकि जापान जैसे छोटे से देश में 110 मीलियन टन और अमेरिका में 210 मीलियन टन का उत्पादन हो रहा है। फिर भी हम कहते हैं कि हमारे यहां आयरन ओर बेकार पड़ा है, इसकी कहीं खपत नहीं है, इसलिए छटनी करनी पड़ेगी। बेलाडीला के सम्बन्ध में हमने एक बार नहीं कई बार कहा है। जब हम स्टील मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स पर बोल रहे थे तब भी मैंने कहा था कि वहां पर एक मिनी स्टील प्लांट बनाने की आवश्यकता है। अगर आपने अपने आयरन ओर का वहां उपयोग किया होता तो आज छटनी की आवश्यकता न होती। बहुत पहले यहां पर एक माडरेनाइज प्लांट बनाने के लिए वहां की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था और मांग की थी कि वह प्लांट वहां के लिए मंजूर किया जाए लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसको नहीं माना। वहां इसके अलावा कोई और इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। अगर यह हो जाता तो भी मजदूरों की छटनी नहीं होती। अब उनसे कहा जा रहा है कि जा कर कहीं और काम ढूंढ़ो नहीं तो फिर गोलियों से भूने जाओगे। अभी दस महीने भी नहीं बीते हैं कि बेलाडीला से थोड़ी ही दूर पर नौ मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया था। अभी उन नौ मजदूरों का खून सूखा भी नहीं था कि बेलाडीला की धरती पर कितने ही लोग मारे गये। कितने लोग मारे गये, इसके बारे में कोई पांच सौ कहता है, कोई सौ कहता है और कोई 26 कहता है। लेकिन चूंकि आपने जुडीशल इक्वायरी की बात कही है तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी जज की नियुक्ति नहीं हुई और न उसका वेतन-मान तय हुआ है। अभी कोई मामला भी तैयार नहीं किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में इतना और जरूर कहना चाहता हू कि अगर इस सब मामले पर इस्पात मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार किये होते तो यह जो हृदय विदारक घटना घटी है यह न घटी होती। आज इस घटना पर हमें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने समय पर कदम उठाया होता तो यह नौबत न आती। अभी थोड़े दिन पहले बात आयी बोकारों से लोगों को भिलाई लाया गया था, उस समय मंत्री जी ने कहा था चूंकि कन्ट्रक्शन के वर्कर्स थे और वह काम समाप्त हो गया इसलिये उस मजदूरों को काम देने के लिये हम 500 लोगों को भिलाई ले आये। क्या बैलाडीला के लोगों के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि इन 1375 लोगों को कहीं और काम दे देते दिसम्बर में नोटिस दे दिया गया, फरवरी और मार्च में प्रतिनिधि मंडल आया। आप कहते हैं कि कुछ लोगों ने भड़काया कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह की अव्यवस्था फैले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा मौका ही क्यों देते हैं? जो लोग अराजकता

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

फैलाना चाहते हैं वह परिस्थिति से लाभ उठायें इसकी जिम्मेदारी हमारी है . इसलिये मैं इस्पात मंत्रालय को सीधा जिम्मेदार मानता हूं इस घटना के लिए और मैं कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र की उच्चतम नैतिक परम्परा को आदर्श प्रस्तुत करते हुए अगर इस्पात मंत्री महोदय त्याग-पत्र दे दें तो इसमें बढ़ कर के अच्छी बात और कोई नहीं होगी। क्या वह इस पर विचार करेंगे ?

13.00 hrs.

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या अभी भी आप इस पर विचार करेंगे इतनी जानें जाने के बाद, तीन, तीन कोलोनीज की झोंपड़ियां जला दी गई, कोई अपना घर अपने आप नहीं जलाता है जिसमें बच्चे रहते हों, उनके बरतन, कपड़े रहे हों, उनमें अपने हाथ से कोई आग नहीं लगाता। 20 वर्ष की महिला, 10 वर्ष के बच्चे को गोली लगी है, दो गर्भवती मातायें जंगल में डर कर भागीं, उनका असामयिक बच्चा पैदा हो गया, इससे बढ़ कर शर्मनाक कोई बात हो सकती है? इसलिए क्या अभी भी इन अभागे 7 हजार मजदूरों को, 1375 अभी रिट्रेंच हुए हैं, अगस्त, सितम्बर में दो खदानों के मजदूर और रिट्रेंच होंगे, और दिसम्बर 1979 में और रिट्रेंच होंगे.......

MR. SPEAKER: Mr. Shastri, I have been ringing the bell for a long time.

SHRI Y. P. SHASTRI: Sir, I had said at the outset that I will be taking more time. I will only take a few minutes.

MR. SPEAKER: Please conclude now. There is other important work.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या इन मजदूरों को काम देने की व्यवस्था आप करेंगे? इसका आश्वासन आज आप देने को तैयार हैं? उनको निश्चित रूप से काम मिलना चाहिये।

तीसरी बात जो आपने कही है कि 5,000 रु० स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, 5,000 रु० एन० एम० डी० सी० ने दिया और 1,000 रु० ठेकेदार ने दिया। यह कोई बड़ी कृपा नहीं है। इनको काम देना आपकी जिम्मेवारी है, और इनका अधिकार है काम पाना। इसलिये मैं चाहूंगा अपनी असफलता के कारण जो इनको इस तरह की क्षति उठानी पड़ी, इस तरह जो परिवार बरबाद हुए, क्या उनको आजन्म पेंशन देने की व्यवस्था आप करेंगे? और जुडिशियल इनक्वायरी निष्पक्ष हो सके, चूंकि आदिवासी लोग हैं, भोलेभाले लोग हैं, डर गये हैं, बस्तर में तीन बार गोली चल चुकी है, लोहान्डी गुडा में 1961 में, 1966 में जगदलपुर में और तीसरी बार गोली चली है, वहां कोई गवाही देने के लिये नहीं आता डर के मारे। इसलिए निष्पक्ष जांच हो सके इसके लिये क्या आप वहां के पुलिस अधिकारियों को, एस. डी. एम और कलेक्टर को निलम्बित कर के बाहर करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके?

SHRI BIJU PATNAIK: Shri Yamuna Prasad Shastri has become unduly exicited. If my resigning from this Ministry and Shri Yamuna Prasad Shastri's taking over the Ministry will give them employment, I am prepared to resign today. Let him say that. (*Interruptions*).

Listen to me now patiently. Please sit down.

SHRI VASANT SATHE: His party Member is asking him and he says 'sit down'. Sir, it is a breach of privilege, direct breach of privilege.

SHRI BIJU PATNAIK: I can tell anything to our own party-men.. .... (*Interruptions*).

Mr. Shastri's anguish I fully share He is my honoured friend and I can take some liberty with him.... (*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: This is a House of Parliament......

AN HON. MEMBER: This is not your own house.

SHRI C. M. STEPHEN: The behaviour of a Minister is not to be guided by his personal relationship with a Member. The Mnister must address Members with proper dignity.

SHRI BIJU PATNAIK: When Members on the other side got up and howled then it was not improper. (*Interruptions*).

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को बैठाने का काम तो आपका है, मंत्री महोदय का काम है जवाब देने का। अगर आपका काम मंत्री महोदय करेंगे तो किस लिए यहां बैठे हैं ?

SHRI BIJU PATNAIK: I am replying to Shastrijis question. Shastriji please listen carefully. I have said in my statement about this. I do not know whether Shastriji heard my statement carefully. This situation needs to be handled with care and consideration. I have said this because of the position in the world as such and as I appealed to the House and they would agree with me, the violence will not solve the problem of unemployment, as unemployment in the Iron and Steel Industry has been thrust upon us by world conditions....

AN HON MEMBER: How many times....?

SHRI BIJU PATNAIK: I do not know why Mr. Stephen seems to be insisting on my making statements which are likely to prejudice the judges as also the Government.

MR. SPEAKER: Don't get incited?

SHRI BIJU PATNAIK: I do not have blood pressure. You all seem to have it. It is not possible for this Ministry to continue to provide employment—temporary employment, these are all temporarily employed by the contractors—on the basis that a certain quantum was to be exported. Mr. Shastri is entirely wrong when he says that this could be fed to the Indian Steel Industry. The Indian Steel Industry itself is running mines which employs thousands of workers to fulfil its requirements. If I have to take the Bailadila ore, then thousands would be thrown out of employment there. For this purpose, it is specially designed, the railway line was constructed, outer harbour was built at a cost of Rs. 110 crores only for export to Japan. I do not wish to say many more things because I cannot commit anything in this House. I have asked them and they are coming. Mr. Tanabe, Executive Vice-President and Mr. Imai, General Manager of Nippon Steel Corporation of Japan, who are the buyers of this item, are coming to see me in another 15 days. I know their problems and they also know our problems, because if something can be sorted out whereby an increased offtake can take place so that the workers' employment canat least be continued for some time, that would be a relief. Mr. Shastri talked of mini-steel....(*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: He mentioned about mini-steel plant.

SHRI BIJU PATNAIK: He talked of mini-steel plants. Mini-steel plants do not use iron ore. They onyl use steel scrap. And the so-called pellet plants also....(*Interruptions*).

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : आयरन ओर से ही तो स्क्रैप स्टील बनेगा और स्टील इनगाट्स बनेगा, स्क्रैप स्टील बनेगा।

श्री बीजू पटनायक : आयरन ओर से जो बनता है वह ब्लास्ट फरनैस से बनता है, मिनी स्टील प्लाइट्स से नहीं।

[Shri Biju Patnaik]

Similarly he talked about pelletisation plant. A pelletisation plant employs about 200 people, but it takes five years to build this project. These are not immediate solutions. I am trying for an immediate solution. I have offered and I have told the contractor to use at least 800 men on temporary work somewhere. But I do not wish to say anything more about the violence because you will throw it out of record. But the violence was sponsored. By whom? Let the judge find out. The question here is, can I guarantee to this House, can I assure this House that with the dwindling purchases by the outside world, I will still continue to mine the tonnage that is meant for export? The answer is 'no' however unpleasant it may be, the answer still is 'no'. These men came for ordinary work, these are contract labourers and these are not the permanent labourers of NMDC or the Ministry who are working in the various mines and who have been there for years. These are contract labourers taken for the last two, three years for temporarily making up till the machines are ready—Mr. Sathe's machines—the machines and the Frankkensteins are ready now. Let Mr. Sathe suggest, let Mr. Stephen suggest, do I stop these hundred crore machines in operation? Do I stockpile another two million tonnes all over the country which will increase the loss of NMDC by another five or ten crores? Let him give me the answer because stock-piling these things, interest charges, transport and re-transport, all these will cost crores of rupees. Let Mr. Sathe give me the direction, let the House give me the direction, I shall carry it out. But in the absence of that, I am doing my best to see whether the export can increase within a foreseeable time and till such time because of the mechanisation introduced by the previous Government which is now coming to roost, some people will have to go out of emplyment and in this industry this cannot be helped.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): The Minister for Labour is sitting by his side. He should intervene. It is an alarming statement that there will be retrenchment.

श्री दया राम शाक्य (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य में बताया गया है कि मैसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी का ठेका 31-3-78 को समाप्त हो गया था, जिस के परिणामस्वरूप 1375 श्रमिकों को काम से अलग कर दिया गया। इस के अलावा दो ठेके अगस्त सितम्बर, 1978 को और एक ठेका 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले हैं।

सरकार को पहले से ही यह जानकारी थी कि वहां पर चार ठेकों के अन्तर्गत लगभग 7,000 श्रमिक काम कर रहे हैं, जो धीरे-धीरे बेकार हो जायेंगे। एक तरफ सरकार की योजना है कि हम देश में बेकार लोगों को रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ यह जानकारी होने के बावजूद कि उस खान में 7,000 कर्मचारी बेकार होने वाले हैं, उस ने कोई कार्यवाहीं नहीं की। यह स्वाभाविक है कि वहां पर जो लोग बेकार हो गये हैं, या बेकार होने वाले हैं, उन में असंतोष और परेशानी हो। माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से भी यह जाहिर होता है कि वास्तव में उन लोगों के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस के कारण उन पर गोली चलानी पड़ी। इस वक्तव्य में कहा गया है कि कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए गये और उन्होंने ईंट-पत्थर फेंके।

13.14 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या श्रमिकों की कार्यवाही के फलस्वरूप पुलिस के किसी आदमी को कोई गम्भीर चोट आई, जिस के कारण पुलिस को सेल्फ-डिफेंस का बहाना

से कर गोलीबारी करनी पड़ी ? इस वक्तव्य से साफ जाहिर होता है कि जब पुलिस ने गोलीबारी की, तो उससे पहले पुलिस का कोई आदमी मरा या घायल नहीं हुआ था।

इस के अलावा बस्ती में आग लगाई गई, और महिलाओं तथा भागते हुए व्यक्तियों पर गोली चलाई गई। क्या यह सम्भव था कि कर्मचारी स्वयं अपने रहने के घरों को आग लगा दें, जिन में उन का सामान पड़ा था और जिन में उन के बच्चे रहते थे ? इस से प्रकट होता है कि जो रिपोर्ट दी गई है, वह सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने आप को बचाने के लिए दी गई एक टेंटिड रिपोर्ट है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वे लोग ठेके पर काम करने वाले थे। क्या ठेके पर काम करने वाले व्यक्तियों को काम देने का उत्तरदायित्व सरकार का नहीं है ? हमारी घोषणा है कि हम प्रति-वर्ष देश के पचास लाख बेकार लोगों को काम देंगे। तो उस में चिन्ता उन व्यक्तियों की ज्यादा होनी चाहिए जो वास्तव में काम पर लगे हुए हैं और जो बेकार हो गए हैं या बेकार होने वाले हैं। मैं समझता हूं इस में सरकार की ओर से खास तौर से लापरवाही बरती गई। यदि उन को यह आश्वासन दे दिया जाता कि उन को काम दिया जाएगा और 1370 लोगों को फौरन काम दे दिया जाता तो इस प्रकार की घटना सामने न आती। सरकार की तरफ से जो यह इनकार किया जा रहा है कि हम उन को काम नहीं दे सकते, यह गलत है। सरकार की घोषणा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को काम देने का उत्तरदायित्व सरकार पर है। इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का उत्तर देना ठीक नहीं है। इस उत्तरदायित्व को समझते हुए मैं समझता हूँ कि सरकार भविष्य में इस बात का ध्यान रखे कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई कर्मचारी बेकार होता है या काम से अलग होता है तो उस के लिए कोई न कोई काम दिया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला सब-जूडिस है, मैं इस पर अधिक न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों। एक ओर तो हम देश में लोगों को सस्ता लोहा नहीं दे पाते हैं और छोटी-छोटी चीजें नहीं दे पाते हैं और दूसरी ओर जो थोड़ा बहुत उत्पादन होता है देश में खनिजों के द्वारा उन को कन्वर्ट कर के उपयोगी चीजें नहीं बना पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो अधिक से अधिक उत्पादन होता है उस का हम ऐसी चीजों में उपयोग करें, उस को कन्वर्ट करके उस से ऐसी चीजें बनाएं जो जनता के उपयोग में आ सकें। इस तरह हम उस उत्पादन का उपयोग करें और इन कामदारों को बेकार न होने दें।

SHRI BIJU PATNAIK: I have already answered these questions. These are contractors' labour who were employed for short temporary period. There are thousands and thousands of contract labour working around Delhi. Does anybody guarantee their employment? Tears have been shed by some members that some 1000 or 2000 or 5000 contract labour are likely to go unemployed. They are on the spot. I have no doubt they will get employment in the countryside. They will be making roads, breaking stones, etc. With the policy of the Janata Government, there will be enough work in the villages for them when they go back. They are purely contract labour. They are only taken for a temporary purpose. Their main work is loading, cutting, stone breaking, iron ore breaking, etc. This type of work they will no doubt get in the countryside. There is nothing to get so excited about. Therefore, I said this was motivated and the firing took place. I do not wish to say more. Let the High Court judge decide who was guilty. Law and order is a State subject and I do not wish to go into it.

SHRI VASANT SATHE: Normally the contractors employed them in

[Shri Vasant Sathe]

other places also. That should have been done.

SHRI BIJU PATNAIK: I have no doubt that the same contractors will employ them somewhere or other contractors would employ them. Every day around Delhi we see thousands of workers—women and little children also. That does not evoke any sympathy because they do not belong to any union. All this noise is because of the*** union. It is their policy to create violence and make public statements. All those will come before the judge. "These workers do not mater; we know that these temporary workers cannot be continued. but it is our policy to create violence and bring the government into disrepute." All the statements have come. I do not wish to say more; let the Judge take all things into account.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: He again ends on that not that union leaders are responsible, when Mr. Sathe has said that it is not the union leaders. When the judicial inquiry is there, why should he say it again?

SHRI BIJU PATNAIK: I have not said it against any individual.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: He cannot say about the Union like that.

13.19 hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SECOND REPORT

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I beg to present the second Report of the Committee on Public Undertakings on Central Inland Water Transport Corporation —Reckless and Fraudulent Sale of numerous vessels.

MR. DEPUTY SPEAKER: Matters under Rule 377.

13.20 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) SUPPLY OF BENZENE IN HINDUSTAN STEEL PLANTS M/S. SYNTHETICS AND CHEMICALS LTD., BAREILLY.

SHRI SURENDRA BIKRAM (Shahjahanpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have given the notice under Rule 377 regarding payment of unpaid dues to Government of India's Hindustan Steel Plants in respect of excess Benzene received by Messers. Synthetics & Chemicals Limited, Bareilly.

Various plants of Messers. Hindustan Steel Limited have been suplying Benzene to Messers. Synthetics & Chemicals Limited for the last more than 14 years. In many tankwagons the factory received excess Benzene which was acknowledged by Synthetics & Chemicals Ltd., to Hindustan Steel Limited but all the payments for all this excess quantity of benzene received every month were not made by the consumer Company. The Minister for Steel & Mines should make full enquiries and in case still there are amounts unpaid by the consuming industry, the Company be asked to immediately pay the entire dues with interest and penalty. The dues are expected to be several lakhs of rupees. A thorough enquiry by competent persons in respect of all tankwagons right from the beginning will have to be made at Bareilly and at Hindustan Steel Plants to be doubly sure. Sir, this is a very serious matter.

(ii) REPORTED SACKING OF SEVEN EMPLOYEES OF GANDHI DARSHAN

SHRI VASANT SATHE (Akola): Sir, I may be permitted to raise the following issue of urgent public importance under Rule 377, and I hope that the Government will come out with a statement in response to this.

*** Expunged as ordered by the Chair.

It is reported that seven of the 103 employees of Gandhi Darshan have been sacked and four of the six pavilions in the complex closed. This has created a feeling of insecurity among the employees of the Gandhi Darshan. And now we are talking so much of Gandhi, this Government is wedded to him and his policy and his name. It is reported that the Gandhi Darshan Employees Welfare Association have been told that they should be prepared for reduction in salary and retrenchment. The situation is getting serious as a result of suicide committed by the wife of one of the Gandhi Darshan employees who cut her throat with a kitchen knife because her husband lost his job. The agitation of the employees is going on since last so many days without any tangible result in sight. The Government's intervention in this matter, at least in the name of Gandhiji, is sought and I plead with the Minister for Parliamentary Affairs—I do not know whether it is the Works & Housing Ministry which controls or the Education Ministry which deals with it.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Education Ministry.

SHRI VASANT SATHE: Then, you are here very much. I am sure with your kind heart you will kindly look into this and try to see that the matter is resolved and justice is done.

(iii) REPORTED POLICE FIRING ON AGRICULTURISTS IN VEDASANDUR VILLAGE IN MADURAI DISTRICT

SHRI R. V. SWAMINATHAN (Madurai): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise under Rule 377 on an important incident that has taken place in Tamil Nadu.

MR. DEPUTY SPEAKER: You must read the text.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Just a few words, Sir. It has been reported on the 9th that police have resorted to opening fire on agriculturists in Vedasandur village in Madurai District, who have been agitating for the redressal of their grievances. I do not know what is the reason for the police to resort to opening fire and also, the Army has been called for. I hope that Government will come forward with a statement on what has happened, what is the reason and who is behind all these things.

(iv) SERVICE CONDITIONS OF TEMPORARY OFFICERS IN INDIAN RAILWAYS

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Mr. Deputy Speaker. Sir, with your permission. under Rule 377 I draw the attention of the House to a matter of urgent public importance.

Sir, this is a matter pertaining to the service conditions of temporary officers on Indian Railways who have been recruited by selection through the UPSC interview, which is one of the recognised modes of recruitment laid down by the Establishment Code and recruitment rules. Every year, hundreds of such officers are selected by UPSC as well as for every other section in other Ministries. These officers are suffering in their seniority, because they have not been equated with the direct recruits in the Railways.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must read from the written text, which you have given.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: There are certain important points. There are court rulings against this.

MR DEPUTY-SPEAKER: Whatever you have to say, you should have given in writing. You should read whatever you have given in writing.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: There is great stagnation and frustration caused to the temporary officers on Indian Railways due

[Dr. Vasant Kumar Pandit]
to the wrong interpretation and decision by the Railway Board, the discrimination in making permanent and giving seniority to the officers selected through interview by the UPSC and those appointed through direct recruitment. The decisions have also been given against the stand taken by the Railway Board given by the Allahabad High Court, and again recently upholding the rights of 'temporary officers' as equal to those of direct recruitment, given by the Supreme Court in the case of Patwardhan *vs.* State of Maharashtra. The inaction on the part of the Railway to respond to the decision by cancelling the illegal amendment to the Establishment Code made during the period of Emergency, and that too with retrospective effect. This has to be remedied, and the early solution necessary on this issue, because of which a large number of officers, over 1000 officers, are suffering in their future and in their seniority, inspite of 20 years of good excellent recorded service.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we go on to the discussion on the Budget.

एक माननीय सदस्य : मैंने भी रूल 377 में नोटिस दिया था ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: In regard to rule 377, those whose notices have been accepted, have been called.

जिन-जिन सदस्यों ने नोटिस दिया था, अगर वे सब खड़े हो जायें, तो 300 नोटिसिज होंगे—इस लिए सब को मौका नहीं मिल सकता है, जिन के नोटिसिज एक्सेप्ट हो गये हैं, उन को बुलाया गया है ।

13.27 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—*Contd.*

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND THE DEPARTMENT OF CULTURE—*Contd.*

श्री रामनरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत 30 वर्षों में अगर किसी विषय की सब से अधिक दुर्दशा इस देश में हुई है, सब से अधिक खिलवाड़ अगर किया गया है, तो वह शिक्षा है । यह वर्तमान शिक्षा पद्धति किस लिए बनी थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी यह मानता है कि केवल क्लर्क पैदा करने के लिए यह शिक्षा पद्धति लागू की गई थी । आज हमारे स्कूल, कालिज और यूनिवर्सिटीज गुलाम, बेकार और बेईमान बनाने के कारखाने हैं । मैंने गुलाम शब्द का प्रयोग इस लिए किया कि लड़के ने स्कूल में पैर रखा, उस का सब से पहला लक्ष्य होता है, नौकरी करना, तो स्कूल में आते ही यह गुलामी उस के सिर पर सवार हो जाती है । जब नौकरी में चला गया, तो कोई नहीं पूछता कि तुम को कितनी तनख्वाह मिलती है, सब से पहला सवाल यह होता है कि ऊपरी आमदनी कितनी है । इस तरह से ये बेईमान बनाने के कारखाने हुए । जब लड़का मेज-कुर्सी पर पढ़ने लगता है, तो गोबर से उस को दुश्मनी हो जाती है । वर्तमान सभ्यता के मुताबिक उस को काफी चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए । बाप ने न जाने किस तरह से, अपना अनाज बेच कर, उस को पढ़ाया, पढ़ने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वे कारों की फौज में भरती हो जाते हैं और इस फौज मे भरती हो कर वे जो कर रहे हैं—वह हमारे और आप के सामने है । उन को पैसा चाहिए, क्योंकि उन का खर्चा बढ़ा हुआ है, घर से उन को मिलेगा नहीं, दिन में मेहनत करने का कोई साधन नहीं है, तब फिर वे रात में ही मेहनत करने लगते है । यह है हमारी शिक्षा की हालत ।

हमारे पुराने मित्रों ने, पुरानी सरकार ने, शाब्दिक परिवर्तन तो बहुत किये, पहले कहा गया कि हम मौलिक परिवर्तन करेंगे, कुछ दिन मौलिक परिवर्तन चला, उस के बाद कहना शुरू कर दिया कि हम आमूल-परिवर्तन करेंगे ।

जब 'आमूल' भी पूरा नहीं हुआ, तब तीसरा शब्द आ गया कि हम 'आमूलचूल' परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन हुआ क्या? कुछ नहीं, सिवाय इस के कि 10 प्लस 2 प्लस 3 की थ्योरी खड़ी कर दी गई। इस के बारे में मैं बाद में कहूंगा लेकिन मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि यह हिन्दुस्तान के लिए है ही नहीं और हमारे प्रधान मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वह सफल नहीं होगा। यह तो उन लड़कों के लिए ठीक हो सकती है जो कनवेंट स्कूलों में पढ़ते हों या पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हों। जहां टाट पर बैठने वाले बच्चे हों वे 20 सब्जेक्ट्स को क्या पढ़ेंगे। इसलिए मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि कृपा कर के आप कोई बढ़िया शिक्षा नीति बनावें। कमीशन तो पुरानी सरकार ने बहुत बनाए हैं और उन से काम चलने वाला नहीं है। अगर किसी मामले को टालना हो, तो कमीशन बना दो। कमीशन का मतलब है टालू मिक्सचर। किसी मसले को पांच वर्ष के लिए टरकाना हो, तो कमीशन बना दो और ये कमीशन क्या करते हैं कि फलां विद्वान ने यह कहा था और फलां विद्वान ने वह कहा था। 'कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा'। अनुभव के आधार पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो प्रयोग हुए हैं, उन का इस्तेमाल किया है कभी सरकार ने? क्या गांधी जी ने शिक्षा के बारे में जो प्रयोग किया था, उस का इस्तेमाल सरकार ने किया है? 1921 में जब असहयोग आन्दोलन चला था तो विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहा गया। उस के बाद काशी विद्यापीठ खोली गई, गुजरात विद्यापीठ खोली गई और शान्ति निकेतन में पेड़ के नीचे और सादगी से पढ़ने का आदर्श रखा गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर ने और भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु और उस को प्रकाश में रखते हुए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। तो काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की राष्ट्रीयता, शान्तिनिकेतन की सादगी और गुरुकुल कांगड़ी की भारतीयता इन तीनों को मिला कर आप क्यों नहीं एक नई शिक्षा नीति बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के बाद यह एकेडिमिक एजूकेशन देने का क्या मतलब है, सिवाय इस के कि आप बेकारों की फौज को बढ़ाते हैं। क्यों आप बेकार में पैसा बहा रहे हैं। उस के बाद आप रोजगार की शिक्षा दीजिए, पेशे की शिक्षा दीजिए। जिस पेशे की आप शिक्षा देते हैं उस में उस लड़के को आप एक्सपर्ट बनाइए। जिस सबजेक्ट में आप को एक्सपर्ट बनाना है उसमें उस का एडमिशन किया जाए लेकिन यह बेकारों की फौज बढ़ाने से क्या फायदा। मैं यह तो कहता हूं कि यह जो आप एग्रीकल्चरल कालेज या यूनिवर्सिटी खोलते हैं, इनको वहां क्यों नहीं बनाते हैं जहां पर पूरी जमीन हो और वहां पर क्यों आप दूसरे लोगों को नौकर रखते हैं। आप उन लड़कों से ही काम करवाएं और उत्पादन बढ़वाएं और उस उत्पादन से जो पैसा प्राप्त हो, उस से कालेज का काम चलाएं और लड़कों को अपने घर से पैसा न खर्च करना पड़े। इसी तरह से आप टैकनिकल इंस्टीट्यूशन्स वहां पर खोलिये जहां पर कारखाने ज्यादा हों और वहां पर लड़कों का जाना अनिवार्य कर दीजिए और यह कर दीजिए कि इतने घंटे वहां पर काम करना अनिवार्य होगा। थ्योरी के लिए आप कुछ घंटे रख दीजिए। इस तरह से आप कोई दृष्टि बनाइए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंधेरे में ही हाथ मारते रहोगे जैसे कि पिछले 30 वर्ष मारते रहे हैं और कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अशान्ति है लेकिन उस के कई कारण हैं। कई कारण तो ये हैं कि वह लक्ष्यविहीन, दृष्टिविहिन और कार्यक्रमविहीन है और यह शिक्षा एकदम भेड़ों की फौज खड़ी करने वाली है और कहीं ऐसा न हो कि यह शिक्षा समुद्र में गिरा दे। जब कोई दृष्टि नहीं,

[श्रीरामनरेश कुशवाहा]

लक्ष्य नहीं, कार्यक्रम नहीं और उसी पुरानी परम्परा पर आप चले आ रहे हैं तो इसी तरह से अगर आप चलते रहे तो यह एक दिन गड्ढे में गिरा देगी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि ये कारण तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप भी कम कारण नहीं हैं। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम 42 वें संविधान संशोधन विधेयक को वापस ले लेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप को यह कहने की क्या जरूरत थी कि समवर्ती सूची में शिक्षा को नहीं लेंगे। जब बार बार हमारे नेता चाहते हैं कि 42 वें संविधान संशोधन विधेयक में जो अच्छी चीजे हैं, वे रहेंगी, तो आप ने कैसे अर्थ निकाल लिया कि यही सब से खराब चीज है और इस को निकाल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसा कर के आप ने कितना बड़ा अनर्थ किया है। इस के चलते सारे देश के प्राथमिक शिक्षक संघ और दूसरे संघों के लोग यहां पर इस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए थे और उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ हो रहा है, जो शिक्षक आन्दोलन हुआ है, वह इसी तरह चलते हुए हुआ है। यह मैं जानता हूं कि विरोधी पक्ष की इस में बहुत बड़ी भूमिका है और कुछ दूसरे लोगों की भूमिका है लेकिन आग लगाने का काम आप ने किया है। जब घर के ढेर में आग रखी थी, तो उस में हवा दे कर आप ने जला दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने बल पर शिक्षा को समवर्ती सूची से हटा दें। हम यह नहीं कर सकते हैं जब तक कि उधर के भाई हमारे साथ न हों। हमारी भोजपुरी में एक कहावत है—:

भिन शहरा खौखियावे
और सांझ से मुंह बावे।

पांच वर्ष के बाद ही आपकी हैसियत होगी कि आप इसे हटा सकें।

जनता पार्टी ने शिक्षा में समानता का अवसर देने का वायदा किया था। क्या हमारी यही समानता है कि देश में पब्लिक स्कूल चलते रहेंगे और बड़े लोगों के बच्चे उनमें पढ़ते रहेंगे? क्या आपके दृष्टिकोण से यह समानता है? किस के लिए यह समानता है? जनता पार्टी ने फैसला किया था कि पब्लिक स्कूल तोड़ दिये जायेंगे लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ये चलते रहेंगे। आप कहते हैं कि अगर कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो क्या बुरा है। आज एक गरीब का लड़का पैदल चल कर पढ़ने जाता है और उसे सिर पर छत तो क्या, स्कूल में पेड़ की छाया भी नहीं मिलती है। यह कैसी शिक्षा है कि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, मिनिस्टर का लड़का, मिनिस्टर, एम० पी० का लड़का एम० पी० एम० एल० ए० का लड़का एम० एल०ए० बने और उनके बच्चों को शहरों के पब्लिक स्कूलों में पढ़ने की सुविधा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा दिनों तक यह चलने वाला नहीं है। अगर आप इसको जल्दी से जल्दी समाप्त नहीं करेंगे तो निश्चय ही शान्ति नहीं होगी।

इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी अशान्ति का बहुत बड़ा कारण है। आजकल लड़के कहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन इम्तिहान जरूर पास करेंगे क्योंकि हम को नौकरी लेनी है। अगर पढ़ने के लिए मास्टर साहब कहेंगे तो छुरा मार देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों नहीं नौकरियों के लिए इम्तिहान लेते हैं? आप एकेडेमिक एजूकेशन के लिए इम्तिहान ले रहे हैं। आप यह इम्तिहान लेना छोड़ दीजिए। चाहे लड़का पढ़े चाहे न पढ़े। अध्यापक अपने आप देखेगा कि लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि यदि लड़का

छठी क्लास में है तो उसे स्कूल के इम्तिहान में अध्यापक कम अंक देता है लेकिन जब फाइनल इम्तिहान आता है तो हर अध्यापक चाहता है उसके सब लड़के पास हो जाएं। जब आप इम्तिहानों का महत्व नौकरी से जोड़ देते हैं तो छुरी और चाकू चलते हैं। अगर आप इन्हें बन्द कराना चाहते हैं तो इम्तिहानों को नौकरी से मत जोड़ो। इन इम्तिहानों को अध्यापक की मर्जी पर छोड़ दीजिए। जिसको चाहे अध्यापक पास करे, जिसको चाहे फेल करे। नौकरियों में आप इम्तिहान लीजिए। जो क्वालिफाई करे उसको नौकरी में लीजिए, वरना मत लीजिए। जब वहां भी इम्तिहान लेते हैं, वहां भी इम्तिहान लेते हैं तो छुरे चलते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन इम्तिहानों को आप मत लीजिए। नहीं तो पता नहीं, क्या हो जाएगा।

अध्यापकों की एक मांग है कि राष्ट्रीय वेतनमान बनाया जाए। मैं तो कहता हूं कि सभी राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं सब के लिए आप राष्ट्रीय वेतनमान बनाइये। केवल अध्यापकों के लिए ही नहीं, सब के लिए बनाइये। आप न्यूनतम और अधिकतम दोनों वेतनमान तय कीजिए। ये वेतनमान जोब ओरियेन्टेड,पद-आधारित होने चाहिएं, क्वालिफिकेशन ओरियेन्टेड नहीं होने चाहिएं। अब यह नहीं चलने वाला है, वही हाई स्कूल पास प्राइमरी का अध्यापक 300 रुपया पायेगा और वही हाई स्कूल पास अगर बैंक का या एल०आई० सी० का चपरासी है तो वह 800 रु० पायेगा। यह नहीं चलने वाला है। बड़ी नौकरियों की बात हो सकती है उनको सारी चीजें फ्री देते हैं योग्यता के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर कर के तनख्वाह को एडजस्ट कर सकते हैं, चर्चा भी नहीं बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा झगड़ा भी समाप्त हो जायेगा। इसलिये शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय वेतनमान बनाइये, और साथ ही साथ हमारी सरकार को भी राष्ट्रीय वेतनमान बनाना चाहिये, और यह जनता पार्टी के चुनाव-घोषणा-पत्र के अनुकूल है।

दूसरी बात मुझे शिक्षा माध्यम के सम्बन्ध में कहनी है। अंग्रेजी की बड़ी वकालत की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। श्रीमन्, हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। क्या आपको मद्रास को समझने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे देश के लोगों को केरल को समझने की जरूरत नहीं है? महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, नागालैंड आदि को समझने की जरूरत नहीं हैं? सबसे पहले इंगलैंड को ही समझने की जरूरत है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुद हम और आप जो अंग्रेजी बोलते है क्या यह इंगलैंड की जनभाषा है? आयरलैंड में आयरिश बोली जाती है, स्काटलैंड में स्काटिश बोली जाती हैं। और हम जो अंग्रेज़ी बोलते हैं यह तो बहुत छोटे से हिस्से वैल्श की भाषा है। भू-मध्यसागर के पास फ्रेन्च बोली जाती है। हमारे पड़ोस में बर्मा, नेपाल, श्रीलंका आदि देश हैं, उनकी भाषाओं को क्यों नहीं पढ़वाते हैं। क्या इनसे हमें सम्बन्ध नहीं रखना है? क्या आप अपने पड़ोसियों से नाता नहीं रखना चाहते हैं? अगर आप हृदय से बात करना चाहते हैं तो आपको उनकी मातृभाषा में बात करनी पड़ेगी। और दक्षिण के भाई ठीक कहते हैं कि तुम उत्तर वाले लोग बेईमान हो, तुम हमारी भाषा नहीं पढ़ना चाहते हो, हम तुम्हारी भाषा को क्यों पढ़ें। उनकी इस भावना को मैं समझता हूं। आपने जाल बट्टा कर रखा है शिक्षा नीति में। मेरा निवेदन है कि यह धोका आप न चलाइये। संस्कृत पर समान श्रद्धा सारे देश के लोगों की है, जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे मातृभाषा के साथ जोड़ कर। लेकिन जब त्रिभाषा सूत्र में रखा है तो तुरन्त हिन्दी क्षेत्र के शिक्षा विभाग के लोग एकदम

[श्री रामनरेश कुशवाहा]

जाल बट्टा करते हैं और त्रिभाषा के स्थान पर संस्कृत को पढ़ाते हैं। न बंगला, न तेलगू, न मराठी, न गुजराती, न कन्नड़ पढ़वा रहे हैं। तो उनका यह कहना सही है कि तुम हमारी भाषा नहीं पढ़ते हो, हम तुम्हारी भाषा क्यों पढ़ें। यह संस्कृत के हिमायती लोग मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत को हिन्दी के साथ जोड़ कर के हिन्दी को भी अपने साथ डुबा देना चाहते हैं। जिस तरह संस्कृत क्लासिकल लैंगुएज हो गई है उसी तरह से हिन्दी को भी क्लासिकल लैंगुएज बना देना चाहते हैं।

उर्दू और हिन्दी का एक झगड़ा खड़ा होता है। अब यह चपला नहीं चलेगा। अगर हिन्दी के विद्वान उर्दू को हिन्दी की शैली मानते हैं तो सूर, तुलसी और कबीर के साथ अकबर इलाहाबादी, ज़ोक, अनीस क्यों नहीं पढ़ाये जायेंगे? फिराक गोरखपुरी क्यों नहीं पढ़ाये जायेंगे? हिन्दी के पाठ्यक्रम में उर्दू के लेखकों और कवियों की कविताओं को रखवाइये, उनके लेख पढ़वाइये, पाठ्यक्रम में रखिये, तब उर्दू वाले सोच सकते हैं कि हमारी भाषा तो चल रही है, लिपि भले ही फारसी न हो। और तब यह झगड़ा भी नहीं खड़ा होगा। लेकिन यहां तो बेईमानी होती है। जब उर्दू का हक देना होता है तो कहते हैं कि उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है, हिन्दी की एक शैली है। अगर यही बात है तो जिस प्रकार मैथिल, अवधी, ब्रजभाषा चलती है उसी प्रकार उर्दू क्यों नहीं पढ़वा रहे हैं? उर्दू के लेखकों, कवियों की रचनाओं को हिन्दी के पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ले कर एम०ए० तक जब तक नहीं रखेंगे तब तक यह झगड़ा खत्म नहीं होगा। हिन्दी के जो शुद्धता के पक्षपाती हैं वे हिन्दी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिन्दी जब राष्ट्रभाषा बनेगी तो उसमें उर्दू, बंगला, तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ के शब्द होंगे राजनीतिक शुद्धता के नाम पर चाहते हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा न होने दें। एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र इस पर चलता रहा है, मेरा निवेदन है कि आप इस षड्यन्त्र को तोड़ने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री राम नरेश कुशवाहा : बहुत जरूरी बातें कहनी हैं, इसलिये थोड़ा समय और लीजिये।

मैं कहना चाहता हूं कि रेल के कर्मचारियों में और लड़कों में अघोषित युद्ध हो जाता है। लड़के रेल का टिकट लेंगे नहीं और आप उनको छोड़ेंगे नहीं, तो रोज टी०टी० और गार्ड से पीटा-पाटी होगी। आप प्रिंसिपल और हैडमास्टर के सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं यह छोड़ देते हैं कि लड़कों को अपने घर से जहां पढ़ने के लिये जाना है वहां तक का फ्री-पास उनको दे दिया जायेगा। इससे व्यर्थ का रोज का झगड़ा तो खत्म होगा। मैं आपसे निश्चित रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि लड़कों के साथ बड़े लोग भी बिना टिकट का लाभ उठाते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित रूप से बड़े लोग बिना टिकट सफर नहीं कर सकेंगे, उनको टिकट लेना पड़ेगा और इससे टिकटों की बिक्री बढ़ जायेगी।

रेल मंत्रालय की मांग के समय पिछले साल भी मैंने कहा था कि लड़कों को स्कूल से घर के लिये फ्री पास दे दिया जाये ताकि यह झगड़ा हमेशा के लिये निपट जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कहता हूं कि लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उनको पोषण दे नहीं सकते, फ्री एजूकेशन का खर्चा दे नहीं सकते, उनके बाप-दादों को इस लायक बना नहीं सकते कि उनकी पढ़ाई का खर्चा वह कर सकें,

तो फिर आप घर से आने जाने के लिये उनको फ़ी पास नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। आप कह दीजिये कि यह व्यर्थ का नारा है, हम किसी को पढ़ाना नहीं चाहते। सीधी सी बात है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, सैंट्रल यूनिवर्सिटी है, केन्द्रीय सरकार की यूनिवर्सिटी है। इसमें जातिवाद और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है जितना कहीं नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपके पास एक लड़के डा० त्रिमोहन प्रसाद की दरख्वास्त हमने भेजी थी। वह हर प्रकार से क्वालीफाइड था, जितने उम्मीदवार थे, सबसे ज्यादा क्वालीफाइड था, लेकिन उसे इसलिये नहीं रखा गया कि वह बैकवर्ड क्लास का था। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप जांच करा लीजिये, उस लड़के को बुलवाकर देख लीजिये कि सबसे ज्यादा योग्य है या नहीं, लेकिन मौके पर हमको भी बुलवा लीजिये ताकि सब साबित हो जाये। लेकिन नहीं, वह बैकवर्ड क्लास का था इसलिये उसे नहीं लिया गया। उसके बारे में श्री हरिहरसिंह वैद्य, वाइस चांसलर श्री भगौती, और डा० कुडप्पा ने चाहा कि प्रमोट कर दिया जाये, लेकिन 8, 10 बरस हो गये, उस बेचारे को इसलिये प्रमोट नहीं किया गया कि वह बैकवर्ड है। मैं कहना चाहता हूं कि वाइवा में कौन फर्स्ट आयेगा? यूनिवर्सिटी में प्रथम आने वाले का एक-आधा नम्बर ज्यादा होता है, फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड में एक दो नम्बरों का फर्क होता है, लेकिन इस वाइवा में बुलाकर अपने साला बहनोई, और कुनबे वालों को 5, 10, 20 नम्बर अधिक बढ़ाकर दे देते हैं। जो पढ़ने वाला है वह पढ़ते-पढ़ते मर जायेगा, वह न डिवीजन ला पायेगा, न पोजीशन ला पायेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कोढ़ आप कब तक चलायेंगे? आप इसकी व्यापक जांच कराइये और वाइवा को तो एकदम खत्म कराइये। इसी तरह से मैं कहता हू, कि नौकरी में से इंटरव्यू को समाप्त कराइये और यूनिवर्सिटी एक्जाम से वाइवा खत्म कराइये। एक्जाम कुछ विशेष परिस्थिति में ही कराइये। रिसर्च कुछ विशेष क्षेत्रों में कराइये। आप रुपया देते हैं अनुदान के लिये। वहां कुछ लोग बड़ी तन्ख्वाह लेकर मौज मस्ती करते हैं, शहरों में आजाते हैं रिसर्च के लिये लेकिन वह किस काम का रिसर्च करते हैं। वह दूसरों से लिखवाते हैं कुछ पैसे देकर। जो दूसरों से थीसिस लिखवाकर देते हैं, कुछ ऐसे लोगों को आप डाक्टरेट दे देते हैं और मान लेते हैं कि वह एम०ए० की क्लास को पढ़ाने के लिये क्वालीफाइड है। मैं बन्द कर रहा हू। मैं आप का बड़ा ही आभारी हूं कि आप ने मुझेथोड़ा अधिक समय दिया लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि आप कोढ़ पर पर्दा डालने का प्रयास न कर के उस का आपरेशन कीजिए, उस घाव को अच्छा करने के लिए अच्छी से अच्छी दवा कीजिए और जो सड़ रहा है, उस को उखाड़ करके साफ़ कीजिए, उसे अच्छी कीजिए। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आप की मांगों का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि आप इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर नयी रोशनी लाएं, नये कार्यक्रम लाएं, शिक्षा को उद्देश्य-परक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support the Demands for Grants presented by the hon. Education Minister who is a reputed educationist himself and who had been in the teaching profession right from the very beginning. I would like to raise certain points for his consideration.

Since the formation of this Government, it has been the desire—and the same has been expressed from various

[Prof. Dilip Chakravarty]

forums—that there should be a new idea, a new outlook, in running our system of education, including the structure. I will recall that Gandhiji's ideas seem to be still relevant to the Indian situation. We really did not make any serious effort to implement the same. As a result, we simply increased the divisive tendencies in the Indian educational system.

The new ten-plus-two-plus—three pattern of education would prove meaningful only if basic education, as conceived by Gandhiji, is introduced at all stages without any mental reservation.

I would also like to point out that the essential principles of basic education, namely, productivity, having correlation, of the curriculum with productive activity and the intimate contact between school and the community around, should guide our educational system.

I am aware—and I expect the Education Minister also to make his observations on the same —that Lok Nayak Shri Jayaprakash Narayan submitted, quite some time back, a note to the Government of India. At least that is what I saw in the press. The Lok Nayak gave certain ideas. First of all, he took into consideration the various ills in our present educational system and he wanted right kind of men, whose competence and value-commitment are beyond question, to be appointed in the educational institutions. He made out certain points. I am making a short summary of the same. He also mentioned about duplication of our efforts and dead uniformity in the teaching programme and emphasized evolving a coordinated programme for imparting education. He insisted on introducing massive programmes of non-formal education—about this, I will make a detailed statement—and mobilising teachers and students for a crash programme. He further emphasized that higher education, both general and professional, should be self-financing with arrangement for loan/merit scholarships, particularly for the poor and meritorious students. The Lok Nayak desires to relate opportunities of higher education in the formal system to employment opportunities in the country. He also wants equality of educational opportunity and social justice for all groups in the society. Thirty years after freedom we find that, even whatever equality or semblance of equality was there before the country was free, is no longer there. The Lok Nayak has emphasized organizing debates throughout the country so that a national consensus can emerge through these debates on the reorientation of our educational system. In the absence of such a consensus, the Lok Nayak laments, the idea of 'Total Revolution' would be no more than slogan-mongering in the service of power politics.

I would draw your attention to the report of the Education Commission; page 251, para 10.05, emphasizes creation of common school system of public education. I quote:

> "The main problem before the country is to evolve a common school system of public education which will cover all parts of the country and all stages of school education and strive to provide equality of access to all children." This system will include all schools conducted by government and local authorities and all recognised and aided private schools. It should be maintained at an adequate level of quality and efficiency so that no parent would ordinarily feel any need to send his child to the institutions outside the system such as independent or unrecognised schools. This is the goal which the country should strive to reach, and a number of steps will have to be taken for its early realization."

Needless to add that, in spite of this recommendation for having common

schools, even after 12 years of the submission of the Report of the Education Commission we are only straying far away from the same ideal and the result is, as I had mentioned at the outset, only the encouragement of disentigrating tendencies.

Initially, I had mentioned that the boys in schools are divided into sectors—as I had often said in a rather bantering mood when I addressed students or the teaching community in different parts of the country on Gandhian ideals. The basic education schools are meant for children of the peasantry who are just supposed to vote in the General Election. The ordinary schools for higher education and secondary education were meant for middle-class people who could at best aspire to be the MLAs and MPs and the children of the rich could go to public schools or schools outside the country to become Minister thereafter. This is the system which is prevailing in the country. From the very beginning we have been dividing the population into so many sectors: no one sector can come near the other. This was not so when we were going to school, but now there is a clear-cut division on the basis of economic capacity of the parents of the children. This is a serious situation and is really creating disintegration tendencies in the society.

Now, much has been made out about the problem of illiteracy and from time to time we hear of programmes to remove illiteracy in the country. According to the 1977 statistics, the country's population is 62 crores and the number of literates is only 19 crores while the illiterates number 43 crores. Of these, the males constitute 17 crores and the females 26 crores. There is a total of 43 crores who are illiterates, and I have given the components—dividing them into male and female. Then, out of these 43 crores, those upto four years of age constitute 9 crores, those between five and 24 years constitute 16 crores and those who are 25 years and above constitute 18 crores. So, there are 18 crores of adult illiterates in the country. How are you going to tackle this problem? Every year we have new schools and we record a percentage of increase in literacy. But that should give no satisfaction to the elites of the country. Sometimes they give figures and statistical data and try to say that the country is making progress. But, as a matter of fact, during all these years we have had an increase only in absolute terms, in the number of illiterates in the country.

Now, 16 crores need formal education. But what is the provision for them? I am sure the Education Minister will confirm that, according to 1971 statistics, there was a provision for 6 crores of students of all categories and now these facilities have been extended to about 7 crores of students. But what will happen to the other 9 crores that are left out of this ordinary system or the ordinary way of things? Every year, 9 crores are being left out and we cannot make any arrangement for them to get accommodation in schools—starting from primary stage, to the secondary stage— and other institutions. Something has to be done: some programme has to be taken up.

Now out of these, for those who are out of school and cannot be accommodated in schools—*i.e.*, upto 24 years of age—some arrangements have to be made for formal education, part-time education and whole-time education. I am aware of the difficulties of the Government. Suddenly, it cannot make all the arrangements necessary for an extra number of nine crores, but something has to be done from now. Unless we can set some pace immediately, we cannot solve this gigantic problem.

14.00 hrs.

For the adult illiterates, who number not less than 18 crores, I am sure, the Education Minister, is already having a scheme. I would like to know the outcome of his thinking.

[Prof. Dilip Chakravarty]

Sir, if we can have a crash programme and can spend Rs. 810 crores during five years, or Rs. 160 crores per year, we can remove this adult illiteracy from the country within this period. I would like to elaborate this a little. There are six lakhs of villages in this country. If we form a cluster of villages, with two villages in each cluster, and in each cluster have seven or eight adult education centres, in that case, we may have 20 lakh such centres in the country as a whole. In each centre, at least 100 students may be taught for 1.5 hours daily. This would cost Rs. 270 crores annually. I know, the Education Minister has problems; he has to think in terms of infrastructure and has to see that there is no wastage of money and that there is proper utilization of it. But as I said, if we have a bold programme for five years to remove illiteracy from the body-politic, possibly we can succeed in that. But that requires a little amount of boldness and more allotment of funds for education. We have ignored this part for so long. It was long after the submission of the Education Commission's report that the then Education Minister, Shri Triguna Sen thought of having a national policy on education, but that education policy could not be executed.

About the adult education, I would like to quote from the report of the Education Commission itself. Let us see what the Commission observed on this particular problem. The Commission said in para 17.10, page 424 of its report:

"The campaigns were too limited in scale to achieve a significant advance and generate enthusiasm for further effort. They also tended to be sporadic and uncoordinated—government departments, voluntary agencies, educational institutions and individuals working more in isolation than in active collaboration with other agencies. They were often launched hastily, without the careful assessment of the needs and interests of adults without awakening public interest or stimulating the desire to learn and without adequate provision for the follow-up work in the absence of which no lasting results could be obtained. It is, therefore, not surprising that they failed."

I do not know whether the Government have taken all this into consideration. I have great faith in our Education Minister and I would expect from him a bold statement, a bold step laying down the outline of new education policy whereby we could remove the blot from the body-politic of this country.

The other day, on the 17th March, 1978, I was addressing a conference of retired teachers in Varanasi. They adopted a resolution to the effect that their services be utilised in the scheme for removing illiteracy from the country. Similar efforts could be made in this respect. This is because I am aware of the money being wasted. At least from my own experience, I know that in the University of Calcutta, a particular organization to which money was funnelled year after year was not doing any work in the direction of removing illiteracy. They were making publications and making profits. They have a big building of their own and if you ask them for an account in the field of removal of illiteracy, they would be repeating the same figures year after year. That need not be repeated and caution must be taken so that this experience is not repeated.

I would refer to certain other aspects of our academic life. Last year our Education Minister mentioned that of the 104 Universities and 9 institutes deemed to be Universities, there were problems only in a few of the Universities. But, in reality, it is not so. At any point of time, you may see there are many universities which

are not working. Even as late as 19th March, this year, you find that not a single university in Bihar was operating. So, everyday some of the Universities in some parts of the country are reported to be in an intolerable situation.

I was connected with the University of Calcutta for long 18 years with its management. It has now been superseded by the Government of West Bengal. I am not telling you anything which you do not know, especially how it functioned during the emergency. We had a Vice-Chancellor who was trying to find out patrons who could get him an extension and in his effort to find out patrons, what did he do? A Class I officer of the Government of India, a Deputy Director-General of the CBI applied for the reduction of his age. It came before the Syndicate. I know what was done. On the day of his retirement he reduced his age by 2 years and a half. 38 years after he passed the Matriculation examination. The Union Home Ministry has since then been inquiring. What is the report? The report is not forthcoming. Even today it is not forthcoming. I received a letter from the Union Home Minister, Mr. Charan Singh—which is the latest and dated March 14, 1978:

"Please refer to your D.O. letter of 8th October, 1977 regarding the alleged irregularities made by Dr. S. N. Sen, Former Vice-Chancellor of Calcutta University in the date of birth of Mr. A. B. Choudhary, an erstwhile officer of CBI. Even prior to the receipt of your letter we had requested the Calcutta University to let us know the circumstances under which the date of birth as given in the Matriculation certificate had been altered nearly 38 years after the issue of the certificate. The report from the Calcutta University is awaited. The Government have not yet accepted the change in the date of birth of Mr. Choudhary."

This is dated 14th March, 1978. I had been to the Chief Minister of West Bengal. I had been to the present State Minister on Higher Education and wanted a thorough inquiry, a high power inquiry into the affairs of this particular university for the last 10 years on academic, administrative and financial aspects of the University because this is not the one instance, there are many. Only a few days ago in the West Bengal legislature the Minister for Higher Education in order to cover up his deficiencies—what are his deficiencies I do not know and he happens to be a friend of mine—mentioned wrongly that on the basis of a letter from me which is not a fact, superseded the University of Calcutta. I never wrote a letter in regard to supersession. He made a wrong statement. Even till this date it is still to be corrected. On the contrary, I would urge upon the Minister of Education to have a Commission of Inquiry into the working of all our Universities, not only the Calcutta University because there is a particular type of cancer in higher education....

SHRI DHIRENDRA BASU (Katwa): It is the same everywhere.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY... and particularly into their activities during the emergency. This is urgent. Otherwise only talking of ideologies is not going to solve our problem.

I would also request the Union Education Minister to expedite the Vishwa Bharati Act. While framing it, I would like him to keep in mind the teaching community and the new law, I am sure, will give adequate representation to the teachers and will give precedence to elective principles.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Introduced in the Rajya Sabha.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I am not talking about the details. There are many institutions which are financed by the Government of India, Union Ministry of Education. One such institution is the Indian Council of Historical Research, New Delhi.

I will seek your permission for one or two more minutes because I got a wrong reply last year.

For a new member the things never come in the ballot. I never had an opportunity to ask a question on the floor of the House.

The reply given to me was not true. That is why I would like to make a statement.

It is now widely known that the Indian Council of Historical Research —which could have developed into a premier research organisation in our country—has not been able on the whole to come up to the expectations it originally raised.

Larger percentage of expenditure is done on T.A., D.A., of the officers who move round the country, not for publications or research. I would like the Minister to please give a report of the serious publications made by the Indian Council of Historical Research. Although at long last a new Chairman (Professor A. R. Kulkarni) has been appointed for the Council and some betterment is anticipated through the exertions of this new Chairman, matters will not really improve if the same set of incompetent and unscrupulous persons—who were brought into the Council through irregular methods—are still retained or allowed to continue to impair the Council's activities from vintage positions. Shri B. R. Grover, who is in fact a henchman of the clique that dominated the Council's proceedings and who has no claim over scholarly and administrative abilities, was brought to the Council in October, 1974. The position of Director, to which Shri Grover was appointed, was not advertised—contrary to the normal rules for such appointments. Although a selection committee was formed to render the irregular selection look regular and to consider the only one candidate, Shri Grover did not appear before it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up in a minute.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I would like to draw the attention of the Union Education Minister that Shri Grover was registered in Delhi University as a scholar. He could not complete his thesis. Now as soon as he was brought as Acting Director of the Indian Council of Historical Research, he becomes All-India expert of repute in History. Through him and with his assistance in Calcutta University certain irregular appointments in History were made. And he is publicised as a scholar of repute in History.

I would like the hon. Minister to know about it and assure us that something more will have to be done to put the historical research on a proper keel.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): I am very happy to participate in the discussion on the Demands for Grants for the Ministry of Education and Social Welfare.

For every country education is an essential subject for social change and for human civilisation. Man cannot live without food and clothing. At the same time if education is not there, the man cannot live with confidence.

In every civilized country there is a proper system of education. In the socialist countries more emphasis is given on educating the people.

After 30 years of independence we see our developing country has no education policy by which our people can educate themselves. Our illite-

racy is 30 per cent. This is the result of 30 years of independence and the rule of the Congress Government. They talked about the welfare of the women. They shed crocodile tears for the welfare of women. Only 20 per cent of the women are illiterate in the country. This is the position, after 30 years of independence. It is a very difficult question for the nation to face. If the nation has to face a problem like this, it looks very bad in the eyes of the other countries. We are really backward in this respect and the other countries come to know that education is not properly treated here. They come to know that education is not properly taken up here. I would request the hon. Minister to take the necessary steps for formulating a proper educational policy which will enable rapid expansion of education, which will remove illiteracy. The rights of women should be ensured properly. Adult education should be developed and in this way there should be proper education reform in all spheres.

In the Forty-second Amendment, Education has been included in the Concurrent List. It is a joint responsibility but Sir, sometimes everybody's responsibility is nobody's responsibility. This is the position. The States should be given sufficient powers. The responsibility of educating the people should be with the States and the financial responsibility should be borne by the Central Government. In this connection I want to mention that the administrative power is vested upon the Central Government. If immediate action is required to be taken the State Government cannot take necessary steps against any instituiton or enact any law or any rule. The State Governments have to wait for the assent of the President. What we should ensure is that the State Governments should be given all the authority on the subject.

352 L.S.—10

In India today there is lot of student unrest which has taken place. The reason is this. There is lot of frustration among themselves. After educating themselves they cannot find out any jobs. After coming out from colleges and universities there is no way out for them, they have to run for jobs, they run about from one office to another. This is the position. Therefore, I want to emphasise that Education should be job-oriented. There should be a proper education policy formulated to solve the problem of the outburst of students. During the pre-independence days also there was outburst of students. They fought for independence. Before independence and also after independence whenever any injustice has been there, they have fought against it. They have played an important role. They form a very sensitive part of the whole society. Whenever any injustice is there they always fight against that. During the last 10 years, and particularly during the emergency, we saw that the congress took the advantage of this sensitive section of society and goondaism was introduced in schools, colleges and universities particularly in West Bengal. They utilised the students for their own purpose. And that is why in Deoria, U.P. minority students were assaulted and their belongings were looted; their books etc., were set on fire by the upper-class students. This is a shameful fact.

I think the students' attitude is going towards a path which is not expected to be a good one. During the Janata regime if some politicians are involved in all these activities why we should blame this Government. Let us try to have a policy by which the problems of the students are solved.

We see students being found copying and demanding large-scale gracing etc., and they are indulging in arson, loot etc. It is not only shameful to the society but it is also shameful to the whole of our educa-

[Shri Mukand Mandal]

tional system. So, necessary steps should be taken so that the students are satisfied and they do not bother about anything else; they only bother about the welfare of the society as a whole.

I think educational reform is required. As regards this, my party has circulated a document entitled 'People's plan for education'. That has been circulated by my party and discussed also and that has received the blessings of Jayaprakash Narayan. I request the hon. Minister to formulate the education policy. He could make use of this document for the purpose. At the time of formulating the educational reform priority should be given to the following factors: first priority should be for universal elementary education. When we talk about universal primary education, what we find here is that after primary education, most of the students are not in a position to proceed further in their studies. When they can't go to the secondary stage there is no question of their going to the college or university education. My request is that for the students of the age group of 11—14 there should be compulsory education provided by the Government. Steps in that ragard must be taken by the Government.

Coming to adult education, literacy percentage should go up in our country. For that purpose, programme should be undertaken. People living in rural area do not bother about education. They do not know what is going on; they do not know much about culture. That is why I suggest that a cultural programme should be taken up by Government and, at the same time, adults should be given an opportuinty to take part in sports etc. There should be non-formal education to the youth. There is frustration among the youth and so they do not join the colleges or universities. They should be treated properly by us so that they are not neglected by our Indian society. So, in this respect necessary steps should be taken.

Fourthly, there should be greater access of the backward sections to secondary and higher education. More than 25 per cent of our population belongs to scheduled castes and scheduled tribes. I know post-matric scholarships are given to scheduled caste and scheduled tribe students but my point is that most of these students cannot pass through the school level. So, how can they expect to get post-matric scholorships. I request the Government that free education should be given from primary to university level.

Fifthly, there should be decentralisation of education administration so that people are involved in the reform programmes.

Sir, I want to conclude only by saying that the report has correctly assessed that women in India suffer from social disabilities and prejudices which have affected their participation in the mainstream of national life despite the equality guaranteed to them in the Indian constitution. I would request the hon'ble Minister to take such steps which may enable the women to stand on their own and work side by side with men in the national-buildig activities. With these words I conclude.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Mr. Deputy Speaker, I forget to mention. Sixty-seven marks as grace have been given by the present Vice-Chancellor, after the MBBS results were finalised, and published by the Syndicate of Calcutta University, on an *a la carte* basis to enable some plucked candidates to get the degree. This should also be enquired into.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की मांगों पर बहस के दौरान, शिक्षा मंत्री द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों की मैं सराहना करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री

महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी दिशा देने की कोशिश की है—मैं उसका भी स्वागत करता हूं। परन्तु शिक्षा के लिए जो धनराशि रखी गई है उससे कोई भी बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा वेलमीनिंग शिक्षा मंत्री भी इस देश में शिक्षा के स्तर को सुधार नहीं सकता है—ऐसा मेरा विचार है। पहले पंचसाला प्लान में 7.2 प्रतिशत धनराशि शिक्षा के लिए रखी गई थी। दूसरी योजना में वह धनराशि कम होकर 6.2 प्रतिशत हो गई। तीसरी योजना में वह धनराशि 7.5 प्रतिशत रखी गई। चौथी योजना में वह 5.2 प्रतिशत रह गई और पांचवीं योजना में 3.3 प्रतिशत रह गई। जो इस साल का बजट है जोकि 6ठी योजना का पहला साल है उसमें 2 प्रतिशत से भी कम पर आ गई है। मैं समझता था जनता सरकार के आने के बाद कम से कम यह जो एक बहुत बड़ी कमी रही है, बहुत बड़ी बुराई रही है कि शिक्षा के ऊपर धनराशि कम होती चली गई, इसको जरूर सुधारने का प्रयत्न किया जायेगा परन्तु अफसोस है कि इस साल 1.9 प्रतिशत हमारे टोटल प्लान का शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है जोकि मैं समझता हूं बहुत कम है। जो योजनायें और जो विचार इस सदन में रखे जा रहे हैं उनका पूरा करना इस धनराशि के माध्यम से असम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल एजूकेशन पालिसी जो इस पालियामेन्ट के अन्दर यूनेनिमसली एप्रूव की गई थी, उस में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, मैं उन को यहां पर कोट करना चाहता हूं। उस में कहा गया था—

"The reconstruction of education on the lines indicated above will need additional outlay. The aim should be gradually to increase the investment in education so as to reach a level of expenditure of 6 per cent of the national income as early as possible.

उपाध्यक्ष महोदय, यह रेजोल्यूशन 1968 में इस हाउस के अन्दर सारे मेम्बर्स ने यूनेनिमसली पास किया था। यह नेशन के लिये एक प्लेज था कि बहुत जल्दी टोटल नेशनल इन्कम का 6 प्रतिशत एजूकेशन पर खर्च किया जायगा, लेकिन हो क्या रहा है—प्लांड-एक्सपेंडिचर का, टोटल-एक्सपेण्डिचर का सिर्फ 2 परसेन्ट एजूकेशन पर रखा जाता है, नेशनल-इन्कम की बात तो बहुत दूर है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लेज हम ने अपने देश के सामने किया था, बजाय इस के हम उस प्लेज को पूरा करने के लिये उस को इम्कीच करते, हर साल एजूकेशन पर टोटल-आउट-लें कम होता चला जा रहा है. मैं समझता हूं कि इस को बहुत जल्द ठीक करने की जरूरत है। हमारा छटा प्लान बन रहा है मैं समझता हूं कि उसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा। और छठे प्लान का जो पहला साल है उस में 2 परसेन्ट वाली बात उस में से निकाल दी जायगी।

हमारी नेशनल एजूकेशन पालिसी में कुछ और बातें भी कही गई थीं। इस के आखिर में यह कहा गय था—

"The Government of India will also review every five year the progress made and recommend guidelines for future development"

वह जो नेशनल एजूकेशन पालिसी बनी थी, इस का हर पांच साल के बाद रिव्यू होना चाहिये, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी उस का रिव्यू नहीं किया गया।

यहां यह भी कहा जा रहा है कि एजूकेशन का जो सेन्ट्रल प्रोग्राम है, जो नेशनल पालिसी

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

है, उस को बदला जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस के हक़ में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हर रोज नेशनल एजूकेशन पालिसी नहीं बना करती। यहां कहा जाता कि नया कमीशन या नई कमेटी बनाइये। कमीशन्ज और कमेटीज की तो वहां पहले ही कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ इम्प्लीमेन्टेशन की। 10+2+3 की जो बात है—यह तो। अभी पिछले दो सालों से ही लागू हुई है जो एजूकेशन कमीशन यहां बैठा था, उसने 1966 में 10+2+3 को रिकमेंण्ड किया था। उस के बाद पार्लियामेंट के अन्दर जो नेशनल एजूकेशन पालिसी बनी, उस में भी इस को रखा गया। एजूकेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस ने भी इस को रिकमेण्ड किया, तमाम एजूकेशनिस्ट ने मिल कर इस को रिकमेण्ड किया, इस लिये कमजोरी या गल्ती इस सिस्टम में नहीं है, उस के इम्प्लीमेन्टेशन में है, उस के अन्दर रखी गई टैक्स्ट-बुक्स में है, उस के अन्दर रखे गये कोर्सज में है, उस के सबजेक्ट्स के अन्दर है। एजूकेशन मिनिस्टर साहब पिछले एक साल के अन्दर इस में काफ़ी परिवर्तन लाये हैं, कोर्सज में कमी की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे एक बात यहां क्लियर कर दें। रोज-रोज यह कहा जा रहा है कि इस में चेन्ज किया जा रहा है, इस को बदला जा रहा है, 10+2 के बाद फिर हायर-सैकण्डरी आ रहा है, 8+4 हो रहा है—इस का क्या असर हो रहा है—इस से लाखों करोड़ों स्टूडेन्ट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस समय जो 12वीं क्लास है, उस में बच्चों को अभी भी मालूम नहीं है कि उन को क्या पढ़ना है। इस लिये मैं चाहता हूं कि एजूकेशन मिनिस्टर साहब इस बात को क्लीयर करें कि इस 10+2+3 की पालिसी को चेन्ज नहीं किया जा रहा है, केवल इस के सब्जैक्ट्स में, कोर्सिज में चेन्ज किया जा रहा है।

हमारी एजूकेशन पालिसी के साथ दो-तीन महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं। मेरे बहुत से साथियों ने कामन-स्कूल्ज और पब्लिक स्कूल्ज का जिक्र किया है। मैं भी उन के साथ अपनी आवाज को जोड़ना चाहता हूं। यू०जी०सी० और एजूकेशन कमीशन की रिकमेण्डेशन्ज को यहां पढ़ कर सुनाया गया कि नेबर-हुड स्कूल्ज होने चाहिये, पब्लिक स्कूल्ज होने चाहिये। इस के बारे में काफ़ी बातें आप के सामने रखी गई। इस के साथ-साथ नेशनल एजूकेशन पालिसी में जो शब्द इस्तेमाल किये गये थे, वे इस प्रकार थे—

"To promote social cohesion and national integration the Common School be adopted. Efforts should be made to improve the standard of education ingeneral schools. All special schools like Public schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free studenship to prevent segregation of social classes."

यह तो नेशनल एजूकेशन पालीसी में कहा गया है परन्तु 10 साल बीतने के बाद भी आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो सिर्फ मरिट पर एडमिट कर रहा हो और आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो फ्री स्कालरशिप इतनी ज्यादा दे रहा हो। आज उलटी बात हो रही है। जितने पर सेन्ट पब्लिक स्कूल 1968 में थे जबकि नेशनल एजूकेशन पालीसी बनी थी, उस से कम से कम 5, 7 गुना पब्लिक स्कूल बढ़ गये हैं और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। एजूकेशन मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि जब तक अच्छी एजूकेशन नहीं दे सकते, तब तक इन स्कूलों को बन्द करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो इस का अर्थ यह नहीं है कि शुरू से लेकर दो क्लासिज चलती चली आएं।

जो स्कूल पहले से हैं वे बन्द नहीं किये जा सकते लेकिन कम से कम आगे के लिए तो इस तरह के स्कूलों का बनना बन्द कर दिया जाए और जितने स्कूल हैं उन को उसी संख्या तक फ्रीज कर दिया जाए और जो आज ऐसे स्कूल बने हुए हैं उन के अन्दर मेरिट से एडमिशन हो, इस को देखना चाहिए।

पब्लिक स्कूलों के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि रीजनल लगएज के अन्दर पढ़ाई हो, यह घोषणा की गई थी। हायर सकेण्डरी तक रीजनल लैंग्वेज में और हिन्दी में पढ़ाई हो, ऐसी बात थी। जब मैं नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल का मेम्बर था, तो उस की एक कान्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया था और उस में एक एक करोड़ रुपया हर स्टेट को इस काम के लिए दिया गया था और यह कहा गया था कि हर स्टेट एक करोड़ रुपये में अपने यहां रीजनल लैंगुएज में ट्रान्सलेशन का काम करवाए। वह एक्सपेरीमेंट जानबूझ कर इन अंग्रेजीदां वालों ने फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि रीजनल लैंगुएज के अन्दर ठीक तरह से ट्रान्सलेशन नहीं होगा और टेक्स्ट बुक्स प्रीपेयर नहीं होने दी गई और वह काम अधूरा रह गया और आज रीजनल लैंगुएज के अन्दर हायर एजूकेशन पूरी तरह से नहीं हो रही है और जहां कहीं हो भी रही है, तो उन को कम्पीटीशन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ़ ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

अब चार, पांच चीजों का जिक्र और मैं कर देना चाहता हूं। एक बात तो मैं यू०जी० सी० के बारे में कहना चाहता हूं कि यू०जी० सी० जिस तरह से कार्य कर रही है, उस के अन्दर काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने 1961 में स्टैण्डर्ड्स आफ़ एजुकेशन के बारे में एक कमेटी बनाई थी। वह कमेटी 1961 में बनी और उस की रिपोर्ट 1964 में आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद आज तक 1978 तक, उस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ है। 14 साल हो गये हैं और वह रिपोर्ट उसी तरह से कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है।

उसी तरह से एजूकेशन कमीशन 1964 में बना और अभी तक उस की सिफारिशों पर क्या अमल हुआ है, इस का कुछ पता नहीं है। एजूकेशन पालीसी कितनी सक्सेसफुल हुई है, इस का कुछ पता नहीं है।

इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1970 के अन्दर एक कमेटी यू०जी०सी० के काम को रिव्यू करने के लिए बनाई गयी थी और उस की रिकमेंडेशन्स गवर्नमेंट ने मान ली परन्तु साढ़े तीन साल बाद उस के ऊपर एक दूसरी रिव्यू कमेटी बना दी और ढाई साल बाद उस रिव्यू कमटी की रिपोर्ट वहां पहुंची और अभी तक उस रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस के ऊपर विचार करने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

इस के साथ ही यू०जी०सी० में एक अजीब बात यह है कि वहां पर सारी पावर्स चैयरमैन को दे दी गई हैं, 1956 में एक रेजूलोशन पास कर दिया और उस में यह कह दिया कि सारी पावर्स कमीशन के चेयरमैन को देते हैं और दूसरे रेजोलूशन से चेयरमेन जिस को चाहे अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है। चेयरमेन को सारी पावर्स देने से और पावर्स के डेलीगेट होने से कितना मिसयूज उन पावर्स का हुआ है, इस को मैं आप को बताता हूं। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमेन, जो कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम होते हैं, उन के अन्दर दो- तीन साल में 13 बार विदेशों में गये हैं। इस तरह से आप देखें कि इन कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम में जब कि यहां से इनटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स को जाना चाहिए

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

था, 13 बार खुद यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमेन गये हैं। यह स्थिति इस लिए पैदा हुई कि सब पावर्स उन को दे दी गई थी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि श्री नूरुल हसन जब एजूकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत सोचे समझे तरीके से यू०जी०सी० में, नेहरू यूनिवर्सिटी में, आई०सी०एच०आर० और साहित्य एकेडेमीज में जानबूझ कर खास खास जगहों पर अपने आदमियों को रखा है और ऐसे आदमियों को रखा है जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड-होल्डर्स हैं या उन के साथ उनका ताल्लुक है। ऐसे आदमियों को उन्होंने सब जगहों पर बठा दिया था। जब कभी एजूकेशन मिनिस्टर साहब से पूछा जाता है कि ये जो सब जगह पर उन्होंने अपने आदमी बिठा रख हैं, उन्हें हटाया क्यों नहीं जाता है तो हमार एजूकेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये आटोनोमस बाडीज हैं, मैं उनके अन्दर कुछ नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार की मनोवृत्तियों के लोग वहां पर हैं जो हमारे एजूकेशन सिस्टम को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। वे वहां पोलिटिकल इरादे से काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वे गड़बड़ी करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एन०सी आर०टी० हिस्ट्री की किताबें लिखती है जब उन किताबों का क्रिटिसिज्म होता है तो एजूकेशन मिनिस्टर साहब घबरा जाते हैं आज इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि हिस्टोरियंस के माध्यम से गलत बातें कही जाएं। जब एजूकेशन मिनिस्टर ने उन किताबों का रिव्यू किया तो कहा गया कि उन्होने एकेडेमिक फील्ड के अन्दर इन्टरफियर किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो हिस्ट्री की किताबें थीं वे किस ने हटायी थीं? उन सारी किताबों को हटा कर, एन०सी०आर०टी० ने एक खास नुक्तेनिगाह से किताबें लिखीं और उन्हीं को आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ा और कोई रजिमेन्टेशन नहीं हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा सेक्यूलर स्टेट है और यहां शिक्षा भी सेक्यूलर, सर्व धर्म समभाव की होनी चाहिए। इस देश में किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। परन्तु हिन्दु धर्म के, हिन्दु कल्चर के खिलाफ़ इन किताबों में सब तरह की, मैं यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, नीचतम तरीके के बातें लिखी गयी हैं और उन किताबों को यहां आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये किताबें हमारे बच्चों को जबर्दस्ती पढ़ायी जाती हैं। बच्चों को वे किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इन किताबों में—सब लोग जानते हैं कि हिन्दु गो मांस के बारे में एक भावना रखते हैं—इन किताबों में लिखा है कि आर्य लोग गो मांस खाते थे, सुअर के मांस का इस्तेमाल तब नहीं होता था। उस समय के लोग, आर्य लोग अपने शव फर्श के नीचे गाड़ देते थे। आर्य लोग न केवल गो मांस भक्षी थे, बल्कि बर्बर और अनाचारी भी थे। इसी तरह से यह लिखा गया है कि वैदिक समाज के पुरुषों की जीविका केवल लूटमार थी। अगर इन सारी किताबों का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि ये एक खास दृष्टिकोण से लिखी गयी हैं। मैं हैरान हूं कि अब तक इन किताबों को क्यों नहीं हटाया गया? मैं यह मानता हूं कि जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उन पर किताबें लिखी जाएं, वे बाजार में बिकें। लेकिन ऐसी किताबें जबर्दस्ती बच्चों को न पढ़ायी जाएं। मैं यह बात केवल हिन्दु धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं, किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बातें किताबों में न लिखी जाएं जिनसे किसी भी धर्म के बारे में बच्चों में अनास्था पैदा हो। मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी पुस्तकों को फौरी तौर पर हटा दिया जाए जिससे

कि किसी भी धर्म के बारे में घृणा फैलती हो। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी गलत बात इस प्रकार की किताबों में नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। आज स्पोर्टस की हालत बहुत खराब है। अभी हमारा हाकी में डिबेकल हुआ। जब ऐसी कोई चीज हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, बड़ी बड़ी कमिटीज बिठायी जाती हैं। एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट्स की भी कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट अधूरी रह गयी है। दूसरी बहुत सी कमेटियों की रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई हैं। हमारे देश में टोटल प्लान आउट-ले का केवल दो परसेंट रुपया एजूकेशन पर खर्च होता है। उस एजूकेशन के बजट का एक परसेंट रुपया स्पोर्टस पर खर्च किया जाता है। एक साल के अन्दर स्पोर्टस पर केवल 26 लाख रुपया खर्च कर के क्या यह सोचा जा सकता है कि हिन्दुस्तान वर्ल्ड चेम्पियन पैदा कर सकता है। अकेले ओलम्पिक्स पर ही काफी पैसा खर्च हो जाता है। पश्चिमी जर्मनी स्पोर्टस पर एक साल में 96 करोड़ रुपया खर्च करता है। ईस्ट जर्मनी अपनी टोटल बजट का एक बटा पांच यानी बीस परसेंट रुपया स्पोर्टस पर खर्च करता है और हमारे यहां एक का दस हजारवां भाग स्पोर्टस पर खर्च किया जाता है। एक पैसा पर केपिटा हम स्पोर्टस पर खर्च करें और उसके बाद यह उम्मीद करें हमारे यहां चम्पियन पैदा हों तो यह नहीं हो सकता है। आज जो देश में स्पोर्टस की हालत है, उसके बारे में रेडिकल, रिवोल्यूशनरी थींकिंग की जरूरत है। एजूकेशन मिनिस्टर उसके बारे में सोच रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्दी उसके बारे में विचार कर कोई नेशनल पालिसी बन जाएगी। ऐसा हमें अश्योर भी किया गया है। स्पोर्टस में हमें दुनिया में बहुत बेइज्जत होना पड़ता है। मुझे आशा है स्पोर्टस के बारे में हमारी हालत जल्दी सुधरेगी।

एक बात मैं एशियन गेम्स के बारे में कहना चाहता हूं। हमने वर्ल्ड बाडी के सामने कमिटमेंट की हुई कि हम हिन्दुस्तान में 1982 में एशियन गेम्स आयोजित करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी है कि एक साल बीत गया, अभी तक उसके बारे में तैयारी शुरू नहीं की गयी है। एशियन गेम्स एक दिन में तो आयोजित किये नहीं जा सकते हैं। 1976 के अन्दर ओलम्पिक के टाइम पर यह कमिटमेंट किया गया था। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसकी परमिशन दे रखी है और कहा था कि यह कमिटमेंट की जा सकती है। 1978 आ रहा है। उसके अन्दर एक पैसा भी एशियन गेम्स की मद में खर्च करने की व्यवस्था नहीं की गई है। 1982 में ये होनी हैं। मैं मानता हूं कि इन पर कम से कम खर्च करने की कोशिश होनी चाहिये। यह जो कमिटमेंट है इसको गवर्नमेंट मान चुकी है और कह चुकी है कि इसको जरूर पूरा करेंगे। उसके लिए इसी साल से पूरी तैयारी शुरू कर दी जानी चाहिये। उसके लिए जो पैराफरनेलिया बनाना है, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिये, जो एपेरेट्स चाहिये, स्टेडियम चाहिये, सब बनाने हैं। सारे भारत में एक साइकल ट्रैक नहीं है, एक कबड्डी स्टेडियम नहीं है, सारा साल चलने वाला एक स्विमिंग पूल तक नहीं है, किसी भी गेम का पूरा इंटरनेशनल इक्विपमेंट नहीं है। ऐसी हालत में यह कमिटमेंट पूरा नहीं हो सकता है। यह कमिटमेंट अगर अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा तो आगे भी स्पोर्टस को बड़ा भारी फिलिप मिलेगा। इस वास्ते एशियन गेम्स यहां करने की पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी जानी चाहिये।

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

डिग्री को एम्प्लायमेंट से डी लिंक करने के बारे में जो बात काफी दिनों से चली आ रही है इसको जल्दी करना चाहिये ताकि डिग्री के लिए हायर एजूकेशन में जाने के लिए जो सख्त कोशिश लोग करते हैं वह न करें। ओपन यूनिवर्सिटी चालू करने के बारे में भी कहा गया था। दो साल तक तो कोई प्राबलैम नहीं होगी क्योंकि टैन प्लस टू में तीन साल तक लड़के यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाने वाले लड़कों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आप से सम्भालना मुश्किल हो जाएगा। नए कालेज और यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जा रही हैं। ऐसी हालत में डिग्री को एम्प्लायमेंट से डी लिंक करने के बारे में तथा ओपन यूनिवर्सिटी के कंसैप्ट को चालू करना बहुत जरूरी है।

एजूकेशन को जो कनकरेंट लिस्ट में रखा गया है इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिये। इसको स्टेट सबजैक्ट बना कर छोड़ देना बहुत गलत होगा। 42वां एमेंडमेंट जो था उस में दो तीन अच्छी बातें हैं। एक ग़रीबों को कानून सहायता देने की थी। एक आइ और थी। उसके साथ साथ एजुकेशन को कनकरेंट सबजैक्ट बनाया गया था। यह एक अच्छी बात है। इसको रिटेन करना चाहिये।

मारल एजूकेशन स्कूलों के अन्दर देने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। नैशनल एजुकेशन पालिसी में इसको स्थान दिया गया था। स्कूलों से ही देश के अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए वहीं से मारेल एजूकेशन देना शुरू करना ठीक होगा। इस पर काफी जोर दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री महोदय ने जो एक वर्ष में काम किया है उसकी पर: सराहना करता हूं और उनकी मांगों का समर्थन करता हूं।

*SHRI R. KOLANTHAIVELU (Tiruchengode): Mr. Deputy Speaker, Sir, at the very outset, I am glad to point out that the hon. Minister of Education has formulated policies and programmes reflecting the Janata Government's ideals and assurances to the people of the country and I am sure that he will be able to get them implemented through the Demands for Grants for which he seeks the approval of the House. He is guided by the two cardinal tenets—improving education and enthusing the youth of the country. Without reiterating what is contained in the Annual Report of the Ministry of Education, I would refer to a few pertinent issues.

In comparison with other countries of the world, we are educationally backward and economically underdeveloped. If we demand that our present educational system must be revamped, our Minister would counter us by referring to the financial constraints. The Minister of Education cannot demand overriding priority though Education is the basis of all growth, and he has to function effectively within the available resources. Our aim should be to utilise the allocated money cautiously for the betterment of education.

We have so far been formulating syllabi to meet the needs of above-average children. We should bear in mind that the educational syllabi should cater to the requirement of common people, majority of whom are below poverty line, if we are to eradicate illiteracy from among them. As he had himself been an illustrious teacher, I am sure that the hon. Minister knows fully well what kind of syllabi should

*The original speech was delivered in Tamil.

be there if education is to reach the grass-roots and what type of teachers should be there to guide their children of the common people. The well-being of the country lies in its enlightened society and in creating such a society education plays the pivotal role. Education should not merely be job oriented as its primary aim. If our educational achievements are high, then other countries will look at us with respect and they will also try to emulate our precepts and practice. I request that the hon. Minister should bestow his personal attention in the matter of introducing an educational system which enhances our prestige abroad and which enables our people to eke their livelihood with self-respect.

We must realise that the common people have ejected us to this august House. I am not referring to the educational needs of the people who have their exercised their votes in polling booths. I am referring to the educational requirements of youth below the age-group of 18 who have not yet been enfranchised. I am a member of the Ministry's Consultative Committee and I am aware of the Minister's avid interest in implementing the Directive Principle of State Policy regarding introduction of free and compulsory primary education throughout the country and universalisation of elementary education in the next 5 to 10 years. I have no grouse or grievance about his approach to resolving the problems of education. Education cannot be reformed or refurnished overnight, as it concerns the people living throughout the length and breadth of the country. The rigours of the people must be borne in mind before we think of introducing radical changes in educational pattern.

If we are true to the saying that India lives in villages, I should regretfully say that adequate attention has not been paid to education in rural areas and in semi-urban areas. Similarly 65 per cent of the youth in the country does not know about educational scholarships offered by the Central Government, foreign scholarships for higher studies etc. They do not know whom to approach and how to fill up the formalities. A sense of competition must be aroused in them. They must know that if they secure good marks they can get higher education abroad and also get highly remunerative jobs. I demand widesspread dissemination of information about such scholarships and other educational amenities existing for the benefit of the youth.

Unfortunately our temples of learning have become hunting grounds for politicians and the students have become the steping-stone for them to assume offices of power and authority. I demand that political parties should be banned from the arena of educational institutions. The students should abjure politics and they should not be overpowered by the fascination of political favours.

Knowingly or unknowingly Education was incorporated in the Concurrent List of the Constitution, besides the State List. The Janata Government assured that the State List would have the exclusive prerogative of having Education and it would be removed from the Concurrent List. But this has not become yet a reality. India is a land of diverse culture and languages and she has given to the world the unique concept of Unity in Diversity. When linguistic fanaticism and fracas are raising their ugly head, it is essential that the States are enabled to meet the immediate needs of the people living within its jurisdiction. We cannot afford to duplicate our efforts and fritter away our limited resources. I am sure that the Education would be removed from the Concurrent List forthwith.

[Shri R. Kolanthaivelu]

It is sometimes bruited about that money is not being spent properly on certain things. We are having our national Government established by the will of the people, committed to the fulfilment of their hopes and aspirations. This aspect of utilising the available resources effectively must bear repetition.

Education must not only have laudable objectives but also have the capacity to generate enthusiasm among the youth. It is not enough that our speeches on educaiton are published in the newspapers. Educational opportunities must receive universal aprobation. It is not feasible to have one uniform syllabus for the entire country. Education must tap the latent talents of the local people. Moreover, it must suit the local genius also. Education must be the main tool for removing the backwardness of the country. We should not be complacent about the rural needs so far as education is concerned.

15 hrs.

It is not relevant to refer to the conflicts and controversies in a country of our size. But it is imperative that education becomes universal so that understanding and appreciation become part of national life. Every parent wants his boy to get good educaiton and remunerative jobs.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Only for boys, not girls? Should not educational opportunities and avenues of vocation be created for girls?

*SHRI R. KOLANTHAIVELU: Yes for girls also, without whose support the Government cannot exist. Education should not only by updated but also adjusted to the local needs and requirements. The nation grows if its people are educated Educational accomplishments are natural concommitants of economic growth of the country. Our aim should be better educational standards, to augment the educational opportunities and to abolish the scourage of illiteracy from the country.

With these words I conclude my speech.

SHRI A. E. T. BARROW (Nominated—Anglo-Indians): I am constrained to quote from *As you Like it*:

"Time travels in divers paces with divers persons I'll tell you who Time ambles withal, who Time trots withal, who Time gallops withal and who he stands still withal".

For the Member who is waiting for his name to be called. Time stands still withal, for the Member who is speaking. Time gallops withal. So, as Time will gallop when I speak, I shall plunge into my subject straightaway.

I am raising the question of policy with regard to the minority-run schools established under Article 30 of the Constitution. I am doing so with confidence in our hon. Education Minister because of his statesman like approach to educational matters. I am also raising this because there is considerable confusion when Members speak of public schools and private institutions because they do not distinguish between these and the minority-run institutions which are founded under Article 30 of the Constitution. There is, therefore, much misinformed criticism of minority-run institutions.

At this stage I would like to emphasize that India is a land of minorities, linguistic and religious. Bengalis are a linguistic minority in Tamil Nadu; Tamilians are a linguistic minority in West Bengal; Christians and

*The original speech was delivered in Tamil.

Muslims are religious minorities, and even Hindus are a religious minority in the Punjab.

The right to establish and administer educational institutions by minorities is given in Aritcle 30 of the Constitution. I am quoting the first part of this article. Article 30(1) states:

> "All minorities, whether based on religion or language. shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

I want to stress that this protection in regard to education has been given to minorities, in our Constitution, for a very good and definite reason.

At this stage, I feel it is necessary to pause and consider the need for the protection of rights of minorities in a democracy. The principle of giving special rights to minorities is an internationally accepted one. It is not to have a pampered privileged section in society but to give the minorities a sense of security and a feeling of confidence.

In 1921, Albania subsequent to her admission to the League of Nations signed a declaration relating to the position of minorities in her territory. In 1933, Albania decided that all private schools should be abolished and sought to justify this on the ground that it was a general measure applicable to majority as well as to minority institutions. The Council of the League of Nations felt that this was a matter which should be referred to the highest judicial body and they referred the case to the Permanent Court of International Justice at The Hague. The Court observed.

> "The idea underlying the treaties for the protection of minorities is to secure for certain elements incorporated in a State, the population of which differs from them in race, language or religion, the possibility of living peaceably alongside that population and co-operating amicably with it, while at the same time preserving the characteristics which distinguish them from the majority, and satisfying the ensuing special needs...."

The Court went on further to say:

> "There must be equality in fact as well as ostensible legal equality in the sense of the absence of discrimination in law. Equality in law precludes discrimination of any kind; whereas equality in fact may involve the necessity of different treatment in order to attain a result which establishes an equilibrium between different situations."

15.08 hrs.

[SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN *in the Chair.*]

In the 1974 case: Ahmedabad St. Xavier's College Society Vs. the State of Gujarat, Mr. Justice Mathew. paraphrased this observation of the International Court in clear, lucid and unambiguous terms:

> "The problem of the minorities is not really a problem of the establishment of equality, because if taken literally, such equality would mean absolute identical treatment of both the minorities and the majorities. This would result only in equality in law but inequality in fact. The distinction need not be elaborated for it is obvious that equality in law precludes discrimination of any kind; whereas equality in fact may involve the necessity of differential treatment in order to attain a result which establishes an equilibrium between different situations'. It may sound paradoxical but it is nevertheless true that minorities can be protected not only if they have equality but also, in certain circumstances differential treatment."

The hon. Minister will appreciate this because of his long experience in law.

[Shri A. E. T. Barrow]

It is also interesting to review the provisions of Article 25 to 30 by studying the debates of the Constituent Assembly. These article from the backbone of the fundamental rights guaranteed to minorities.

Sardar Patel who was the Chairman of the Advisory Committee dealing the question of Minorities in a speech delivered in February, 1947 stated:

> "This Committee forms one of the most vital parts of the Constituent Assembly and one of the most difficult tasks that has to be done by us is the work of this Committee. Often you must have heard in various debates in the British Parliament that have been held on this question recently and before when it has been claimed on behalf of the British Government that they have a special responsibility, a special obligation for protection of the interests of the minorities."

> "They claim to have more special interest than we have. It is for us to prove that it is a bogus claim, a false claim, and that nobody can be more interested than us in India in the protection of our minorities. Our mission is to satisfy every interest. and safeguard the interests of all the minorities to their satisfaction."

In the Constituent Assembly when Clause 18 of the Draft Constitution, the present Articles 29 and 30, was being discussed, two senior members, K. M. Munshi and Mahavir Tyagi, wanted the clause to be referred to the Advisory Committee, the reason being that the Constituent Assembly should wait and see what rights the minorities were being given in Pakistan. In effect, as Dr. Ambedkar put it, they wanted that "the rights of the minorities should be relative, not absolute." Dr. Ambedkar repudiated this in these words:

> "Now, Sir, with all deference, I must deprecate any such idea. Rights of minorities should be absolute rights. They should not be subject to any consideration as to what another party may like to do to minorities within its jurisdiction. "We have said that no minority shall be precluded from establishing any educational institutions which such minority may wish to establish...."

I would not continue the quotation, but would like to emphasize that, against this background and against the successive judgements of the Supreme Court, I feel that the Education Minister should create in his Ministry a judicial cell with experts who will look into the rights of minorities when Bills and Rules are drafted. I would request the hon. Minister to ask State Governments also to do the same thing. Time and again, the minorities have to go to the Courts to get their rights enforced. This, I feel, should not be necessary. In particular, I would ask the Education Minister now to have some of the rules under the Delhi Education Act reviewed in the light of the judgements given in the Supreme Court. I am taking only two instances.

Rule 59 requires that, under the scheme of management of recognised schools—and there is no difference made between minority-run schools and other schools—two members are to be nominated by the Director of Education. In the case of minority unaided schools, the Director or Education will nominate two persons from the same minority. In the Christian Chruch, you have different denominations. If the schools is run by the Catholic Church. the Director of Education may, in his wisdom or otherwise nominate two members from the Church of North India. This principle has been struck down by the Supreme Court, and yet, we find it in these rules. I know these rules have not been framed by the present Education Minister; these rules were framed before. I am only seeking his help to get these rules rationalised.

In the case of the Ahmedabad St. Xavier's College Society vs. The State

of Gujarat the judges of the Supreme Court have said that the requirement of outside persons on the Governing Body constitutes an encroachment on the right to administer minority-run institutions. Chief Justice Ray struck down the relevant provision in these terms:

"The provisions contained in section 33A(1)(a) of the Gujarat University Act have the effect of displacing the management and entrusting it to a different Agency. The autonomy in administration is lost. New elements in the shape of representatives of different types are brought in. The calm waters of an institution will not only be disturbed but also mixed. The provisions in section 33A(1)(a) cannot, therefore, apply to minority institutions."

Mr. Justice Mathew and Mr. Justice Chandrachud, the present Chief Justice of the Supreme Court, also struck down the provision thus:

"....The requirement that the College shoud have a Governing Body which shall include persons other than those who are members of the Governing Body of the Society of Jesus would take away the management of the College from the Governing Body constituted by the Society of Jesus and vest it in a different body."

"The effect of the provision is that the religious minority virtually loses its right to administer the institution it has founded."

Therefore, I think it would be contrary to the judgements if the Delhi Administration insists that they will nominate persons to minority-run institutions.

Then, I would refer to Rule 118. Rule 118 lays down the procedure for disciplinary action against members of the staff. In particular, Rule 118 (iv) requires that findings and decisions of Governing Body should be submitted to the Director of Education for his approval. The Supreme Court has struck down a similar section in the Case of St. Xavier's Society Vs. The State of Gujarat.

Then, I would like to quote the words of Justice Mathew and Justice Chandrachud:

"Of course it is up to the State in the exercise of its regulatory power to require that, before the services of a teacher are terminated, he should be given an opportunity of being heard in his defence. But to require that for terminating the services of a teacher, after an enquiry has been made, the management should have the approval of an outside agency like the Vice-Chancellor or his nominee would be an abridgement of its right to administer the educational institution."

If the Minister likes, I can submit a memorandum to him on these matters so that he can deal with it. But I would still make a plea to have a judicial cell in the Ministry of Education so that the minorities need not be compelled to air their grienances in public.

Now, I come to something else. Schools in Delhi are being given only provisional recognition. I will send you the names, but I give a classic instance. Here is a letter dated 1st April, 1978 which says "...your school have been granted recognition up to 30th April, 1978". From 1st April, 1978 to 30th April, 1978! (*Interruptions*). Yes, it may be an April-fool letter; otherwise how can this be? It says that the application for renewal must be sent six months prior to the expiry of the recognition period, on the prescribed form! But how can they send it? They have to send it six months before, and they get the order on 1st April, 1978!

[Shri A. E. T. Barrow]

These schools are well-established schools and Members from both sides of the House and members from your Ministry come to me for admission to these schools. They have been established for 15 to 20 years but they get recognition from year to year or from month to month. This is a serious state of affairs and I would like this to be looked into. Unless safeguards are properly implemented now, can you instil a sense of confidence and a sense or feeling of security in minorities; how can these institutions work?

Finally, may I conclude on this point—the 10+2 pattern. If it is going to be 8+4, is there going to be any change in the content? I was a member of the Ishwarbhai Committee and I was a member of the Adiseshaiah Committee also. We planned a pattern of content which, I think, all educationists would approve of. The Adiseshaiah Committee went into the question whether there should be an examination at the end of standard VIII. On p. 9 of the Report it is stated, "A second issue that was considered was whether the free and compulsory primary school should be an 8-year school as envisaged in the Constitution, whether there should be a public examination at this stage to make it off and give it status, and whether vocationalization could be pushed down to Classes IX and X of the 10-year School." We came to the conclusion, "that it is not desirable to recommend a public examination at this stage"—that is, at the end of the Eight Standard, because from the primary school there should be an uninterrupted transition to get all children into the next stage of the 2 or 3-year secondary school.

If you have an obstacle, have an examination at the end of the 8th standard, you will have more dropouts at this stage than ever. As my friend, Shri Vijay Kumar Malhotra has said not only in Delhi, but throughout the Country schools want a firm decision with regard to the 10+2 pattern. Are we going back to the 11-year pattern or 12-year pattern with an examination at the 8th standard and another examination at the 12th year? If the hon. Minister comes out with a firm statement in this respect, it will relieve the anxiety of thousands of parents and children throughout the Country.

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : सभापति महोदया, शिक्षा विभाग की मांगों के अनुमोदन में मैं खड़ा हुआ हूं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह एक स्वाभाविक कल्पना थी कि हम अपनी शिक्षा की रचना ऐसी करेंगे कि जिस रचना के आधार पर हम सामाजिक जीवन में जीवन के मूल्यों को स्थापित कर सकें और शिक्षा के माध्यम से एक नया परिवर्तन व्यक्ति और समाज में ला सकें। लेकिन दिखायी यह देता है कि हम इस ओर गये ही नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा की रीति-नीति को निर्धारित करने वालों के पास कोई दिशा ही नहीं थी, वे विदिशा में जा रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्हें क्या बनना है या बनाना है। कौन-सी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाए, कौन-सी शिक्षा चलायी जाए, किस प्रकार का अक्षर ज्ञान दिया जाए, उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। ऊपर से हम नारे देते रहे और उन नारों के आधार पर ही हम शिक्षा में परिवर्तन की बात सोचते रहे। इससे समाज के अन्दर एक गिरावट आयी।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे यहां एक उक्ति है कि कोई कलाकार किसी मूर्ति को बनाने बैठा। उस मूर्ति का चित्र ही उस के सामने स्पष्ट नहीं था। फिर वह मूर्ति कैसे बना सकता था। अगर गणपति की मूर्ति बनानी हो और उसकी सूंड नहीं लगायी जाए, उसे पीछे लगा दिया जाए तो वह बन्दर की मूर्ति बन जाएगी। हमने भी शिक्षा जगत में ऐसा ही किया है। आज सारे

भारतवर्ष में ऐसी स्थिति दिखायी देती है । हम अपने जीवन मूल्यों को भूल गये हैं। आज हम अपने विद्यार्थिओं को दोष देते हैं। हम उन्हें पिछले तीस वर्षों में किस रास्ते पर ले आये हैं। आज कालेजों में उछृंखलता है, स्कूलों में उछृंखलता है। हड़तालें होती हैं। बड़े बुजुर्गों का वहां अपमान किया जाता है। मुझे अपने विद्यार्थिओं को अपने घर के नाश की ओर प्रेरित होते देख बड़ा आश्चर्य होता है। वे फर्नीचर को आग लगाते हैं, विश्व-विद्यालय के उपकरणों को नष्ट करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ये उपकरण किसकी सम्पति है। वे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी चलाने लगते हैं।

यह छुआछात, ऊंच-नीच का विचार जो समाज में पाया जाता है, यह किसने दिया है? हम भावात्मक एकता की बात करते हैं और राजस्थान में रहने वाले लोग राजस्थान का नारा लगाते हैं, तमिलनाडु में रहने वाले तमिलनाडु का नारा लगाते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्र का नारा लगाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि सारा भारतवर्ष मेरा है, हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसा मुझे बनना है। मैं यह नहीं सोचता कि जय भारत की बोलूंगा, भले ही राजस्थान उसके अन्तर्गत आ जाए। यह भावना बच्चों में कहां से पैदा होगी? समाज में यह भावात्मक एकता राष्ट्रीय एकता कहां से पैदा होगी? मूलत: जो हमारी एक बेसिक एप्रोच थी वही गलत थी। हमने यह नहीं देखा कि उसका परिणाम क्या होगा। उसका आज परिणाम यह है कि अपने घर के अन्दर अपने मां बाप को तथा अपने देश की प्रापर्टी को ही हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। एक वर्ष में मंत्री महोदय ने कुछ काम करने का प्रयास किया है जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जो परिवर्तन उन्होंने अभी तक किया है वह अधूरा है। उससे जो मौलिक दिशाबोध बच्चों को होना चाहिये नहीं हो पाता। जीवन मूल्य क्या है, समाज की निर्धनता कैसे मिटेगी समाज का कलंक कैसे धोया जा सकेगा, इस प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। हम देखते हैं कि एक बालक हाई स्कूल पास कर लेता है तो उसके बाद उस में श्रम के प्रति प्रतिष्ठा पैदा नहीं होती है। वह लेबर करने को तैयार नहीं होता है, मेहनत करने को तैयार नहीं होता है। वह घर का काम करने से शरमाता है। घर के अन्दर काम करने के लिए उसको नौकर चाहिये। देश का काम करने से वह शरमाता है। हमारी शिक्षा श्रमोन्मुखी होनी चाहिए, परिश्रमोन्मुखी होनी चाहिए। एग्रिकलचरल कालेज से कोई एम एस सी करके निकलता है तो वह लेक्चरार बनना चाहता है, यूनिवर्सिटी में जा कर लड़कों को पढ़ाना चाहता है, किसान की तरह से जमीन का विकास करके खेत पर उस टैक्नालाजी का उपयोग करने के लिए वह तैयार नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा दे कर जो जीवन मूल्य हम बच्चों में स्थापित करना चाहते हैं वे नहीं कर पाएंगे। हमारे माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मलहोत्रा ने बताया है कि नवयुवक भावात्मक एकता के बजाय विघटनकारी प्रवृत्तियों के अन्दर लगे हुए हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अन्दर यदि इस प्रकार की बच्चों को शिक्षा दी जाए जिस प्रकार की अब दी जा रही है, जिस प्रकार की अब किताब पढ़ाई जा रही हैं कि आर्य जो थे वे जड़ प्रदार्थ थे, वे कुछ समझते नहीं थे, वे गोमांस खाते थे, ऐसी अनगल बातें यदि बच्चों के मस्तिष्क में बिठाने.....

श्री वसन्त साठे (अकोला) : सच बात है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : यह विवादास्पद है। इस तरह की चीज पढ़ाना सर्व धर्म सम भाव के विपरीत है। इसको ठीक किया जाना चाहिए। अगर साठे साहब इसको सच मानते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको ज्ञान नहीं है। हम जिस बालक का

[श्री भानु कुमार शास्त्री]

जब वह प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है भाग्य सौंपना चाहते है वह किस के हाथ में सौंपना चाहते है इसको भी आप देखें। उसके लिए आपने एक स्केल निर्धारित कर रखा है। आपने कहा है कि वह मैट्रिक होना चाहिये और जी टी सी होना चाहिये। ट्रेण्ड होना चाहिये। जो बच्चों को बनाने वाला है, वह सब से कम क्वालिफाइड होगा। भावी पीढ़ी का भाग्य आप जिस के हाथ में सौंपना चाहते हैं वह सब से कम क्वालिफाइड होगा यह कौन सा नापने का स्केल है। आप कहते हैं कि जो शिक्षक बच्चों का जीवन बनाने वाला है वह मैट्रिकुलेट होना चाहिये क्योंकि वह प्राइमरी शिक्षा देगा, वर्ण माला सिखाएगा। क्या बच्चे के ऊपर इस प्रकार के संस्कार नहीं पड़ेंगे कि वह भी वही करे जो अध्यापक करता है, क्या बच्चा भी उसका अनुकरण नहीं करेगा, उसके पद चिन्हों पर नहीं चलेगा? मैं समझता हूं कि इस में परिवर्तन होना चाहिए और जो सब से ज्यादा क्वालिफाइड है सब से ज्यादा शिक्षित है वही छोटे बच्चों को पढ़ाए। केवल मैट्रीकुलेट उसको पढ़ाए इस प्रकार का विचार नहीं होना चाहिये।

देश का तेजी के साथ नैतिक ह्रास हो रहा है। तीस वर्ष में बहुत अधिक ह्रास हुआ है। उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विभिन्न आयोग और समितियां भी गठित हुई है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, डा राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, ईश्वर भाई पटेल समिति, श्रीप्रकाश समिति, सेवा ग्राम समिति, आदि समितियां और आयोग बैठे है। उपकुलपतियों की मीटिंग आनन्द में हुई, राजकोट में हुई, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन राजस्थान विद्यापीठ में हुआ। सब विद्वान वहां एकत्र हुए। इन लोगों ने जीवन में नैतिक मूल्य पैदा करने के लिए शिक्षा आयोगों ने जो हमें इस प्रकार का विचार दिया है क्या कारण है कि हम उसको अपना नहीं सके है। बच्चों को क्यों हम नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते है? नैतिक शिक्षा न देने के कारण प्रारम्भ से ले कर ऊपर तक नीचे से ले कर ऊपर तक नैतिक ह्रास हो रहा है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

आज देश के अन्दर एक अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है। यह वातावरण 10 प्लस 2 प्लस 3 प्रणाली को लेकर फैला हुआ है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको 8 प्लस 4 प्लस 2 करना होगा। कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी इसको देख लिया जाना चाहिए। इसको निश्चित कर लेना चाहिए। कौन सा सिस्टम एडाप्ट करना है यह तय हो जाना चाहिए। कोई भी सिस्टम एडाप्ट कीजिए लेकिन एक बार उसको आपको कर लेना चाहिए। राजस्थान में 10 प्लस 2 प्लस 3 एडाप्ट नहीं किया गया है। 10+2+3 में एक यह अवगुण है कि उसमें संस्कृत को एक भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत एक भाषा नहीं है, बल्कि वह हमें जीवन देने वाली एक व्यवस्था है। इस लिए उसे एक भाषा के स्थान पर रखा जाये, अर्थात् जिस की इच्छा हो, वह उस को ले और जिस की इच्छा न हो, वह न ले, ऐसा न कर के उसे पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना चाहिए।

मंत्री महोदय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, सरस्वती के मंदिर में, जो उपकुलपति नियुक्त किये जाते है, अगर उन में से किसी के बारे में कोई शिकायत आये, कोई करप्शन का मामला पकड़ा जाये, कोई कमीशन जांच के लिए बैठे और उस के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे दें, तो कम से कम उस के बाद ऐसे

व्यक्ति को उपकुलपति न बनाया जाये । क्या हम इस प्रकार के उपकुलपतियों को रख कर शिक्षा का प्रसार कर सकते है ?

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उदयपुर में जो एक उपकुलपति थे, पहले वह मध्य प्रदेश में थे । मैं उन के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I rang a bell earlier. Please conclude.

श्री भानु कुमार शास्त्री : इस विषय में एक समाचारपत्र में कहा गया है :—

The Madhya Pradesh Chief Minister Mr. P. S. Sethi told the Vidhan Sabha to-day that the Government had initiated against Dr. P. S. Lamba, former Director of Agriculture and at present Vice Chancellor of Udaipur University for the alleged embezzlement of funds in an insecticide purchase deal while he was in Government service.

The Chief Minister said on the basis of the Vigilance Commission's Report, a fine of Rs. 5.000/- had been imposed and a show cause notice served on him.

मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति को, जिस के खिलाफ चार्जशीट दे दी गई, जिस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया गया, उसे उदयपुर में वाइस चांसलर बना दिया गया। उदयपुर में फिर एनक्वायरी कमीशन बैठा। वहां से उन्हें हटाया गया और फिर उन्हें हरियाणा में इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब जनता सरकार शासन में आई है। उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाने से क्या लाभ है। क्या हम ऐसे लोगों को रख कर अपने देश का चरित्र निर्माण कर सकेंगे ?

यदि इस प्रकार का कोई भी उदाहरण मंत्री महोदय की जानकारी में आ जाये, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को हटा कर एक आदेश उपस्थित करना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

You send a list of examples to the Minister.

श्री भानु कुमार शास्त्री : इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): The Demands for Grants of Ministry of Education, Social Welfare and Culture are really disappointing. Why I should say 'disappointing' I shall explain all the reasons.

There is no question about the capability of our Education Minister. I have got fullest confidence in him. Out of Rs. 12.000 crores only Rs. 412 crores have been provided for the Department of Education, Social Welfare and Culture. How are the projects as mentioned therein to be implemented? We have had discussions time and again about the language issue, to teach Hindi everywhere, in all cities and towns and villages. But where is the money provided for it? So, that sort of debate will not serve any purpose. We find that for adult education only a few lakhs of rupees have been provided. 67 per cent of the people in the country do not enjoy literacy. Only 33 per cent of the people enjoy literacy. We should remove illiteracy and we should develop the nation. So, this Department should have been given the topmost priority. Education is the backbone of the nation. If the nation is to be developed, if the aspirations of the people are to be fulfilled, education must spread in the villages. The benefit of education must be available for the farmers, for the agriculturists of the country. Until and unless we remove illiteracy, until and unless we develop the

[Shri Dhirendranath Basu]

nation along these lines, I am afraid, there will be revolutions.

We find that even now there are no primary schools in the villages and anchals. These primary schools should be set up there. Government should provide more funds for this purpose. Although the Education Minister stated yesterday that there are 20 lakhs primary teachers to teach literacy in the villages, the position today is that we require about 31 lakh teachers and for this sufficient funds should have been provided. We require 11 lakh teachers more. If there are no funds provided how can things improve? So, this is an important thing which should be looked into.

Then, in page No. 5 in regard to the Demands for Grants in the Ministry of Education and Social Welfare you will find the subject of promotion of Hindi along with the other languages. Unless there are efforts made, how can you promote the Hindi language? There should be the three-language formula as announced by the former Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He is no more with us today but this three language formula, that is, Regional language, English and Hindi should be taught. This should be taught every where even in the primary schools. In the colleges Adult Education Centres should be opened where Hindi should be taught. People are eager to learn Hindi. In some of the schools and colleges with which I am connected, adult education centres have been opened. People are eager to learn Hindi. But money should be provided for that.

MR. CHAIRMAN: What is the third language in the Hindi-speaking region?

SHRI DHIRENDRANATH BASU: They should also learn other languages. What is the harm?

I have said about the three-language formula. The three-language formula should be accepted and should be implemented properly.

To-day we find that in many of the villages there is no radio or T.V. But, in some schools and colleges, of course, we find radio and T.V. That is why people gather together and listen to the radio or T.V. as to what our leaders are saying and what the education policy of the Government is. In all villages in primary schools, libraries or other institutions, radios and T.V. should be provided by Government. And Central Government should have come forward with the provision of money because the resources of the State Governments are very scanty. Unless sufficient funds are provided for by the Centre, how can they impart education to all? Unless illiteracy is eradicated from this country, we cannot prosper.

Even after thirty years of Independence, illiteracy is prevalent in this country. In this country 67 per cent of people do not know how to read and write. We have to teach them. They are eager to learn. But, facilities are to be provided for the purpose. Unless the facilities are provided, how can we teach them? So, facilities should be provided through different institutions, schools or colleges and Government of India must come forward with the necessary funds for that purpose. Funds are very scanty. How can you expect them to implement any of the schemes—job-oriented scheme?

A sum of Rs. 26 lakhs only has been provided for the technical education. What is meant by job-oriented education? It means provision of jobs to students after the technical education. What is the positon to-day? 80 per cent of graduates are still unemployed. Why? That is because of the faulty policy followed by our Government. People are eager to learn by going for the engineering and other technical education. Unless we encourage young people, they will only go in for the higher studies in colleges—not for technical education—and they will remain unemploy-

ed. I would request the hon. Minister, through you, that sufficient funds should be provided. He should now insist upon the Finance Minister for the provision of more and more funds.

You will be surprised to learn about the students indiscipline. In schools and colleges, there is indiscipline. In Bihar, all the universities have been closed. In all other universities in almost all provinces, there is chaos; there is indiscipline in schools and colleges. What is the reason?

MR. CHAIRMAN: I request you to conclude now.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: The reasons must be found out. We will have to go to the root of it. One of the reasons is that political parties are involving the students into politics. Students should not be allowed to indulge in politics. I would appeal to all sections of the House not to inject the politics among the students in the colleges. They should be disciplined.

MR. CHAIRMAN: He is listening to you carefully.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: Students will have to learn discipline. Unless we make them understand that they are the future leaders of this nation, they will get frustrated. Why are they frustrated? Because lakhs and lakhs of graduates or educated youths are still unemployed. They are not getting any employment.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I have called Shri Balbir Singh.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: I am concluding. I request the hon. Minister, through you, to provide more funds for the adult education and for teaching Hindi in all schools and colleges and in all primary schools throughout the country.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस शेर से शुरू करता हूं :

"मंजिलों को न पा सकेंगे वे रहनुमाई न
कर सकेंगे।

जिन्हें अभी तक दियार हस्ती में रहगुजारों
की जुस्तजू है।।

हमारे हिन्दुस्तान में शिक्षा के मैदान में जितना घपला हुआ है, उतना शायद किसी और बात में नहीं हुआ है। शिक्षा शास्त्री जो यह शिक्षा की नीति को बनाने वाले हैं और जो यह पिछले सालों में करते रहे हैं, उस सारे को पढ़ा जाए और देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि उन शिक्षा शास्त्रियों को किसी मेन्टल होस्पीटल में भेजने की जरूरत पड़ेगी। यह मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वे शिक्षा शास्त्री बैठे और उन्होने कहा कि यहां इम्तिहान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इन को घटाया जाए। जब ये इन को घटाने के लिए बैठ गये, तो फ़ैसला क्या हुआ कि जहां पहले प्राइमरी में चौथी जमायत में इम्तिहान होता था, वहां आज चौथी में भी होता है और पांचवीं में भी होता है। फिर उन्होने कहा कि मिडिल का इम्तिहान बन्द हो जाना चाहिए और अब हम देखते हैं कि आंठवीं में, नवीं में, दसवीं में, ग्यारहवीं में, बारहवीं में और सोलवीं क्लास में, एम०ए० और हर क्लास में इम्तिहान होता है। वे कहते तो यह थे कि इम्तिहान कम हों लेकिन उन्होंने जो उस का हल निकाला, तो हर साल इम्तिहान शुरू होने लगे। फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ़ तो हायर सैकेण्डरी सिस्टम शुरू होगा यानी 11वीं जमायत तक पढ़ाई होगी और फिर कालेज में प्रि-यूनिवर्सिटी क्लासेज होंगीं और जिस तरह की स्कीम ये लाएं उन्होने यह दिखाया कि जैसे ये एजूकेशन सिस्टम को रिवोलूशनाइज कर देंगे, यह क्रान्ति ला देंगे। इस तरह से तालीम के मैदान में अरबों रुपया खर्च करने

[चौधरी बलबीर सिंह]

के बाद फिर यह कहा कि यह सिस्टम फेल हो गया है और अब यह नया सिस्टम शुरू किया गया है। पता नहीं किस आदमी के दिमाग की यह बात थी। अरबों रुपया खर्च करने के बाद एक सिस्टम इन्होंने निकाला था कि दसवीं और फिर बारहवीं क्लास के बाद इम्तिहान होगा और बी०ए० और एम०ए० यानी सोलहवीं क्लास का इम्तिहान होगा और यूनिवर्सिटी का वह इम्तिहान था। अब उस सब को इन्होंने बदलने की बात कर दी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हायर सैकेण्डरी सिस्टम को लागू करने के लिए इन्होंने पहले इन स्कूलों को ग्रान्ट दी और फिर जो कालेज हैं उन को ग्रान्ट दी। क्योंकि 11वीं क्लास स्कूलों में चल गई थी, इसलिए उनको ग्रान्ट दी और कालेजों को प्रि-यूनिवर्सिटी क्लासेज के लिए ग्रान्ट दी। उनके यहां क्लास का नम्बर घट गया और उनके यहां क्लास बढ़ गई, इसलिए इनको ग्रान्ट दी। अब आप देखें कि 10 प्लस 2 प्लस 3 की एक नई बात आ गई है। पहले 8 प्लस 3 प्लस 3 आया था लेकिन कहीं पर 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 भी कायम रहा। अब जो यह 10 प्लस 2 प्लस 3 आया है, इसका मतलब यह है कि जो गरीब लड़का पहले 14 साल में बी०ए० पास कर के, ग्रेजुएट हो कर बाजार में आता था और डिग्री प्राप्त करने के बाद यह सोचता था कि अब मुझे काम मिल जाएगा अब उस गरीब लड़के को 14 साल की जाये एक और साल लगाना पड़ेगा और गरीब आदमी पर एक साल का खर्चा और पड़ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये सब बातें जो आप चला रहे हैं, ये कैसे चलेंगी।

मैं आप को बताऊं कि पंजाब में, हमारे यहां की टीम हाकी में हार गई ओलम्पिक में, इस हारने का क्या नतीजा निकला? नतीजा यह निकला कि पंजाब में उन्होंने फिजिकल एजूकेशन कम्पलसरी कर दी। अब आप यह देखिये कि वहां पर फिजिकल एजूकेशन तो कम्पलसरी हो गई, लेकिन वहां पर टीचर का कोई इन्तजाम नहीं था। कम्पलसरी एजूकेशन किसी के दिमाग में आ गयी और उसको चालू कर दिया। इसमें भी हम हार गये। जब दुनिया के मुकाबले में हम किसी जगह पर नहीं आते तो हम उनकी नकल क्यों करते हैं? हमें पढ़ाई को एक प्लाण्ड तरीके से चलाना चाहिए। अगर आपको फिजिकल एजूकेशन देनी है तो बाकायदा-तौर पर आप टीचर्स का इंतजाम करें। आपने 10 जमा 2 जमा 3 शिक्षा पद्धति शुरू कर दी। इसमें क्या हो रहा है कि आपके टीचर्स को पता नहीं कि उनको क्या पढ़ाना है।

शिक्षा मंत्री जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बार पंजाब के हैडमास्टर मुझे हैडमास्टरों की कान्फ्रेंस में ले गये। उसमें हाई स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल के टीचर्स भी आये थे। वहां लेक्चर्स हुए और सभी ने अपने ग्रेड्स के बारे में बताया कि कोठारी कमीशन ने ये ग्रेड देने की सिफारिश की है। थोड़ी देर तो मैं सुनता रहा फिर मैंने कहा कि यह हैडमास्टर्स की कान्फ्रेंस है या शिक्षा वालों की? मैंने कहा कि कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। उसमें यह भी है कि एजूकेशन क्या हो, क्या न हो? इस बारे में किसी ने भी बात नहीं की, सिर्फ अपने ग्रेड्स के बारे में सबने बात की हैं। सभी ने कहा कि हमें ये ग्रेड्स दिये जाएं। यह हमारा हाल है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि बाकायदा एक स्कीम बना कर हम शिक्षा का काम करें। हमारे दिमाग में एक बात यह आ गयी है कि आठवीं क्लास के बच्चों को जिन्दगी में कुछ काम करने लायक सिखाया जाए। पांच साल का बच्चा पढ़ने बैठता है और 13 साल का होने पर आठवीं पास करता है। क्या 13 साल का बच्चा कमाई शुरू कर दे? इस उम्र के बच्चे को तो दूसरी बात सीखनी हैं, जनरल नालेज सीखनी है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने वर्धा स्कीम चलायी थी।

15–20 साल पहले स्कूलों में तकली और रुई सप्लाई की जाती थी। अब कहीं भी तकली और रुई दिखायी नहीं देती।

हमारे यहां के एक आदमी बाहर के मुल्कों में चले गये। वहां इंग्लैंड और अमेरिका की पढ़ाई देख आये। यहां आकर वे यह भूल गये कि हमारे यहां पढ़ाई के क्या साधन हैं? मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में एक स्कूल का खर्चा हमारी एक यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ज्यादा होगा। हमारे यहां कोई अफसर हो जाता है और बाहर जाकर देख आता है कि वहां ऐसी पढ़ाई चल रही है और वही पढ़ाई वह यहां भी चालू करना चाहता है। वह चालू कर भी देता है और साल भर करोड़ों रुपया जाया करने के बाद फिर यह कहता है कि यह स्कीम नहीं चल सकती है। 15–20 साल पहले की बात है। पंजाब में डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन थे। उन्होंने हिन्दी की पढ़ाई देवनागरी लिपि में डायरेक्ट मेथड्स से शुरू कर दी। मैं एक कालेज कमेटी का प्रधान हूं। चार कालेज चला रहा हूं, 11 हाई स्कूल चला रहा हूं। मेरा एजूकेशन से थोड़ा ताल्लुक है। मैं जा कर उन डायरेक्टर से मिला और कहा कि अंग्रेजी के लिए तो डायरेक्ट मेथड की पढ़ाई ठीक है क्योंकि उसमें एक लफ्ज की कई आवाज होती है लेकिन हिन्दी में तो ऐसा नहीं है। यह तो एक बाकायदा लिपि में पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको यह पता नहीं है। दस साल के बाद फिर उन्हें वही पुरानी पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। दस साल पहले उन्होंने जोर लगा कर डायरेक्ट मेथड शुरू कर दिया था। इस ढंग से एजूकेशन में जो तमाशा होता है उसको समाप्त किया जाए। दस जमा दो जमा तीन शिक्षा पद्धति पर पैसा जाया करने के बाद यह रिपोर्ट आ जायगी कि यह सिस्टम फेल हो गया है। फिर एक कमेटी बैठेगी और देखेगी कि यह सिस्टम फेल क्यों हो गया है जो चीज आपने शुरू करनी है उसके लिए आपको सब से पहले यह देखना चाहिये कि आप के पास फंड्ज हैं या नहीं हैं। फिजिकल एजूकेशन किसी प्रकार की शुरू करनी है तो सब से पहले आपको यह देखना चाहिये कि फंड्ज हों और उसके साथ साथ साथ साथ यह देखना चाहिये कि उसके लिए टीचर्ज आपके पास पहले से तैयार हों। किसी भी स्कीम को लागू करने से पहले यह भी देख लिया जाना चाहिये कि उसकी किताबें आपके पास तैयार हों और उन किताबों को पढ़ाने वाले निपुण अध्यापक हों। आज होता यह है कि आप कोई नया सिस्टम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपके पास टीचर नहीं हैं तो आप टीचर तैयार करना शुरू करते हैं और जब तक टीचर तैयार हो कर निकलते हैं उतनी देर के बाद फिर आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि स्कीम फेल हो गई है और यह स्कीम चलेगी नहीं।

खेल जगत में हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। हमारे पास सोने का तगमा अंग्रेजी के जमाने में हुआ करता था। नेहरू जी के जमाने में वह घिस कर चांदी का हो गया। इंदिरा जी के राज में वह कांसे का हो गया। अब वह हमारे पास कांसे वाला भी नहीं है। यह सिर्फ हाकी की ही बात नही है। दुनिया के मुल्कों को आप देखें। जिन का दुनिया के नक्शे पर कोई स्थान नहीं है, जो उस पर नजर भी नहीं आते हैं, सिर्फ बिन्दी ही लगी आपको मिलेगी, कुल एक लाख की उनकी आबादी है, वे सोने के तगमें लिए हुए हैं। हमारे पास टैलेंट न हो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है। हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? जो खिलाड़ियों का चनाव करने वाले हैं वे यह देखते हैं कि उनके दोस्तों के बच्चे आ जाएं, उनके बच्चे आ जाएं, भाई भतीजावाद वहां पर चलता है। जो असली खिलाड़ी हैं उनको धक्के मार कर बाहर फैंक दिया जाता है। दौड़ने में अगर कोई बाजीगर है या दूसरे लोग हैं जो बहुत निपुण हैं उन में से हम बच्चे लें और उनको तैयार करें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दें तो इसके बहुत अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं।

[चौधरी बलबीर सिंह]

हर किस्म का मसाला हमारे पास मौजूद है। उसको सिर्फ तरतीब देने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा किया तो तमाम देश को आप काफी ऊंचा ले जा सकते हैं। चन्द बच्चे जो आगे आ चुके हैं उन्हीं पर पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि एजुकेशन का जो सिस्टम है इस में आप 10 प्लस 2 प्लस 3 लागू करने में जल्दी न करें। इस पर जरा और आप सोच विचार कर लें। फिर इसको आप शुरू करें। आप देखें कि हायर सैकेंडरी की तरह अरबों रुपया जाया न हो जाए।

SHRI CHARAN NARZARY (Kokrajhar): Madam Chairman, I am speaking in support of the Government Demands for Grants under the head 'Education'. I want to make a few general observations.

16 hrs.

The system of our education is a pyramidic structure, as you all know with Universities at the top, having massive dimensions at the base, sustained by innumerable pillars known as the primary schools. Now the standard of our education has fallen because the basic pillars of our education have been decaying due to lack of proper nourishment. That is why, I would request the Education Minister to give proper attention to primary education. There is lack of uniform educational policy in our country because we have seen that different States have adopted different educational policies. This lack of uniform educational policy has seriously disturbed the academic life of the students in general all over the country. On the other hand, the constitutional provisions for safeguarding the language and education of the minority sections of the country have not been properly implemented. The reorganisation of States on linguistic basis has given rise to the emergence of chauvinism of regional languages in different States. As a result, in certain States people who speak their own languages other than the regional languages have suffered a lot. This is a serious problem and the minister should look into it with proper care.

Hindi should remain the national language and there is no disagreement on this point. But side by side, English should also remain in India as a link language between the Hindi-speaking people on the one hand and people who do not speak Hindi on the other. This retention of English should continue till such time when English may be replaced by or our national language which is invariably Hindi.

The tribal languages in different States have not been encouraged properly. Those linguistic groups of the country who do not have a script of their own should be given the Devanagari script. To cite an example, in Assam, the Bodo speaking tribal people have adopted Devanagari script for the Bodo language. Most of the hon. members of this House, I am sure, do not know anything about Bodo people in Assam. If you do not know the Bodo people, it will not be possible to know Assam properly, because as has been admitted by historians, anthropologists and other scholars, 70 per cent of the Assamese language and culture is the contribution of the Bodo people. These people are a militant tribal group who built up a vast empire in north-east India and ruled there for ages together. They are known by different names. From time immemorial they have developed their distinctive culture and civilisation and in the days of Ramayana, Mahabharata and Puranas, they were known as Kirato. They were a militant people and they have been a vital factor in the north-eastern region from the point of national defence too.

Now, the language of the Bodo people has been recognised as the medium of instruction at the primary stage in 1963 and they have got this re-

cognition after a series of agitations for years together. Ultimately, in 1963, this language was recognised as the medium of instruction at the primary stage. After the introduction of Bodo language at the primary stage of education, there arose the question of introducing it at the secondary stage of education also. The Bodo people had to launch a serious agitation and ultimately, in 1968, the Bodo language has been recognised as the medium of instruction up to the secondary stage and in 1976 this Bodo language has been recognised as the modern Indian language by Gauhati University. The total number of the Bodo-speaking people in the whole of the North-East India will be over 20 lakhs. Although the Bodo language has been introduced as the medium of instruction up to the secondary stage and although Devanagari has been adopted by the Bodo people for their language in 1976, no proper care has been taken for the implementation of teaching in Bodo medium as well as Devanagari script. Devanagari has been accepted by the Bodo people at a very great cost. They have to launch a big agitation at the cost of 18 lives. They had to accept the Devanagari script.

Many of the hon. Members have been speaking on the floor of this House that Hindi should be introduced in all States and Devanagari script should be spread for the languages of those linguistic groups who do not have any script of their own. Even then, no concrete step has been taken so far by the Government for this purpose. In Assam for Bodo medium students there are over 3,000 primary schools and most of the schools are running without teachers, without text books, without Government assistance, without school buildings and the State Government is also not giving proper attention to this problem. Time and again repeatedly, the Bodo Sahitya Sabha made representations to the State Government as well as to the Central Government. Nobody bothered for them. Devanagari script has been introduced, but the teachers teaching in Bodo medium are not acquainted with Devanagari script and since the script has been given to them, the Bodo medium teachers should be trained properly and for that special arrangement has to be made. The Bodo Sahitya Sabha has been demanding it. In my own home town, the basic training school where the Bodo medium teachers receive their training, should be converted into a full-fledged training centre of Devanagari Script. That is not being done.

The total number of secondary schools in Assam alone will be over 200 where teaching is in Bodo medium. But most of the tribal schools are also running without teachers, without financial assistance from the Government and the condition is so pitiable that repeatedly the Bodo people have to resort to agitation. It is very unfortunate. That is why, what we have been demanding is that education, if possible should be made a Central subject. If that is not possible, it should be made a concurrent subject, but not a State subject. We are opposed to the concept and idea of including Education in the State list.

Madam Chairman, I would like to request the hon. Education Minister to make a separate allocation of funds for the proper implementation of Bodo medium education in Assam. The present department of education in Assam is not competent enough to cope with the problem which has arisen in this regard. That is why the Bodo Sahitya Sabha has been demanding a separate directorate for Bodo-medium education. At the same time, a separate allocation of funds should be made by the Central Government.. Since Devanagari has been accepted by the Bodo people at the instances of the Central Government in 1976, it is obligatory for the Central Government to look after the proper implementation of Devanagari script for the Bodo language. Otherwise, there

[Shri Charan Narzary]

would be no meaning in accepting it by those people. We are for the nation. We are the defenders in the northeastern region; and if we are to give priority to the question of maintaining the solidarity and integrity of the country by defending the borders in the northeastern India,I believe the Central Government, and particularly the Education Ministry should give proper attention to the academic life of those people.

MR. CHAIRMAN: You should conclude now.

SHRI CHARAN NARZARY: I did not speak on any other subject during this whole session so far. That is why I want to speak for few more minutes now.

MR. CHAIRMAN: I have got a list of speakers who have not also spoken earlier in the session. Please conclude in two minutes.

SHRI CHARAN NARZARY: One more point. Every year, a large number of Bodo students learning in the Bodo medium, are coming out of the high schools, after the Matriculation examination. After that, where will they go? There is no scope for them for having higher education in colleges, because there is no scope for their admission into these colleges, where Bodo has not been introduced as a language subject. That is why colleges have to be started for them; and in my own constituency, at Ramfalbil (Kokrajhar), one such college has been started by the public, under the name and style "Janata College" out of public contributions. The college authority made representations to the State Government, seeking permission, but there was no help. No permission has been accorded by the State Government yet. In the meantime, the number of students is increasing alarmingly.

If, in the interest of tribal education, the Government does not take special care, what will be the fate of those unfortunate boys and girls? It is a serious problem for us. That is why, there is recurrence of unfortunate incidents, troubles and agitations in Assam. If all these problems have to be solved, Government should take certain effective measures and issue special directions to the State Government, to implement the Constitutional provisions and central directives, so that the aspirations of those people are fulfilled.

MR. CHAIRMAN: You should conclue now. I will have to call the next speaker. Mr. Sathe.

SHRI CHARAN NARZARY: With these words, I conclude and hope that something positive will be done by our Education Minister, who is a renowned scholar with a good sense of human understanding.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Madam, today while speaking on the Demands of the Ministry, I want especially to deal with the Department of Social Welfare and Culture. Normally, this wing is not touched very much. We talk so much about general education, which is very important, but I find that this Department is with the hon. Minister, with the assistance of few capable State Minister, Shrimati Barakataki and surprisingly the amount provided for social welfare is Rs. 12.82 crores in 1977-78, which comes to less than about 20 paise *per capita*. I do not know whether from this pittance of an amount much welfare can be achieved. Then this will include the Integrated Child Development Service programme for the entire children of the country, welfare of women, rehabilitation of destitute women, adult education, sports and, most of all, the various social welfare activities that are supposed to be undertaken like problems of juvenile vagrancy and delinquency, beggary, prostitution, alcoholism, drug addition etc. All this has to be managed by this Department. I wish my hon. friend the Minister luck in this. I do not know how he

is going to achieve this. But there are certain matters which I would draw his attention to, where we must adopt a rational attitude towards certain social welfare measures.

I will take first the question of prohibition. I am afraid, if we launch on this prohibition policy as a fad, we are going to be in difficulties. Prohibition is necessary, people should not be addicted to drinking because alcoholism is bad. But can you achieve prohibition by law, by legislation, or the way you are going about it? This has not been achieved throughout the centuries of human nature, either in this country or in any part of the world. Even in this country in those States where it was tried, it failed. Temperance is good and we should try to have it. For example, in the working class area you can say there should be no pubs or selling points. You can put them outside these areas or mill areas. I can understand that. You should regulate it. But to say that there should be total prohibition, the way you want to do it, I am afraid, it is bound to fail. Today we are having a slogan "do not have whisky; go in for pisky." It is madness. The slogan is:

छोड़ा शराब, पियों......

I do not want to utter that word. I am told, I would like it to be confirmed, that one day Mr. Raj Narain was going by the British or some other airlines abroad, and the stewardess or air hostess came and asked him: "Will you have coffee or tea?" and he said "No, pee." She kept the honour of her service, that is a different story, but we will become the laughting stock of the world. This is all I want to say about prohibition.

Then I come to a question which is seldom touched, namely the rehabilitation of destitute women. As long as we have this system of economy where everything is marketable, with the law of demand and supply, even human beings have to sell themselves, in urban areas. People go from Bihar, U.P., Bengal etc., to big cities like Bombay and stay alone. It is a regular human problem. Therefore, when there is a demand, you will find that women , poor women, are ready to sell themselves. How do you approach this problem? You should have coordination with your friend, the Health Minister. The growth of venereal diseases in the urban areas is staggering.

AN. HON. MEMBER: What did you do in the last 30 years?

SHRI VASANT SATHE: On every question you bring in the last 30 years. Morarji Desai was there for 20 years out of the 30 years. Let us take the totality.

MR. CHAIRMAN: Kindly confine yourself to the subject and do not get interrupted. You started with Rs. 12 crores. Please go back to the Rs. 12 crores.

SHRI VASANT SATHE: Do you know that this rehabilitation is a subject under this Ministry?

MR. CHAIRMAN: I know that. Therefore, I request you to be brief.

SHRI VASANT SATHE: I am dealing with that.

That has also to be aproached in a practical manner. See to it that these people are treated properly, medical attention is given, that the disease does not spread, that they are educated and rehabilitated, that these girls do not have to sell themselves. This is how the problem has to be tackled.

Then I come to the question of our culture wing. We have the Sangeet Natak Akademi and the Lalit Kala Akademi. You will be surprised to know that both these Akademis have been without a regular Secretary for the last four years. In the Lalit Kala Akademi there is one gentleman who is called Professor, but I am told he has never been a Professor anywhere. He has been working as Secretary.

[Shri Vasant Sathe]

He goes round the country collecting material, photographs and films which he keeps for himself and does not give even a copy to the Akademi. This is the state of affairs.

Not only this. He wrote a book, he wanted the Akademi to publish it and took some advance—Rs. 7,000 for publication and Rs. 14,000 for photographs. When the Akademi came to know about it, they said that they were not going to sanction it and that they did no want to publish that book. When that was done, he tried to have some other body published it, but the amount was not refunded. This is the type of people you have got. And what were the photographs in that book? Photographs of his wife's dancing. But nobody had heard the name of that lady in the country.

Another very surprising thing that struck me is this. I believe the Sangeet Natak Akademi is under the charge of Mrs. Barakataki. But it Sangeet Natak Academy, can you imagine that a Joint Secretary becomes the Vice-Chairman of the Academy? That means the right hand is the giver and the left hand is the taker, because the Chairman is an old lady, a nominal Chairman, a good great lady. All the activities of the Academy are conducted by the Vice-Chairman and that Vice-Chairman happens to be the Joint Secretary of the Ministry. No, this sort of thing is scandalous. Kindly see to it that the evaluation of these two organisations is done. What is their contribution?

MR. CHAIRMAN: You have taken 11 minutes for 10 minutes.

SHRI VASANT SATHE: In between, you took my one minute. I would say that these are imortant academies. Let us have an evaluation regarding them. What have they contributed to the development of dance, drama and music in the last so many years since the Academy came up? Unless there is a proper evaluation made, unless you do something to further encourage new talent in this country, it will not help. This is our latest heritage. I conclude with the famous couplet.

साहित्य संगीत कला विहीन : –
साक्षात् पशु पुच्छ विषाण विहीन :

Therefore, you must encourage these arts. Kindly do not neglect this general education. Of course, we know what mess we are making there, but, at least, in this small field, if we can do something to preserve this heritage to encourage new talent in this country, it will help us. When people from outside come to India, they come to see two things: our spritual heritage and another our cultural heritage of which you are also a great symbol, madam Chairman and I wish your example is followed by others.

श्री श्याम सुन्दर दास (सीतामढ़ी) सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की डिमांडज का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विषय पर कुछ कहने से पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान कल के समाचारपत्रों में प्राकाशित एक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10+2+3 की पद्धति सर्व-मान्य हो गई है और उस को अब लागू किया जायेगा। मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रि यों के सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भी इस को मान लिया है और राज्यों के एजूकेशन बोर्ड अब इस को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल के समाचारपत्रों में, इंडियन एक्सप्रैस में, प्रकाशित हुआ है कि 10+2+3 टु बि स्क्रैप्ड सून, और उस के बदले में 8+4+3 की स्कीम लागू की जायेगी। अखबारों में वर्णित है कि शिक्षा की क्या पद्धति हो और शिक्षा की क्या नीति हो, शायद इस बारे में प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की राय भिन्न है। अगर शीर्ष

स्थानों में शिक्षा के बारे में इस प्रकार भयंकर मतभेद होगा, तो स्वाभाविक रूप से इस मतभेद का असर शिक्षा संस्थाओं पर, शिक्षकों पर और राज्य सरकारों के ऊपर पड़ेगा। दुर्भाग्य से इस देश में शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था रही है जिस में बराबर प्रयोग होते रहे हैं और कोई भी प्रयोग किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। तो इस माने में एक स्पष्ट नीति सरकार की होनी चाहिए और कम से कम जो बाकी चार वर्ष हैं जनता पार्टी की सरकार के उन चार वर्षों में उन नीतियों का कार्यान्वयन होना चाहिए। पांच में से एक तो समाप्त हो चुका है। अब यह मान लेते हैं कि कोई मतभेद नहीं है, अर्थात 10 प्लस 2 प्लस 3 वाला ही लागू होगा।

इन की रिपोर्ट में जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार इन्होंने स्कूल ऐजके अन प्राइमरी एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन पर ज्यादा जोर देने का प्रयास किया है, इस के लिए मैं इन को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पार्टी के वादे को निभाया है। प्राइमरी एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन में कौन सी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं की चर्चा हुई है लेकिन सारी रिपोर्ट को देखने से यह नहीं लगता हैं कि बाधाओं के निराकरण के लिए सरकार राज्य सरकारों के साथ मिल कर कोई स्पष्ट रास्ता निकाल रही है। बल्कि रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं कि स्कूल गोइंग एज के लड़कों में करीब 87 प्रतिशत लड़के स्कूल जाते हैं, लगता है कि वह आंकड़ा सरासर गलत है। बिहार और उत्तरप्रदेश में अगर किसी एक प्रखण्ड का भी सर्वे कराया जाये तो उस से स्पष्ट हो जाएगा कि स्कूल गोइंग एज के इतने परसेंट लड़के हरगिज स्कूल नहीं जाते। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं वे थोड़ी ही उम्र के बाद थोड़ा बहुत कमाने भी लगते हैं। भोजन और आवास की जो उन की आर्थिक विवशता है जिस के कारण वे स्कूल नहीं जाते हैं जब तक उस के समाधान का कोई उपाय नहीं होगा तब तक शायद प्राइमरी एजूकेशन में कोई ज्यादा सुधार संभव नहीं होगा।

जहां तक एडल्ट एजूकेशन में सुधार की बात है, बहुत पहले भी यह बात आई थी, एडल्ट एजूकेशन के लिए तत्कालीन सरकार ने प्रयास किया था। दुर्भाग्य से एडल्ट एजूकेशन के नाम पर देहातों में जो लालटेनें दी गईं और जो स्लेटें बांटी गईं वह पैसा ज्यादातर बरबाद चला गया। मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि एडल्ट एजूकेशन के नाम पर इतनी जो स्कीम लागू करने जा रहे हैं उस का भी यही हाल हो क्यों कि जब तक उस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम ऐडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट फोर्ज नहीं करते हैं, उस की मशीनरी डेवलप नहीं करते हैं और वालंट्री एजेंसीज की तरह की एजेंसी या जो सोशल वर्कर्स हैं उन की जमात से हम संगठित नहीं करते हैं तब तक शायद एडल्ट एजूकेशन पर जो पैसा खर्च होगा वह पैसा शायद बरबाद हो जाएगा और उस का असर सिर्फ प्राइस बढ़ाने पर होगा क्योंकि वह अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर के रूप में चला जाएगा।

जहां तक हायर एजूकेशन का सवाल है, सेकेन्ड्री एजूकेशन में प्लस 2 स्टेज में वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है। यह भी हमारे घोषणा पत्र के अनुसार है और गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार है कि कार्य और शिक्षा में एक संबंध हो। लेकिन दसवीं कक्षा तक अब मैन्युअल लेबर या ब्रेड लेबर की ओर बच्चे की रुचि पैदा नहीं करते हैं तो दो साल उस को वोकेशनलाइजेशन अगर हम देंगे तो शायद उस का वांछित परिणाम नहीं निकलने जा रहा है और अभी तक शायद अधिकांश जो सेंट्रल स्कूल्स हैं या दूसरे भी स्कूल्स हैं उन के शिक्षकों को, वहां के प्राचार्यों को यह पता नहीं है कि यह वोकेशनलाइजेशन किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रिपोर्ट से एक अच्छी बात निकलती है कि कम से कम

[श्री श्याम सुन्दर दास]

नये कालेज खुलने की जो प्रक्रिया थी उसमें रुकावट आई है और जो यूनिवर्सिटीज का एनरोलमेंट है उसमें स्टैबिलाईजेशन हुआ है। बहुत पहले एजूकेशन में 15 परसेंट खर्चा हायर एजूकेशन पर होता था लेकिन इधर एक तिहाई खर्चा हायर एजूकेशन पर होता है। लेकिन हायर एजूकेशन में, खास कर कालेजेज और विश्व-विद्यालयों में अधिकांश जगहों में स्तर में भारी गिरावट आई है। खास तौर से रिसर्च के नाम पर भयंकर भ्रष्टाचार पनप रहा है। पी एच डी और डी लिट में एग्जामिनर और एग्जामिनी, दोनों का ही कामन इन्ट्रेस्ट रहता है। जो गाइड होते हैं उनके लिए भी यह बात रहती है कि उनके अन्तर्गत कितने पी एच डी पैदा हुए। यही एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें दोनों का कामन इन्ट्रेस्ट रहता है। यू जी सी ने रिडर्स और प्रोफेसर्स के लिए पी एच डी कंपलसरी कर दी है जिसके कारण इसमें बाढ़ आ गई है। कई विधान सभाओं में ऐसी जाली थेसिस पेश की गई हैं जिनको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में लाक स्टाक ऐंड बैरल ले कर उस पर डिग्री दी गई है। तो इस तरह की स्थिति रिसर्च क्षेत्र में है। हम देखते हैं कि यू जी सी के कारण यूनिवर्सिटीज को ज्यादा पैसा मिला तो शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है लेकिन उनका वर्कलोड घट गया है। बहुत पहले एक यूनिवर्सिटी टीचर को सप्ताह में 18 क्लासेज लेने पड़ते थे लेकिन आज कई यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी टीचर को सप्ताह में 5-6 क्लासेज लेनी पड़ती हैं। इस तरह से आर्टिफिशल ढंग से स्पेशल पुप्स ने नाम पर स्पेशल कैटेगरी आफ टीचर्स बहाल किए जाते हैं। इस प्रकार से शिक्षकों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है वह घटता है। इस प्रकार से वर्किंग आवर्स तो घटते हैं लेकिन रिसर्च हो नहीं पाती है। इस तरह से जो सारी शिक्षण व्यवस्था है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि प्लानिंग जो हुई उसमें सिद्धांत : कोई दोष नहीं है तो इतना निर्विवाद रूप से मानना पड़ेगा कि उसका जो भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है राज्यों में वह बहुत गलत तरीके से हुआ है। यूनिवर्सिटीज में ग्रुप पालिटिक्स चल रही है, कास्ट रायट्स होते हैं। कम से कम उत्तर भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय किसी न किसी प्रकार के कर्मचारियों की हड़ताल, विद्यार्थियों या शिक्षकों की हड़ताल के कारण बन्द रहते हैं। एक तरफ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री स्वीकार करते हैं कि हायर एजूकेशन को नेतृत्व देने का काम केन्द्रीय सरकार का है यू जी सी के माध्यम से, यदि इस नेतृत्व का कुछ परिणाम होता तो विश्वविद्यालय में शिक्षा स्तर में उन्नति होती, शोध कार्य होते तथा अनुशासित छात्र पैदा होते परन्तु ऐसी स्थिति देखने में नहीं आ रही है। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो जितनी भी आल इंडिया कांपिटीटिव सर्विसेज हैं उसमें यह ठीक है कि पिछले कई वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों का पर्सेन्टेज बढ़ता गया है लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूलिंग के आधार पर जो आंकड़े दिए गए हैं—खासकर यू पी एस सी की 26वीं रिपोर्ट में 75 तक के आंकड़े दिए हैं उसमें बताया गया है कि हर साल सेन्ट्रल स्कूल से शिक्षा पाये हुए लड़कों का प्रतिशत बढ़ता गया है, पब्लिक स्कूल्स की शिक्षा पाये हुए लड़कों का प्रतिशत बढ़ता गया है। सेन्ट्रल स्कूल और पब्लिक स्कूल—दोनों को मिला कर करीब करीब 42-45 परसेंट लड़के कंपीट करते हैं। यह ठीक है कि स्कालरशिप के द्वारा कुछ गरीब आय के लोगों के लड़कों का प्रवेश मिला, लेकिन कुल मिला कर स्थिति यह है कि आज भी जो सामान्य आय के आदमी हैं, उन के लड़कों को केन्द्रीय स्कूलों या पब्लिक स्कूलों में स्थान नहीं मिल पाता है। जिस के कारण

उन को टाप सर्विसिज में स्थान पाने में कठिनाई होती है। इस लिये यह जो एलीटिस्ट ट्रैण्ड डवलेप हो गया है, उस पर कुछ रोक लगनी चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के एफर्टस के साथ एजूकेशनल-प्लानिंग को भी जोड़ा जाए। आप जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज की तरफ जाना चाहते हैं, उस के लायक ह्यूमन पर्सोनल ट्रेण्ड हो सकें, इस तरह की इंस्टीचूशन्ज के निर्माण की दिशा में भी आप को प्रयत्न करना चाहिये, ताकि जिस तरह की अर्थ व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, उस के लिए हमारे पास मैनपावर तैयार हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : सभापति महोदया मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन ही नहीं करता हूं, अपितु इस बात पर खेद भी प्रकट करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय को जितना धन मिलना चाहिए था, उस का यह 10वां हिस्सा भी नहीं है। इस का मूल कारण यह है कि आजादी के पश्चात जिन लोगों के हाथों में देश का भाग्य आया, जिन्होंने इस देश की योजनायें बनाईं, उन के विभाग में इस देश का केवल भौतिक ढांचा ही था, इस देश का जो जीवित ढांचा था, जो भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसका ध्यान उन्होंने नहीं रखा। साधनों की उन्नति पर उन्होंने पूरा बल दिया, रोटी-कपड़ा और मकान का नारा लगाया, लेकिन इन्सानों की उपेक्षा कर दी गई, जिस का परिणाम यह हुआ कि मानव दानव बन गया। इस देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी, कालाबाजार जोर पकड़ गये और सरकार के बनाये हुए ढांचे को इन्सान ने ही समाप्त करना शुरू कर दिया।

देश की शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? देश में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने के लिये 1967 में विचार किया गया और यह विचार किया संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सांस्कृतिक समिति ने। उस का निर्णय था कि भारत में 334 मिलियन लोग निरक्षर हैं, जो विश्व की जनसंख्या का दो-तिहाई हैं। इस लिये यूनेस्को ने सब से पहले अपना कार्य भारत में प्रारम्भ किया। यह स्थिति 1967 की है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ थोड़ा-बहुत काम हुआ, उस में लड़कियों की शिक्षा की तो सर्वथा उपेक्षा कर दी गई। लड़कियों की शिक्षा हो या न हो, लेकिन एक बात मैं शिक्षा मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं—वे इस बात को नोट करें—राष्ट्र की वास्तविक निर्मात्री शक्ति यदि कोई है, तो वह "माता" है। उस के निर्माण करने से केवल एक परिवार ही नहीं बनता, अपितु एक बहुत बड़ा समाज बन जाता है। परन्तु खेद इस बात का है कि हमारे यहां न केवल राज्यों में, बल्कि केन्द्र में भी लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज व्यवस्था इस प्रकार की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा तो उन्हें कहीं-कहीं मिल जाती है, लेकिन हाई-स्कूल का तो नाम ही नहीं है, बड़ी ही दयनीय अवस्था है। भारतवर्ष के सामने आज शिक्षा की उपेक्षा का जो कुपरिणाम आया है, इस के लिये मैं खास तौर से कहना चाहूंगा—भारतवर्ष का प्रजातन्त्र आज खतरे में पड़ गया है। आज भारतवर्ष का प्रजातन्त्र एक ढोंग, एक तमाशा है। इस समय प्रजातन्त्र का जो ढांचा खड़ा किया जाता है, उस में इलैक्शन्ज होते हैं और ये इलैक्शन्ज जातिवाद के आधार पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रान्त के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर,

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

होते हैं। उसी आधार पर लोग चुन कर आ रहे हैं और यही चीज आज हमारे देश को खा रही है। जितनी भी योजनायें हम बनाते हैं, हम को जनता का सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जनता, जो इस देश की अपढ़ जनता है, वह उन योजनाओं को समझ नहीं पाती है, राजनीतिक सिद्धान्तों को नहीं समझती है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में उन को अन्तर नहीं मालूम है। इन्दिरा गांधी अगर जबर्दस्ती नसबन्दी न कराती तो तानाशाही चलती रहती। इस देश को कोई चिन्ता की बात नहीं थी क्योंकि जनता को जानकारी नहीं है। इसलिए अगर देश को बचाना है, इस देश के आर्थिक ढांचे, सामाजिक ढांचे और प्रजातन्त्रिक ढांचे की रक्षा करनी है तो, सरकार को शिक्षा पर अधिक बल देना होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि फर्स्ट प्लान में जबकि शिक्षा पर बजट का 6 परसेन्ट एलोकेशन था, उस के बाद वह एलोकेशन 5 परसेन्ट हुआ, फिर 4 परसेन्ट हुआ और अब यह घट कर 3.5 परसेन्ट हो गया है। इस का मतलब यह है कि हम ने अपनी भूल का सुधार नहीं किया है। मेरा कहना यह है कि बजट का 10 परसेन्ट हमें एजूकेशन पर खर्च करना चाहिए और जब तक इस देश में अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी, तब तक प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने की आप घोषणा नहीं करेंगे, तब तक यहां काम नहीं बनेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आप ने आर्थिक क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी घोषणा कीजिए। इस प्रकार से हम देश के मानव समाज को, मानव राष्ट्र को बना कर खड़ा करेंगे। केवल पत्थर की सड़कें और हवाई जहाज बनाने में ही हमारा धन खर्च हो रहा है। जो उन का प्रयोग करने वाले हैं उन की उपेक्षा की है। आज हम कुत्तों की नसल सुधारने में लगे हैं, बिल्लियों की नसल सुधारने में लगे हैं, सांड और घोड़े की नसल सुधारने में लगे हैं और अनाज की नसल हम बनाने जा रहे हैं लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ओर हमारा ध्यान नहीं है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। तो मैं यह कहता हूं कि स्कूल में जो बच्चे जा भी रहे हैं, उन में से जो ग़रीब आदमी हैं, जिन के पास खाने का कोई साधन नहीं है, वे ग़रीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते। स्कूल में भर्ती हो जाने के बाद, प्रवेश पा जाने के बाद 74 परसेन्ट बच्चे आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, काश्मीर, जम्मू, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में निकल कर चले जाते हैं। लड़कियों में इस देश में केवल दो-तिहाई को स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। निर्धन परिवारों के बच्चों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी ओर मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश को जो सब से बड़ा खतरा है वह ग़रीबी और निरक्षरता से है।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप को देश का विकास करना है, तो आप को इन की साक्षरता की तरफ़ ध्यान देना होगा, इन की एजूकेशन की ओर ध्यान देना होगा। यह एक धन्यवाद की बात है कि सरकार का इस ओर ध्यान गया है और सरकार ने यह ऐलान किया है कि हम पांच वर्षों में 100 मिलियन लोगों को साक्षर बनायेंगे लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अगर 100 मिलियन साक्षर आप बनाएंगे तो 100 मिलियन जो छोटे बच्चे हैं वे निरक्षर पैदा हो जाएंगे। इसलिए दोनों को आप साथ साथ ले कर चलें। जो प्रौढ़ हैं उन को साक्षर बनाइए और जो बच्चे हैं उन को अनिवार्य शिक्षा आप दीजिए ताकि बीमारी आगे पैदा न हो। इसलिए मैंने इन बातों की तरफ़ आपका ध्यान खींचा है। इसके अलावा भेदभाव को खत्म करने के लिए जो आप के पास महत्वपूर्ण योजना है, उस को आप खत्म न करें।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप प्रौढ़ शिक्षा को जल्दी करना चाहते हैं, तो बच्चों की शिक्षा में और प्रौढ़ों की शिक्षा में आपको अन्तर करना होगा। छोटा स्वरूप बना कर साक्षर बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इन सब चीजों को आप ध्यान कर लीजिए और सब चीजों को ध्यान में रख कर मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि साक्षर बनाने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए युद्ध स्तर पर आप को योजना बनानी होगी। गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर सकेगी। आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य पार्टियों का सहयोग इसमें लेना होगा। स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों का भी सहयोग ले कर ही इस काम को चलाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक शिक्षा सेना का गठन करना होगा। जिस तरह से आपने देहातों में काम दिलाने के लिए सेना गठित करने का प्रस्ताव किया है, उसी प्रकार की आप शिक्षा सेना भी बनाइये। जिस तरीके से रूस और चाइना में यह बनायी गयी, उसी तरीके से यहां भी बनाइये।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि रूस में जब 1920 में क्रान्ति हुई, 80 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। रूस वालों ने 1930 और 1940 तक अपने यहां लोगों को पूर्ण साक्षर बना कर खड़ा कर दिया। इसी तरह से चाइना में स्कूल बन्द कर पठित लोगों को देहातों में भेज दिया गया और उनको कह दिया गया कि तुम सब लोगों को साक्षर बनाओ। उन्होंने कहा कि अगर एक साल पढ़ाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं हो जाएगी। आप भी यह कर सकते हैं। जिस समय जनता पार्टी का उदय हुआ, जिस समय देश में परिवर्तन आया, उस समय इस देश में बड़ा जोश था। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार उसका लाभ नहीं उठा पायी अन्यथा इस देश में एक बड़ा आन्दोलन साक्षरता के लिए चलाया जा सकता था।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि आपको इस काम के लिए बोर्ड बनाने होंगे। केन्द्र स्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, सभी स्तरों पर शिक्षा बोर्ड बनाने होंगे जो लोगों को साक्षर बना सकें। आपको एक नारा भी लगाना होगा कि एक पठित आदमी कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाये। जब तक इस देश में यह नारा नहीं लगाया जाएगा तब तक यह समस्या दूर नही होगी।

MR. CHAIRMAN: It is time for you to conclude now. Mr. Tyagi.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आप शर्त लगा दीजिए कि हर पठित व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनायेगा।

MR. CHAIRMAN: I have got a long list. Please co-operate. Others have also to speak.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं दस जमा दो जमा तीन शिक्षा पद्धति के बारे में कहना चाहूंगा कि शिक्षा का ढांचा आप इस प्रकार का बनाइये जिससे उसमें योग्यता आये। अब तक नौकरी दिलाओ शिक्षा पद्धति ही आपके सामने रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आठवीं कक्षा तक की शिक्षा बहुत आवश्यक है। उसके बाद विद्यार्थी यदि बुद्धिमान है तो उसे कालेज या यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, नहीं तो उसे औद्योगिक क्षेत्र में भेजा जाए। आठवीं कक्षा के बाद ही उसे वहां ले जाइये, उसके दो साल खराब मत कीजिए। इस प्रकार की शिक्षा जो इंसान को इंसान बनाये, अपने स्कूलों और कालेजों में चलाइये। मुझे खुशी है कि आप इस प्रकार की योजना भी बना रहे हैं।

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

सभापति महोदया, मैं एक बात कह कर खत्म करना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: I am sorry, I had requested you....

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Two minutes more, Madam.

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपने मेरे लिए घंटी बजा दी। बस मैं एक मिनट में खत्म कर देता हू। वोकेशनल स्कूल की आपने स्कीम बनायी है। क्या आप केवल मौखिक रूप में ही उन्हें शिक्षा देंगे? उनकी ट्रेनिंग कहां होगी, यह सब व्यवस्था भी आपको करनी होगी।

सभापति महोदया, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत का प्राचीन इतिहास नामक पुस्तक मेरे सामने है।

MR. CHAIRMAN: All your points seem to be the last point. I am sorry, Mr. Tyagi.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यह प्वाइंट मैं निश्चित रूप में कहूंगा, इसे कहे बिना मैं मानूंगा नहीं। इस देश में इतिहास गलत पढ़ाने का आन्दोलन चलाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है कि आर्य लोग गो मांस खाते थे, बहिन भाई का भी यौन सम्बन्ध होता था। यह ऊट पटांग बकवास हमारे देश में की जा रही है। यह 11वीं क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक पढ़ायी जा रही है जिसमें हमारे साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा जा रहा कि हम लुटेरे थे, डाकू थे, बहिन भाई का यौन सम्बन्ध होता था, हम गो मांस खाते थे, अतिथियों को गो मांस देते थे। इसके बारे में मैंने शिकायत भी की है। एक मेमोरेण्डम भी हमारे पास आया है कि इतिहासकारों की कलम पर रोक लगायी जाए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Such an important point should have been mentioned by you earlier. Please conclude now.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आर्य लोग बाहर से आये, कहां से आये, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म के साथ यह छेड़खानी क्यों, दूसरे धर्मों के साथ क्यों नहीं? हमारा देश सेक्यूलर स्टेट है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाये अन्यथा इसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू होगा।

MR. CHAIRMAN: I am sorry, please conclude Mr. Tyagi.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am sorry. Mr. Tyagi, you are behaving like this. I would request Hon. Members not to intrude on the time of other Hon. Members, who also have important things to say.

Now, Shri Sunna Sahib.

*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat): Madam Chairman, within the time of ten minutes, I will have to speak in the speed of rushing waters from a mount to a meadow.

It is an accepted fact that illiteracy is the stumbling block for any progress in the country. I need not stress the inevitable that education is the basis for all social growth. Yet, even after 30 years of our independence, we find that primary education is being neglected. In 1976-77 the enrolment in the age-group of 6—11 was 675.30 lakhs, i.e., 80.9 per cent. In the age-group of 11—14 the enrolment

*The original speech was delivered in Tamil.

dwindled to 170.08 lakhs, i.e., about 37 per cent only. I refer to this to emphasise the extent of droppage of school-going children and the main reason for such a serious slippage is economic backwardness. This has hampered our social progress considerably. This problem of droppage heightens the need for providing more educational amenities to children in the age-group of 6—11. Should I say that this droppage doubles the rate of illiteracy in our country? These two aspects must guide our financial allocation for primary education. I am appalled at the size of baggage of books being carried by children of 2 feet in height. I am sure that their physical and mental growth would be stunted if they are to cramp up all these books. Similarly, I am sorry that the researchers should come out with so many contradictory conclusions about 10 plus 2 plus 3 or about 8 plus 4 plus 2 and make the blossoming buds of humanity the victims of their whims and fancies. We have had a galaxy of Commissions like Sir C. P. Ramaswami Aiyar Commission. Dr. Radhakrishnan Commission. Sir Ramaswami Mudaliyar Commission etc. and now the last was that of Malcolm Adiseshiya, supplemented by the efforts of Ishwarbhai Patel. Both of them are Vice-Chancellors of Universities, who have given their considered views about 10 plus 2 plus 3 system of education. I wonder what shape their recommendations will take at the time of implementation. I would suggest that vocationalisation should be the sole criterion for any pattern of education and that alone will help the nation in future.

Coming now to women's education, you will find that the droppage among girls is as high as 75 per cent and this is due to various reasons. I regret that the hands that feed the future generation of the country should be shackled like this.

17 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

Our Madam Chairman, Shrimati Parvathi Krishnan and our Minister of State for Education must exert all their energies in getting equal status for women in the country. In 1968 a National Committee was constituted to study the status of women in the country. Its Report has come and some lip-sympathy has been paid about the recommendations of this Committee in the form of a Resolution. The poet-patriot of Tamil Nadu Bharathiyar used to sing that no country in the world is equal to India in honouring women. The women of the country should get equal status and that can be achieved only by providing more educational opportunities to girls which will reduce droppage substantially.

I will in brief refer to education of minorities, scheduled tribes and castes. It is not enough to sing Vaishnavo Janata. The other day in reply to a question of Shri Kanwarlal Gupta, it was stated that 15 per cent reservation had been given to Scheduled Tribes. That is not enough. For example, in Uttar Pradesh 150 lakhs of Muslims are living and 25 per cent of India's Muslim population is living in U.P. The U.P. has elected the largest number of Muslims to this House also. Yet in the Muslim Colleges and Schools in the U.P. 50 per cent students belong to non-Muslim communities. I welcome it. I am saying this only to show that the main reason for 50 per cent non-Muslim students in Muslim Colleges and Schools is the economic backwardness of this minority community. This urges the need for more educational facilities to children of this minority community. I am sure that the hon. Minister will bear this while formulating his financial allocations.

My hon. friend Shri Sathe referred to dismal functioning of Sangeet Natak Akademi and Lalit Kala Akademi. I would in particular refer to a Tamil Book which got the prestigious award of Sahitya Akademi. I am sorry to say that this Book does not deserve such a national award. This reveals

[Shri A. Sunna Sahib]

the fact that the people who are adept in the nuances of language and culture of the region have not been associated in the selection of books for award. Such a book which I have read and none has any word of appreciation for it has got the award.

I would refer to another important facet of this Ministry's functioning. I am sorry to say that the sportsmen who bring honour to the country are not honoured properly. If they let down the nation in international events we do not hesitate to condemn them. For example, Michael Feriera who is an International Champion of Billiards, was not given permission to go abroad for competing in an international event. He went on his own with his father's encouragement. He brought laurels to the nation. He won the Championship in Newzealand and even the congratulory message from our President was not conveyed to him. When he came back his creditable victory was not recognised and no reception was sponsored by the Sports Wing of the Ministry. It must be borne in mind that the Sportsmen of the nation are the real muscle of the nation and they must get their due.

I will now refer to the callous attitude of the Archaeological Department towards national monuments in the country. I say this from my experience of the ancient monument of a Fort in my constituency Palghat, which is 400 years old and which is claimed to have been constructed by Tipu Sultan. Previously the region of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka was one zone for protecting and maintaining national monuments. When Karnataka found that its monuments were being neglected, it secured a separate zone after a long struggle and now the ancient monuments in Karnataka are being well looked after. Unfortunately the Fort in Karnataka is in a stage of decay and no attention has been paid to its upkeep. I demand that adequate attention be paid to monuments like the Fort in Palghat by the Archaeology Department.

Lord Krishna says in Gita:

Pavitranaya Sadhunam Vinasayacha
Dushkradham Dharma 'santhapanarthaya sambhavami yuge yuge

To protect the good from the increasing predators of evil God takes birth on earth. Similarly, when illiteracy increases, leading to multiplication of distress among the people, the Government of India should come to rescue them and give succour and shelter in the form of more educational amenities. It is not enough to talk of education. Education must become universal. I know that the Central Government does not possess *Akshayapatram—a* vessel which never goes empty—for allocating as much money as Education needs. Yet Education must get more funds as educational growth is the key to social growth, and a nation is judged by its educational achievements.

With these words I conclude my speech.

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति के अनुदानों पर यहां बहस चल रही है। इस सम्बन्ध में पहली बात मुझे यह कहनी है कि जो शिक्षा प्रणाली इस देश में चल रही है, उसके चलते इस देश का उद्धार संभव नहीं, क्योंकि इस प्रणाली का जहां यह तरीका होना चाहिये था कि वसुधैव कुटुम्बकम् हो सत्य और प्रेम और करुणा का प्रसार एवं, प्रचार हो, सत्यम् शिवम सुन्दरम् की अनुभूति से मानव मानव के प्रति सजग हो, वहां मौजूदा शिक्षा प्रणाली के चलते असत्यम राक्षसम् सुन्दरम् की कहावत चरितार्थ हो रही है। पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली का ही

कम है कि सारे देश में, शिक्षा जगत में आज अशांति का वातावरण फैला हुआ है, कहीं शांति नहीं है। सारे का सारा शिक्षा जगत अपने भविष्य के प्रति आशंका से त्रस्त दिखलाई पड़ रहा है।

मेरा कहना यह है कि शिक्षा भाषा के जरिये आती है। हिन्दुस्तान में नये सिरे से नहीं, बल्कि सही मायनों में तो 15 अगस्त, 1947 को ही वह काम हो जाना चाहिये था। हमें अपनी भाषा नीति पर पुनर्विचार करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो माता-पिता अपने बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ाने लिखाने लग जाते हैं, वह अपना तथा राष्ट्र दोनों का द्रोह करते हैं। महात्मा गांधी की यह उक्ति सही है।

महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलने वाली एक पहली सरकार भी थी। मैं तो उस सरकार को सरकारी गांधीवाद की संज्ञा देता हूं। उस सरकारी गांधीवादियों ने भाषा के सवाल को जिस तरह से उलझाया, शिक्षा के सवाल को जिस तरह से सुलझाया, उसका ही यह कुफल है जो आज देश भोग रहा है। मैं आज कहना चाहता हूं कि भाषा का सवाल सर्वप्रथम हल होना चाहिये था, क्योंकि माता को कहने लगें कि किसी माता के बारे में भी किसी को शक हो कि वह माता उचित नहीं है, इस माता से भी गलत काम हुए हैं तो यह ठीक नहीं है। मां के दूध को जो बच्चा पीता है उससे ही वह पुष्पित और पल्लवित होता है। मां के दूध में जीवन दायिनी और आनन्ददायिनी जो शक्ति है, वह और कहीं नहीं है। लेकिन पिछले 30 वर्षों में महात्मा गांधी की उपेक्षा की गई।

मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मेरे दोस्त तमिल में भाषण कर रहे थे। मैं तो उस दिन को देखना चाहता हूं जब कि लोक सभा में आने पर किसी को लगे कि यह हिन्दुस्तान की सभा काम कर रही है, आज लोक-सभा में जब लोग आते हैं तो कभी-कभी मेरे जैसे लोगों से यह कहते हैं कि क्या यह अंग्रेज सभा है? इस बात से दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि तीस बरस बीत जाने के बाद भी इस देश में यह शिक्षा प्रणाली जारी है और इस के कुफल देखने को मिल रहे हैं।

अंग्रेजी की शिक्षा ने हमें निकम्मा और नकलची दोनों बना दिया है। हम इतने निकम्मे और नकलची हो गये हैं कि आप चले जाइये किसी निचली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में; सब अदालतों में नजीरें पेश की जाती हैं कि अंग्रेजी कोर्ट का यह फ़ैसला है। कोई कभी यह नहीं कहता है कि रूस, चीन या जर्मनी की अदालतों का यह फ़ैसला है। अंग्रेजी के जरिये भोंडी नकल और छिछोरचीपन का काम हिन्दुस्तान में चल रहा है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): पार्लियामेंट में भी ऐसा ही है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह: पार्लियामेंट में भी शायद उसी के जरिये चल रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकभाषा के बिना लोकतंत्र प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के लिए लोकभाषा जरूरी है। लोकमत की सही अभिव्यक्ति लोकभाषा के बिना नहीं हो सकती है। लोक सभा को तीस वर्ष तक चलने के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली का कुत्सित परिणाम यह हुआ कि इस देश में 25 जून, 1975 को तानाशाही आई।

गांधीजी ने भी कहा था कि अंग्रेजी के व्यामोह से हमें पिंड छुड़ाना पड़ेगा, जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक स्वराज्य का कोई मतलब नहीं होगा और अंग्रेजी से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है।

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

संविधान सभा में इस विषय पर काफी चर्चा हुई और संविधान लिखते समय यह व्यवस्था की गई कि पंद्रह वर्ष के अन्दर-अन्दर सार्वजनिक जीवन से, सार्वजनिक प्रयोग से अंग्रेजी का खात्मा होगा। हां, पढ़ाई-लिखाई में अगर कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहे तो, वह पढ़ सकता है। मेरे ख्याल से शायद पहली गलती संविधान सभा की थी कि इस बारे में पंद्रह बरस की अवधि निश्चित की गई। इसी कारण पंद्रह बरस के बाद लोक सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक चलती रहेगी—उस लोक सभा ने यह प्रस्ताव पास किया, जिस की अपनी अवधि केवल पांच साल की थी।

जब आयरलैंड अपनी स्वाधीनता की पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो वहां की सरकार ने पहले ही से अपनी भाषा, गेलिक, को चलाया। इसी तरह इसरायल ने हेब्रु को चलाया—बिना इस बात का अन्दाज किये कि हेब्रु लायक है या नालायक है। जो हेब्रु एक हजार बरस से मरी पड़ी थी, इसराइल ने उस को उजागर किया और उस के जरिये वहां का राजकाज चला। इंडोनेशिया ने भी यही काम किया।

संविधान सभा द्वारा जो पंद्रह बरस का समय दिया गया, उस समय में अंग्रेजी परस्त राजनीतिज्ञ इकट्ठे हो गये। राजनीति, व्यापार और नौकरशाही के त्रिगुट ने इस देश में अंग्रेजी को इस लिए चलाना चाहा इन तीस सालों में जो रंक से राजा बन गये थे, उन के राजा बनने की कहानी पर पर्दा पड़ा रहे, इस देश के भ्रष्टाचार और बेईमानी पर पर्दा पड़ा रहे। आज उन लोगों की इस नीति को मिटाने का समय आ गया है। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस नीति पर पुनर्विचार करें।

इस नीति पर चलने का यह कुफल है कि आज जनता की पीठ पर सरकार बैठी हुई है और सरकार की पीठ पर अफ़सर बैठे हैं, जबकि लोकतंत्र में जनता को बैठना चाहिए था सरकार की पीठ पर और सरकार को बैठना चाहिए था अफ़सर की पीठ पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, उल्टा हो गया है—जनता की पीठ पर बैठ गई सरकार और सरकार की पीठ पर बैठ गये अफ़सर, क्योंकि अफ़सर अंग्रेजी की गिटपिट अच्छी करते हैं, अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं।

1941 की जनगणना के अनुसार इस देश में 1.3 प्रतिशत अंग्रेजीदां थे और 1971 की जनगणना के अनुसार 2.4 प्रतिशत। यहां पर प्रतियोगितायें भी अंग्रेजी में होती हैं, मिलिटरी का अफ़सर या कलेक्टर वह हो, जो अंग्रेजी बढ़िया बोलता है। यह नहीं कि हवाई जहाज बढ़िया चला सकता है, कौन बढ़िया बम फेंक सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या नैपोलियन और रोमेल अंग्रेजी के जरिए अपनी लड़ाई में बहादुरी प्रकट किये थे? कदापि नहीं। लेकिन यहां नौकरियों में इस तरह की व्यवस्था होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नौकरियों में अंग्रेजी का खात्मा किया जाय और अंग्रेजी की जगह पर प्रादेशिक संरक्षण दिया जाय। अनुपात के हिसाब से तमिलनाडु की जनसंख्या जितनी है उतनी नौकरियां वे तमिल में भी परीक्षा दें तो उन को दी जाय। आज त्रिभाषा फारमूला चलता है अंग्रेजी, हिन्दी और एक दूसरी भाषा का। मैं समझता हूं कि इस भाषा ज्ञान में हिन्दुस्तान के दिमाग को चक्कर कटवाया जा रहा है और विषय ज्ञान अधूरा रह जा रहा है। जो टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम है उस में दर्जा 8 तक 14 विषय पढ़ाए जाते हैं। क्या एक छोटे नन्हे बच्चे का दिमाग 4 विषयों को सीख सकता है और वह सीखता है तो क्या 14 विषयों के इस बाज़ व्हाट के चक्कर में उस का दिमाग असंतुलित नहीं हो सकता? अभी तो यहां दस

पर ह मेम्बर बोलते हैं तो मंत्री लोग भूल जाते हैं कि वह सदस्य क्या बोल गए और 14 विषयों को पढ़ाने की कार्यवाही दर्जा 8 तक चल रही है, मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बहुत ही अनुचित है।

प्रावधिक एवं विज्ञान और उद्योग में जापान तथा पश्चिमी जर्मनी सब से आगे हैं, लेकिन वे भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते। आज भाषा ज्ञान पर ज्यादा समय लगता है, विषय ज्ञान पर समय कम लगता है और यही कारण है कि हिन्दुस्तान का राकेट छूटने की नौबत सब से पीछे आई और रूस का राकेट सब से पहले छूटा क्योंकि इस ने रूसी भाषा में अपना काम शुरू कर दिया था।

आज मैं शिक्षा मंत्री जी से निहायत शदब और अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत: खण्डे आर्यावर्त्ते तक बढ़ा हुआ था वह आज सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा रह गया, इस के भी कारण में अगर जाएंगे तो यही चीज पाएंगे।

कौवा आजाद रहता है क्योंकि वह अपनी बोली बोलता है और तोता पिंजड़े में जकड़ा जाता है क्योंकि वह बोल बेटा सीताराम, सीताराम बोलता है। यह बोल बेटा सीताराम की जो कहावत चलती है यह यहां से चलती है। आज यह देश एक परतंत्रता से तो जरूर छूटा लेकिन कई प्रकार की परतंत्रताओं में जकड़ गया है और जो इतना बड़ा देश था वह सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा बन गया है।

लार्ड मैकाले ने 1835 में इस अंग्रेजी की स्थापना की और हिन्दुस्तान की भाषा को दीन हीन और दरिद्र बता कर के की क्योंकि वह जानता था कि अंग्रेजी के जरिए इस देश में राज चलाया जा सकता है। गोली के जरिए तो कभी कभी राज चला करते हैं, अकसर तो बोली के जरिए राज चला करते हैं। करोड़ों लोगों को हीन भावना से ग्रस्त किया जाता है कि राज की भाषा तो दूसरी है और वह भाषा तो हम बोल नहीं सकते इसलिए राज काज भी नहीं चला सकते। इसी अंग्रेजी के चलते ब्रिटिश काल में हिन्दुस्तान की जो शिक्षा थी वह दस प्रतिशत रह गई थी।... (व्यवधान)......

मैं समाप्त कर रहा हूं। नौकरियों में मैंने कहा कि प्रादेशिक अनुपात में सब चीजें मिलनी चाहिएं। प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दुस्तानी को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। त्रिभाषा फारमूला समाप्त करना चाहिए। इस की जगह पर द्विभाषा फारमूला चलाना चाहिए। शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए। आज की शिक्षा क्या है? इस शिक्षा के चलते बेरोजगार बढ़ रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी 4 करोड़ बेरोजगार छोड़ कर चली गई। बड़ा तीर मारती हैं कि हम ने यह कर दिया, जनता पार्टी कुछ नहीं करती। जो चार करोड़ बेकारों की शिक्षा प्रणाली को दे कर जाने वाली हैं वह भी आज कहती हैं कि हम ने बहुत ही तीर मारा है। आज तीस करोड़ बालिग अशिक्षित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। आज शिक्षा अनिवार्य नहीं है और निःशुल्क भी नहीं है। शिक्षा दसवें दर्जे तक अनिवार्य होनी चाहिए। निरक्षरता और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहिए। सम्पूर्ण देश के अन्दर पाठ्यक्रम और शिक्षा के क्रम में एकरूपता होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कुछ है, बिहार में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है, तमिलनाडु में कुछ है, बंगाल में कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का विकास इस दृष्टि से हो कि

[श्री चन्द्र शेखर सिंह]

हिन्दुस्तान की आत्मा और प्रणाली दोनों में परिवर्तन हों। क्योंकि आखिर इसी शिक्षा प्रणाली का तो नतीजा है कि रोजाना माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि फलां जगह हड़ताल हो गई, सारे उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में हड़ताल हो गई। काशी विश्वविद्यालय में हड़ताल हो गई और शिक्षा मंत्री के बार-बार कहने के बाद भी काशी विश्वविद्यालय में आज तक कोई वाइस चांसलर नहीं गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा नीति पर पुनर्विचार कीजिए, शिक्षा नीति को बदलिए। इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन कीजिए कि देश के सोचने के तरीके में आमूल परिवर्तन हो। जब तक देश के सोचने के तरीके में आमूल परिवर्तन नहीं होगा आप बजट बनाते रहेंगे, कभी दो प्रतिशत खर्च करेंगे, कभी पांच प्रतिशत खर्च करेंगे और कभी दस प्रतिशत खर्च करेंगे परन्तु होगा कुछ नहीं। कल यहां सदन में किसी ने कहा था क्या 50 रुपए में संतोष है तो उसका जवाब था क्या तीन हजार में संतोष है। तो संतोष पैसे से नहीं होगा, संतोष प्रणाली से होगा। पैसा कम भी रहता था लेकिन इस देश की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भारत दुनिया का गुरु था, भारत ने दुनिया को संदेश दिया था। इसलिए सवाल पैसे का नहीं है, सवाल नीति का है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया प्रताप चन्द्र चन्द्र की तरफ देख रही है और उनसे पूछना चाहती है :

रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में
अब तो तेरे दिल की चर्चा गैर की महफिल में है।

आपकी जो चर्चा चारों तरफ है उस चर्चा के अनुरूप आप शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कीजिए—यही आपसे मेरा निवेदन है।

इन शब्दों के साथ, जो अनुदान पेश किया गया है उसका तबीयत से तो नहीं, अब मार कर समर्थन कर रहा हूं।

श्री चिरंजी प्रसाद (बांसगांव) : माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने शिक्षा, समाज कल्याण, संस्कृति विभाग के अनुदानों पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। यह बड़ी बिडंबना की बात है और हम सभी लोग जानते हैं कि घर में जो बेटा कमाने वाला होता है उसको मां भी प्यार करती है। शिक्षा विभाग कमा कर देने वाला विभाग नहीं है जैसे कि अन्य विभाग हैं। शिक्षा विभाग केवल देश के लिए विद्वान, वैज्ञानिक और अन्य प्रकार के लोगों का सृजन करता है लेकिन यह कहा जाए कि वह कमा कर दे तो मुझे बड़ा दुःख होता है। वह तो बजट कम हुआ है उससे शिक्षा की बड़ी अवहेलना हुई है। यह विभाग जो एक बड़े ईमानदार मंत्री के हाथ में दिया गया है उससे हमारी बड़ी-बड़ी आशाएं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो शिक्षा के स्तर रखे गए हैं—प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा—इसमें जो नींव है वही बड़ी कमजोर है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब से मानव नशान हुआ होगा, जब से उसने अनुभूति प्राप्त की होगी, वस्तुओं को छू करके और सूंघ करके अनुभूति प्राप्त की होगी लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज देश का दुर्भाग्य है कि प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या आज इतनी कम है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज भी प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है वह मात्र दिखावा है। वह सही आंकड़े नहीं हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं, मैंने स्वयं जाकर देखा है वहां पर रजिस्टर में लड़कों की जो संख्या दर्ज होती है वह संख्या मौके पर नहीं होती है। इसका कारण यह है कि वहां जो अध्यापक होते हैं वे दूर जाना नहीं चाहते हैं। वे लड़कों की संख्या तथा छात्र प्रगति को बढ़ा चढ़ा दिखाकर अपने घर के निकट ही रहना चाहते हैं। इस संबंध में जो एस डी आई रखे

जाते हैं उनका भी मिला हुआ व्यवहार होता है। इसके चलते आज तीस वर्षों के बाद शिक्षित लोगों की संख्या इतनी कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा पाने वाले जो बच्चे हैं उनका अधिकांश समय बड़े घरों में पाखाना साफ करने में बीत जाता है। उनके कपड़े बर्तन धोने में व मजदूरी करने में बीत जाता है। मैं आप के माध्यम से इस सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ऐसे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन को ऐसी जगहों पर न जाने दिया जाय, उन को इसी स्तर पर निश्चित रूप से प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा देनी होगी, अन्यथा बाद में प्रौढ़ बना कर फिर से नये ढंग से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो वह गलत होगा। हम को चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था में ही उन को रोकें, शिक्षा दें, ताकि आगे जा कर प्रौढ़ शिक्षा के लिये हमें अधिक धन न खर्च करना पड़े, अधिक परिश्रम न करना पड़े।

2 अक्तूबर, 1978 से प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की स्कीम है, ताकि देश में जितने प्रौढ़ अशिक्षित हैं, वे शिक्षित हो जाएं, इस के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बात—माध्यमिक शिक्षा की है। बहुत कोशिश कर के शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्रयास किया। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी अधिकार या स्वायत्ता की बात को स्वीकारा गया है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं—इस देश में एक समान कार्य करने वाले लोगों के लिए जब तक एक समान वेतन, एक समान सुविधाएं नहीं होंगी, चाहे उन के बच्चों के लिए हों, मैडिकल सुविधाएं हों, या अन्य सुविधाएं हों तब तक समानता नहीं आएगी, भिन्न-भिन्न स्तरों के नागरिक इस देश में बने रहेंगे। कोई भी आदमी चाहे नीचे स्तर का हो या ऊंचे स्तर का हो, वह इस देश का है, सब खाना खाते हैं, सब को साथ-साथ रहना है, इस लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं—इस असमानता की दूरी को खत्म करना होगा। शिक्षकों के विषय में अभी प्रदेशों में अनेक हड़तालें हुई हैं, लाठी-चार्ज हुए हैं—आप को इन चीजों पर विचार करना होगा और शिक्षा को समवर्ती सूची में ला कर ही इन विद्वद जनों का उपकार करना होगा।

जहां तक उच्च शिक्षा की बात है—अभी अनेक माननीय सदस्यों ने भी कहा है—जब तक नीचे से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का तकनीकी ढंग से, व्यवसायिक ढंग से विकास नहीं किया जायगा, तब तक काम नहीं चलेगा। यदि हम सब को नौकरी के योग्य बनाते जायेंगे तो सब को काम नहीं मिल सकेगा। देखने में ऐसा भी आता है कि जिन के घरों में अच्छी आमदनी है, बहुत बड़ा फार्म है, 10-10 मजदूरों को रख कर काम कराते हैं, लेकिन स्वयं 100 या 150 रुपये की नौकरी करना चाहते हैं। मेरी यह स्पष्ट राय है कि ऐसे लोग जिन के पास खाने-पीने की कमी नहीं है, धन-धान्य से सम्पन्न लोग हैं, उन को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ही लोगों के बच्चे 100–150 रुपये महीना खर्च कर के केन्द्रीय विद्यालय या पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाते हैं और हमारे घरों के लोग, जिन को टाट-पट्टी ले जा कर पढ़ना पड़ता है, उन को शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जब तक इस देश का बुद्धिजीवी तबका इस ओर नहीं सोचेगा, सब को समान लाइन में ला कर, समान अवसर दे कर नहीं दौड़ाया जायगा, तब तक इस देश में दो किस्म के नागरिक बने रहेंगे—एक शासक होगा और दूसरा शोषित होगा। इन के अलावा और कोई नहीं हो सकता।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं—कहीं-कहीं पर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण और समाज कल्याण

[श्री फिरंगी प्रसाद]

से संबंधित कुछ स्कूल चलाये जाते हैं, उन की दशा बहुत गिरी हुई है, उन की दशा को सुधारने की जरूरत है। इस तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाय।

शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। जहां 10+2+3 का फार्मूला चल रहा है, वहां 8+4+3 का भी उल्लेख हुआ है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इस पर आम विचार करें, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक निश्चित नीति तय की जाय, ताकि सब को सन्तोष हो सके कि आप इस देश की शिक्षा पद्धति को अमुक रास्ते पर चलाना चाहते हैं।

एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं—इस का संबंध विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री से है। मैंने एक पत्र केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा था, जिस का नम्बर है—14-5मी 177-स्कूल (5) ता० 30 दिसम्बर, 1977। यह विषय प्रदेश की सरकार से जांच हो कर भी आ गया है। मैंने इस पत्र में लिखा था कि किसी व्यक्ति ने फर्जी और गलत ढंग से गोरखपुर यूनीवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन आज तक उस का निरसन नहीं हो सका। यदि ऐसी परम्परा या कार्य-पद्धति चलती रही तो गलत तरह से डिग्री लेने वालों का मन बढ़ता रहेगा और जो सही ढंग से पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, उन की उपेक्षा होती रहेगी।

जहां तक स्कूलों और कालिजों में हड़ताल की बात है—मैं अभी हाल में गोरखपुर गया था और वहां कुल-सचिव से मिला था। मैंने वहां देखा, यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों को, मार्च का महीना समाप्त हो रहा है, मिलनेवाली दूर की सुविधायें अभी तक नहीं मिली हैं। इस पर लड़के बिगड़ जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी यह कहा जाता है कि छात्रों का उपद्रव है, उस में थोड़ा बहुत इस स्तर से हट कर हमें देखना चाहिए कि उन को मिलने वाली सुविधाएं किस तरह से दी जाती हैं, कितना परेशान कर के दी जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन के द्वारा जो हड़ताल किसी और आधार पर की जाती है, वह जायज है या नाजायज है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग भी इस के लिए जिम्मेवार होते हैं।

मान्यवर, स्कूलों में आज भी छुआछूत की बातें चलती हैं। स्कूलों में मैं ने देखा है कि वहां जो हरिजन टीचर हैं, वे पानी पीने के लिए अपने बर्तन लाते हैं। जब स्कूलों में ही ऐसी बात होगी, तब कैसे इस देश का उपकार होगा। जब बच्चे इस तरह की बातें देखते हैं तो उन के ऊपर इस का असर पड़ता है। ये सब चीजें गांवों के किसी घर साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों में भी होने लगें, तो यह सही छूत नहीं है और वहां पर इस तरह से छुआछूत का प्रचार नहीं होना चाहिए। जब तक इस तरह की बातें रहेंगी, तो देश का कल्याण कैसे हो सकता है।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr Chairman, I would like to bring a few ponits to the notice of the hon. Minister. Firstly, in my opinion, the Ministry of Education is the most unfortunate department for the last 30 years. It is because, whenever we go down the country side, when we discuss education, nobody is sure about the policy of the Government for the next year. There is always confusion in this department. Only yesterday the hon. Minister stated that the policy on 10+2+3 is still not finalized. My only request to the Education Minister is this: whatever policy you want to decide, please do it once and for all so that the students in the countryside and even the parents who want to give education to their children will be sure of the policy of the Government.

Secondly, under the 42nd Amendment Bill, education was included in the Concurrent List. As Shri Malhotra has very rightly stated, this is one of the right decisions taken by the 42nd Amendment Bill. I fully agree with him. I hear that Government are having re-thinking on this issue. If Government take away education from the Concurrent List, confusion would be created and the problem would continue to be there. In order to have the same pattern of education througout the country, it is very necessary that education should be in the Concurrent List. So, I would request the hon. Minister to give second thought to this.

Coming to primary education, according to the Report 848.38 lakh students of the age group 6 to 14 have been enrolled and another 452 lakh students have yet to be enrolled. The target of the Government is to enrol 452 lakh students. I do not know by what exercise they have arrived at this figure. I hope they have taken into consideration the rate of growth of population and, consequently, the children during this seven-year period. If they have not done this exercise, I would request the hon. Minister to do this exercise once more and correct it.

They would like to enrol these 452 lakhs of children in the age group of 6 to 14 within seven years, but seven years is a very long period. If they do not have sufficient funds, I shall presently indicate how they can overcome the problem. We have waited for 30 years. Every year, as so many hon. Members have pointed out, the number of illiterates is increasing in the country. So, if we have to wait for seven more years for bringing all the children in the age group of 6 to 14 under compulsory education, I think it is a very long period. Therefore, I request the hon. Minister to reconsider it and finish it within this Plan period itself.

We all know that it is a must in this age for every boy to have a minimum education. Therefore, wherever there are defects and difficulties found in the implementation of policies, they may appoint some committees to come to conclusions about them, but most of the policies are not wrong, only they are wrongly implemented. The defect lies in implementation. I, therefore,

[Shri G. Narsimha Reddy]

request the hon. Minister to see that they are properly implemented.

We have so many primary schools in our villages—I have my own experience as Chairman of the Zila Parishad of our district—where the teachers do not attend. For your information, teachers come hardly two or three times a month from other places and draw their salaries. You will be surprised to know that there are some villages which do not know that primary schools have been sanctioned for them. So, you can imagin that the teachers of those schools stay somewhere else and draw their salaries. So, the policy is correct, but in implementation we are very much lagging behind. Therefore, we have to take greater care about the implementation part of it.

Coming to secondary education, again we throw the blame on the staff or the students for the failures. We all know very well that the big officers, the well-to-persons and businessmen do not send their children to your Government schools. They send them to the private schools. Why? There are reasons for it. In so many of our secondary and high schools—I can quote so many examples from my State—you do not have mathematics or science teachers. How do you expect the parents to send their children to such schools? This is one of the reasons why the standard of education is going down.

I have yet not understood why they are having this system of higher education. Do we require for our clerical jobs BAs, B.Scs., and B. Coms? I do not think so. You have to draw a line regarding the minimum education required by a person. In my opinion, secondary school education is sufficient to give us all the LDCs and UDCs in this country. Higher education should be selective. Do not force all the boys to go to the colleges and roam about the streets wearing tight pants, seeking jobs. Once the boy of a small farmer or illiterate persons gets a degree, he is not prepared to go back to his father's profession. He does not get a job in Government service. So, instead of improving the standard of his family, we are spoiling the life of the family. Therefore, I suggest that the hon. Minister should think on this issue and decide as to how many boys have to go for higher education. The higher education should be selective like we have medical sciences and engineering sciences. Similarly, if you want some intelligent boys for research work, for literature work, then you have to decide about it. These boys who join colleges, after matriculation, and get degrees have no meaning. Therefore, this is an important issue on which you have to decide, that is, you have to decide how many students you require for higher education. If you decide about it, I am very sure .. you do not require so many colleges in taluka headquarters and in the villages; we do not require so many colleges at all. My personal opinion is that you will have to decide on this issue. If you do not decide on this issue, then you will be creating unemployment problem for the graduates. And these boys who come from the villages, from the poor families will not be able to go back and join the professions of their fathers, they will not be able to do their own profession. The result will be that they will be nowhere. I once more request the hon. Minister to consider this matter again.

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस देश म 90 प्रतिशत शोषित पोड़ित जनता है। उसकी शिक्षा का तथा उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान का मसला हमारे सामने है। आज तक जो शिक्षा की नीति रही है उससे लाभ केवल बड़े लोगों को हुआ है, बड़े घरानों को हुआ है और देश की जो 90 प्रतिशत जनता है, हरिजन, आदिवासी, गिरिजन, मुस्लिम और पिछड़े

वर्गों के लोग हैं उनको कोई लाभ इन पिछले तीस वर्ष के शासनकाल में नहीं हुआ है,— उस नीति से नहीं हुआ है जो इन पिछले तीस वर्ष से अपनाई गई है।

दो चीजों से देश को बड़ा नुक्सान हुआ है, एक अंग्रेजी भाषा और दूसरी जाति प्रथा दोनों ही राष्ट्रीय समस्यायें हैं। इन दोनों के हट जाने से देश में समता वाले समाज का निर्माण हो सकता है। हम सब ने वर्ण विहीन, वर्ग विहीन जाति विहीन समाज को अपने संविधान में व्यवस्था की है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश का जो सब से गरीब तबका है, सब से नीचे का जो तबका है उसको उठाने का काम केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये। आप देखें कि इन पिछले तीस वर्षों में सामाजिक और आर्थिक विषमतायें बढ़ी हैं। देश का मानस सिकुड़ा और संकीर्ण हुआ है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, परसों की हो बात है, बनारस में एक घटना घटी है। वहां पर दो दिन का एक सम्मेलन हरिजनों और पिछड़े वर्गों का आयोजित किया गया था। उस में रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम ने भाग लिया था, उसका उद्घाटन किया था। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने एक बहुत ही मामूली सी बात कही थी जो संविधान के मुताबिक भी थी और जनता पार्टी की नीति से मेल भी खाती थी। उस बात को लेकर बड़ा भारी रोष पैदा हो गया है। वहां पर जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने एक ऐसा निन्दनीय काम किया है जिससे हम सब के सिर शर्म से झुक जाते हैं। उन्होंने यही कहा था कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में पच्चीस प्रतिशत पर ब्राह्मण शिक्षक होने चाहिये और कर्मचारियों में भी गैर ब्राह्मण लोग भरती किए जाने चाहिऐ। साथ ही उपकुलपतियों में कोई गैर ब्राह्मण लोग रखे जाने चाहियें। यह देश में एक परम्परा सी चली आई है, एक संस्कार सा बन गया है जन्म से ही एक जाति विशेष बहुत बड़ी बन गई है, काबिल बन गई है, योग्य बन गई है और बाकी जो हिन्दुस्तान की जातियां हैं वे पिछड़ी हुई हैं। हिन्दुस्तान में दो तीन हजार जातियां हैं। एक ऋषि ने कहा था कि हिन्दुओं में 2003 जातियां हैं। उन्होंने सुपीरियर और लोअर कास्टस का जिक्र किया है। सुपीरियर कास्टस में उन्होंने आठ दस को गिनाया है और बाकी सभी जातियों को अनुसूचित जातियों जन जातियों में, पिछड़ी जातियों में रख दिया है। हजारों वर्षों से कोशिश करने के बावजूद भी इस जाति प्रथा का देश मे खात्मा नहीं हुआ है। महात्मा बुद्ध ने महात्मा गांधी ने, डा० राम मनोहर लोहिया ने तथा और भी सामाजिक विचारकों ने देश में कोशिश की है कि यह जाति प्रथा टूट जाए लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसका खात्मा नहीं हुआ है और यह चली आ रही है। इसके कारण बड़ी भारी देश में विषमता पैदा हुई है।

शिक्षा की नीति का जहां तक संबंध है, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बहुत विद्वान ही नहीं बल्कि कानून के पंडित भी हैं। इस वास्ते उनका ध्यान मैं संविधान को कछ धाराओं जैसे 340,46,15(4) 16(4) की ओर दिलाना चाहता हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह जनता सरकार में एक ऐसा चमत्कारी काम कर जायें जिससे जो दोनों अभिशाप हैं—जाति प्रथा और अंग्रेजी भाषा का नाजायज फायदा उठाना, यह दोनों खत्म हो और हम एक समतावादी समाज बनावें। यह कहना गलत न होगा कि हमारे उप-राष्ट्रपति महोदय ने गुड़गांव में जो भाषण दिया और आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है वह मैं सदन की जानकारी के लिये उद्धृत कर दूं उन्होंने कहा है कि :

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

"A few privileged upper caste families still predominate the senior administrative cadres such as IAS, IPS and IFS primarily because our educational and examination system continues to weigh heavily in favour of the so-called socially superior sections of Indian society."

He has further said:

"It is time that we scrapped the public school system and provide similar schooling to the sons and daughters of all sections of society, whatever be their origin."

मान्यवर, यह उनका भाषण है। हमारे सभी माननीय सदस्यों का यह विचार है कि पब्लिक स्कूलों में एक विशेष जाति के लोग ही पैदा किये जाते हैं और जो धनी लोग हैं, बड़े घराने के बच्चे हैं वही वहां पढ़ते हैं और गरीब लोगों के बच्चों की भर्ती भी नहीं वहां होती है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि जितनी जल्दी आप इनको अबालिश कर दें उतना ही अच्छा रहेगा और यह आपका एक क्रान्तिकारी कदम होगा।

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude in two minutes. There are so many Members who want to speak.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : 5 मिनट मुझे मान्यवर और दे दीजिये। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में पब्लिक स्कूलों के बारे में अवश्य कहें कि उनको कब तक बंद कर रहे हैं। और अगर ऐसा न कर सकें तो यह कानून जरूर बना दें कि कि 70 प्रतिशत बच्चे पब्लिक स्कूलों में हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के भर्ती होंगे।

मान्यवर कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल्स 15(4) और 16(4) इस प्रकार है;

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

इन दोनों आर्टिकल्स के मुताबिक मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि तामिलनाडु की सरकार ने 1971-72 में जो इसके मातहत कानून बनाना है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं जो बहुत ही क्रान्तिकारी और समाजवादी कदम है और मैं उस सरकार को बधाई देता हूं जो उन्होंने आर्डर पास किया है इस संविधान के अनुच्छेद के मातहत वह पढ़ना बहुत जरूरी है :

This is Tamil Nadu Government's G.O. No. 695 dated 7-6-1971:

"The Government have examined the recommendations of the Backward Classes Commission and the High Level Committee very carefully and have decided to increase the existing reservation for backward classes from 25 per cent to 31 per cent and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from 16 per cent to 18 per cent where reservation is provided by the State Government for the above classes.

"In supersession of all previous orders on the subject, the Government direct that, with effect from the academic year 1971-72, reservation of seats be made at 31 per cent for backward classes and at 18 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of all courses in all kinds of educational institutions under all kinds of managements (like Government Local Body

and Aided Managements) where reservations is provided by the State Government for the above classes."

The reservation of seats as per the above orders shall be a condition for the payment of any grant-in-aid from the funds of this Government to any private management or local body or to the Universities (in respect of courses conducted and institutions run directly by them).

The claims of members of the Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be considered for the remaining 51 per cent of seats which are filled on the basis of merit. Where a candidate belonging to Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes is selected on the basis of merit against any of the seats in the said 51 per cent of unreserved seats, the number of seats reserved for Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, should not in any way be affected.

यह चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से गरीब हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिये इस प्रकार से गवर्नमेंट ने आदेश किया था जो कि जायज है।

मैं कहूंगा कि जितने सैन्ट्रल स्कूल हैं जितने स्टेट स्कूल्स हैं उन सब को गाईडलाइन भेज दें कि कम के कम 100 में से 60 सीटें नौकरियों में इन के लिये रिजर्व की जायें। काका कालेलकर साहब ने अपने आयोग की सिफारिश में लिखा है कि 70 फीसदी सीटें रिजर्व का जायें। तभी हम समता का युग देखेंगे वरना विषमता बढ़ती जायेगी और जो बजट पेश किया गया है उसका फायदा 10 फीसदी लोग उठायेंगे और 90 फीसदी उससे वंचित रह जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी सारी नीति को स्पष्ट कर के सभी स्टेटों और सेंट्रल स्कूलों में, सर्विसेज में, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में इस नीति को लागू

"that the Classification of Backward Classes on the basis of caste is within the purview of Art. 15(4), if these castes are shown to be socially and educationally backward. There are numerous castes in the country which are socially and educationally backward. To ignore their existence is to ignore the fact of life. Hence we are unable to uphold the contention that the impugned reservation is not in accordance with Art. 15(4).

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसे सभा पटल पर रख देते हैं, यह बहुत जरूरी है।

इसमें एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को जायज माना है कि इस कानून को बनाना वैलिड है, कांस्टीट्यूशनल है। थोड़ा सा

चीफ जजमेंट का मैं आपको सुनाना चाहता हूं।

आपने देखा होगा कि बिहार में आज भी यह बात उठाई जा रही है कि आरक्षण इकनामिक आधार पर होना चाहिये। इस नजीर को आप देख लें, उससे मालुम होता है कि कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि बैकवर्ड का आधार सामाजिक होना चाहिये ना कि इकनामिक

जातियां जो बनी हैं वह इस हिसाब से बनी हैं कि जों आर्थिक ढंग से गरीब हो गये हैं, पिछड़ गये हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं सफाई और मजदूरी करते हैं वह छोटे रह जाते हैं और जो एयरकंडीशन में रहते हैं वह बड़े हो जाते है। इस तरह से संविधान के निर्माताओं ने समाजिक पिछड़ेपन को आधार माना है उसी पर सुप्रीमकोर्ट ने

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

रूलिंग दिया है इसलिये विहार के मसले को आप देख लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने वहां के मुख्य मंत्री और श्री जय प्रकाश नारायण को पत्र लिखा है कि इस नजीर को देखते हुए आर्थिक पचड़े में न फंसें बल्कि जो सामाजिक आधार इसमें है, उसको लागू करें।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण (कराड) : माननीय सभापति महोदय, मैं इन शिक्षा की डिमांडज फोर ग्रान्टस का समर्थन तो नहीं कर पाती, क्योंकि अभी जैसा सदस्यों ने बताया कि इसके लिये जो डिमांड की गई है, वह पूरी नहीं है। आज तक का इतिहास है कि जो भी शिक्षा पर खर्च किया जाता था वह हमारी लोक-संख्या और बड़े देश के लिये बहुत ही कम है। इसलिये मैं प्रथम तो मंत्री जी को यह कहूंगी कि आप इन डिमांड को पहले बढ़ाने की कोशिश करें और उसके बाद शिक्षा नीति, जिस पर आज इतनी बहस हो रही है और सब लोग उसे बुरा बता रहे हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। हमारे देश की शिक्षा प्राप्त कर के स्वामी विवेकानन्द जैसे बड़े बड़े लोगों और महात्माओं ने भारत जैसे देश को अमरीका आदि विदेशों तक पहुंचाया है। इस लिए हमारे देश की शिक्षा नीति एक दिशा बताने वाली नीति रही है। इस उदात्त शिक्षा नीति को पूरी तरह समझे बिना नीची कर के दिखाना उचित नहीं है।

लेकिन जब से हमें स्वराज्य मिला है, तब से आज तक हमारी कोई शिक्षा नीति बनी ही नहीं है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शिक्षा मंत्रालय आया, जो भी मंत्री बने, उन्होंने अपने अपने स्तर पर शिक्षा नीति को तोड़-मरोड़ कर बनाना चाहा। मैं अपनी पिछली सरकार की एक मिसाल देना चाहती हूं। किसी योग्य व्यक्ति को कोई महकमा न देते हुए मानों लाट्स डाल कर महकमें बांटे जाते थे। पिछली सरकार में डा० कर्णसिंह जैसे विद्वान को शिक्षा मंत्री न बना कर किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया, और उन्हें ऐसा महकमा सौंपा गया, जिस के बारे में वह कम जानकारी रखते थे। अगर उस वक्त उन्हें हैल्थ मिनिस्ट्री

और फैमिली प्लानिंग का काम न दिया जाता, तो जो देश में आज हो रहा है, वह न होता । फैमिली प्लानिंग के संबंध में जो भी ज्यादतियां हुई हैं, उन के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार समझती हूं, क्योंकि वह सब कुछ उन के दुर्लक्ष के कारण हुआ । उन ज्यादतियों का दोष पूरी सरकार पर लगाया जाता है, जबकि पूरी सरकार का इस में दोष नहीं था ।

एक सोशल वर्कर के रूप में मैं ने मंत्री महोदय को कहा था कि ये ज्यादतियां हो रहीं हैं, आप खुद जा कर उनकी जांच करें और इस बारे में एक्शन लें । लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि जबर्दस्ती करने का तो बहाना है, लोग फैमिली प्लानिंग करना नहीं चाहते हैं ।

शिक्षा मंत्री के हाथ में बहुत कुछ है । शिक्षा मंत्री को देश में शिक्षा का प्रसार करने के लिये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और उचित नीति को लागू करना चाहिए । अगर इस के लिए रास्ता देखते रहेंगे, तो बहुत समय बीत जायेगा । जब जनता सरकार ने शासन सम्भाला था, तो उन्हें आश्वासन दिया था कि हम शिक्षा को बहुत बढ़ायेंगे ।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue her speech tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, April 12, 1978/Chaitra 22, 1900 (Saka).

GMGIPND—L—352LS